राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या: 09

बुधवार,

15 फरवरी 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या 22

श्रीमती इन्दिरा देवी (अनुपस्थित)।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री अमित चाचाण।

नोहर में बीमा क्लेम से वंचित किसान

23. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ व रबी फसल वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कुल कितनी बीमा क्लेम की राशि का किसानों को भुगतान कर दिया गया है व कितने किसानों का भुगतान शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार बीमा क्लेम भुगतान से वंचित किसानों को कब तक भुगतान करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत नोहर विधान सभा क्षेत्र में खरीफ 2020 में 47 हजार 959 फसल बीमा पालिसी धारक किसानों को लगभग 116 करोड़ 4 लाख रु. के बीमा क्लेम वितरित किये गये हैं। योजना प्रावधानों के अंतर्गत उक्त मौसम सत्र के कोई बीमा क्लेम लंबित नहीं हैं।

(कृषि मंत्री)

रबी 2020-21 में 57 हजार 456 फसल बीमा पालिसी धारक किसानों को लगभग 263 करोड़ 44 लाख रु. के बीमा क्लेम वितरित किये गये हैं। योजना प्रावधानों के अंतर्गत उक्त मौसम सत्र के कोई बीमा क्लेम लंबित नहीं हैं।

खरीफ 2021 में 3 लाख 61 हजार 755 फसल बीमा पालिसी धारक किसानों को लगभग 181 करोड़ 52 लाख रु. के बीमा क्लेम वितरित किये गये हैं तथा 49 करोड़ 25 लाख रुपये के बीमा क्लेम 72 हजार 556 फसल बीमा पालिसी धारक किसानों को वितरणाधीन हैं। इसके अलावा शेष 11 हजार 859 फसल बीमा पालिसी धारक किसानों के लगभग 8 करोड़ 57 लाख रु. के बीमा क्लेम बीमा कंपनी द्वारा हाल ही राज्यांश प्रीमियम की मांग किये जाने के कारण अवितरित हैं। राज्यांश प्रीमियम भुगतान के उपरांत केन्द्रीयांश प्राप्ति के पश्चात् बीमा क्लेम वितरित हो सकेंगे।

रबी 2021-22 के बीमा क्लेम पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण हुई क्षेत्रफल विसंगति के समाधान कराये जाने के दृष्टिगत प्रक्रियाधीन हैं।

खरीफ 2022 के बीमा क्लेम उपज परिणाम प्राप्ति उपरांत परिकलित किये जायेंगे।

(2) सरकार योजना के प्रावधानों के अंतर्गत बीमा कंपनी के माध्यम से फसल बीमा पालिसी धारक पात्र किसानों को शीघ्र बीमा क्लेम का भुगतान कराने हेतु प्रयासरत है।

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा, आपने उत्तर में कहा है कि किसानों के 49 करोड़ 25 लाख रुपये बीमा क्लेम वितरणाधीन हैं, यह कब तक वितरित हो जाएंगे? शेष 11 हजार 859 फसल बीमा पालिसी धारकों के 8 करोड़ 57 लाख रुपये बीमा क्लेम बकाया हैं, उनका भुगतान कब तक होगा?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 49 करोड़ 25 लाख के बीमा क्लेम हैं, वह 23 जनवरी, 2023 को भुगतान कर दिया है। बाकी 8 करोड़ 57 लाख का बीमा क्लेम बाकी है, वह इसी वित्तीय वर्ष में किसानों को कर दिया जाएगा।

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, बीमा पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए सरकार व विभाग क्या कार्यवाही कर

(श्री अमित चाचाण)

रहा है? नोहर विधान सभा क्षेत्र में आज की तारीख में कितने पालिसी धारकों को कितनी राशि का क्लेम देना बकाया है, वह कब तक दे दिया जाएगा?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिख रखा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को। पोर्टल में जो तकनीकी खराबी थी, उसके कारण 4 हजार 730 फसल बीमा पालिसी नोहर तहसील की वहां विवादित हैं। उन्होंने हमको अगले सत्र के लिए, यानी महीने भर के लिए आश्वस्त किया है कि इनका आगे पेमेंट कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डा. राजकुमार शर्मा।

नवलगढ़ में पेयजल परियोजना का सर्वे

24. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर से जिला झुंझुनूं के कस्बों और गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं? यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं से उक्त जिले के किन-किन कस्बों व गांवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के विभिन्न ग्रामों को उक्त परियोजना से जोड़ने व पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सर्वे किया गया है? यदि हां, तो सर्वे के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या को देखते हुए कस्बों व गांवों को उक्त परियोजनाओं से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जी हां। झुंझनूं जिले के 9 कस्बों एवं 653 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल आधारित 05 पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति अब तक जारी की गई है तथा इनमें से 01 परियोजना का कार्य पूर्ण किया जाकर जिले के 05 कस्बे एवं 258 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। परियोजनावार स्वीकृति विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं में झुंझनूं जिले के सम्मिलित कस्बे एवं ग्रामों की परियोजनावार सूची क्रमश: परिशिष्ट-ब एवं परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जल संसाधन विभाग की सहमति के अनुसार कुम्भाराम लिफ्ट के स्थान पर सतही जल स्रोत इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आर.डी. 103.00 पर प्रस्तावित आफ-टेक से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के कस्बा नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ तथा समस्त 109 ग्रामों की पेयजल मांग सम्मिलित करते हुए आधारभूत संरचनाओं के कार्य एवं उक्त क्षेत्र के 59 ग्रामों में पेयजल वितरण प्रणाली इत्यादि के कार्यों का प्रावधान सम्मिलित करते हुए, सीकर एवं झुंन्झुनूं जिलों के 18 क़स्बे, 1133 ग्राम एवं 2836 ढाणियों में हर घर जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किये गये सर्वे के उपरांत राशि रुपये 8082.76 करोड़ की बनाई गई परियोजना के प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष तकनीकी परीक्षण में वर्तमान में विचाराधीन हैं। तकनीकी परीक्षण उपरान्त इन प्रस्तावों की स्वीकृति पर राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की आगामी समय में प्रस्तावित बैठक में निर्णय सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। उक्तानुसार कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के शहर नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ तथा समस्त 109 आबाद राजस्व ग्रामों में भू-जल उपलब्धता अनुरूप की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है। भू-जल की उपलब्धता, पेयजल की आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में जल योजनाओं का संवर्धन/पुनर्गठन का कार्य सतत प्रक्रिया के तहत किया जाकर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने के विभाग द्वारा पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, कुम्भाराम लिफ्ट योजना में रखें, मंत्री महोदय, एक तो प्रार्थना आपके माध्यम से, कृपया करके इस योजना को चेंज नहीं करें। दूसरा, हमारी 9 पंचायतें ऐसी हैं, गोठड़ा, देवगांव, खिरोड़, बसावा, चिराना, लोहार्गल, देवपुरा बनी, बागोरियों की ढाणी, देवा की ढाणी, गिरधरपुरा, जिसमें पेयजल है ही नहीं, सतही पेयजल है ही नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो अधिकारियों ने कहा है कि वहां पेयजल सुचारु रूप से चल रहा है, इन 9 पंचायतों में हालत खराब है। प्रार्थना आपकी, आप विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि 9 पंचायतों के लिए विशेष योजना बनाएं। कुम्भाराम लिफ्ट योजना से जोड़ें नवलगढ़ से।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। माननीय सदस्य, प्रश्न।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की तारीफ भी करना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के प्रति इतनी संवेदनशीलता के साथ वह कामों में रुचि लेते हैं। पेयजल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन गांवों के बारे में माननीय विधायक महोदय ने इंगित किया है, इनके बारे मैं दिखवाऊंगा। मेरे अधिकारी आपसे विशेष रूप से सम्पर्क करके, अगर वहां कोई कमी है तो उसको पूरा करने का हर सम्भव हम प्रयास करेंगे।

जो प्रोजेक्ट हमने भेजा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट यह बड़ा काम्प्लीकेटेड प्रोजेक्ट हो गया। कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल में जितनी पानी की उपलब्धता थी उसके हिसाब से हमने गांवों में जल उपलब्ध करा दिया। उनको उन योजना में जोड़ दिया। जहां नहीं है वहां आर. डी. 103 मुख्य कैनाल की, वहां से आफ-टेक करके हम पानी लेकर जा रहे हैं। मैं माननीय विधायक महोदय को आश्वस्त करता हूं कि आपके यहां जो योजना बनी है, भविष्य में कोशिश करेंगे कि इसमें कोई चेंज नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

सवाई माधोपुर में अवैध खनन के प्रकरण

25. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सवाई माधोपुर में विगत तीन वर्षों में अनियमितता व अवैध खनन के कितने प्रकरण सामने आये? सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने अवैध खनन को रोकने एवं निगरानी के लिए चैक पोस्टों पर सी सी टी वी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की पालना कर दी गई है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (खान मंत्री के स्थान पर): (1) सवाई माधोपुर ज़िले में विगत तीन वर्षों (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा

(श्री रामलाल जाट)

2022-23 (दिनांक 20.01.2023 तक)) में खनिज रियायत धारकों द्वारा की गई अनियमितता तथा अवैध खनन के 71 प्रकरण सामने आये हैं। खान विभाग द्वारा इन प्रकरणों में दिनांक 20.01.2023 तक की गई कार्यवाही का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में अवैध खनन के 164 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इनमें विधान सभा क्षेत्रवार की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा बजरी लीज एल.ओ.आई. होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी की रिट याचिका संख्या 9836/2019 में आदेश दिनांक 31.05.2019 से खनिज बजरी के अवैध खनन को रोकने/निगरानी के लिए पूर्व से उपलब्ध सी.सी.टी.वी. कैमरों को याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा स्थापित किये गये चैक पोस्टों पर लगवाने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में राज्य में बजरी निर्गमन के मुख्य संवेदनशील मार्गों की चैक पोस्टों पर खानधारक/एल.ओ.आई. होल्डर्स द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये गये हैं। अन्य चैक पोस्टों पर खानधारक/एल.ओ.आई. होल्डर्स द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे उपलब्ध नहीं करवाने से नहीं लगवाये गये हैं। अत: विभाग का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पहला पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में अवैध खनन की जांच करने हेतु सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई थी? उस कमेटी ने विधान सभा क्षेत्र बामनवास में अवैध खनन होने की पुष्टि की है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध खनन करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कमेटी बनायी है, कमेटी ने जांच की जिसमें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय चन्द्रभानजी, मुझे रोज रिमाइंड करना पड़ता है। अनफोर्च्यूनेट।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): जिसमें मैंने परिशिष्ट-1 पर इनको

(श्री रामलाल जाट)

यह बताया है कि 71 प्रकरण सामने आये हैं, जिनमें कार्यवाही की है। सबके शास्ति लगायी है, किसी के खनन पट्टे जांच करके अपखंडित किये गये, जिसमें पांच खनन पट्टे जो इनको परिशिष्ट-1 पर दिया, जिसमें क्रम संख्या 2 से 6 तक कुल पांच खनन पट्टे दिनांक 10.02.2023 को खंडित करके निरस्त कर दिया गया। बाकी सारे खनन पट्टों पर पेनल्टी लगायी जो लगभग पेनल्टी 66 लाख के करीब है, जो कुछ ने जमा करवा दी।

मुख्यतः मिट्टी, जो नेशनल हाईवे बना है, उसमें मिट्टी ले जाना पाया गया या किसी सीमा में गार्ड नहीं था, उनके यह पेनल्टी लगी, किसी ने वृक्षारोपण नहीं किया, उनके वह पेनल्टी लगी। कुछ लोगों ने जमा करवाया और जो जमा नहीं करवाया गया, उनको निरस्त कर दिये गये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी, क्या यह सही है कि दिनांक 18 मार्च, 2021 को राजस्थान विधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में अवैध रूप से संचालित खानों की एक विशेष कमेटी बनाकर जांच की जायेगी? यदि हां, तो जांच में जो कोई गलती पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी? तत्पश्चात् एक विशेष कमेटी द्वारा जांच की गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मैं प्रश्न पर ही आ रही हूं। मेरी लास्ट लाइन प्रश्न पर ही है। कमेटी ने जांच में अवैध खनन पाये जाने के बावजूद भी आज तक उक्त अवैध खनन को बंद क्यों नहीं किया गया? इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? हां या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it. यह प्रश्न काल है। ऐसा नहीं है कि आप बिलकुल ही बोले ही जायें।

माननीय मंत्रीजी।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का पहला, दूसरा क्वेश्चन है, जो दर्ज प्रकरण इन्होंने विधान सभावार मांगा है, जिनमें पांच प्रकरणों में अवैध माइनिंग पकड़ी गयी है। पांचों

(श्री रामलाल जाट)

का निस्तारण हुआ है, जिनमें 11 लाख 35 हजार रुपये इनके शास्ति लगी है। पूरे जिले के लगभग 66,15,810/- रुपये की शास्ति लगी है और मैंने पूर्व में यह बताया है जो कि परिशिष्ट-1 पर दर्ज है, इनको यह विवरण दिया है, उसमें पांच जो पट्टे हैं, वे जांच में निरस्त किये गये। बाकी कुछ में पुलिस एफ.आई.आर. भी हुई, जिसमें पुलिस एफ.आई.आर. में चालान भी हुआ। एक केस में एफ.आर. लगी है और बाकी माइनिंग डिपार्टमेंट की जो पालिसी है, वह नेशनल हाईवे में अधिकतर मिट्टी ले जाना पाया गया, उन पर शास्ति लगाकर, पेनल्टी लगाकर वसूल किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनका प्रश्न यह है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में आश्वासन दिया है, उस पर कोई कार्यवाही हुई है क्या?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का इसमें हवाला नहीं है लेकिन जो कमेटी बनायी है, हो सकता है वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से बनायी है। कमेटी ने जांच की जिसमें सारे माइनिंग पट्टे, इनके टोटल पट्टे 71 हैं, जिनका एक-एक चाहे तो मैं नाम बता दूं?

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आप खाली सिम्पल बतायें कि कमेटी के बाद एक्शन हुआ या नहीं हुआ? that's all.

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कमेटी गठित हुई, जांच की गयी, उसमें पांच अपखंडित किये गये, बाकी सब पर शास्ति लगी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

कोटड़ी पंचायत समिति में रिक्त पद

26. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटड़ी में विकास अधिकारी का पद वर्तमान में रिक्त है? विगत दो वर्षों में उक्त पंचायत समिति से कितने विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत समिति में विकास अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी नहीं। विभागीय आदेश क्रमांक 573 दिनांक 13.02.2023 द्वारा श्री रामबिलास मीणा को विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। (प्रति संलग्न)

विगत दो वर्षों में पंचायत समिति कोटड़ी से स्थानान्तरित विकास अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है-

क्रम संख्या	नाम अधिकारी
1	श्री संदेश पाराशर
2	श्री रामबिलास मीणा
3	श्री विनेश कुमार
4	श्री गुलाब सिंह गुर्जर

विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

(2) जी हां। विभागीय आदेश क्रमांक 573 दिनांक 13.02.2023 द्वारा श्री रामबिलास मीणा को विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, आपने यह जवाब दिया कि कोटड़ी पंचायत समिति में चार विकास अधिकारी लगाये परंतु मेरे पास यह पंचायत समिति की सूचना है, इसमें 19 लगाये हैं। 01.04.2020 के बाद में 19 लगे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण रहा कि इतने विकास अधिकारी बदले? इसका कारण बतायें और यह जो अभी आपने मेरे क्वेश्चन के बाद जो विकास अधिकारी लगाया है, वह कितने दिन रहेगा? वहां पर कोई काम करेगा या किसी फाइल पर साइन करेगा? यह आप बताने की कृपा करें।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): काम करेगा। बिलकुल निश्चित रूप से काम करेगा, आप निश्चिंत रहें।

दूसरा, आपने 19 का प्रश्न किया है, आप 19 विकास अधिकारी बता रहे हैं, वह आपके पास पूरे तथ्य नहीं हैं और जो विकास अधिकारी हमने लगाये हैं, वह बता दें चार के अलावा? संदेश पाराशर लगे थे और वे एक साल के करीब रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया बीच में, उस वजह से हमने जो बीच में

(श्री रमेश चन्द मीना)

लोग लगाये हैं, सबसे पहले मैं आपको पूरा-पूरा बता देता हूं। सुश्री स्नेहल धिगदे नाना, आई.ए.एस., 25.01.2021 से 22.02.2021, ये एक माह रही हैं। राजेन्द्र सैन जो बीच में खाली था तो राजेन्द्र सैन, जो सहायक विकास अधिकारी थे, यह कार्यवाहक तीन महीने रहे हैं। ठीक है? और उसके बाद कलेक्टर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इन 15 का कोई मतलब नहीं।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्वेश्चन यह पूछना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं समझ गया, आप बैठें। माननीय मंत्रीजी, खाली इनका प्रश्न का उद्देश्य यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था से ये 10 आदमी लगाये हैं। अब जो लगा रहे हैं, वह काम करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में एश्योर करने के लिए वे पूछ रहे हैं।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बिलकुल काम करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक महोदय को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई प्रोब्लम है, कोई दिक्कत है, आपको कहीं पर कोई परेशानी है तो उसकी जांच भी करवायेंगे। जयपुर से स्टेट कमेटी भेज देंगे। आपका कोई काम बाधित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अशोक डोगरा।

बूंदी में खाद्य सुरक्षा में पंजीकृत परिवार

27. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में खाद्य सुरक्षा योजना हेतु कुल कितने पात्र परिवार हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में पंजीकृत हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सभी परिवारों को उक्त योजना में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में खाद्य सुरक्षा योजना हेतु कुल 65972 पात्र परिवार (253475 यूनिट) पंजीकृत हैं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत समावेशन निष्कासन निर्धारित मापदण्ड अधिसूचना दिनांक 27-09-2018 के अनुसार चयन की प्राथमिकता श्रेणियों में बिन्दु संख्या 5 के उपबिन्दु-

A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना

B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना

C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना

D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना

E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेन्शन योजना

F. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेन्शन योजना

उक्त श्रेणियों में चयनित लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारक मानते हुए उनके परिवारों को आवेदन उपरान्त खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान करवाया जाता है। अधिसूचना दिनांक 27-09-2018 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी ने आखिरी पैरा में जो लिखा है, उक्त श्रेणियों में चयनित लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक मानते हुए उनके परिवारों को आवेदन उपरांत, अब आवेदन उपरांत तो आपके पोर्टल तो बंद ही रहते हैं, कभी चलते ही नहीं हैं। अब वह विकलांग है या वृद्ध है, उनको आवेदन शब्द हटाते हुए क्या सबको लाभ देने का विचार रखते हैं?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह आपको मैंने नीचे सूचना दी है और जो कैटेगरीज हमने तय की है, उसमें आपको मैंने सैकण्ड में यह जवाब भी दिया है। यह जो पोर्टल अभी हमने खोला था, इस पोर्टल पर जो एप्लाई करते हैं उनको दिया जाता है।

ऐसे भी जो नि:शक्तजन हैं, मान लीजिए जो विकलांग हैं और उसके घर में कोई इनकम टैक्स पेयर है, किसी के घर में चौपहिया वाहन है, तो ऐसे में जो डिजर्व करते हैं, उनकी पूरी कैटेगरीज तय है और भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून जब बना उसके बाद सारी कैटेगरीज तय कर दी, राजस्थान सरकार ने उसको लागू कर दिया। अभी पोर्टल खुला, उस पोर्टल पर

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

तेजी से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको यह लगता है कि कोई कमी रह गयी तो अभी वापस पोर्टल पर, यदि पोर्टल खुलता है तो आप उसको एप्लाई करवायें। यदि कहीं बहुत ज्यादा नीडी है, ऐसे में एम.एल.ए. को यह लगता है कि यह व्यक्ति कोई रह गया है, मैं पूरे सदन को यह सूचित कर रहा हूं, तो वह एस.डी.एम. के पास जाकर या यदि वह वहां नहीं जा सकता है तो एस.डी.एम. को यह पावर्स दिये गये हैं कि उनको इस खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में वह जोड़ सकता है।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.डी.एम. वगैरह की हमने कई बार ट्राई कर ली, वे इसको एंटर्टेन करते ही नहीं हैं। वे तो यह कहते हैं कि पोर्टल लगा हुआ है तो आप पोर्टल पर जायें। जब कोई विकलांग है या वृद्ध है तो उसको, जो जरूरतमंद है उसका तो करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह प्रश्न सबका है। पोर्टल निश्चित तौर पर खुलना चाहिए, वह नहीं खुल रहा है और लोग एप्लीकेशन देते हैं एस.डी.एम. के पास, एस.डी.एम. उसको वापस वैरिफाई करने के लिए भेजता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो आपकी प्राथमिकता है, वे प्राथमिक श्रेणियां वंचित हैं। आप विभाग के द्वारा यह निर्देशित करें कि जितने भी इस कैटेगरी के आ गये हैं उनको तात्कालिक प्राथमिकता के आधार पर निकालें और आप एस.डी.एम. को बाउंड करें कि वह यह एक्सक्यूज नहीं करे। कंफ्यूजन यह हो रहा है कि लोग एप्लीकेशन देते हैं एस.डी.एम. के पास और एस.डी.एम. यह कहता है कि पोर्टल में जाओ, तो यह दोहरी व्यवस्था कर रखी है और पोर्टल में जब तक नाम नहीं जुड़ेगा तब तक उसका नाम आयेगा ही नहीं, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को जितनी रिलीफ मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। इसमें विभाग थोड़ा इंटरेस्ट लेकर इसको कार्डिनेट करे।

अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

जोधपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भत्ता

28. **श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का मानदेय, क्रय सामग्री, भवन किराया की कितनी-कितनी राशि, कितने-कितने समय से किन कारणों से बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पब्बाराम)

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल उपलब्ध कराते हुए नेट रिचार्ज के लिए भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त भत्ता कितने समय से बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त बकाया राशि का भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जिला जोधपुर में कुल 12 परियोजनाओं में 2279 आंगनबाड़ी केन्द्र व 262 मिनी केन्द्र स्वीकृत हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय नियमित रूप से दिया जा रहा है। जोधपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का माह दिसम्बर 2022 तक का मानदेय भुगतान ब्लाक भोपालगढ़ को छोड़कर शेष सभी 11 ब्लाक्स में कर दिया गया है।

जोधपुर जिले में क्रय सामग्री का वित्तीय वर्ष 2022-23 का भुगतान जिले के 12 ब्लाक्स में से 10 ब्लाक्स में कर दिया गया है। शेष 2 ब्लाक्स जोधपुर सिटी एवं बालेसर में क्रय सामग्री भुगतान प्रक्रियाधीन है।

जोधपुर जिले में आंगनबाड़ी भवन किराये का भुगतान 11 ब्लाक्स में कर दिया गया है तथा एक ब्लाक बाप में प्रक्रियाधीन है।

शेष भुगतान का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पोषण अभियान अन्तर्गत पोषण ट्रेकर पर कार्य करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डाटा प्लान की राशि दी जाती है। पूर्व में पोषण अभियान अन्तर्गत पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन के संचालन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 200 रुपये प्रतिमाह अर्थात् 2400 रुपये प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान था। दिनांक 01.08.2022 को भारत सरकार द्वारा नवीन गाइडलाइन के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकताओं को मोबाइल डाटा प्लान की राशि 2400 रुपये प्रतिवर्ष के स्थान पर 2000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है। पूर्व में मोबाइल डाटा प्लान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा 80 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत वहन की जाती थी। उसमें केन्द्र सरकार द्वारा अपना अंश 80 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। इस कारण राज्य सरकार द्वारा व्यय राशि 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। मोबाइल डाटा प्लान की राशि का भुगतान भारत सरकार से केन्द्रांश राशि प्राप्त नहीं होने के कारण जुलाई 2022 से बकाया चल रहा है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(3) भारत सरकार द्वारा मानदेय की राशि दिसम्बर 2022 तक की जारी की गई है, अन्तिम त्रैमास की राशि आज दिनांक तक भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है, जिसके लिए भारत सरकार को पत्र भी दिनांक 30.01.2023 को लिखा गया है। परिशिष्ट-अ में उल्लेखित बकाया मानदेय, क्रय सामग्री एवं बकाया भवन किराया का शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा।

भारत सरकार से पोषण अभियान अन्तर्गत भी केन्द्रांश राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। राशि जारी करने के लिए भारत सरकार को पत्र दिनांक 12.10.2022, 14.12.2022 व 25.01.2023 को लिखे जा चुके हैं। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर बकाया डाटा प्लान का भुगतान कर दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा प्रश्न ही पूछ लेता हूं ताकि समय बचे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहुत ही अल्प मानदेय पर जीवित रहने वाली बहनें हैं, उनका केन्द्र या आपका विभागीय स्तर पर कहीं पर भी कोई मानदेय बकाया है तो अपने अधिकारियों को मोबिलाइज करके, तुरन्त उनका मानदेय दिलवाया जाए।

दूसरा, सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के ज़रिये गर्म पोषाहार एवं नाश्ते की आपूर्ति की गई, 2019 से 2022 तक उन बहनों का बकाया भुगतान है, आप यह कब तक कर देंगे? इतना-सा बता दें।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, उसका जवाब इन्होंने पढ़ा हुआ माना। इन्होंने मानदेय कर्मचारियों के सन्दर्भ में चिन्ता व्यक्त की, वह भी उचित है। हम लोगों ने अभी भी, मानदेय कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर एक स्टाईपेंड दो से तीन लाख रुपये उनको देने की घोषणा की है माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो मैं समझती हूं कि हिन्दुस्तान में पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरह की पेंशन योजना मानदेय कर्मचारियों के लिए बनाई गई है।

पिछले चार वर्षों से लगातार हम हर वित्तीय वर्ष में मानदेय

(श्रीमती ममता भूपेश)

कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा रहे हैं, उनका मानदेय बढ़ा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने अभी तक, चार वर्षों में एक बार भी मानदेय कर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने एसएचजी की चिंता की है, मैं आपके माध्यम से सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि दस दिन के भीतस्भीतर एसएचजी का भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह।

छबड़ा में सड़क सुविधा से वंचित राजस्व ग्राम

29. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के सभी राजस्व गांव वर्तमान में ग्राम पंचायत मुख्यालय से सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौनसे गांव हैं जो उक्त सुविधा से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सरकार सड़क सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में डामर सड़क सुविधा से वंचित राजस्व गांवों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक आबादी वाले 5 राजस्व गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं, जिनमें से 4 राजस्व गांवों के सड़क मार्ग वन क्षेत्र में स्थित हैं तथा एक गांव कांसल (570) को डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, जिसको मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने जवाब में बताया है कि चार गांव वन विभाग की भूमि आने के कारण सड़क सुविधा से जुड़े हुए नहीं हैं मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उसके लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए विभाग ने कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अभी यह चारों फाइनेंस को भेज दिए हैं। उसमें वन विभाग के अन्दर कई बार, जमीन का ट्रांसमिशन होता है, उसमें जमीन देनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सम्पूर्ण कार्यवाही कर ली है। उसके उपरांत भी, जहां-जहां जो परेशानी थी, जो पैसा जमा होता है, उसके लिए भी हमने अलग से व्यवस्था करके फाइनेंस को भिजवा दिया है। मेरे हिसाब से यह शीघ्र स्वीकृत हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: चारों सड़कें स्वीकृत हो जाएंगी?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चारों सड़कें स्वीकृत हो जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। मदन दिलावर।

बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना

30. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2022-23 में बेघर एवं पुनर्वास हेतु सर्वे करवाकर जन आधार कार्ड बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कितने कार्ड बनाये गये व कितने लाभान्वित हुए? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा, रिसर्च, शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु जामडोली, जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय कहां व कब स्थापित किया गया तथा इसमें कितने लाभार्थी लाभ ले रहे हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, 2022 का केबिनेट बैठक में दिनांक 24.11.2022 को अनुमोदन करवाया जाकर दिनांक 08.12.2022 को अधिसूचना जारी की गई है। नीति के प्रावधानानुसार कार्ययोजना तैयार कर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों का सर्वे एवं पहचान-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा, रिसर्च। शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु जामडोली, जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किए

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

जाने हेतु "बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2022" का सक्षम स्तर से अनुमोदन होने के उपरान्त स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति क्या है, उसमें क्या प्रावधान है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पालिसी के बारे में प्रश्न नहीं पूछते। सीनियर आदमी है। Please be specific.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या साहब?

श्री अध्यक्ष: पालिसी के बारे में प्रश्न नहीं पूछते हैं, please be specific.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): तो उसमें प्रावधान क्या है, इतना बता दें? अभी तक प्रावधान के अनुसार शहर व गांव में, कौन-कौनसे गांव में सर्वे चल रहा है? सर्वे के मुताबिक कितने-कितने लोगों का, किस-किस गांव-शहर में चयन कर लिया गया है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी टॉस्क फोर्स की पहली बैठक 10 जनवरी, 2023 को हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा है कि इसके प्रावधान क्या हैं। ऐसे गरीब लोग जो या तो खुद गरीब हैं, वह सक्षम नहीं हैं या गांव से मजबूरी में शहरों में काम करने के लिए आए हुए हैं जो बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, चिल्ड्रन होम, राजकीय होम या जहां भवनों का निर्माण चल रहा है, वहां खुले में रहते हैं, उनको छत उपलब्ध कराने की यह नीति है। जिसके अन्दर प्रति व्यक्ति को सर्वे कराकर, कम से कम...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पालिसी के बारे में नहीं। आपने किया है काम, कितने गांव हैं, आप उसका जवाब दे दें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अभी 10 जनवरी को मीटिंग हुई है। इसके अन्दर हमने ईओ.आई. जारी करने की प्रक्रिया जारी कर दी है। साथ ही साथ, इसमें जो ग्राम पंचायत का सर्वे है वह वहां ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग करेगा, जिसका प्रति सर्वे हमने इंसेंटिव रखा है। सर, प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। अभी जनवरी में ही इसकी पहली मीटिंग हुई है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो रेगुलर चलती रहेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इन्होंने खण्ड-2 में जवाब दिया है कि सक्षम स्तर से अनुमोदन करवाया जाएगा, तो सक्षम स्तर कौन है, उसके पास अनुमोदन के लिए पत्रावली कब भेजी है, अभी तक पेंडिंग क्यों है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सक्षम स्तर तो, लास्ट में तो विधान सभा ही है। अभी इसमें, इसी सत्र में इसका विधेयक लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके अन्दर आ जाए और बहुत ही जल्दी इसी सत्र में, विधान सभा में हम प्रस्तुत करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सब गम्भीर है। I will not allow it. I will not allow it. रिकार्ड नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न। रामनिवास गावडिया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: Mr. I will name you. Mr. Madan Dilawar! रिकार्ड नहीं किया जाए। Mr. Madan Dilawar, I will name you. I will name you, I said. Mr. Rathore, I will name him. Mr. Rathore, I will not tolerate it. Mr. Jogeshwar (Whip), I don't expect this thing from a senior member. कोई इम्पोज करेंगे आपकी बात को क्या? यह हाउस आपके इम्पोज करने के लिए है? आप सीनियर आदमी हैं, आप अपनी बात को यहां पर इम्पोज करेंगे? मंत्री जी क्या बोले। (व्यवधान) आप कहते हैं वो ही जवाब आएगा? आप खुद मंत्री रहे हैं। (व्यवधान) आप सुन नहीं रहे क्या, प्रोब्लम है कुछ ...(व्यवधान) माननीय सदस्य। Don't comment! बैठे-बैठे कोई भी नहीं बोलेंगे। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 31

श्री रामनिवास गावड़िया।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

देवली-उनियारा में जनजाति छात्रावासों की स्थापना

32. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत चार वर्षों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने छात्रावास खोले गये? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अनुसूचित जनजाति के छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु प्रदेश में विगत 4 वर्षों में 15 नवीन छात्रावास खोले गये हैं। विधान सभावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या 39.4 में श्रीपुरा देवली, टोंक में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): महोदय, मेरा मूल प्रश्न है कि प्रदेश में विगत चार वर्षों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कितने छात्रावास खोले गये? इसका मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया, मैंने देख लिया।

अगला प्रश्न खण्ड-2, मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने का सरकार का इरादा है या नहीं? मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट 2023-24 में श्रीपुरा में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं जनजाति छात्रावास और आवासीय विद्यालय को क्या आप एक ही मानते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): जी, सर।

श्री अध्यक्ष: बैठकर सुनें, अच्छा रहेगा।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावास और आवासीय विद्यालय अलग-अलग हैं।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि आवासीय विद्यालय, जहां बच्चे रहकर वहीं पढ़ेंगे। छात्रावास वह है...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज आप बैठें। आप प्रश्न पढ़ें। इन्होंने प्रश्न लिखा है, क्या सरकार का विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने का विचार है? तो छात्रावास का है, आपने विद्यालय का जवाब दिया, यह प्रश्न है। प्रश्न यह लिखा हुआ है कि छात्रावास खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, उत्तर दे रहे हैं विद्यालय खोल रहे हैं। आप छात्रावास के बारे में बोलें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जब शेम कर रहे हो, तो मेरा काम आप कर लो। अजीब है बिलकुल।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही निवेदन कर रहा हूं। छात्रावास और आवासीय विद्यालय में अन्तर यह है कि छात्रावास में बच्चे रह कर सरकारी स्कूल पास में जो चल रहा है, वहां पढ़ने जाते हैं और आवासीय विद्यालय का अर्थ यह है कि बच्चे वहीं रहकर वहीं...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्न यह नहीं पूछा है। आप छात्रावास खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? सीधी बात है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): छात्रावास खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: बस। उत्तर यही आना चाहिए न, इसमें तो विद्यालय लिखा हुआ है। जवाब में विद्यालय की जगह लिखना चाहिए था कि छात्रावास खुलेगा। प्रश्न छात्रावास का है और हम विद्यालय के बारे में बोल रहे हैं। यह उनका प्रश्न है। माननीय सदस्य।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): प्रश्न का जवाब जैसा इन्होंने दिया, मैंने सुना। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया फिर भी...

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न का सोल्युशन हो गया न, खोल रहे हैं। बात खतम हुई।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): खोलेंगे। ठीक है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): नहीं सर, मेरा सवाल एक और है। मंत्रीजी ने जिलों और स्थानों के नाम दिये जहां इन्होंने छात्रावास खोले हैं।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

प्रमुख जिले झालवाड़, बारां, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर, अलवर इत्यादि की जनजाति की आबादी को छोड़ दिया है तो क्या उनको जनजाति को लाभ देना चाहते हैं या इरादा कुछ और है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

उच्चैन व नदबई में आबकारी निरीक्षक कार्यालयों की स्थापना

33. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई के तहसील मुख्यालय उच्चैन व नदबई में निरीक्षक कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भरतपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र नदबई के तहसील मुख्यालय उच्चैन व नदबई में आबकारी विभाग का निरीक्षक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब बाकी क्या बचा है जब मना कर दिया है?

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा वर्तमान में बयाना में आबकारी निरीक्षक का जो कार्यालय है, वहां की दूरी नदबई से 50 किलोमीटर पड़ती है और नदबई में बड़े स्तर पर अवैध शराब का धंधा होता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो, माननीय सदस्य।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): कई बार ऐसा हुआ है कि शराब माफिया चले जाते हैं, भाग जाते हैं। दूरी ज्यादा होने के कारण वहां पुलिस नहीं पहुंच पाती है। क्या वहां पर नया कार्यालय खोलने का विचार रखते हैं?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भरतपुर, बयाना, डीग में निरीक्षक वृत्त कार्यालय पहले से ही है, जिसमें 67, 54 और 62 है। नदबई और उच्चैन में कुल मिलाकर 20 दुकानें हैं। वहां पर कार्यालय सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मनोज कुमार।

सुजानगढ़ ब्लाक में भवन विहीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र

34. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सुजानगढ़ ब्लाक में कितने पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने भवन विहीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या सरकार उक्त भवन विहीन चिकित्सा उप केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) वर्तमान में सुजानगढ़ ब्लाक में 25 पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 19 पशु चिकित्सा उप केन्द्र राजकीय भवन विहीन हैं जो कि पंचायत द्वारा प्रदत्त/वैकल्पिक व्यवस्था में उपलब्ध करवाये गये भवनों में संचालित हैं।

(2) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न नहीं पूछना है? धन्यवाद।

अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

डार्क जोन क्षेत्रों का सर्वे

35. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने भू-गर्भ जल के डार्क जोन क्षेत्रों का पुनः सर्वे कराये जाने का नीतिगत निर्णय किया था? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में भू-जल की दृष्टि से कितने ब्लाक अतिदोहित, गंभीर, कुछ गंभीर एवं सुरक्षित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भू-जल दोहन के नियंत्रण के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

भू-जल मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जी हां। नीतिगत निर्णय की पालना में राज्य भू-जल विभाग प्रतिवर्ष नियमित रूप से सर्वे करता है तथा

(भू-जल मंत्री)

एक नियमित अंतराल के पश्चात् राज्य के भू-जल संसाधनों का आकलन किया जाता है। इसी क्रम में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड व भू-जल विभाग द्वारा संयुक्त स्तर पर राज्य के भू-जल संसाधन की नवीनतम आकलन रिपोर्ट 2022 तैयार कर अन्तरविभागीय राज्य स्तरीय कमेटी से अनुमोदन करा कर जारी कर दी गई है। परिशिष्ट-1 (पेज नं. 1 से 17)

(2) वर्तमान में भूजल आकलन की नवीनतम रिपोर्ट 31.03.2022 के अनुसार राज्य के 295 ब्लाक एवं सात शहरी क्षेत्रों में से 219 ब्लाक को अतिदोहित श्रेणी, 22 संवेदनशील, 20 अर्द्धसंवेदनशील, 38 सुरक्षित में वर्गीकृत किया गया है। शेष 3 ब्लाक में भू-जल लवणीय (Saline) होने के कारण रिपोर्ट में इनका भू-जल आकलन नहीं किया गया है। (सात शहरी क्षेत्र सम्मिलित- अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर) परिशिष्ट-1 (पेज नं. 1 से 17)

(3) जी हां। राज्य में भू-जल के समुचित उपयोग तथा राज्य के औद्योगिक इकाइयों के सुविधा हेतु भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की बजट घोषणा की पालना में विभाग द्वारा ड्राफ्ट बिल का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। विधि विभाग से प्राप्त सुझावों का समावेश कर ड्राफ्ट बिल वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को लगाने के पीछे मेरा मकसद एक ही था कि राजस्थान को मालूम पड़ जाये कि हम भू-जल दोहन कितना कर रहे हैं और हमारी हालत क्या है।

मंत्री महोदय, खण्ड 1 में आपने केन्द्रीय भू-जल बोर्ड और भू-जल विभाग राजस्थान के सर्वे का जिक्र किया है। क्या यह सही है कि यह सर्वे इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान में भू-जल का दोहन रिचार्ज से 151 परसेंट से ज्यादा हम कर रहे हैं? आपने जिन सात बड़े शहरों की बात लिखी है अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, इनमें से कितने शहर ओवर एक्सप्लोइटेड श्रेणी में आते हैं?

इसके साथ ही आपने भू-जल संरक्षण प्रबन्धन प्राधिकरण की बात कही है, जिसकी घोषणा 03 मार्च, 2022 को हुई थी। अभी तक आप इसका प्रारूप तैयार नहीं कर पाये। आगामी बजट आ रहा है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ने जो रिपोर्ट दी, उसमें यह कहा था कि कृषि और घर के लिए तो आप ट्यूबवैल बना सकते हो, बाकी सब पर चार्ज लगाने की बात थी कि इतने-इतने रुपये लगेंगे। क्या उस रिपोर्ट के आधार पर इंडस्ट्रियल या दूसरा जो है, उस पर चार्ज लगाने की बात करेंगे?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राजस्थान में भू-जल की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। माननीय सदस्य ने कहा कि 151 प्रतिशत हम दोहन कर रहे हैं, यह भी सही है। सात शहरों की स्थिति अच्छी नहीं है। पूरी रिपोर्ट मैंने सब्मिट की है।

जहां तक प्राधिकरण बनाने की बात है, उसका ड्राफ्ट बनाया। उसमें कुछ आपत्तियां थीं, दो बार, एक बार लॉ डिपार्टमेंट और एक बार वित्त विभाग की कुछ क्वेरीज थीं, उन क्वेरीज को पूरा करके परसों ही मैंने फाइल का क्लियर करके भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ही हम इस प्राधिकरण का गठन कर पायेंगे और इसमें जितने कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, बहुत सारे निर्णय होते हैं हमारे यहां पर अभी तक प्राधिकरण है नहीं। जितने भी निर्णय हमारे होते हैं, केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण जो बना हुआ है उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं और उसी के दिशा-निर्देश में हम काम करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय बड़ा चिन्ताजनक है। मैं सिर्फ एक बात ही आपको कहना चाहता हूं, यह जो केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण है इसमें घरेलू और कृषि उपयोग के अलावा इंडस्ट्रियल में दो ब्लाक में क्रिटिकल में 25 रुपये प्रति घनफुट, सेमी क्रिटिकल में 20 और सुरक्षित में 10 पहले से इनकी यह जो निर्धारित दर है, क्या राजस्थान में एक भी किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या उद्योग से आपने क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और डार्क जोन में पैसे वसूले हैं? आपने उनको कोई डिमाण्ड नोटिस भी दिया है?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उन पर पेनल्टी के रूप में कितना शुल्क लगाया है या नहीं, यह जानकारी वर्तमान में मेरे पास नहीं है। आपने चाहा है, मैं आपको भिजवा दूंगा। आप यह मान कर चलिए कि अब तक जो कुछ हुआ है वह केन्द्रीय भू-जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार हुआ है और आगे जब हमारा अपना प्राधिकरण बन जायेगा, उसमें निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास होगा। केन्द्र

(डा. महेश जोशी)

सरकार भी चाहती है कि राज्य अपने स्तर पर प्राधिकरण बनाये और बहुत शीघ्र क्योंकि फाइनल हो चुका है, हम इसके गठन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर शहर में डेयरी बूथों का आवंटन

36. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बजट 2021-22 में नगरीय इकाइयों में 5000 डेयरी बूथ आवंटित किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा के तहत जयपुर शहर के दोनों निगम क्षेत्रों में कितने डेयरी बूथ आवंटित किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (गोपालन मंत्री के स्थान पर): जी हां। उक्त घोषणान्तर्गत नगर निगम जयपुर (हेरिटेज) में कुल 4 डेयरी बूथों तथा नगर निगम (ग्रेटर) में कुल 6 डेयरी बूथों का सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा आवंटन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जो लिस्ट दी है यह तो सारी हेरिटेज की है, जयपुर ग्रेटर नगर निगम में आपने एक भी डेयरी का आवंटन नहीं किया है।

अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। जयपुर नगर निगम में चाहे वह ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, इसके लिए 18 फरवरी, 2022 को एसीएस की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें यह तय किया गया कि एक हजार डेयरी बूथों का आवंटन जयपुर शहर में किया जायेगा। आपने अभी तक नौ किये हैं। साढ़े चौबीस हजार आवेदन तो जयपुर ग्रेटर में हैं और बारह हजार आवेदन जयपुर हेरिटेज में हैं। इस प्रकार से 36 हजार से ज्यादा आवेदन आपने गरीबों से शुल्क लेकर जमा कर लिए और दो साल होने के बाद भी एक भी व्यक्ति को आपने अभी तक डेयरी बूथ आवंटन नहीं किये तो क्या आपका विचार है? आप इनको डेयरी बूथ आवंटन करेंगे या जो मुख्य मंत्रीजी की घोषणा थी, वह केवल घोषणा ही रहेगी? कृपया बताइये।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हेरिटेज और ग्रेटर निगम का सवाल है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2021-22 में

(श्री रामलाल जाट)

कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में 5 हजार डेयरी बूथ आबंटन किये जाने की घोषणा की थी, इसके विरुद्ध हमने पूरे राजस्थान में 5,269 बूथ खोल दिये। जयपुर का जहां तक सवाल है तो माननीय सदस्य की जानकारी में देना चाहूंगा कि जयपुर में 268 बूथ खोले गये। शहरी एरिये में जरूर कम खुले, यह मैं मानता हूं। उसका कारण भी है। पहला प्रश्न आपने किया था कि जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में से एक में बूथ खोले और एक में नहीं खोले। मुझे जो रिपोर्ट दी गयी है, जयपुर हेरिटेज में एक श्रीमती बानो बेगम पत्नी इब्राहिम खान को दिया..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह उत्तर आ गया। चार और छह मिले हैं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): जयपुर ग्रेटर में छह मिले हैं। गीता सैनी, केशव ..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह भी हेरिटेज में ही हैं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): जो मेरे पास रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इनका कहने का मतलब यही है कि जो आपने छह बताये हैं, वह भी उसी में हैं। आपको जो उत्तर दिया है उसमें माननीय सदस्य के हिसाब से दसों के दस केवल हेरिटेज में हैं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): आपने दसों के दस बताये, मुझे जो सूचना दी वह अलग-अलग की दी है। छह बूथ एक में और चार बूथ दूसरे में।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह सूचना गलत दी है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): आप मेरा जवाब आने दो। मैं इन दोनों को दिखवा लूंगा। अगर गलत सूचना दी गयी है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। दोनों का मुझे अलग-अलग दिया है।

दूसरा, मुख्य मंत्रीजी की मंशा साफ थी, चिंतन शिविर में भी इस पर चर्चा हुई तो अभी 5 हजार के अगेन्स्ट में 5,269 पहले खोल दिये। सैकण्ड में, 2022-23 में जब घोषणा की 5 हजार की, उसमें एक हजार अलग-अलग जिलों को टारगेट दिया और वह खुल चुके हैं।

इनकी सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जयपुर डेयरी सरस दूध विक्रेता संघ अन्य बनाम जयपुर नगर निगम, यह हाई कोर्ट गये। रिट संख्या 3964 जो कोर्ट में लगी, उन्होंने आदेश जारी किया कि 200 मीटर का रेडियस चाहिये। जो इनकी यूनियन है, उनकी वजह से हमारे सामने यह दिक्कत आ

(श्री रामलाल जाट)

रही है। फिर भी हमने नये नियम बनाये, उन नियमों में एक कमेटी गठित की गयी, जिसमें अकेले डेयरी के हाथ में नहीं है। इससे नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका, आयुक्त अधिशाषी अभियंता, एक तो इसका अध्यक्ष होगा, सैकण्ड जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि होगा, तीसरा दूध संघ का एम.डी. होगा, चौथा यातायात ट्रैफिक का प्रतिनिधि होगा। संबंधित विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास का प्रतिनिधि होगा। राजस्थान आवासन मण्डल, जहां इफेक्ट होता है, वह होगा। रीको जहां इफेक्ट होता है, वह होगा। स्वायत्त शासन विभाग के दो मनोनीत सदस्य, इनकी कमेटी, इनके झगड़े की वजह से, जो मेरे पास रिपोर्ट है, हमने एप्लीकेशन मांगी, आवेदन मांग रखे हैं। एक स्थान पर एक से अधिक एप्लीकेशन आने पर लाटरी का प्रावधान कर रखा है। इन्हीं को करना है। हमारी डेयरी या हमारे गोपालन डिपार्टमेंट को नहीं करना है। इन्हीं के पाले में गेंद है। यह चाहे जैसा करवा लें। अगर दिक्कत आ रही है तो चिंतन शिविर में मुख्य मंत्रीजी ने इसकी चिंता की कि शहरी एरिये में कम खुले, ग्रामीण एरिये में ज्यादा खुले, तो इसमें भी आप खोलें। ग्रामीण में खोल रहे हो, अच्छी बात है, शहर में भी खोलें। अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय एक कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। अभी आदेश भी जारी किया है, तो बहुत जल्दी इनकी जो मांग है उसके आधार पर हम कार्यवाही करके खुलवाने का काम करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.सी.एस. पवन गोयल की अध्यक्षता में फरवरी, 2022 में मीटिंग हुई। उसमें यह जो नाम बता रहे हो, यह सारे अधिकारी थे और उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि एक हजार बूथ जयपुर शहर में आबंटित किये जायेंगे। उसके बाद 36 हजार लोगों ने नगर निगम में आवेदन कर दिया और एक भी अलाट नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, आप बैठें। माननीय मंत्रीजी, इनका सीधा प्रश्न है कि 36 हजार एप्लीकेशंस आयी हुई हैं, क्या सरकार इस पर निर्णय करेगी, जिससे वहां पर जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज, दोनों जगहों पर बूथ खुले? मोटा प्रश्न है, दैट्स आल।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): बिलकुल निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी

37. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने आवासों का निर्माण करवाया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में लाभार्थी परिवारों का चयन आवास आबंटन से पूर्व किया गया था? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में आबंटियों को अनुदान की राशि का भुगतान किया जा चुका है? क्या सरकार को अनुदान के भुगतान में अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? अनुदान से वंचित लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में निर्मित आवासों का ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले को कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ का ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त अवधि में आबंटियों को अनुदान की राशि का नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है

जी नहीं। सरकार को अनुदान के भुगतान में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त अवधि में प्रथम किस्त (अनुदान राशि) प्राप्त करने से शेष 142 आवासों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो

(श्रीमती संतोष)

जवाब दिया, उसमें बताया है कि अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कई प्रकरण हैं जिसमें आवास पूर्णता का सर्टिफिकेट, जिसने पहले जमा करवाया है, उसको भुगतान अभी तक नहीं किया गया, लेकिन जो बाद में करवाता है उसको पहले भुगतान कर दिया जाता है। कई ऐसे मामले मेरे क्षेत्र के हैं, तो क्या यह अनियमितता के अंदर नहीं आता? इसका क्या कारण है?

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जॉब कार्ड किसी का था और मकान किसी और को आबंटित कर दिया। ऐसा एक प्रकरण 22 A, जो मेरी नवगठित पंचायत है, सतपाल पुत्र जगदीश के नाम से मकान था, जॉब कार्ड नंबर 270 है और किसी अन्य संतोष देवी के नाम से बना दिया गया। क्या यह अनियमितताओं में नहीं आता है? इसी के साथ, जो 4 एम.एस.आर. हमारी पंचायत है, उसके अंदर स्वीकृत मकान, जो मुझे आंकड़े दिये गये हैं, उसमें 68 बताया गया है और वह लाभान्वित बताया गया है, वह 70 है। यह जो आंकड़े दिये गये हैं, यह जो जवाब दिया गया है, इसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो अनियमितता की बात आप कर रहे हैं, कोई पर्टीकूलर शिकायत हो तो आप मुझे बता दें। अगर किसी ने अनियमितता की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अनियमितताओं के अलावा कोई शिकायत आती है कि वह भूमिहीन है या 142 प्रथम किस्त वाले शेष रहे हैं, उसमें 132 जो आदमी हैं, खाता आधारित थे और उनका आधार कार्ड से मैच नहीं हो पा रहा था, इसलिये उनका नहीं हो पाया। दिसम्बर-जनवरी में उनका खाता आधारित करके एक महीने के अंदर उनके खातों में पैसा पहुंच जायेगा प्रथम किस्त का।

दूसरा, आप जो जॉब कार्ड की कह रहे हैं, आपके विधान सभा क्षेत्र में 13 जॉब कार्ड डुप्लीकेट हैं, वह प्रदर्श नहीं हो रहे, जिस वजह से उनका भुगतान नहीं हुआ है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): फर्स्ट किस्त आ चुकी है, लेकिन सैकण्ड किस्त नहीं डाली जा रही है। इसी में एक प्रकरण आ रहा है, इसके क्या कारण हैं? बाद में जो आवेदन हुआ है, उनकी तो आ गयी है लेकिन जो पहले से आवेदित हैं, उनको नहीं दी जा रही है।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फर्स्ट, सैकण्ड और थर्ड किस्त के बारे में, माननीय सदस्य, आपको बताना चाहूंगा कि उसकी नींव भरने पर फर्स्ट किस्त जारी हो जाती है। भूमिहीन है तो भूमि अलाटमेंट होगी उसके बाद उसको किस्त मिलेगी। पैसा तो मिल जाता है, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाता है। सैकण्ड किस्त, लेंटर लेवल पर काम करेंगे तो सैकण्ड किस्त मिल जायेगी। पहली किस्त 15 हजार की है, सैकण्ड 45 हजार की है और थर्ड छत लेवल पर पहुंचेंगे तो 60 हजार मिलेंगे। उसने काम नहीं किया होगा, इसलिए वह पीछे रह गये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया।

नवीन राशन डीलरों की नियुक्ति

38. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की संख्या बढ़ जाने व सीमा से अधिक राशन कार्ड होने के कारण नये राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार राशन कार्डों की संख्या के आधार पर राशन डीलर की नियुक्ति करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। विभागीय दिशा-निर्देशानुसार 500 एनएफएसए राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिट पर पुनर्निर्धारण किया जाकर आवश्यकतानुसार उचित मूल्य दुकान का गठन किया जाता है। इस संबंध में जारी विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 26.12.2019 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जवाब बिन्दु संख्या 1 में समाहित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिशा-निर्देश तो जारी हैं 26.12.2019 में, लेकिन इन दिशा-निर्देशों के तहत कितनी कार्यवाही की गयी है क्योंकि दुकानें तो नई बन नहीं रही हैं। राशन कार्ड अधिक संख्या में बन गये हैं, बहुत से राशन डीलरों की मृत्यु हो गयी है, बहुत से लोगों ने सरेण्डर कर दिया है, तो उसका एडिशनल चार्ज दूसरे डीलर को दे देते हैं। गांव के लोगों को, ढाणियों वालों को इतना दूर चलकर आना पड़ता है, छह-छह, दस-दस किलोमीटर चलना पड़ता है और जब जाते हैं तो राशन डीलर कहता है, आज तो गेहूं नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या जल्द से जल्द इन नियमों की पालना होगी या नये राशन डीलरों की दुकानें आबंटित होंगी?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात बतायी है, मैं आपके पास डी.एस.ओ. को भेजूंगा। वैसे तीन किलोमीटर से ज्यादा दूर कोई भी डी.एस.ओ. दुकान नहीं खोल सकता। यह अटैचमेंट को लेकर जो कर रहे हैं, अभी आपके यहां के इंटरव्यू चल रहे हैं। कमेटियां बन गयी हैं, फिर भी आपके पास कोई सुझाव हों, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यह पब्लिक से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। राशन की दुकान यदि कहीं दूर है तो आप प्रस्ताव बनाकर भेज दें। बाकी सदस्यों को भी मैं यह कह रहा हूं कि यदि आपके क्षेत्र में कहीं पर राशन की दुकानें ज्यादा दूर हैं तो आप प्रस्ताव बनाकर भेजें और आपका यदि कोई प्रस्ताव डी.एस.ओ. लागू नहीं कर रहा, क्योंकि यह तो जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, तो आप मेरे पास डायरेक्ट शिकायत भेजें, ऐसे डी.एस.ओ. के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

39. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं का भवन होना आवश्यक है? यदि हां, तो आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्या-क्या आवश्यक सुविधायें दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ऐसे कौनसे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जिनका स्वयं का भवन नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन केन्द्रों हेतु भूमि आबंटित कर भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी नहीं। आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु स्वयं का भवन होना आवश्यक नहीं है। स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र वर्तमान में उपलब्धता के आधार पर स्वयं के भवन,

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

सरकारी विद्यालय, सामुदायिक भवन, नि:शुल्क भवन एवं किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों के बैठने हेतु स्थान, पेयजल, शौचालय, रसोई इत्यादि आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(2) बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में कुल 497 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से स्वयं के भवनों अर्थात् विभागीय भवन में 282 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। शेष 215 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से किराये के भवनों में 61, सरकारी विद्यालयों में 82 एवं सामुदायिक भवन/नि:शुल्क भवन/अन्य भवनों में 72 केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। जिनका सूचीवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों तथा विद्यालयों में निर्धारित नोर्म्स के अनुसार करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गखा)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 497 में से 282 भवन बने हुए हैं 215 किराये पर चल रहे हैं, वह कब तक बनेंगे?

दूसरा, मेरा प्रश्न है कि जो भवन बने हैं, क्या आंगनबाड़ियां उन्हीं भवनों में संचालित हो रही हैं?

तीसरा, मेरा निवेदन है कि, मंत्री जी, जो राजस्व गांव हैं और कोई वार्ड है, जिसमें आंगनबाड़ियां नहीं खुली हैं और जहां घनी आबादी है, क्या उन स्थानों पर आंगनबाड़ियां खोलने का विचार रखती हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 282 जो भवन बने हुए हैं और किराये के भवनों के बारे में तो उत्तर में बताया है कि प्राथमिकता के आधार पर नये भवन बनते हैं। यह स्पष्ट है। उसमें प्रायोरिटी आ रही है। नि:शुल्क भूमि बनेगी, तमाम चीजें आपकी जानकारी में मैंने इस उत्तर के माध्यम से दी हैं।

जहां तक नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के बारे में जो चिंता माननीय सदस्य ने व्यक्त की है, पिछले 4 वर्षों से मैं इस विभाग में कार्य कर रही हूं और लगातार तमाम पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने नई आंगनबाड़ी केन्द्र

(श्रीमती ममता भूपेश)

खोलने के अपने-अपने सुझाव और अपनी-अपनी डिमांड्स हम लोगों को दीं। वर्ष 2015 से आज तक भारत सरकार के पास हम लोगों ने, मैं 2018 से आयी हूं, हमने 6 बार पत्र लिखा, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी नई आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु नहीं दिया। 2015 से आज तक एक भी नई आंगनबाड़ी केन्द्र सरकार ने हम लोगों को अलाट करने के लिए नहीं दी।

मुझे खुशी है कि इस वित्तीय वर्ष के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने तमाम सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 8 हजार नई आंगनबाड़ी और 2 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का ऐलान किया है, घोषणा की है। वह हमारे सभी सदस्यों के लिए और खास तौर से उन बच्चों के लिए, उन लाभार्थियों के लिए, उन गर्भवती माताओं के लिए, उन धात्री माताओं के लिए, उन किशोरी बच्चियों के लिए जिनको दूर जाना पड़ता था, जिनके नजदीक आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं थे, उनके लिए हमने एक घोषणा की है माननीय सदस्य की चिंता के आधार पर। अपने प्रस्ताव हम विभाग द्वारा मंगवायेंगे। जहां जनसंख्या के आधार पर हमें उचित लगेगा, वहां नई आंगनबाड़ी हम लोग खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण बेनीवाल।

नागौर में भूमि अवाप्ति के मुआवजे का भुगतान

40. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर से जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागौर से नागड़ी तक भूमि अवाप्ति का कितने किसानों को कुल कितनी राशि का मुआवजा दिया जाना शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मुआवजे से वंचित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) नागौर से जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागौर से नागड़ी तक कुल 293 किसानों को राशि रु. 10,19,84,500 का मुआवजा दिया जाना शेष है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कुछ खसरों में भूमि विवाद के कारण मुआवजा वितरण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

नहीं हो पाया है, जिनका निस्तारण भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर) द्वारा किया जा रहा है। भूमि विवाद के निस्तारण उपरान्त मुआवजा वितरण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूं, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किसी भी विवाद के कारण जमीन अवाप्ति के बाद अभी तक मुआवजे से वंचित लोगों को ब्याज सहित मुआवजा समयबद्ध रूप से दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कई बार प्रकाशन किये। 2016 में प्रकाशन किया, 2017 में प्रकाशन किया। मैंने जो माननीय सदस्य को परिशिष्ट-1 में जवाब दिया है, उसमें किसान, जो खातेधारक हैं, उनके सारे प्रमुख कारण लिखे हुए हैं। यदि किसान मुआवजा लेना चाहेंगे तो हमने संबंधित जिला कलेक्टर को, उसमें कारण मैं बता देता हूं, मुआवजा से वंचित रहे किसान, मुआवजा फाइल/ दस्तावेज, कब्जा सुपुर्दगी प्रपत्र, प्रार्थी का शपथ-पत्र, 50 शुल्क का स्टांप पेपर, प्रार्थी के बैंक खाते का निरस्त चैक, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि जमा नहीं होने के कारण मुआवजे की कार्यवाही प्रभावित होना, तकरीबन 161 खातेदार हैं जिनकी राशि 2 करोड़ 165 लाख रुपये है।

श्री अध्यक्ष: लंबा नहीं, ब्रीफ, हो गया। माननीय सदस्य।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह सिर्फ एक पन्ना है, जिसके अंदर कहीं भी जो आप पढ़ रहे हैं, वह नहीं है।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तो मेरी सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पढ़ें। जो प्रश्न पूछा है, उन्होंने उसका जवाब दिया है।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय मंत्री जी, जिन खसरों में भूमि विवाद था, उनका विवाद निस्तारण अवाप्ति से पूर्व या अवाप्ति के समय

(श्री नारायण बेनीवाल)

क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि कोई जिम्मेदार है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक की जायेगी? जमीन अवाप्त होने से पिछले 7 साल से किसान प्रभावित हुआ है।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन पर हमने रोड बनाया है, वह पहले से ही पीडब्ल्यूडी की जगह है। उससे किसी तरह का रोड बाधित नहीं हुआ। हम लोग तकरीबन फोर लेन के आसपास जगह भूमि अवाप्ति के लिए जमीन लेते हैं, तो उसके कारण से हमने जमीन का मुआवजा दिया। उससे कहीं रोड बाधित नहीं हुआ।

हमने कहा कि हम लोग फिर भी प्रकाशन दे देंगे। यदि किसान मुआवजा लेना चाहेंगे तो हम लोग मुआवजा दिलवा देंगे। परंतु 2016-17 का गजट नोटिफिकेशन है, उसी के आधार पर मुआवजा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, हो गयी बात। अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

नोखा में त्रिलोक मेघवंशी अनुदानित कन्या छात्रावास

41. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र नोखा में विभाग के सहयोग से त्रिलोक मेघवंशी अनुदानित छात्रावास संचालित है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परिसर में विधायक कोष से पच्चीस लाख की लागत से कन्या छात्रावास हेतु भवन भी बनाया गया है?

(3) क्या सरकार नोखा में त्रिलोक मेघवंशी अनुदानित छात्रावास में अनुदानित आवासीय कन्या छात्रावास स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नोखा में विभाग द्वारा अनुदानित त्रिलोक मेघवंशी अनुदानित छात्रावास संचालित किया जा रहा है।

(2) हां। यह सही है कि उक्त परिसर के सामने त्रिलोक सेवा समिति की भूमि पर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कन्या छात्रावास के भवन निर्माण हेतु 20 लाख रुपये एवं कन्या छात्रावास में शौचालय निर्माण हेतु 5 लाख रुपये स्वीकृत कर निर्माण करवाया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) नोखा में त्रिलोक मेघवंशी अनुदानित आवासीय कन्या छात्रावास स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव विभाग में लम्बित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। हां, आप बोलें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार एससी का समाज कन्या शिक्षा के प्रति इतना जागरूक हुआ है कि सामाजिक सहयोग से विधायक निधि से हॉस्टल बना दिया है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्होंने विभाग में आवेदन भी कर दिया है, इसको स्वीकृत कर दें। इससे कन्या शिक्षा के प्रति जागरूकता समाज में आयेगी। आवेदन कर दिया गया है।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान सरकार बच्चियों की एजुकेशन के लिए चिंतित है। खास तौर से एस सी के लिए भी चिंतित है। अभी बजट के अंदर काफी प्रावधान भी किये गये हैं। अभी तक प्रस्ताव आये नहीं हैं। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे पास प्रस्ताव आयेगा हम इसको स्वीकृत कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा। प्रश्न पूछें सीधा।

चौमूं में धार्मिक स्थलों का विकास

42. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत तीन वर्ष में धार्मिक स्थलों को विकसित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला जयपुर में कौन-कौन से धार्मिक स्थलों को विकसित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में भी धार्मिक स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सामोद में स्थित वीर हनुमान मंदिर, महारकलां के मालेश्वर नाथ को भी विकसित करने की योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बजट में धार्मिक स्थलों को विकसित करने की घोषणा की है। पिछले तीन वर्षों में जयपुर जिले से संबंधित कोई घोषणा नहीं की गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के धार्मिक स्थलों को विकसित करने हेतु कोई घोषणा देवस्थान विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(3) इस तरह की कोई योजना देवस्थान विभाग में विचाराधीन नहीं हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बजट 2019-20 में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए घोषणा माननीय मुख्य मंत्री ने की थी। जयपुर जिले में एक भी पर्यटक स्थल के रूप में या धार्मिक स्थल के रूप में बजट में प्रस्तावित नहीं किया है। मैं तो मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वीर हनुमान जी का मंदिर है, जिसका पाप तो आपको लगेगा। रोप-वे बंद कर रखा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): एक मालेश्वर नाथ का मंदिर है, एक महामाया का मंदिर है। इन धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए आपके पास जिला कलेक्टर की जो कमेटी है उससे भी प्रस्ताव भेजा गया है, क्या उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने की मंशा रखते हैं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दोनों मंदिर चौमूं विधान सभा क्षेत्र के प्रन्यास अधिनियम 1969 के अंतर्गत यह जो मंदिर हैं, वह अभी देवस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

दूसरा, आपने कहा कि कलेक्टर की कमेटी से इसका सर्कूलर है जो मंदिरों का अभी तक विकास हुआ है अराजकीय मंदिरों का, वह कलेक्टर की समिति से जो फाइल हमारे पास आ गयी, वह हम वित्त विभाग में भेज देते हैं। जैसे ही वित्त विभाग से स्वीकृति आती है, हम काम चालू कर देते हैं। जैसे अभी हाल ही में मोहन राम के मंदिर की धर्मशाला का काम चल रहा है। इसी नियम से जो भी 25-30 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वह इसी आधार पर किया जा रहा है। अगर हमारे पास आ जायेगी तो हम वित्त विभाग को भेजकर, वित्तीय संसाधन के आधार पर इसको जीर्णोद्धार करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल।

प्रतापगढ़ में स्वीकृत मां-बाड़ी केन्द्र

43. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला प्रतापगढ़ में विगत पांच वर्षों की अवधि में कुल कितने मां-बाड़ी केन्द्र, डे केयर केन्द्र स्वीकृत किये गये? उक्त केन्द्रों में किस-किस सरकारी योजनान्तर्गत बच्चों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रों पर घटिया सामग्री वितरित किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) विगत 5 वर्षों में प्रतापगढ़ जिले में 163 नवीन मां-बाड़ी केन्द्र स्वीकृत कर संचालित किये गये है। मां-बाड़ी एवं डे-केयर केन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में प्रतापगढ़ जिले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन केन्द्रों की जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं घटिया क्वालिटी की, क्या कमेटी गठित करके पोषाहार में सुधार कराने की कृपा करेंगे?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्य अगर हमें कोई शिकायत देंगे तो हम उसकी कमेटी बनाकर जांच करा लेंगे।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): ऐसे एक कामन कमेटी गठित करा दें, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा अख़बार में आया था और हमने उसकी जांच कराकर उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही थी, वह कर दी थी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय: 12:00 बजे)

धन्यवाद। प्रश्न काल में पहली बार सभी प्रश्न लिए गये हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से नगरपालिका आसीन्द के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ में राजस्थान-मध्यप्रदेश सीमा पर निम्बाहेड़ा-नीमच मार्ग पर परिवहन विभाग के कार्मिकों द्वारा अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं व्यापार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से नरेना नगरपालिका के अध्यक्ष के भ्रष्टाचार मामले में छह माह कारावास में रहने के उपरान्त भी पद पर बने रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में ट्रांसफार्मर्स की आपूर्ति में विलम्ब एवं अघोषित विद्युत कटौती से हो रही परेशानी के संबंध में।

(7) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से राजकीय विभागों में प्लेसमेंट एजेन्सियों के माध्यम से पदस्थापित कर्मचारियों को स्थायी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में फलसूंड पेयजल योजना से जल आपूर्ति करने के संबंध में।

(9) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में घुमन्तु, घुमक्कड़ व विमुक्त परिवारों को निःशुल्क भू-खण्ड उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन गांवों के संग में आवासीय योजना के पट्टे एवं आवास योजना की किस्तें नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से कलेक्टर कार्यालय, डूंगरपुर के अभिलेखागार से राजस्व रिकार्ड की चोरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अपनी मांगों के लिए साधारण सभाओं का बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की आबंटित राशि का उपयोग विकास कार्यों में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री अर्जुन लाल जीनगर एवं श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण में विलम्ब होने व रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से स्टेट हाईवे संख्या 32-ए के निर्माण कार्य की धीमी गति होने एवं सलूम्बर क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से चम्बल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली की नया गांव सड़क क्षतिग्रस्त होने से आमजन को हो रही असुविधा के संबंध में।

(19) श्री छगन सिंह, सदस्य की ओर से निजी अस्पतालों द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ न दिया जाकर रोगियों से शुल्क वसूल करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(20) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश के मेडिकल कालेजों में ब्लड बैंकों में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

फिर भी माननीय सदस्य श्री रामलाल शर्मा, श्री फूल सिंह मीणा, श्री ज्ञानचंद पारख एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में जल जीवन योजना के तहत असफल नलकूपों को पुन: चालू कर पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में।

(2) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से जालोर में फसल बीमा कम्पनियों द्वारा निर्धारित मापदण्डों की उपेक्षा कर फसली नुकसान का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से बनास नदी पर निर्मित मातृकुण्डिया बांध के पानी को कृषि हेतु उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना में उच्च क्षमता के जीएसएस स्थापित करने के संबंध में।

(5) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से प्रदेश में कृषि भूमि में रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग में उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से ओड व भाट जाति के आर्थिक व शैक्षणिक स्तर को प्रोत्साहित करने के संबंध में।

(7) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय बाड़मेर में जीरा मण्डी अतिशीघ्र प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

(8) श्री पुखराज गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में जल जीवन योजना के अन्तर्गत बन्द पड़े ट्यूबवैल को पुन: प्रारम्भ कराकर पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में।

(9) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर के घड़ियाल वन क्षेत्र में निवासरत परिवारों को आवासीय पट्टे जारी नहीं किये जाने से आधारभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल में पत्थर खनन उद्योग पर अधिक रायल्टी वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारु करने हेतु बीसलपुर तृतीय फेज का स्वीकृत कार्य तत्काल प्रारम्भ करने के संबंध में।

(13) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजस्व ग्राम डूंगावतफला की तरमीम राजस्व रिकार्ड में जमा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में अनुसूचित जनजाति परिवारों को कृषि विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से दिए जाने के सबंध में।

(15) श्रीमती गंगा देवी, सदस्य की ओर से राजकीय सेवाओं में प्रदेश के मूल निवासियों को अधिकतम प्रतिनिधित्व दिए जाने के संबंध में।

(16) श्री हरीश चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दिए गये 295 को पढ़ा हुआ माना जाएगा, क्योंकि आज हम बजट पर चर्चा करेंगे, कल हमारी चर्चा लिमिटेड हो पाएगी। कल 3 बजे प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात कहेंगे, 4 बजे मुख्य मंत्रीजी अपना जवाब देंगे और 5 बजे हम सदन की कार्यवाही को स्थगित करेंगे। इसलिए आज 295 पढ़ा हुआ माना जाएगा।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब की दौड़ पूरी हो गई है, अब नेता, प्रतिपक्ष बन जाएं।

श्री अध्यक्ष: ये दोनों आपस में बैठकर फैसला कर लेना।

श्री रामलाल शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नरेना नगरपालिका अध्यक्ष का कारावास में रहने के उपरांत भी पद पर बने रहना

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर इंगित करना चाहता हूं कि जहां पर राज्य सरकार यह कहती है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन इसी राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले के अंदर भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के अंदर एक ग्राम पंचायत है नरेना, उस नरेना ग्राम पंचायत में 2020 में सरपंच पद पर पीर मोहम्मद नामक व्यक्ति सरपंच बनता है। मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा 2022-23 के अंदर इस नरेना ग्राम पंचायत को नगरपालिका का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जनवरी, 2022 के अंदर यह सरपंच पीर मोहम्मद, सचिव और एक एलडीसी, तीन लोगों को एसीबी कार्यवाही करते हुए, एसीबी इनको गिरफ्तार करती है और 43 दिन तक ये पीर मोहम्मद जेल की सलाखों के पीछे रहता है। पंचायती राज विभाग द्वारा धारा 48 की कार्यवाही की जाती है। उस कार्यवाही पर स्टे लेकर आता है, उसके बाद वापस सरपंच के पद पर काबिज होता है। दूसरी तरफ स्वायत्त शासन विभाग, चूंकि नगरपालिका घोषित हो चुकी थी, स्वायत्त शासन विभाग से मिलीभगत करके नगरपालिका अध्यक्ष का चार्ज लेकर और पिछले 11.11.2022 को कोर्ट का स्टे भी खारिज हो गया, उसके बावजूद भी तीन महीने लगातार बीते समय में यह आज भी नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। इन तीन महीनों के अंदर जाने-अनजाने कितनी बेशकीमती जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरा आपसे एक निवेदन और है कि राजस्थान की सरकार सिर्फ वोट बैंक की खेती की तरफ ध्यान रखती है। इसी तरह का मामला अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति के खिलाफ हो जाता तो सरकार अब तक कार्यवाही करते हुए तत्काल उसको घर बैठाने का काम कर देती। मैं आपसे, सदन से और आपके माध्यम से सरकार

(श्री रामलाल शर्मा)

से चाहूंगा कि तत्काल तीन महीने पहले स्टे खारिज होने के बावजूद भी आज दिन तक पद के ऊपर यह क्यों बना हुआ है और आज दिन तक जो ट्रेप हुए व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वापस उनको जोइन कराने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसको गम्भीरता से ले।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में आवासीय योजना के पट्टे

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तत्कालीन ग्राम पंचायत बड़ी के ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी बड़ गांव पंचायत समिति, नरेन्द्र सिंह झाला काफी समय से ग्राम पंचायत, बड़ी में बतौर ग्राम विकास अधिकारी, 2008 से 2018 तक एक ही पंचायत में रहा। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में उसका तबादला हो गया, मगर आज दिन तक उसके पास में कैशबुक भी है और आज दिन तक उसने किसी को चार्ज नहीं दिया जबकि वह बड़गाव पंचायत समिति का बीडीओ बन गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीडीओ बन गया है, मगर उस पंचायत का चार्ज अभी तक नहीं दिया है। पूर्व सरकार के अंदर जो प्रशासन गांवों के संग...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठो, मैं पढ़ देता हूं।

'उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में प्रशासन गांवों के संग दिए गये ग्रामीणों को पट्टे और आवास योजना के तहत आने वाली किस्तें नहीं दीं।' इस पर बोलना है, आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: उस पर ही बोलो, माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): प्रशासन गांवों के संग अभियान में पूर्व सरकार के दिए हुए पट्टे भी सचिव ने नहीं दिए। उसके बाद में हमारे आदिवासियों के, ग्रामीणों के पट्टे हैं, जो वास्तव में आवास दिये हैं, उनकी दो किस्तें दे दीं। प्रथम और तृतीय किस्त भी दे दी। दूसरी किस्त आज भी बाकी है। ऐसे अधिकारी सचिव रहकर, ग्राम विकास अधिकारी से लेकर बीडीओ है और वह इतने सालों से वहां पर जमा हुआ है और भ्रष्टाचार को पनपा रखा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ऐसे विकास अधिकारी और बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो 15 साल तक वहां रह गये हैं, उनकी जांच करके संज्ञान लें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली की नया गांव सड़क क्षतिग्रस्त होने से आमजन को कारित असुविधा

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, पाली की नया गांव रोड, जो पाली की मुख्य सड़क है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर भी स्थित है, पांच बड़े विद्यालय भी हैं, पांच वार्ड भी लगते हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछली बार बजट घोषणा में 25 करोड़ रुपये की राशि इसके निर्माण में दी। माननीय मंत्री महोदय, एक साल होने को आ गया, ठेकेदार काम करने को तैयार भी है, पर कुछ काम जो नगर परिषद् के पार्ट का है, शहर में बिजली के पोल हटवाना या अन्दर जो पाइप लाइन चल रही है, उसे बाहर की ओर शिफ्ट करना, सड़क के एक ओर पहले से किये हुए नाला निर्माण पर से अतिक्रमण हटाना और एक ओर नाला निर्माण करना, ताकि यह सड़क सुरक्षित रहे।

जो सम्बन्धित ठेकेदार है, वह लगातार नगर परिषद् को कह रहा है कि यह काम आप करवा दें ताकि मैं यह काम पूरा कर सकूं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं कि यह सड़क पहले नहीं बनी। पिछले तीन सालों में इस सड़क पर लगभग दो करोड़ के टेंडर होकर उसकी राशि खर्च हो गयी, आधा-अधूरा काम हुआ। फर्जी बिल उठा। पेमेंट भी हो गया। माननीय मंत्री महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि जो एमबी बुक बनी, उसकी अगर आप जांच करवाएंगे तो पाएंगे कि जो लोडिंग टैम्पो है, उसे लोडिंग ट्रक बताकर पेमेंट उठा दिया। वहां हालत यह हो गयी है कि आस-पास के दुकानदार और वार्ड के वासी वहां से जब गुजरते हैं तो पूरा मिट्टी से सन जाता है। इतनी मिट्टी उड़ती है, जबकि वह मुख्य रोड है। जब मुख्य मंत्री जी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

ने 25 करोड़ की राशि इस सड़क के निर्माण हेतु दे दी, उसके बाद में एक साल तक भी वह सड़क नहीं बनी, यह वहां की जनता के साथ बहुत भारी अन्याय है। मेरा सरकार से आग्रह है कि पहले जो इस सड़क पर पैसा खर्च हुआ है, उसकी जांच करवाये और साथ ही जो राशि मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृत की है, तत्काल नगर परिषद् को पाबन्द करके वह सड़क बनवाने का काम करे।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

मेडिकल कालेजों के ब्लड बैंकों में व्याप्त अव्यवस्थाएं

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार राजस्थान की अवाम को राइट टू हैल्थ देने के लिए कटिबद्ध है। मंत्री महोदय, उससे पहले हमें राजस्थान की शीर्ष संस्थाओं में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ मानव संसाधन, अच्छे इक्विपमेंट्स और अच्छे नियंत्रण पर ध्यान देना होगा।

अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा बजट नहीं गया जिसमें मुख्य मंत्री जी ने एस.एन. मेडिकल कालेज की चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की बात नहीं की हो। यह मारवाड़ का सबसे बड़ा ढाई हजार बेडेड हास्पिटल है, जिसमें प्रतिदिन 200 से 300 आपरेशंस होते हैं। सैकड़ों लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए रक्त का दान भी यहां करते हैं।

इस मेडिकल कालेज के ब्लड बैंक और माइक्रोबायोलॉजी लैब के बारे में जो जानकारी हासिल हुई, उससे दिल दहल उठा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसी 11 फरवरी को इस मेडिकल कालेज के ब्लड बैंक माइक्रोबायोलॉजी के अन्दर से जिन लोगों के 12 फरवरी को शिड्यूल्ड आपरेशंस थे, उन गम्भीर रोगियों के ब्लड सैम्पल्स की थैलियों को कुत्ते उठाकर ले गये, श्वान उठाकर ले गये। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। यह प्रतिबन्धित क्षेत्र है, जहां मनुष्य भी नहीं जा सकते। जब ये सारी बातें सामने आयीं तो आपके प्रिंसिपल कछावा ने कहा कि अब दुबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी।

मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने लखनऊ में 3 हजार ब्लड बैंक की थैलियां, जो राजस्थान के चौमूं, सीकर और जयपुर के ब्लड बैंक्स से निकल गयीं और जिनके अन्दर सैलाइन वॉटर डालकर उनके वॉल्यूम को दुगुना किया गया, उन्हें पकड़ा। उन्हें पकड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने आपके ड्रग कंट्रोलर से कहा कि ये जो सारी थैलियां हैं, इन पर निशान आपके हैं। इसके बाद भी उनकी जांच नहीं हुई। यह शराब की तस्करी के साथ रक्त की तस्करी भी प्रारम्भ हो गयी है राजस्थान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में। अत: मैं चाहता हूं कि आप एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएं और इन ब्लड बैंक्स का इंस्पेक्शन कराएं। यह जो जोधपुर की घटना हुई, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

मैं कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहता। निश्चित तौर पर जब राइट टू हैल्थ की बात आती है, अख़बार जब इन हालातों को लिखते हैं, तब यह बात उठती है। मंत्री महोदय, इसकी जांच कराएं। कोविड में आरएनए टैस्ट जब हो रहे थे, 53 लाख रुपये के किट्स इसकी एस.एन. मेडिकल कालेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक्सपायर हो गये। इनकी आप टास्क फोर्स बनाकर जांच कराएं।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर एवं जयपुर के लेखों पर) (वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21)

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर एवं जयपुर के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21;

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लेखों पर) (वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21)

2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नहीं सुधरेंगे...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसके बाद 2021 तक आ गये हैं। आपको पता है। I have taken it. ...(interruption) Please. मैंने उस दिन भी कहा है, I am the first speaker who have taken the meeting of all the secretaries! None has taken it.

श्री परसादी लाल।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20) तथा दसवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 तथा दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

(समय: 12:16 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विश्वविद्यालयों के निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हू:-

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23)

1. महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 से 2022-23;

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23)

2. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 से 2022-23;

(श्री टीकाराम जूली)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23)

3. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा-42 के अन्तर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 से 2022-23;

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23)

4. हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा-43 के अन्तर्गत हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 से 2022-23;

एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

5. एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2021 की धारा-43 के अन्तर्गत एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23)

6. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 की धारा-38 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 से 2022-23;

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23)

7. गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम, 2012 की धारा-41 के अन्तर्गत गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 से 2022-23;

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23)

8. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 की धारा-42 के अन्तर्गत राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 से 2022-23;

(श्री टीकाराम जूली)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23)

9. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 की धारा-42 के अन्तर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 से 2022-23;

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23)

10. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 की धारा-41 के अन्तर्गत महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 से 2022-23.

श्री सभापति: श्री सुभाष गर्ग।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह गलत बात है। 2019-20 का गंगा सिंह विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन, कोटा विश्वविद्यालय का 2019-20 का, भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय का 2020-21 का, हरिदेव जोशी का 2019-20 का, दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय का 2019-20 का, क्या है यह? इन प्रतिवेदनों का हम क्या करें? क्या इन प्रतिवेदनों को हम चाटें?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, इनके वक्त में भी चार-चार, पांच-पांच वर्ष पुराने आते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमने गलतियां की हैं, इसीलिए आज यहां बैठे हैं। (व्यवधान) यह कोई एक्सक्यूज है? हमने गलती कर दी। हम यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): न आप गलती करते हैं, न हम गलती करते हैं, डिपार्टमेंट की गलतियां हैं। (व्यवधान)

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 की धारा-44 के अन्तर्गत बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री इन्द्राज गुर्जर।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, धन्यवाद कि आज बजट बहस में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारी सरकार ने एक बेहतरीन बजट राजस्थान की जनता को समर्पित किया है, क्योंकि हर बार जब बजट होता था, बड़ी उत्सुकता राजस्थान की जनता में होती थी कि इस बार के बजट में जनता को क्या मिलेगा। हमारी सरकार की शुरू से मंशा रही कि अच्छी चिकित्सा सुविधा, अच्छी पढ़ाई, किसानों की बिजली की अच्छी व्यवस्था हो। यह प्राथमिकता हमारी सरकार की रही।

सभापति महोदय, राजस्थान देश में पहला स्टेट है जहां आमजन को जीने के अधिकार के साथ चिकित्सा व्यवस्था बिलकुल सुदृढ़ की गयी है। हमारी सरकार पिछली बार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेकर आयी, दस लाख रुपये तक का इलाज फ्री किया और इस बार उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया। राजस्थान पहला स्टेट है पूरे देश में जहां प्रत्येक व्यक्ति का 25 लाख रुपये तक का इलाज फ्री होने जा रहा है। उसके अलावा, जो दुर्घटना बीमा है चिरंजीवी योजना में, पहले पांच लाख था, अब उसे बढ़ाकर दस लाख रुपये किया, मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, किसान का बेटा हूं, किसान की बात जरूर करूंगा। पहले जब बिजली के बिल आते थे, हर दूसरे महीने बिल आते ही किसान किसी से उधार लेने के लिए भागता था। बड़े-बड़े बिल आते थे। हमारी सरकार ने इस बात को समझा, किसानों की भावनाओं को समझा और 2000 यूनिट प्रतिमाह थ्री फेज की बिजली फ्री की, जो शायद पूरे देश में राजस्थान पहला माडल स्टेट होगा जिसने किसानों के लिए बिजली फ्री की। पिछली बार घरेलू बिजली में 50 यूनिट फ्री की, जिसको इस बार बढ़ाकर 100 यूनिट कर दिया और लगभग 90 प्रतिशत लोगों के जीरो बिल राजस्थान में आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ओपीएस की बेहतरीन स्कीम पूरे देश में पहली बार राजस्थान सरकार लेकर आयी, उसका दायरा बढ़ाते हुए बोर्ड, कारपोरेशन जितने भी थे, उन सबको इसमें शामिल किया, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इतना बेहतरीन बजट है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हमारे अपोजिशन के जो साथी हैं, इनका धर्म है विरोध

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

करना। सरकार कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन उसका विरोध करने का इनका फर्ज है। मैं तो इन सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना ई आर सी पी है, जिस पर हमारे सांसद और विपक्ष के कोई भी विधायक बोलना नहीं चाहते हैं। देश के प्रधान मंत्री जी आये तो मुख्य मंत्री जी और सचिन पायलट साहब, दोनों ने इस बात का उनसे निवेदन किया कि अगर आप आ रहे हो तो ई आर सी पी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा करके जाएं। हम सब लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि राजस्थान की धरा पर और वह भी पूर्वी राजस्थान की धरा पर प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर जाएंगे क्योंकि, सभापति महोदय, पानी के हालात खराब हैं। बोरिंग कराते हैं तो छह-छह महीने में बोरिंग सूख जाते हैं, पीने के पानी की किल्लत हो चुकी है। ई आर सी पी अगर नहीं आ पायी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में क्षेत्रों में पीने का पानी नहीं बचेगा, लेकिन वही गोलमोल बातें करके, घुमा-फिराकर प्रधान मंत्री जी भी चले गये। निश्चित रूप से मैं राजस्थान की सरकार को भी और केन्द्र की सरकार को भी कहना चाहूंगा कि वे इनके पाले में गेंद डाल रहे हैं ये उनके पाले में गेंद डाल रहे हैं और जब जल शक्ति मंत्री हमारे राजस्थान के हैं तो क्यों नहीं दोनों एक जगह बैठकर इसका समाधान निकालें। मैं तो आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि एक दिन का सत्र ई आर सी पी पर बहस के लिए बुलाया जाये, इस पर बहस की जाये, पक्ष और विपक्ष के लोग इस पर अपनी बात रखें कि किसकी कमी है। निश्चित रूप से जनता इस बात को नहीं मानती है कि कौनसी पार्टी क्या करना चाहती है, जनता को तो पानी चाहिए। जनता पानी मांगती है और पानी देने में अगर हम लोग विफल रहे तो न वे बीजेपी को बख्शेंगे, न वे कांग्रेस को बख्शने का काम करेंगे। सभापति महोदय, इस बात पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि गर्मी का सीजन आने वाला है, पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच जाती है तो क्यों नहीं जब हर बात के लिए हम लोग विशेष सत्र बुला लेते हैं, एक-एक दिन की बहस करा लेते हैं, तो जब 13 जिलों की ई आर सी पी इतनी बड़ी योजना है, उस पर एक दिन सदन में बहस करायी जाये। पक्ष-विपक्ष अपनी बात रखे और सरकार अपना जवाब पेश करे तथा अगर कुछ कमियां हैं तो निश्चित रूप से उन कमियों को ठीक करके केन्द्र सरकार को भेजने का काम करें तो फिर गेंद इनके पाले में जाएगी, फिर पता चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं इंटरवीन नहीं करना चाहता, पर बड़ा उत्तम सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है। इनका सुझाव स्वीकार है, प्रतिपक्ष तैयार है, आप बहस कराओ ई आर सी पी पर।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): प्रतिपक्ष की सारी सीटें खाली हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके पीछे मैदान खाली है।

श्री सभापति: बोलिये। प्लीज, कंटीन्यू। बैठिये, प्लीज बैठिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा विषय है। सभापति महोदय, 13 जिलों के करोड़ों लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना है और 13 जिलों में लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जब हम गांवों में जाते हैं तो हर व्यक्ति पानी की बात करता है। हमने सड़कें अच्छी बनाईं, हमने हास्पिटल अच्छे बनाये, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाये, हम सब काम बेहतर करना चाहते हैं। हमने कालेज खोले, हमने नगरपालिका बनाई, हमने सब डिविजन बनाये, लेकिन जब पानी नहीं मिलता है तो सब पर पानी फिर जाता है। मैं निश्चित रूप से मांग करना चाहूंगा कि आज हम सत्ता में हैं, कल पता नहीं कौन होगा, हम होंगे या दूसरे होंगे, लेकिन यह जवाब उनको भी देना पड़ेगा। निश्चित रूप से इस सदन में बैठने वाले हर व्यक्ति को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 13 जिलों की इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को लटकाने के दोषी कौन हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह सत्र बुलाने की मैं मांग करता हूं और सब लोगों से निवेदन करता हूं कि एक दिन की बहस ई आर सी पी पर करायी जाये और अगर कुछ कमियां हैं तो हमें ठीक करनी चाहिए और उनकी कमियां हैं तो उनसे भी हम आमने-सामने खड़े होकर बात करेंगे।

सभापति महोदय, इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र को मुख्य मंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एडीजे कोर्ट का हमारे विराटनगर को कैम्प कोर्ट दिया, सड़कें भी दी हैं, ग्राम भांकरी में पीएचसी भी दी है।

सभापति महोदय, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें सदन में आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि हम प्रत्येक नगरपालिका को 20-20 किलोमीटर सड़क देंगे। सभापति महोदय, जो पुरानी नगरपालिकाएं हैं, उनके पास तो अपने संसाधन हैं, उनके पास पैसा है और वे

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

सड़कें लगभग बना भी चुकी हैं तथा कई जगह तो कह रहे हैं कि हमारे पास बनाने के लिए जगह ही नहीं है, लेकिन जो पिछले तीन-चार साल में नई नगरपालिकाएं बनी हैं वहां पर सड़कों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मेरे वहां पावटा, प्रागपुरा बहुत बड़ी नगरपालिका है, 25-30 किलोमीटर सड़क वहां हम बना चुके और 20 किलोमीटर आ गई, तो भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें तो नई नगरपालिकाओं में 20 किलोमीटर के बजाय 40 किलोमीटर सड़क देने का काम करें, ताकि हमारे लोगों को राहत मिले।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार भी प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये नॉन-पेचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए दिये थे, इस बार भी घोषणा की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 20 करोड़ रुपये किये जाएं ताकि सड़कों का बेहतर जाल हम लोग विधान सभा क्षेत्रों में बिछा सकें।

सभापति महोदय, राजस्थान की सबसे बड़ी आय अगर किसी चीज की है तो वह है टूरिज्म की। पर्यटन से बहुत बड़ी आय हमारे प्रदेश को होती है और बहुत बड़ा रोजगार हम लोगों को मिलता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में जहां महाभारतकालीन अवशेष हैं, जहां सम्राट अशोक के शिलालेख भी हैं, जहां जैन नसियां भी है, जहां प्रसिद्ध गणेश जी का मन्दिर भी है, जहां हमारे बीजक की पहाड़ी भी है, सरिस्का के बिलकुल समीप का हमारा विधान सभा क्षेत्र है तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इसको पर्यटन सर्किट में जोड़ा जाए ताकि विराटनगर के लोगों का रोजगार बढ़े। दिल्ली-जयपुर के नजदीक होने से वहां पर पर्यटक आना भी चाहते हैं।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, थोड़ा समय दें, इतनी जल्दी हर बार ही हो जाती है मेरे साथ।

सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मांग की थी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में त्रिवेणी धाम एक बहुत बड़ा मन्दिर है, वहां के संत नारायण दास जी महाराज का अपना नाम पूरे देश के संत समाज में रहा है। उसकी ग्राम पंचायत साईवाड़ लगती है।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

साईवाड़ ग्राम पंचायत में पीएचसी है और मैंने पिछली बार भी मांग की थी कि उस पीएचसी को सीएचसी किया जाए। वहां पर हजारों साधु उस मन्दिर में रहते हैं और 24 घंटे में कभी भी इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है तो 25-20 किलोमीटर पहले कोई साधन नहीं है। इसलिए अगर उस साईवाड़ पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कर दिया जाए, 24 घंटे की सीएचसी हो जाए तो हमारे हजारों साधु तथा 4-5 ग्राम पंचायतों नाथावाला, साईवाड़, बाड़ीजोड़ी, चिमनपुरा, देवीपुरा को उसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमारे उप स्वास्थ्य केन्द्र मण्डा, पालड़ी व बड़ोदिया को पीएचसी में क्रमोन्नत करने की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

सभापति महोदय, सड़कों की कुछ घोषणा मेरे विधान सभा क्षेत्र की हुई है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। निश्चित रूप से मैं मांग करूंगा कि हमारे भाबरू से बीलवाड़ी वाया लुहाकणा व राजनौता से अलवर-ज्ञानपुरा, अलवर बोर्डर तक की सड़क को बनाने का काम किया जाये।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एमबीसी बहुत बड़ा समुदाय है। देवनारायण योजना स्पेशल रूप से एमबीसी के लिए लागू की गई है तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि देवनारायण योजना के तहत बालिका आवासीय विद्यालय विराटनगर में स्वीकृत किया जाये, ताकि हमारी बालिकाओं को वहां पर पढ़ाई का मौका मिल सके।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी यह मांग की थी कि विज्ञान का युग है और स्कूलों में जब तक हम विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमने घोषणा की है कि ब्लाक स्तर पर चारों फैकल्टी खोलेंगे, लेकिन ब्लाक से गांवों की दूरी 20-20, 30-30 किलोमीटर पड़ती है और इलेवंथ का स्टूडेंट गांव से वहां आ नहीं सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि हमारे वहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागावास अहीरान, बाड़ीजोड़ी, पालड़ी, राजनौता, नाथावाला, जयसिंहपुरा व भामोद में विज्ञान संकाय खोला जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को विज्ञान पढ़ने का मौका मिले।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी मांग की थी और उच्च शिक्षा मंत्री जी हमारे पड़ोस के विधान सभा

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

क्षेत्र के हैं और पावटा उनका भी सब डिविजन लगता है तथा मैंने प्रोग्राम में भी उनसे निवेदन किया था कि पावटा गवर्नमेंट कालेज में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाएं, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को वहां अच्छी शिक्षा मिल सके। सभापति महोदय, हमारे वहां के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, खेड़ा, विराटनगर को मैं प्रवेशिका में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, थैंक यू।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट समय मुझे दीजिए। एक मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ग्राम धोलीकोठी में डा. विजय अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट, लखनऊ को बीजेपी सरकार ने डीएलसी रेट पर जमीन अलाट की थी। यह बहुत महंगी जमीन थी, जिसको डीएलसी रेट पर अलाट कर दिया गया। उन्होंने आज तक नियमों का पालन नहीं किया, न वहां भवन का काम चालू हुआ है। इस बात को सात-आठ साल हो गये हैं। उस जमीन को रोककर बैठे हैं। ग्रामीणों का रास्ता बन्द कर दिया। यह सिवाय चक की जमीन थी, सैकड़ों ग्रामीणों का रास्ता बना हुआ था। मैं उस अलाटमेंट को निरस्त करने की मांग करता हूं, क्योंकि हमारी बेशकीमती जमीन को डीएलसी रेट पर देने का काम किया गया। वह जमीन अलवर-विराटनगर रोड पर ही पड़ती है। निश्चित रूप से इससे हजारों लोगों का बुरा हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धन्यवाद। श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का अन्तिम पांचवां बजट प्रस्तुत हुआ है। बजट के बारे में कौल एण्ड शकधर ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में आय-व्यय का विवरण एक पवित्र और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हर लोकतांत्रिक सरकार का राजधर्म है कि बजटीय घोषणाएं उसी वित्तीय वर्ष में पूरी हों। मुझे बड़ी पीड़ा है कि यह राजधर्म इस सरकार के लिए अधर्म बन गया है।

राजस्थान के इतिहास में मुख्य मंत्री द्वारा पिछले बजट का पृष्ठ

(श्री वासुदेव देवनानी)

जोड़कर पढ़ाना घोर लापरवाही है तथा राज्य के संसदीय इतिहास को कलंकित कर दिया। जो बजट जैसे गम्भीर, गोपनीय दस्तावेज के प्रति लापरवाही बरते, वह जनता के प्रति कितना लापरवाह होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में कोई सदन का नेता नहीं करे।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री ने कहा कि चार वर्षों के कुल 2722 घोषणा बिन्दुओं में से 85 प्रतिशत से अधिक धरातल पर उतरी हैं। यह सरासर असत्य और जनता के साथ धोखा है। एक सर्वे के अनुसार केवल 49 प्रतिशत घोषणाएं पूरी हुईं, 51 प्रतिशत तो अभी अधूरी पड़ी हैं। सत्र 2022-23 की बात करें, 1029 घोषणाओं में से केवल 33 प्रतिशत पूरी हुई हैं, बाकी का कोई पता-ठिकाना भी नहीं है।

अब वर्तमान बजट कैसे लागू होगा? आपके कार्यकाल का समय तो केवल 5 महीने रह गया है। उसके बाद तो आचार संहिता लग जायेगी। आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये केवल लोक लुभावनी घोषणाएं रह जायेंगी। जनता सब समझती है, आपने 2013 में भी बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं, नम्बर एक मुख्य मंत्री के बड़े-बड़े दावे किये थे, बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये थे, हर मामले में नम्बर वन, लेकिन जनता ने आपकी उन घोषणाओं पर विश्वास नहीं किया और आपको 21 सीटों पर लाकर पटक दिया और अब कितने आओगे? मैं इसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं। आपकी सरकार के मंत्री कह चुके हैं। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जितने, उसमें 8 या 9 आदमी ही बैठते हैं। आप भी मान रहे हैं कि जनता हमें 9 सीटों तक ही सीमित कर देगी। यह आपकी हालत है।

अब आपके इस बजट के बारे में बात करें। अब यदि मैं अजमेर की बात करूं। गत बजट में आपने जिला मुख्यालय पर सावित्री बाई फुले वाचनालय संचालित करने की घोषणा की थी। वह कहां गई? धरातल पर कहीं है ही नहीं, केवल घोषणाएं रह गई हैं। इवन, आपने 2 करोड़ 20 लाख की लागत से मिनी फूड पार्क अजमेर में बनाने की घोषणा की थी, कहां है? शायद हवा में चल रहा होगा। फूड पार्क की कहीं दूर तक खबर नहीं है।

अजमेर सम्भाग मुख्यालय पर आपने सेन्टर फोर एक्सीलेंस फोर माइक्रो इर्रिगेशन की घोषणा की थी, केवल कागजों में है। आप बतायें तो सही कि 85 प्रतिशत कहां है? अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में दो जनता

(श्री वासुदेव देवनानी)

क्लीनिक खोलने की घोषणा की गई थी, आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। आज तक 27 करोड़ की लागत से जवाहर लाल नेहरू हास्पिटल, जनाना हास्पिटल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ ही नहीं है और आपने कह दिया कि बनेंगे। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट, अजमेर में पी.जी. गर्ल्स होस्टल, ट्रोमा वार्ड भवन, कार्डियक, मेडिकल कालेज भवन, कहां हैं? हवा में। केवल आपने थोड़ी बहुत शुरुआत कर दी। मुझे सब पता है आप जो बोलने वाले हो। ये तो आपके समय, आप चले गये, इसलिए इन्होंने भी ठण्डे बस्ते में डाल दिया। इसलिए, रघुजी, आपके साथ यह हालत हुई है। अब आप गुजरात चले गये। मैं कह रहा हूं कि इस बजट के अन्दर अजमेर को बहुत निराशा हाथ लगी है। वहां आपका कोई नुमाइंदा नहीं है।

अजमेर के अन्दर पेयजल की समस्या बड़ी विकराल बनी हुई है। वहां पर इस सर्दी के मौसम में भी 48 से 72 घंटे में पानी मिल रहा है। इसके निजात के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है, न इसके इलाज के बारे में सोचा गया है। हमने इनको कहा, आप बीसलपुर (तृतीय फेज) का क्रियान्वयन प्रारम्भ करें, लेकिन केवल अभी तक वह फाइलों में ही चल रहा है, उसके क्रियान्वयन का कोई जिक्र नहीं है।

किशनगंज थाने के पास नया थाना बनना था, कोई नया थाना नहीं बना। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दो लिखे थे, एक भी नहीं बना। एमडीएस यूनिवर्सिटी बिना शिक्षकों के बेहाल हो रही है। उसमें किसी प्रकार की भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। आखिर अजमेर के साथ ऐसा दोहरापन क्यों कर रहे हैं? चूंकि अजमेर की जनता जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज को लगातार जिताती है, उनके साथ आप इस प्रकार दुर्व्यवहार कर रहे हो, यह जनता सहन नहीं करेगी। आने वाले समय में एक बार और बदला चुकाकर के आपका इलाज करेगी। इतना मैं आप लोगों को कहता हूं।

आपने यूजर चार्जेज अजमेर में थोप दिया। फिर आगे बढ़ें, आपने अभी बजट में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में साइंस पार्क सेन्टर के लिए 30 करोड़ रुपये की घोषणा की जबकि आपने अजमेर का साइंस पार्क अभी तक अटका रखा है। केन्द्र ने पैसा भेज दिया, लेकिन व्यवहार में इशारा कर रखा है कि अजमेर में मत बनाओ, इसलिए आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

आपने विश्वविद्यालय की घोषणा की है, अच्छा है, विश्वविद्यालय बनने चाहिए। आपने महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के अन्दर,

(श्री वासुदेव देवनानी)

माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा सम्भाग के अन्दर, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर के अन्दर, भाई, अजमेर ने आपका क्या बिगाड़ा है? अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार, इसी कारण आपके ये हाल हुए हैं। यह सौतला व्यवहार अजमेर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक चिकित्सा मंत्री थे तब तक थोड़ी बहुत अजमेर की सुनवाई होती थी। इनको विदा करने के बाद आज अजमेर बिलकुल इस प्रकार निहत्था, असहाय हो गया है। मुख्य मंत्री को केवल सपनों में जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर ही दिखाई देता है। इनको बाकी सारा प्रान्त दिखाई नहीं देता है।

ये सारी घोषणाएं आपने की हैं। अजमेर को तो आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये बाकी की योजनाएं आखिर लागू कैसे होंगी? आपके पास किसी प्रकार के संसाधन नहीं हैं। राजस्थान कर्ज के अन्दर डूब रहा है। 2020-21 में 4 लाख 10 हजार 499 करोड़ का कर्जा था, यह बढ़कर 2023-24 के अन्दर, जो अनुमान है, वह 5 लाख 89 हजार 781.22 करोड़ हो जायेगा, अर्थात् प्रति आदमी एक लाख के कर्जे के अन्दर जीयेगा। जो नया पैदा होने वाला बालक है, पैदा होने के दिन ही उसके ऊपर एक लाख का कर्जा हो जायेगा। परिवार के ऊपर लगभग 4 लाख का कर्जा है। इस तरह कर्जा लेते जाओ, लोगों के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं किये जाओ।

आपका सकल राजकीय घाटा भी लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 के अन्दर 59 हजार 375 करोड़ था और यह 2023-24 में बढ़कर 62 हजार 771.92 करोड़ हो गया है। इधर राजकीय घाटा, उधर कर्जा और फिर भी राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप घोषणाएं लागू कैसे करोगे? जनता को कितना भ्रमित करोगे? यह हालत तब है जबकि आपका केन्द्रीय करों का अंश लगातार बढ़ रहा है। आपको 2020-21 में 35 हजार 551 करोड़ रुपया मिला, 2021-22 में 54 हजार करोड़ और 2022-23 में 57 हजार 230 करोड़ मिला, 2023-24 में 61 हजार 552.47 करोड़ मिला। फिर भी, केन्द्र को गाली दो, मोदीजी को दो गाली। गाली देने से, केन्द्र तो अनुदान बढ़ा रहा है। जरा कुछ तो सोचें, लेकिन इनमें सोचने का है ही नहीं और उलटा रात-दिन केवल एक ही बात है, अडानी से प्यार, राहुल द्वारा गाली। यानी, अडानीजी को हमारे अशोक गहलोत साहब तो प्यार करेंगे और राहुल गांधी उनको गालियां देते रहेंगे। माननीय गहलोत साहब, बताओ तो सही आप हो किसके साथ? राहुल के साथ हो या अडानी के साथ हो, इतना तो बताओ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, गाली नहीं निकाली है, कोई गाली नहीं निकाली है। जो सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है। इसको एक्सपंज करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ये बताओ, मैं तो पूछना चाह रहा हूं। आपका प्यार है या नहीं? मेरे पास आपकी फोटो है। आप बात कर रहे थे, हजारों बीघा जमीन दी है, आपने जमीन दी है, अडानी के साथ प्यार क्यों?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): राहुल गांधीजी ने गाली कब निकाली? राहुल गांधीजी ने उनकी पोल खोली है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ये इंटरप्ट करेंगे, मेरा उतना टाइम बढ़ाना पड़ेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बजट पर बोलें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह धमकाना नहीं चलेगा, मंत्री महोदय। आज मैं सच बोलूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर देखें और बजट पर बोलिये। यह बजट पर वाद-विवाद है। प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दो-दो मंत्री एक निरीह और सज्जन आदमी को धमका रहे हैं। एक भोलेभाले अजमेर से आने वाले सिन्धी समुदाय के व्यक्ति को धमका रहे हो।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनकी असत्य बातें सुनने के लिए सदन नहीं चल रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं दबाव में नहीं आऊंगा। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनकी असत्य बातें सुनने के लिए सदन नहीं चल रहा है यह।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बजट पर बोलिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अडानी के भक्त क्यों बनते हो?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आपने शिक्षा मंत्री रहते क्या-क्या किया था, सबको पता है।

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करिये अपना।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अडानी के बारे में बोल रहा हूं तो देवनानी को धमका रहे हो, यह कैसे चलेगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बजट पर बोलिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि यह बजट युवाओं को समर्पित होगा। यह युवाओं के साथ सरासर धोखा है। आपने दावा किया, युवाओं को समर्पित तो करेंगे और इस अनुसार आपने बजट के पेज-5 पर लिखा, 'युवाओं का प्रज्वलित मस्तिष्क धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मेरा विश्वास है यदि युवा शक्ति को सही दिशा दी जाये, तो वह मानवता की चुनौतियों का सामना कर शान्ति व समृद्धि के साथ नये समाज का निर्माण कर सकती है।' स्लोगन बहुत अच्छा है। सुनने में और बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सरकार की अकर्मण्यता के कारण गत चार वर्षों में सोलह परीक्षाओं के पेपर लीक हुए।

सभापति महोदय, सत्तर लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कानून पास हुआ। आज तक जारोली से कभी पूछताछ नहीं की। जिसने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के बिना पेपर लीक नहीं हो सकता, उसको बुलाकर पूछताछ तो करो। केवल कानून बनाओगे। एसओजी लगातार आपके दबाव में है क्योंकि उसके तार पूरी तरह ठेठ मंत्रियों तक और बड़े उच्चाधिकारियों तक जा रहे हैं और आज तक कुछ भी उस पर कार्यवाही नहीं हुई। इसका एक उदाहरण देता हूं अभी सैकंड ग्रेड के चारों पेपर आउट हुए। 339 प्रश्न मिले जबकि एफआईआर में केवल 30 प्रश्नों का जिक्र किया है, क्यों? यह दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? यह तो बताओ। इस प्रकार का व्यवहार और सारे सरगना फरार लेकिन फिर भी किसी प्रकार का नहीं। कारण एक ही है कि राजनीतिक संरक्षण, उच्च स्तर की भागीदारिता के कारण आज अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं। आज तक कितनों को पकड़ा, इनको कुछ पता नहीं और युवाओं को आप रोजगार देंगे। क्या रोजगार दिया?

आज देश में बेरोजगारी की दर 8.3 परसेंट है, राजस्थान में बेरोजगारी की दर 28.5 परसेंट है। इतनी होने के बाद भी केवल युवाओं के बारे में कुछ सोचना नहीं। युवा नीति लायेंगे। पांच महीने में तो आपका नीतिगत दस्तावेज तक नहीं आ पायेगा, क्यों युवाओं के लिए युवा नीति की बात करते हो? नौकरियां नहीं हैं। बेरोजगारी भत्ता नहीं है। 28 लाख लोग बेरोजगार हैं,

(श्री वासुदेव देवनानी)

बेरोजगारी भत्ता केवल 50 हजार को मिल रहा है। राजस्थान का हर दूसरा ग्रेजुएट आज बेरोजगार है। आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थी न। 2019 का बजट मैंने पढ़ा। उसमें आपने लिखा था कि जितने लोग सेवानिवृत्त होते जायेंगे उतने पद हम भरते जायेंगे। पांच वर्ष के अन्दर कितने सेवानिवृत्त हुए, कोई हिसाब है क्या? मेरे अनुमान के अनुसार लगभग तीन लाख लोग सेवानिवृत्त हुए हैं और आपने भरे कितने, 1 लाख 42 हजार, उसमें भी आधे तो हमारी सरकार के द्वारा जो नियुक्त थे उनको आपने केवल नियुक्ति पत्र दिया है। इस प्रकार आपके राज में आपके नाकारापन के साथ आज आरपीएससी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है।

युवाओं के साथ क्या किया, संविदा कर्मियों के लिए बी.डी. कल्ला साहब की कमेटी बनी, आज तक उनको नियमित करने का कोई हिसाब-किताब नहीं। कौन करेगा, इनका कुछ पता नहीं। मंत्रालयिक कर्मचारियों को आपने बुलाया, बातचीत की, उस बातचीत में एक भी मांग उनकी आपने स्वीकार नहीं की। आज आन्दोलन पर सड़क पर हैं। पूरे कर्मचारियों की वाहवाही तो लूट रहे हो, यह वाहवाही केवल अपने ग्रुप के अन्दर, वाहवाही केवल सदन के अन्दर केवल एमएलएज कर रहे हैं, जनता तो आपकी कोई वाहवाही नहीं कर रही है।

सभापति महोदय, एक सदस्य कल भी और परसों भी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे कि हमारा राजस्थान माडल देश को अपनाना चाहिये। राजस्थान माडल को तो गुजरात ने नकार दिया। हमारे वहां के प्रभारी बैठे हैं। मुख्य मंत्री वहां के मुख्य प्रभारी थे, लेकिन वहां की जनता ने उसको नकार कर केवल 16 सीटों पर आपको समेट दिया और यही हालत राजस्थान में भी होने वाली है। आपको नकारने वाले हैं और राइट टू हैल्थ की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरे पन्द्रह मिनट हैं, मैं डिस्टर्ब हुआ तीन मिनट। मैं पांच मिनट लूंगा उससे अधिक नहीं लूंगा। मैं पहला वक्ता हूं।

आज राइट टू हैल्थ की बात करते हैं। राइट टू हैल्थ क्या है? सरकारी अस्पतालों की हालत कितनी खराब है, न तो वहां डाक्टर हैं, न सुविधाएं हैं, न उपकरण हैं। केवल हम राइट टू हैल्थ की बात करेंगे। आज तो स्थिति यह

(श्री वासुदेव देवनानी)

बनी है कि गहलोत सरकार को तो अपने रिपीट होने के ख्वाब दिख रहे हैं और प्राइवेट हास्पिटल को पैसा कमाना है। बीच में दोनों में जनता बुरी तरह पिस रही है, आज जनता पर किसी का ध्यान नहीं है। आपने घोषणा की थी कि हम जनता क्लिनिक खोलेंगे। राजस्थान में केवल घोषणा की, इक्का-दुक्का, 10-12 कहीं खुल गये। हर जगह खुलने थे। कहीं पर विचार नहीं और सरकारी अस्पतालों के हालात तो ऐसे हैं पूरे वेंटीलेटर पर हैं।

सभापति महोदय, आप चाहते हो प्राइवेट अस्पताल डंडे के जोर पर गरीबों का इलाज करें। मैं आज भी कह रहा हूं कि नहीं करेंगे। करोड़ों खर्च किये हैं उन्होंने, रियायती दर और फ्री इलाज क्यों करेंगे। आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना में मात्र 1700 रुपये आप उनको देने वाले हैं, जिसमें भोजन भी सम्मिलित है। इसमें केन्द्र की योजना भी सम्मिलित है। केन्द्र की आयुष्मान भी उसी में है। केन्द्र की सरकार का पैसा और साथ में अपनी केवल वाहवाही और आपने कहा कि दस लाख से पच्चीस लाख कर दिया। आपने कितनों को दस लाख दिये, यह तो बताओ सदन में। दस लाख दिये नहीं केवल वाहवाही लूटने के लिए आपने पच्चीस लाख कर दिया। इसलिये मेरी आपके माध्यम से मांग है कि सभी रिक्त पद भरो और पूरी सुविधाओं की व्यवस्था करो, तब जाकर के आपका राइट टू हैल्थ लाने का अधिकार है।

सभापति महोदय, आज आप दिल्ली और पंजाब का एग्जाम्पल उठा कर देख लो। आज किसान बदहाल हैं। आपने दस दिन में कर्जा माफ करने की घोषणा की। तीन वर्षों में 1887 किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है। न उनको यूरिया खाद मिल रहा है। केवल एक-दो बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय, आज प्रदेश में महंगाई, मोदी जी के खिलाफ आन्दोलन, प्रदर्शन, आपके यहां पेट्रोल, डीजल और बिजली सबसे महंगी है। रेट्स सबसे अधिक है, नौ बार आपने बढ़ाई। तीन सौ यूनिट वालों को आज बिजली 8.30 रुपये से 13.34 रुपये प्रति यूनिट दे रहे हैं। शहरी सैस 35 पैसे, विद्युत शुल्क 40 पैसे, फ्यूल चार्ज 35 पैसे और अब 8 पैसे और बढ़ाने पर आमादा हो। अडानी को 2552 करोड़ रुपये देने के कारण 5 पैसे प्रति यूनिट और बढ़ाने को सरकार तैयार है। इन हालातों में इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, कैसे विकास होगा?

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अन्त में है, शान्त प्रदेश, कैसे बनेगा खुशहाल? बजट में पृष्ठ 9 पर आपने कहा है 'शान्ति के बिना हमारे तमाम सपने मिट कर खाक हो जाते हैं। प्रदेश में न 6 वर्ष की बच्ची, न 60 वर्ष की वृद्ध महिला सुरक्षित है। जयपुर में हत्याओं की घटना में 15 प्रतिशत डकैतियां 75 प्रतिशत आत्महत्याएं तीन वर्ष में 15,781 हुई हैं।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): गैंगवार हत्याएं, सीकर, अजमेर, जोधपुर, चित्तौड़, जयपुर में गैंगवार हो रही है। मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। दो घंटे में एक बालिका का अपहरण, एक घंटे में दो महिलाएं लापता। देह व्यापार चल रहा है। अवैध हथियारों की बाढ़ आ गई है। अभी किशनगढ़ में बैंक लूटा। राजस्थान स्पोर्ट्स काउन्सिल के चेयरमैन कृष्णा पूनिया के खिलाफ +++ जारी हुआ है। मंत्री आंजना के भतीजे को सुपारी देने की बात हुई है। इस प्रकार मैं अजमेर के ....

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। Thank you very much.

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, मैं एक सैकंड में खतम कर रहा हूं। आज सड़कों की बात हुई है। सड़कें 2020-21 की बनी नहीं, 2022-23 की टेण्डर प्रक्रिया नहीं हुई और 2023-24 की घोषणाएं कर दीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय हो गया प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ये घोषणाएं ....(व्यवधान) इस प्रकार यह हिन्दू विरोधी सरकार जिसने अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इन्दिरा गांधी किया। यह अन्नपूर्णा के प्रति अन्याय है।

श्री सभापति: श्री अमीन खां। चालू करें। थैंक यू। अब अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: थैंक यू वैरी मच। माननीय सदस्य श्री अमीन खां, बोलिये आप। थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत ने 2023-24 का सदन में जो बजट पेश किया वह काबिले तारीफ है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, इन्होंने गलत जानकारी दी है सदन को, उनका +++ नहीं हुआ है, जमानती वारंट जारी हुआ है।

श्री अमीन खां (शिव): हमने किसी गांव में, ढाणी में, सड़क पर, मोहल्ले में, गली में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो...

श्री सभापति: यह जो अभी बाद में आया है इनका समय होने के बाद में वारंट वाली बात है, that is a bailable warrant; not a +++ उसको डिलीट कर दीजिये।

श्री अमीन खां (शिव): किसी आदमी ने यह नहीं कहा कि इस बजट में कोई कमी रही। हर व्यक्ति ने यह तारीफ की है कि इससे ज्यादा शानदार बजट कोई आदमी पेश नहीं कर सकता। इस बजट की हिन्दुस्तान की आजादी के बाद में पहली बार जितनी एकतरफा लोगों ने तारीफ की है ऐसी कभी नहीं की है। हम मुख्य मंत्री को इस बात के लिए उनकी सूझ-बूझ को, उनकी समझदारी को धन्यवाद देते हैं। कौनसा वर्ग इस बजट में छूटा? पहले सरकारी कर्मचारियों को जहां पेन्शन नहीं मिलती थी वह पेन्शन चालू हो गई। सामाजिक न्याय के तहत जिन गरीबों को पांच सौ रुपये मिलते थे, उनको एकदम आदेश से आज हजार रुपये तय हो गये। बिजली के पैसों में कमी की गई। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने किसानों को जितने भी बिजली के कनेक्शन दिये गये, उनमें एक पैसा भी कभी बढ़ोतरी नहीं की गई। बीजेपी की सरकार में किसानों के कनेक्शनों पर पैसे बढ़ाये गये, कम नहीं किये गये। आज राजस्थान में कौनसे वर्ग पर कौनसी जगह पैसों की बढ़ोतरी की? चार साल में एक नये पैसे का राजस्थान की जनता पर कर नहीं लगाया, इससे ज्यादा राजस्थान की खुशहाली के लिए क्या सोच हो सकती है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं जिसने राजस्थान की जनता के हित में बेहतरीन कदम उठाया है और पब्लिक में इस चीज की कहीं पर भी बुराई नहीं हुई है। मेरा यह निवेदन है कि इससे ज्यादा कोई रास्ता नहीं है। लोग मानें या नहीं मानें, वह बात अलग है, लेकिन उनकी ईमानदारी, काबिलियत और उनकी सोच को राजस्थान की जनता बार-बार धन्यवाद दे रही है।

इसके साथ मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारी बोर्डर डिस्ट्रिक्ट है। बोर्डर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में चार हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें बी.ए.डी.पी. के करीब 800 करोड़ रुपये सालाना आते थे, वह

(श्री अमीन खां)

भारत सरकार ने बंद कर दिये। बाद में जब डा. मनमोहन सिंह देश के प्रधान मंत्री बने तो जैसलमेर, बाड़मेर जिलों को पिछड़ा जिला घोषित किया। उसके तहत दोनों जिलों को 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना बजट आता था, जिससे उस सीमावर्ती एरिये का अच्छा विकास हुआ, उसको भी भारत सरकार ने बंद कर दिया। पीने के पानी की योजनाओं में रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके के लिए 90 परसेंट भारत सरकार फंड देती थी और 10 परसेंट स्टेट का उसमें हिस्सा होता था। आज 50 परसेंट भारत सरकार दे रही है और 40 परसेंट राज्य सरकार। इसमें भी पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों का फंड काटा है, यह भारत सरकार का काम है।

प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएमजीएसवाई का बहुत अच्छा प्रोग्राम लागू किया था, वह भी अब बंद कर दिया। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पीएमजीएसवाई प्रोग्राम के तहत 250 की जनसंख्या वाले जो गांव वंचित रहे, उनको मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है, काम बंद नहीं किया गया। इसके लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को हम बार-बार धन्यवाद देते हैं।

मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ कमियां रह गई हैं, कृपा कर उनको मंजूरी दें। एक तो हरसानी उप तहसील घोषित की है, उसमें पीएचसी को सीएचसी कर दिया जाये। एक, धारवी खुर्द गांव है, उसमें 33 केवी का ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाये। हमारा गडरारोड ब्लाक है, वह आधे से ज्यादा डेजर्ट नेशनल पार्क में है। डेजर्ट नेशनल पार्क घोषित होने के बाद वहां पक्का कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति नहीं देते हैं, कच्चे काम की एन.ओ.सी. दे देते हैं। मेरा निवेदन है कि तीन-चार पंचायत हैडक्वार्टर को कच्ची ग्रेवल सड़क से जोड़ने की स्वीकृति दी जाये। रेगिस्तान में पक्की सड़क पर तो एक किलोमीटर पर 20-25 लाख रुपये खर्च होता है और ग्रेवल रोड पर रेगिस्तान में 3-4 लाख से ज्यादा खर्च नहीं होता है। यह पंचायत हैडक्वार्टर हैं:- सनद का पार से धराबा 13 किलोमीटर, हरसानी-नाजला रोड से कुडरिया 3 किलोमीटर, हरसानी आजरा रोड से सांखलीफाटा से अचरेरी कलां 9 किलोमीटर, खुर्रानी उबेरी 9 किलोमीटर। विभाग ने इनके एस्टीमेट भी बना दिये हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन ग्रेवल रोड की स्वीकृति दी जाये। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के पांचवें बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, पांचों बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली का 2019 के बजट में एक बार नाम आया था और वह भी इसलिए आया था कि राजस्थान में कालेज के 12 भवन बनेंगे, जिनमें मावली भी था। 2019 खतम हो गया, कोई भवन नहीं बना। 2020 में आया कि कालेजों में 350 कमरे बनेंगे, कुछ नहीं हुआ। 2021 में आया डी एम एफ टी से भवन बनेंगे, बड़ी मुश्किल से अक्टूबर, 2021 में मैंने कालेज के भवन के लिए डी एम एफ टी से 6 करोड़ रुपये पास करवाये, आज वह भवन बन रहा है।

माननीय सभापति महोदय, बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी की पीड़ा मैं समझ सकता हूं क्योंकि लोक सभा चुनाव में उनके खुद के वार्ड में कांग्रेस हार गई। वह खीझ पूरे राजस्थान पर निकाल रहे हैं। 20 पृष्ठों में 32 बार जोधपुर का नाम आया है। माननीय सभापति महोदय, हम कट-मोशन के प्रस्ताव देते हैं, आप क्यों हमसे कागज खराब करवा रहे हो? एक बार भी मावली का नाम उसमें नहीं आया। माननीय कल्ला साहब विराजमान हैं, तुलसीदास जी ने कहा है, मैं निवेदन करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी से न्याय की उम्मीद है।

मुखिआ मुखु सो चाहिऐ खान पान कहुँ एक।
पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित बिबेक।।

ऐसा हमारा मुखिया होना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी पीड़ा को समझेंगे। मावली में पानी की भारी समस्या है। बागोलिया की डीपीआर पहले भी बन चुकी है, एक रुपया बागोलिया के लिए दिया नहीं है। अनेक वर्षों से मावली के लोग तरस रहे हैं। हमारे मावली के पास के दो विधान सभा क्षेत्र हैं, एक तो माननीय अध्यक्ष महोदय का विधान सभा क्षेत्र 'नाथद्वारा' है, दूसरा बाई इलेक्शन वाला विधान सभा क्षेत्र 'वल्लभनगर' है। वहां उनके ढेरों काम हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप न्याय करें। न्याय करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी, एक किसी शायर ने कहा है,

रकबा तेरी जमीन का मीलों हुआ तो क्या हुआ,
रकबा तेरे दिल का दो इंच भी नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है उदय सागर में हिन्दुस्तान जिंक अवैध पानी ले रहा था, मैंने उस अवैध पानी को बंद करवाया। 30 साल से हिन्दुस्तान जिंक, वेदांता का बड़ा ग्रुप अवैध पानी ले रहा था। उदय सागर का

(श्री धर्मनारायण जोशी)

500 क्यूबिक पानी फ्री है, आप उसकी योजना बनवाएं। राज्य सरकार योजना बनवाकर मावली के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करावे। पांच साल से हमारे उदय सागर की नहरें टूटी हुई हैं। अनेक बार उसके रिपेयर के प्रोजेक्ट बनाकर अधिकारियों ने भेज दिये। सारी नहरें टूटी हुई हैं और नहरों के टूटी होने के कारण दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो किसानों के खेत में खेती नहीं हो रही है और आपका पानी भी वेस्ट जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसकी प्लानिंग करके नहरों को सुधारा जाये।

स्वास्थ्य मंत्री जी अभी विराजमान नहीं हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि हमारे यहां पर घासा बड़ा केन्द्र है, घासा में डिस्पेंसरी क्रमोन्नत की जाये। मावली तहसील न होने से वहां पर सैटेलाइट हास्पिटल स्थापित किया जाये। फतेहनगर में मैं ट्रोमा सेंटर के लिए निवेदन करता हूं, ट्रोमा सेंटर बनाया जाये। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं।

(समय: 13.00 बजे)

मेरा आपसे निवेदन है कि फतेहसागर में पिछली बार नर्सिंग कालेज की घोषणा की थी। शायद राजस्थान में पहला उदाहरण होगा जब नगरपालिका ने नर्सिंग कालेज के लिए जमीन का पट्टा डिपार्टमेंट को दे दिया, परन्तु जमीन देने के बाद भी वह फाइल वहां की वहां अटकी हुई है, नर्सिंग कालेज की स्थापना नहीं हुई है। आपने छोटे-छोटे स्थानों पर नगरपालिका बना दी है। मावली बड़ा केन्द्र है, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मावली भी नगरपालिका में क्रमोन्नत की जाये।

मावली में पानी की भारी समस्या बार-बार आती है, क्योंकि मावली में 74 गांव ऐसे हैं जहां पर जमीन में भी पानी नहीं है और ऊपर से भी पानी की आवक नहीं है। मावली और वल्लभनगर के लिए जाखम परियोजना बनी हुई है। मेरी इस बार इच्छा थी और अधिकारियों से भी बात की, उन्होंने कहा कि शायद बजट में आ सकता है। लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की जाये।

माननीय मंत्री महोदय, मावली में कालेज खुला, कालेज प्राइमरी स्कूल में चल रहा है। भवन के डी.एम.एफ.टी. का काम चल रहा है, वहां पर फैकल्टी खोली जाये। केवल आर्ट्स की फैकल्टी है। मेरी प्रार्थना है कि वहां पर साइंस और कामर्स फैकल्टी भी खोली जाये। आपने अपने घोषणा-पत्र में जोर-जोर से घोषणा की थी कि इन्होंने 22 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं बन्द कर दीं।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

आपकी मजबूरी होगी, आपने कहा कि सब वापस खोलेंगे। कोई बात नहीं, यदि नहीं खोली तो। वे जो भवन पड़े हुए हैं, उनको पंचायत को दे दिये जाएं, जिससे उनका उपयोग होगा, नहीं तो तोड़-फोड़ होगी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, पूरे पांच साल में दो स्कूल के लिए निवेदन किया था। फतेहनगर के पास में चूण्डावतखेड़ी है, वह आजादी के पहले का मिडल स्कूल है। 80 बच्चियां वहां से 8 किलोमीटर पैदल चलकर फतेहनगर आती हैं, इसलिए स्कूल को क्रमोन्नत किया जाये। पालवास के स्कूल को भी क्रमोन्नत किया जाये। बड़गांव में पूरे गांव के लोगों ने इकठ्ठा होकर धरना दिया। धरना देने के बाद भी, मैंने आपके आफिस में निवेदन किया था और मैंने पत्र भी भेजा, वहां साइंस और कामर्स फैकल्टी खोली जाये। मावली में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय तो खोल दिया, लेकिन उनका आफिस नहीं है। यह भी मेरा निवेदन है कि उनका आफिस खोला जाये।

भाजपा की सरकार ने टोल माफ कर दिया था और आपने आकर टोल लगा दिया। आपको आश्चर्य होगा कि फतेहनगर से दरीबा टोल नाका है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि टोल नाके का टोल वसूली का समय आठ महीने पहले ही खतम हो गया है, लेकिन अभी भी वहां पर टोल वसूला जा रहा है। यह सरकार की अकर्मण्यता है।

आपने उस समय कहा था कि इन्होंने हमारे विश्वविद्यालय बन्द कर दिये। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनजाति विश्वविद्यालय वसुन्धरा जी की सरकार ने कंटीन्यू रखा है। आपने वह विश्वविद्यालय खोला, दो साल तक केवल वीसी और एक बाबू उदयपुर यूनिवर्सिटी में बैठे रहे और वापस भाजपा की सरकार आयी, उस विश्वविद्यालय को बांसवाड़ा में शिफ्ट किया। उसमें आज एक लाख विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आपने यहां पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोला। पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थिति यह थी कि वहां के वीसी साहब, अयोग्य वीसी, मुझे लगता है कि अगर वे नहीं हटते तो दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय की तरह यह भी अखाड़ा बन जाता। मैंने यह पिछली बार भी निवेदन किया था। उसका समाधान आपने कर दिया।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें। Please, only two minutes.

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी जोर-जोर से चिल्लाते हैं। मानगढ़ धाम को प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। 50 साल आपका राज रहा है, आपने 50 साल में क्या किया? आप 50 साल में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते। आपको किसने मना किया? बेणेश्वर धाम को डवलप किया। मुख्य मंत्री जी कोरिडोर के लिए मातृकुंडिया गये और वहां पर घोषणा की कि मैं कपासन की मस्जिद को दो करोड़ रुपये देता हूं। यह मुख्य मंत्री जी की वहां की घोषणा है।

ओसियां के माननीय विधायक ने पंडित नेहरू जी का नाम लिया था। पंडित नेहरू जी ने जेल भोगी। मुझे अच्छी प्रकार से पता है कि जेल भोगी। उनके वहां पीए थे। अन्दर उनका स्टाफ था और वे वहां 'भारत एक खोज' किताब लिख रहे थे। जेल सावरकर जी जैसे ने भोगी, जिन्होंने 12 साल जेल भोगने के बाद, वे कोल्हू के बैल की तरह हंके। पंडित नेहरू जी का जहां तक सवाल है, वे आजादी के बाद प्रधान मंत्री बने हैं। वे सितम्बर, 1946 में प्रधान मंत्री बने हैं। वे यूनियन जैक झण्डे के नीचे प्रधान मंत्री बने थे। अंग्रेज अधिकारियों ने उनको शपथ दिलायी। यह इतिहास का रिकार्ड है। माननीय सभापति महोदय, यह मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: Thank you very much.

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मेरा एक और निवेदन है। आपने देवस्थान में सारी जमीनें लेकर मन्दिरों के ट्रस्ट बना रखे हैं। मेरा निवेदन है कि देवस्थान के मन्दिरों को सरकार से मुक्त किया जाये। पुजारियों की तनख्वाह बढ़ायी जाये। पुजारी सामग्री को बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। थैंक यू। आप कन्क्लूड करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मेरे दो-तीन निवेदन और हैं। मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

वादे मत करो, तुम +++ हो,

तुम +++ से इन वादों को निभा नहीं पाओगे,

जब बात आयेगी इतिहास से तो तुम वादों से ही मुकर जाओगे।

मेरी पुन: प्रार्थना है कि मावली को कंसीडर किया जाये, भेदभाव नहीं किया जाये। इतना ही निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: +++ को निकाल दें। श्री सुदर्शन सिंह रावत।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो ऐतिहासिक बजट दिया है, उस पर आपने बोलने का अवसर दिया। लगातार दो वर्षों तक कोरोना की मार झेलने के बावजूद राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने लगातार पांचवां शानदार बजट पेश किया है और यह कमिटमेंट दोहराया है कि राजस्थान की जनता के प्रति राजस्थान की सरकार जवाबदेह है। माननीय मुख्य मंत्री जी का मुख्य मंत्री के तौर पर 14 साल का अनुभव इस पूरे बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने तमाम घोषणाएं की हैं, जो गांव के आदमी, गरीब, दलित, पिछड़े, महिलाओं, नौजवानों के लिए जरूर थीं, उन तमाम घोषणाओं को माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में इनकारपोरेट किया है। पूरे राजस्थान का कवरेज है, इसका सभी संभागों का, सभी क्षेत्रों का माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रोपर ध्यान रखा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार के 45 लाख करोड़ के बजट के बावजूद जो सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं हुई उसकी तुलना में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने साढ़े तीन लाख करोड़ के स्टेट बजट में उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में जिस तरीके से बी.पी.एल. लोगों के लिए विशेष तौर पर काम किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

पिछले चार बजटों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत सौगातें इस राजस्थान को दी हैं। इस बजट में भी महंगाई राहत पैकेट दिया, कल्याण कोष बनाया है। कृषक कल्याण कोष को बढ़ाकर 7 हजार करोड़ किया। ओ.पी.एस. का कवरेज दायरा बढ़ाया। महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट दी है। 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है। ई.डब्ल्यू.एस. को भी फ्री इलाज में शामिल किया है। 500 करोड़ रुपये के युवा विकास कोष का गठन किया है। कक्षा एक से 12वीं तक छात्रों को भी फ्री शिक्षा की घोषणा की है और देवनारायण और कालीबाई स्कूटी 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार की है। 11 लाख किसानों को 2 हजार फ्री यूनिट बिजली देने का माननीय मुख्य मंत्री जी ने मानस बनाया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद इस लक्ष्य से भी देना चाहूंगा कि भीम और देवगढ़ में पिछले चार साल में बेशुमार सौगातें दी हैं और इस बजट में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने नगरपालिका दी है, जिसकी मांग कई सालों से लंबित थी, उसको देने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृपा की है।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

उसके अलावा भीम और देवगढ़ के लोगों को एडीजे कोर्ट के लिए 100 किलोमीटर दूर राजसमन्द जाना पड़ता था और एडीजे कोर्ट भी भीम को दिया है, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद दूंगा।

जो फौजियों और पूर्व सैनिकों की समस्या थी, पूर्व सैनिकों को अपने जिला सैनिक कार्यालय के लिए उदयपुर जाना पड़ता था, पूर्व सैनिक या शहीद वीरांगना को कोई छोटा-सा भी काम हो तो उदयपुर जाना पड़ता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़कर, क्योंकि उदयपुर संभाग के 50 प्रतिशत फौजी भीम और देवगढ़ से आते हैं, राजसमन्द जिले के तकरीबन 70-80 प्रतिशत फौजी भीम-देवगढ़ से आते हैं, भीम और देवगढ़ में जो मांग थी, उसमें भीम और देवगढ़ में जिला सैनिक कार्यालय दिया है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हमको सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल भीम में दिया है। बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय देवगढ़ में दिया है। देवगढ़ में रीको भी दिया है। भीम और देवगढ़ के लिए जो सभी चीजें मुख्य मंत्री जी ने दी हैं, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। राजसमन्द जिले को जो मेडिकल कालेज माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है, वह तारीफ के काबिल है।

लगातार तीन दिन से बजट पर जो बहस चल रही है। उसमें विपक्ष के सभी ज्ञानवान साथी सिर्फ एक ही चीज पर अटके हुए हैं कि रेवड़ियां हैं। हमें झुनझुने पकड़ा दिये। गरीबों का जो काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें कवरेज किया है, वह ऐतिहासिक है।

जिस पेज के बारे में विपक्ष के ज्यादातर सदस्य चिंतित रहे और 34 सैकण्ड का एक भाषण जो कि पेज एड होने के कारण मानवीय त्रुटि के कारण हुआ, उसके ऊपर ही विपक्ष का ज्यादातर ध्यान केन्द्रित रहा। मैं सदन के ध्यान में उस पेज नंबर 3 को लाना चाहूंगा। ये वो ही पेज नंबर 3 है, जिसमें राजस्थान को माननीय मुख्य मंत्री जी ने मैक्सिमम राहत पैकेज दिया है। इसी को देखकर आप लोगों की घबराहट निश्चित तौर पर बढ़ रही है। इस पूरे पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 में जो बी.पी.एल. के लोगों के लिए मैक्सिमम कवरेज हुआ है, एनएफएसए के जो हमारे एक करोड़ लोग हैं, उनको राशन किट देने के लिए 3 हजार करोड़ रुपया है। गैस सिलेण्डर के लिए है 15 सौ करोड़ रुपये, फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए 7 हजार करोड़ और वैट रिबेट, डीजल के लिए 7 हजार 500 करोड़, कुल मिलाकर 19 हजार करोड़ माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें दिए हैं।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, कई वर्षों तक परम्परा रही है और हम सदन में आये हैं, कई लोक सभा और विधान सभा में हमारे लोग रिप्रजेंट करते रहे हैं और दोनों सदनों में जन-प्रतिनिधि के तौर पर हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम हमारे इलाके की समस्याओं को उठाएं। बड़े दु:ख के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर, केन्द्र सरकार के अंदर जाकर जो राजस्थान से 25 सांसद हमने चुनकर भेजे हैं, उन सांसदों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया। कोई भी मांग केन्द्र सरकार से प्रोपर तरीके से नहीं की, न तो क्षेत्र के लिए और न राजस्थान के लिए। पिछले चार सालों में केन्द्र सरकार की एक तरह से राजस्थान के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं रही और तमाम सांसद जो हमारे चुनकर गये, वह 25 के 25 सांसद कहीं न कहीं इसमें नाकामयाब रहे। मैं इस बात के लिए यह जरूर कहना चाहूंगा कि बजट के लिए हमारे तमाम विपक्ष के साथी कहते नजर आ रहे हैं राजस्थान के बजट में हमारी विधान सभा क्षेत्र का नाम नहीं है, परंतु मैं कहना चाहूंगा दिल्ली में केन्द्र में सरकार आप लोगों की है, 25 के 25 सांसद आपके चुनकर भेजे हैं, राजस्थान की जनता ने, कितनी बार दिल्ली के बजट में राजस्थान का जिक्र हुआ, आपके लोक सभा क्षेत्रों का जिक्र हुआ, यह बताने की कृपा करें। कहीं पर भी आपको दिल्ली में कोई स्थान नहीं मिला। प्रधान मंत्री जी ने तमाम योजनाओं में बोलने के लिए मना कर रखा है। इसीलिए हमारे सांसद दिल्ली में कहीं पर भी अपने आप को रिप्रजेंट नहीं कर पा रहे हैं।

बजट के बाद में राजस्थान पत्रिका का जो यह पेपर है, यह अपने आप में सब कुछ दर्शाता है। इसमें लिखा है कि जनता का तो पता नहीं, अपने सांसद तो खुश हैं। यानी जनता खुश है या नहीं है, परंतु बिना घोषणाओं के आपके सांसद जरूर खुश हैं। इन सांसदों की अक्षमता के कारण, निष्क्रियता के कारण निश्चित तौर पर राजस्थान कई चीजों में पीछे रह गया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार के बजट में हमें सोशल सिक्योरिटी को क्यों कवर करना पड़ा, उस बात पर आना चाहूंगा। उज्ज्वला योजना केन्द्र सरकार लेकर आयी। 2016 में इसको लांच किया गया। 2016 में जब उज्ज्वला को लांच किया तो उस समय 8 करोड़ लोगों का टारगेट किया। 2019 तक उसको पूरा कर लिया। उसके बाद फिर 2021 में उज्ज्वला 2.0 लेकर आये। उसके अंदर 01 करोड़ का प्रावधान किया, फिर उसको एक्सटेंड करते हुए 60 लाख और दिये। कुल मिलाकर 9 करोड़ 60 लाख लोगों को आज दिन तक उज्ज्वला में कनेक्शन दिया। इस कनेक्शन से

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

हुआ क्या? उज्ज्वला योजना का कनेक्शन तो आपने दे दिया, परंतु उनको सिलेण्डर कौन लाकर देगा? जिस दिन उज्ज्वला योजना आयी थी, उस दिन 419 रुपया रेट थी गैस सिलेण्डर की, आज की तारीख में 1056 रुपये 50 पैसे रेट है गैस सिलेण्डर की। यह जो गैस सिलेण्डर की बढ़ी हुई रेट है, इससे आपकी उज्ज्वला योजना फेल हो रही थी। माननीय मुख्य मंत्री जी का हम धन्यवाद देंगे कि इस फेल होती उज्ज्वला योजना को आक्सीजन देने के लिए, इसको कहीं न कहीं इम्पेट्स देने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 500 रुपये में सिलेण्डर देने की बात की है। गरीब आदमी अब जरूर निश्चित तौर पर जो उज्ज्वला योजना में आपके रीफिलिंग नहीं हो रही थी, वह तमाम रीफिलिंग होने लग जायेगी। जो 1056 रुपये में से 500 रुपये मुख्य मंत्री जी देंगे, उसके कारण गरीब को सहायता मिलेगी।

वर्ष 2022 के बजट में आप लोगों ने जरूर 200 रुपये की एक सब्सिडी देने की घोषणा की दिल्ली में। उस सब्सिडी का क्या फायदा? पहले सिलेण्डर खरीदो, उसके बाद वह सब्सिडी आपके खाते में आयेगी। अब मुख्य मंत्री जी के सपोर्ट के बाद 556 रुपये देगा उपभोक्ता और 200 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद नेट उसके 356 रुपये लगेंगे। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को यह बजट में घोषणा लानी पड़ी।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद हम बात करते हैं मनरेगा की। दिल्ली की सरकार इसको बंद करना चाहती है। जब से मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं, तब से रोजाना कह रहे हैं कि यह गड्ढे खोदने की योजना मैं बंद करूंगा। ये राजस्थान की नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी जॉब ओरियंटेड स्कीम है। 60 हजार करोड़ रुपया इसका बजट कर दिया। 33 परसेंट के करीब इसको डाउन कर दिया और हर बार आप डाउन करते हैं, परंतु बाद में आर ई में आपको इसको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि यह डिमांड-ड्रिवन है और आप कितनी भी कोशिश करेंगे जो कांग्रेस की सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की लाई हुई स्कीम है, उसके ऊपर जनता का पूरा फोकस है। यही एकमात्र रूरल डवलपमेंट में, गांव में लोगों को सहायता देने का है। मनरेगा का बजट कम आप करें और मनरेगा के बजट के अंदर 125 दिन, 100 दिन के अंदर 25 दिन जोड़कर माननीय मुख्य मंत्री जी और कांग्रेस की सरकार दे, राजस्थान की।

आयुष्मान भारत योजना लेकर आये। कैप लगा दिया उसके ऊपर। कोई उसका फायदा नहीं ले पा रहा था। उस आयुष्मान भारत को ठीक करने

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

के लिए चिरंजीवी योजना लेकर आये माननीय मुख्य मंत्री जी। 5 लाख की कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख की और 10 लाख को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया। यह कवरेज भी करेक्ट करने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। आप लोगों की दिल्ली की जो केन्द्र सरकार है, वह अडानी और अम्बानी को तो प्रमोट करती है, परंतु इन कर्मचारियों के बारे में कौन सोच रहा था? माननीय मुख्य मंत्री जी ने ओ.पी.एस. देकर इन कर्मचारियों के बारे में सोचा और अब तमाम लोगों को इस कवरेज में लाकर काम किया। यह काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया।

सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो केन्द्र की सरकार ने क्या दिया? 10 लाख लोगों को मात्र 300 करोड़ रुपये की योजना। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में 90 लाख लोगों को 9 हजार करोड़, इस योजना से लाभान्वित किया। तमाम लोगों को पेंशन से सिक्योरिटी दी। महंगाई आप बढ़ाएं, कंट्रोल आप कर नहीं पाएं और उसके कारण आम आदमी पर बोझ पड़े तो उसको ठीक कौन करे? राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार। बिजली फ्री देकर 01 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने का काम अशोक गहलोत की सरकार करे।

सांसद मद, यह सांसद मद तो देखने को ही नहीं मिल रहा है। बीच में लैप्स भी हुआ, बंद भी हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी फ्लोर आफ द हाउस पर, आपके और हमारे सबके कहने पर, अध्यक्ष जी के कहने पर हमारा विधायक मद सांसद के बराबर 5 करोड़ रुपये किया। यह करने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। गौ माता के नाम पर वोट आपको लेना है, सरकार बनानी है, सत्ता में आना है, परंतु गौ माता के लम्पी में आहत होने के बाद, उसको 40 हजार रुपये देने की घोषणा अशोक गहलोत जी को करनी है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को करनी है।

खाद्य सुरक्षा योजना केन्द्र में कांग्रेस की सरकार लायी थी, यूपीए की सरकार लायी थी, उसको देखना आपको था। 5 किलो गेहूं के साथ ये दूसरा जो राशन का किट देना था, यह केन्द्र सरकार को अपने कवरेज में लेना चाहिए था, परंतु राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने फूड पैकेट देकर, दाल, तेल, चीनी, नमक और मिर्ची सब व्यवस्था की ताकि गरीब आदमी को, सिर्फ आटा क्या खाएगा, गेहूं क्या खाएगा, उसको दूसरी चीजों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

मेडिकल कालेज आपको खोलने थे। मैंने इस पत्रिका में देखा हमारी सांसद महोदया ने भी बोला कि क्षेत्र को रेलवे, सड़क, मेडिकल कालेज जैसी कुछ मांगें इस बजट में मिलने की उम्मीद है। आपकी उम्मीद को पूरा कौन कर रहा है? राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत इसको पूरी कर रहे हैं। तीनों जगह बचे हुए जिलों में मेडिकल कालेज राज्य के खर्चे से करने की माननीय मुख्य मंत्री जी योजना लाए हैं। आप लाते हैं सारे अडानी, अम्बानी बेस लॉ। जो अडानी और अम्बानी को फायदा दें, किसान कानून और तमाम कानून, बाद में आपको स्क्रेप भी करने पड़ते हैं।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में रही तो सारे राइट बेस लॉ लेकर आयी। चाहे राइट टू इंफोर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, एन एफ एस ए और मनरेगा। केन्द्र की सरकार बेरोजगारी कम करने में इस बजट में भी नाकामयाब रही। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे गरीब आदमी को पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए थी। 6 सालों के बाद, 2019 में पहली बार गहलोत साहब ने इस पेंशन को बढ़ाया। अब फिर बढ़ाकर इसको 1000 रुपये न्यूनतम किया और कुल मिलाकर इस पेंशन को एक खैरात नहीं बताकर, उनका अधिकार बता दिया कि 15 प्रतिशत पेंशन अब हर सालाना आपको बढ़ेगी। हक बना दिया उनका, स्वाभिमान बढ़ा दिया। एक गरीब आदमी के आंसू पोछने का काम किया तो अशोक गहलोत की सरकार ने किया।

हमारे प्रधान मंत्री जी का, केन्द्र सरकार का पूरा विजन धनाढ्य लोगों की तरफ है। होना चाहिए, बिजनसमैन को भी हमको सपोर्ट करना है, बिजनसमैन को लाना है, होना चाहिए। अच्छी नीतियां होनी चाहिए। देश में व्यापार भी जरूरी है, परंतु जो उस व्यापार को चलाने वाले गिग कर्मचारी हैं, गिग कर्मचारी, किसी विधान सभा में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सभापति महोदय, हिन्दुस्तान की, भारत की किसी विधान सभा में, लोक सभा में इस गिग वर्कर के बारे में एक वर्ड नहीं बोला गया। राजस्थान में भी तीन-चार लाख हैं। ये वे वर्कर हैं जो एप के माध्यम से नौकरी लगते हैं। जिनका अपाइंटमेंट कोई आफिशियल नहीं हो पाता है। उन तमाम लोगों को भी 200 करोड़ का एक कार्पस फंड बनाकर गिग वर्कर्स को कवर किया है। आटा-दाल, तेल महंगा आप करो और केन्द्र सरकार उसको कंट्रोल नहीं करे और आठ रुपये में गरीब को खाना खिलाये, इंदिरा रसोई के द्वारा अशोक गहलोत की सरकार खिलाये, यह सोचने की बात है।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

कोरोना का मिस-मैनेजमेंट आप करो, फ्लाइट्स आपसे नहीं रुके और वैक्सीन जो हमारे साइंटिस्ट बनाये उसका श्रेय आप लो परंतु जब कोरोना से एक परिवार के अन्दर कोई बच्चा अनाथ हो जाये तो उसको सरकारी नौकरी देने का निर्णय ले तो अशोक गहलोत की सरकार ले।

आप जे.जे.एम. की बात करते हैं। यह दूसरी या तीसरी बड़ी योजना है आपकी जो फेल हो रही है। जे.जे.एम. के अन्दर अगर बात करें तो राजस्थान से जल शक्ति मंत्री गये। हमको पूरी उम्मीद थी कि 90 प्रतिशत का हमको कवरेज आयेगा और स्पेशल स्टेटस मिलेगा, वह नहीं मिला परंतु राजस्थान की सरकार ने 10 परसेंट का जो 45:45:10 था, उसको घटाकर 10 परसेंट को राजस्थान की सरकार ने वहन करने का निर्णय लिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पब्लिक कंट्रीब्यूशन जो था, वह खुद ने ले लिया। अब यह योजना कैसे केन्द्र सरकार की रह जायेगी? 45 और 10 मिलाकर 55, तो 55:45 से क्या केन्द्र की योजना में भी ज्यादा इंवेस्टमेंट अब स्टेट करेगा? यह कहां कि उलटी गंगा बह रही है?

माननीय सभापति महोदय, तमाम योजनाएं चाहे ई.आर.सी.पी. थी, यह आपको करनी थी, गहलोत साहब ने 13 हजार करोड़ रुपये इसके लिए दिये। किसानों के काले कानून आप लाओ और अलग से किसान बिल अशोक गहलोत लेकर आये। यह अंतर है अशोक गहलोतजी की वर्किंग में, एक गांधीवादी मुख्य मंत्री की वर्किंग में और केन्द्र सरकार की वर्किंग में।

पी.एम.जी.एस.वाई., आप सभी लोग यह जानते हैं कि यह चार-छह महीने डिले आयी है इस बार पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कें। क्यों? ताकि राज्य सरकार बदनाम हो और चुनाव के पहले सड़कें नहीं बनें परंतु राजस्थान में अशोक गहलोतजी की सरकार ने पांच सड़कें प्रति जिले को इस बजट में दीं और दस करोड़ रुपये हम लोगों को हर विधान सभा क्षेत्र के लिए सड़कों के लिए मिल रहा है।

आंगनबाड़ियों के लिए मैंने यह पता किया था कि सब जगह आंगनबाड़ियों के लिए हमारी चिट्ठियां गयीं तीन बार स्टेट से कि नई आंगनबाड़ी खोलने की अनुमति दी जाये पर उसका जब केन्द्र ने कोई सहयोग नहीं किया तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आठ हजार बड़ी आंगनबाड़ियां और दो हजार मिनी आंगनबाड़ियां खोलने की कोशिश की।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, यह बजट पूरी तरह से यह बताता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री एक आम आदमी का बोझ कम करने के लिए लगे हुए हैं, उसका भार कम करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे विपक्ष के साथी सिर्फ एक आदमी को भारी करने पर लगे हुए हैं और वह इतना भारी आप कर देंगे कि वह एक इंजन की सरकार से काम नहीं चला पायेंगे। राजस्थान में कोई योजना देनी है तो भाषण में यह आता है कि डबल इंजन की सरकार दो, उसके बाद राजस्थान को कुछ न कुछ देंगे। जो 25 सांसद दिये हैं, उसके कारण से राजस्थान को कुछ नहीं मिलेगा? डबल इंजन की सरकार देंगे तब ही राजस्थान को कुछ न कुछ मिलेगा।

श्री सभापति: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, यह जो तमाम रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं, इन सोशल सिक्योरिटीज की स्कीम्स को ये रेवड़ी कहते हैं। जनता देख रही है और यू-ट्यूब के माध्यम से। मैं मेरे विपक्ष के साथियों को भी यह कहना चाहूंगा कि हम यह चाहते हैं वापस आप भी जीतकर आओ और हम भी जीतकर आयें, सरकार हम बनायें और आप इसी तरह से अगली सरकार में भी हमको देखो परंतु आप यह रेवड़ियां बोलना बंद करो। गरीब को जब सहायता मिलती है, एक हजार रुपये की पेंशन अगर गरीब को मिलेगी तो वह कोई रेवड़ी है क्या? अगर मनरेगा में काम मिलेगा तो वह कोई रेवड़ी है क्या? अगर गरीब को कोई सहायता मिल रही है, अशोक गहलोतजी ने पांच सौ रुपये में सिलेंडर देने के लिए कह दिया तो यह रेवड़ी है क्या? इन तमाम चीजों को आप दृष्टिगत रखें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वैसे तो बहुत कुछ दिया है पर मैं यह चाहूंगा कि दो-चार चीजें और भी हैं। देवगढ़ में एक पचास बेड का एम.सी.एच. देने की कृपा करें। देवगढ़ शहर के आस-पास माइन्स बहुत हो गयी हैं तो देवगढ़ शहर को बाईपास देने की कृपा करें। भीम में एक कालेज में पी.जी. देने की कृपा करें और सात पंचायत क्षेत्र जो हमारे ब्यावर के पास है, उसमें एक सी.एच.सी., देवगढ़ में आर.एस.ई.बी. का आफिस और देवगढ़ में देवनारायण छात्रावास और सावित्री बाई फुले छात्रावास भीम में खोलें और मैं सारे सदन की तरफ से यह कहना चाहूंगा कि सभी सदस्यों को पांच-पांच पी.एच.सी. देने की कृपा करें और मिसिंग लिंक को दस करोड़ रुपये से बढ़ाकर और ज्यादा करने की कृपा करें।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे माननीय सदन के नेता द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, जनता उससे यह अपेक्षा करती है कि वह सरकार उसके हित में काम करेगी और जो कहेगी, उस वादे को पूरा करेगी और इसी यकीन के साथ जनता को अपने नेतृत्व पर बहुत भरोसा होता है।

जब से यह वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ है, तब से मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को सुन रही हूं। वे बहुत सारी चीजें जो इस बजट में उल्लेखित की गयी हैं, उनके बारे में बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह मुख्य मंत्रीजी ने रेवड़ियां नहीं बांटी हैं, यह जनता को सुविधा देने का काम किया है। निश्चित रूप से यदि वह सुविधा के रूप में जनता तक पहुंचे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सिर्फ कहे और करे नहीं तो यह जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपको मैं दो-तीन चीजें बताना चाहूंगी, आप कैसे कहते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो क्या कहते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो क्या कहते हैं, बताना चाहूंगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी का इसी सदन में, इसी बिल्डिंग में दिये गये भाषण का उल्लेख करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2009-10 में जब मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी थे तो उन्होंने महंगाई के बारे में कहा। अभी एल.पी.जी. गैस के सिलेंडर की बात हो रही थी तो महंगाई के बारे में क्या कहा था इन्हीं मुख्य मंत्री महोदय ने, वह मैं उल्लेख करना चाहूंगी। बजट 2009-10 का पैरा नम्बर 4- जब महंगाई की दर डबल डिजिट में थी तब मुख्य मंत्रीजी क्या कह रहे हैं? 'वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से हमारा देश और हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। वर्तमान परिवेश में मैं केन्द्र सरकार के इस समस्या से निपटने के लिए जो कदम उठाये हैं तथा दो दिन पूर्व प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में जो दिशा दी गयी है, उसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की गति को बनाये रखना

(श्रीमती अनिता भदेल)

सम्भव हो सकेगा। हमारी सरकार ऐसे कदम और उठायेगी और प्रदेशवासियों को मंदी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी।'

माननीय सभापति महोदय, उस समय महंगाई दर डबल डिजिट में थी। अभी महंगाई दर सिंगल डिजिट में है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी एल.पी.जी. गैस सिलेंडर देने की बात करके महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं जबकि पेट्रोल-डीजल के वैट को नहीं घटा रहे हैं। यदि वास्तव में महंगाई कम करनी है तो पेट्रोल और डीजल के वैट को घटायें तब ही महंगाई कम होगी।

दूसरे बजट भाषण, 2010-11 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी पैरा नम्बर 132 पर यह कह रहे हैं कि- 'वर्तमान में महंगाई की समस्या से हम सभी चिंतित हैं।' उस समय सिर्फ चिंतित थे और आज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसा दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? वर्ष 2009-10, 2010-11 में यह आपका बजट भाषण है। यह बजट भाषण की कापियां पिछले पांच साल के कार्यकाल की मेरे पास हैं और इस बजट भाषण में वर्ष 2013 में जब माननीय मुख्य मंत्रीजी का अंतिम बजट था, अंतिम वर्ष था, जब चुनावों में जाना था तो दो-तीन घोषणाएं मैं लेकर आयी हूं, जिन घोषणाओं में उन्होंने सेम टू सेम घोषणाएं की हैं, उसमें कोई अंतर उन्होंने करने की, मतलब इन अधिकारियों ने जैसा बजट दिया, वैसा का वैसा बजट हम उठाकर यहां विधान सभा में ले आये। अधिकारी यह नहीं देखते हैं कि हमने यह 2013 में क्या घोषणा करवायी थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को भी यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप 2013 का बजट उठाकर देखना कि मुख्य मंत्रीजी ने कौनसा, उसमें पैरा भी चेंज नहीं किया, संख्या भी चेंज नहीं की। इससे और बदतर बात क्या होगी?

माननीय सभापति महोदय, आंगनबाड़ी बच्चों को दो यूनिफार्म, यह इस बजट की घोषणा है। आप 2013-14 जो कि चुनावी वर्ष था, चुनावी वर्ष का जो बजट भाषण था, उसके पैरा नम्बर 112, पेज नम्बर 42 पर लैंग्वेज भी आप देखिये- 'समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे शाला पूर्व शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आते हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले प्रत्येक बच्चे को 2 यूनिफार्म उपलब्ध कराई जायेंगी, जिस पर 50 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्चा होगा एवं इससे लगभग 12 लाख 23 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे।'

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसी बजट भाषण वर्ष 2023-24 के बजट में, वर्ष 2013-14 और 2023-24, दोनों वर्ष कौनसे हैं? चुनावी वर्ष हैं, पांचवां साल है। पांच साल के कार्यकाल का अंतिम वर्ष है। उसमें फिर ये कह रहे हैं कि दो यूनिफार्म उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करता हूं। यह दोनों यूनिफार्म, यह वर्ष 2013-14 का बजट भाषण भी है और वर्ष 2023-24 का बजट भाषण भी मेरे पास है, तो कैसे आप यह कह सकते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन चीजों का उल्लेख करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपने वर्ष 2022 में महिलाओं के बारे में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कि महिलाओं के लिए यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन महिलाओं के लिए जो पिछले बजट भाषण की घोषणा है, इन बजट भाषणों की सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी तब पता पड़ेगा कि कितनी बजट घोषणाएं पूरी हुई हैं और कितनी बजट घोषणाएं सिर्फ थोथी साबित हुई हैं?

आप यह देखिये कि 20 हजार महिलाओं को वर्क फ्रोम होम की घोषणा प्रस्तावित थी 2022 के बजट में। वर्क फ्रोम होम मिला कितनी महिलाओं को? 1,385 को, कितना परसेंट है? 20 हजार के अगेंस्ट 1,385 को मिला तो मेरे को यह लगता है कि यह ऊंट के मुंह में जीरा जितना है।

फिर आप आगे घोषणा करते हैं कि हम मैट्रो का सैकण्ड फेज लेकर आयेंगे लेकिन मैट्रो के सैकण्ड फेज का कोई अता पता नहीं है कि वह कहां गया, कहां नहीं गया।

इसी प्रकार से आपने 2013-14 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि हम प्रत्येक महिला को, अभी इसमें थोड़ा-सा चेंज किया है, अधिकारियों ने थोड़ी-सी स्मार्टनेस दिखायी है, इस बार उन्होंने दो साड़ी और एक कम्बल की बजाय एक फूड किट का प्रोविजन करवा दिया। अधिकारियों ने मुख्य मंत्री महोदय से करवा दिया कि कैसे-कैसे सीधे-सीधे रेवड़ी बांटनी हैं। पिछले बजट भाषण में दो साड़ी और एक कम्बल बोला था। इस बजट भाषण में बोला कि हम फूड पैकेट देंगे। अब यह रेवड़ी नहीं है तो क्या है? यह पूरी होने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिए कि महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल की घोषणा की लेकिन शिक्षकों के 70 प्रतिशत पद आज भी इन स्कूलों में खाली पड़े हैं। इसी प्रकार से 30 हजार सफाई कर्मचारी भर्ती करने की बात की। बहुत ताज्जुब की बात है। मंत्री महोदय आपको निवेदन करना चाहूंगी। 2013-14 का बजट उठा कर देख लेना, आपके पास कापी नहीं है तो मैं आज

(श्रीमती अनिता भदेल)

लायी हूं। इन पांच सालों की पांच प्रतियां हैं और पिछले पांच सालों की पांच प्रतियां भी हैं। सेम-टू-सेम घोषणा। 30 हजार सफाई कर्मचारियों की 2023 के बजट भाषण में की गई थी और 2013 के बजट भाषण में भी कही लेकिन उसकी पूर्ति नहीं कर पाये क्योंकि पांच महीने का कुल समय आपके पास रहा। वह भर्ती आने वाली सरकार में माननीय वसुन्धराजी ने 20 हजार स्वच्छता सैनिकों की भर्ती उस समय की। यह हम कह सकते हैं कि कितनी बजट घोषणाएं आपकी अधूरी हैं, जिनको आपने पहले करने की घोषणा तो की लेकिन उनको पूरा नहीं किया।

इसी प्रकार आपने कहा कि हम बजट में बहुत सारी घोषणाएं करेंगे लेकिन आप उनको पूरा कर ही नहीं पाये। मैं राजस्थान पत्रिका 10 फरवरी का उल्लेख करना चाहूंगी। मैं अनेकों बार कहती हूं प्रेस के साथियों को भी कहती हूं कि जब बजट आता है, बजट में क्या-क्या आया, बहुत बढ़चढ़ कर उसको प्रिन्ट करते हैं और अख़बार के माध्यम से उसको जनता तक पहुंचाते हैं लेकिन इतना एनालिसिस भी कर लीजिए कि पिछला बजट भाषण जो दिया था उसकी कितनी घोषणाएं पूरी हुईं। निश्चित रूप से 50 प्रतिशत बजट घोषणाएं पूरी नहीं हुईं। उसका यही कारण है कि आप उस चुनाव में गये तो 20 की संख्या पर सिमट कर आ गये।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक और उदाहरण है मेवात मगरा बोर्ड का। मुझे यह समझ में नहीं आता कि लास्ट के वर्षों में ही मेवात और मगरा बोर्ड को पैसा क्यों दिया जाता है? आप देखिए 2009-10, 2010-11, 2011-12 की घोषणाओं को। 5 करोड़ से शुरू होता है। मुरारी लालजी, 5 करोड़ से बात शुरू हुई। 2009-10 में 5 करोड़, 2011-12 में 10 करोड़, 2012-13 में 25 करोड़, फिर 2013-14 में 50 करोड़। हो गये पांच साल पूरे। अब 50 करोड़ से गाड़ी आगे चलनी चाहिए न। लेकिन वापस दो-तीन साल तक तो हम भूल ही गये कि मगरा और मेवात बोर्ड को पैसा देना है। लास्ट के दो वर्षों में आपने घोषणा की। 2022-23 और 2023-24 में घोषणा की। 2013-14 में 25 करोड़ पर अटके थे, उस 25 से आंकड़ा 50 करोड़ पर आ गया। पिछले साल फिर 25 से नीचे आ गया। धीरे-धीरे करते-करते फिर पांच साल जब पूरे होंगे तो फिर 50 करोड़ पर पहुंच जायेगा। बहुत ही अन्याय है माननीय सभापति महोदय, इस क्षेत्रों के लोगों के साथ। बहुत ज्यादा अन्याय है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से कमेटीज के गठन, फोर्सेज के गठन की बात की गई है। आप देखिए। मैंने कम्पेयर किया है। माननीय मुख्य मंत्री

(श्रीमती अनिता भदेल)

महोदय ने 2012-13 ने घोषणा की थी। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप इन अधिकारियों को समझाइए कि मुख्य मंत्रीजी से ऐसी घोषणाएं मत करवाइए, जो लोगों को पता चले कि यह फर्जी घोषणा है।

2012-13 के पेज नम्बर 59, पैरा नम्बर 165 में कहा कि 'राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए कृत संकल्पित है और अवैध खनन को प्रभावी रूप से रोकने के लिए खनिज रक्षा दल बनाया जायेगा'। मुझे बताइये कि खनिज रक्षा दल के बनने से अवैध खनन रुक गया है क्या? नहीं रुका है, लेकिन इस बजट भाषण में फिर वही घोषणा। एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा और यह जो दल है वह खनिज रक्षा दल की भांति ही स्पेशल टास्क फोर्स बनाने से पेपर का लीक होना रुक जायेगा। रक्षा दल बनाने से पेपर लीक होना रुक जायेगा क्या? इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, हम पेपर लीक को नहीं रोक सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार एफआरबीएम एक्ट की चर्चा हुई। आप देखिएगा कि हम इस प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं। आज राजस्थान पत्रिका की खबर है कि हर व्यक्ति पर 50 हजार रुपये के लगभग कर्जा हम देकर जा रहे हैं। मैं पिछले पांच सालों का आंकड़ा बताती हूं। 2018-19 में 3 लाख 39 हजार 368 करोड़ रुपया कर्जा था, वह 2023-24 में बढ़कर 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ रुपया हो गया। इसका मतलब है कि इन पांच सालों में 2 लाख 40 हजार 413 करोड़ रुपये का कर्जा चढ़ाया है और यह कर्जा निश्चित रूप से इस प्रदेश को जिस तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनोमी क्रेश हुई है न, उसी तरह से हम इसकी अर्थव्यवस्था को क्रेश की ओर ले जा रहे हैं। फिर हम कहेंगे कि केन्द्र सरकार हमें मदद नहीं कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, आप देखिए कि किस तरह से अधूरे काम, यदि करप्शन का नया तरीका ढूंढना हो तो आप उस काम को लिंगरआन कर दीजिए तो आटोमेटिकली करप्शन हो जायेगा। जितना बजट प्रोविजन आपने इस वर्ष रखा है और जिस काम के लिए रखा है, यदि वह काम उस वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं होता है तो उसकी निश्चित रूप से लागत बढ़ती है और यह लागत करप्शन का एक बहुत बड़ा माध्यम साबित होता है।

माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग और सभी निर्माण के कार्य परियोजनाओं की स्वीकृति जारी होने के बाद 90 कार्यों की परियोजनाएं 5 वर्ष से अधिक अपूर्ण हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करिये प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूं। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूं। समाप्त कर रही हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि किस तरह से भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक ने बात कही है कि 770 उपयोगिता प्रमाण पत्र हमने जमा नहीं कराये, जिस वजह से हमारा भार बढ़ा है।

माननीय सभापति महोदय, एक लास्ट विषय है जिसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। प्रदेश में राइट टू हैल्थ को लेकर बहुत हल्ला हो रहा है। सरकार राइट टू हैल्थ बिल लेकर आ रही है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहिए लेकिन हम अपनी सरकारी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करें और सिर्फ निजी हास्पिटल्स पर ही डाल दें तो फिर हम स्वास्थ्य का अधिकार नहीं दे सकते। यह राइट टू हैल्थ नहीं है, यह राइट टू ट्रीटमेंट है क्योंकि हैल्थ में तो सारी चीजें कवर हो जाती हैं।

माननीय सभापति महोदय, शुद्ध के विरुद्ध अभियान यह मेरा लास्ट है। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। 2009-10 में कार्यकाल शुरू हुआ। 2009-10 में माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के रूप में हम कार्यक्रम प्रारम्भ करेंगे और लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे। 2010-11 में कहते हैं कि गुणवत्ता परखने के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब प्रत्येक जिले में स्थापित करेंगे। फिर दो साल गौण हो जाते हैं। 2011-12 में कहते हैं कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राज्य में जिला मुख्यालय पर मोबाइल वैन से हम पीपीपी मोड पर शिफ्ट हो गये। स्थायी प्रयोगशालाएं शुरू करवायेंगे पीपीपी मोड पर हर जिले में। मोबाइल लैब तो लगी नहीं। अब पीपीपी मोड आ गया।

माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण 2019-20 में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। बजट भाषण 2020-21 में आप उल्लेख कर रहे हैं कि मिलावटखोरों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जाएंगे। वह फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां गये? 2022-23 में कह रहे हैं कि प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्ट्रेट आफ फूड सेफ्टी बनाने की मैं घोषणा करता हूं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): फास्ट ट्रैक कोर्ट से आप डायरेक्ट्रेट पर आ गये। 2022-23 में आप डायरेक्ट्रेट पर आ गये और कहा कि हम शुद्ध के विरुद्ध अभियान के लिए 200 नये सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित करेंगे और सात फूड सेफ्टी लैब का कार्य शीघ्र पूर्ण करेंगे।

श्री सभापति: श्री रामनारायणजी मीना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने डिस्ट्रिक्ट थे उनमें एक में भी लैब नहीं बनी।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बस लास्ट। मैं यही पाइन्ट कह रही हूं, इससे ज्यादा नहीं। लास्ट में बोल रहे हैं कि फूड सेफ्टी और ड्रग कन्ट्रोलर के कार्य का एकीकरण कर कमिश्नरेट, फूड सेफ्टी और ड्रग कन्ट्रोल करेंगे। वह तो आपने बनाया नहीं है।

श्री सभापति: अब रिकार्ड नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: थैंक यू। अब रिकार्ड नहीं हो रहा है। समय हो गया आपका।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता द्वारा प्रस्तुत बजट पर काफी गम्भीर बातें कही गयीं लेकिन हमारे प्रतिपक्ष द्वारा तैयारी करके कहना चाहिए था। ऐसा कुछ लगा नहीं। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बोलिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में जन हितैषी और गरीब के हित में यदि कोई बजट है तो उस श्रेणी में यह बजट आता है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सच-सच बोलना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): रामलाल जी, आपको लीडर आफ अपोजिशन तो बनाया नहीं जा रहा। मैं आपके समाज का आदमी हूं। आचरण वैसा का वैसा ही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कंटीन्यू प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): कोई बात नहीं। जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया, माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी कहां से होती है? कोई भी केस पहले ACB द्वारा जांच की जाती थी, उसमें चालान किया जाता था। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के शासन में करीब आज से 20 साल पहले एफ.आर. लगना शुरू हुआ और करप्शन को बढ़ोतरी मिली।

(श्री रामनारायण मीना)

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्रीजी दौसा आये थे। उनकी स्पीच को उठाकर मेरे साथी लोग देखें। इतना अहम भरा, मैंने यह कर दिया। भारत यह कर रहा है, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने सड़क बना दी, मैंने यह काम कर दिया। प्रधान मंत्रीजी को यह भी तो कहना चाहिये था कि मैंने गरीब के हित में क्या किया? माननीय सभापति महोदय, जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वह LIC हो, बैंक्स हों, आज उनके मित्र के द्वारा जब कमजोरी महसूस की गयी फाइनेंशियली, तो हमारे इकोनोमिस्ट बता रहे हैं कि 30 से 40 हजार करोड़ के करीब अकेले भारतीय स्टेट बैंक को घाटा हुआ है। यही स्थिति LIC की है।

माननीय सभापति महोदय, आज पूंजीकरण की ओर जिस तरह से देश बढ़ता जा रहा है, यह अमेरिका नहीं है। माननीय सभापति महोदय, उससे उलट राजस्थान का बजट है। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें किसी तरह की कमी छोड़ी गयी हो। गरीब को पेंशन हो या गरीब के हित में काम हो या इंदिरा रसोई का मामला हो।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के हित में मैं कृषि मंत्रीजी से आशा करूंगा कि वह मुख्य मंत्रीजी से बात करके जो कृषि उपज मण्डी अधिनियम बना है, वह किसानों के हक में बनाया गया था, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच में कोई दलाल या बिचौलिया नहीं हो। यह दुर्भाग्य है कि आज भी आढ़त चल रही है। यदि किसान का पैसा कोई व्यापारी लेकर बैठ जाता है तो उसके खिलाफ किसी भी तरह का प्रोविजन नहीं है। ऐसे व्यापारी को भी लाइसेंस मिलता जा रहा है। मैं आशा करूंगा इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा कि इस तरह की बजट में जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाये। कोई भी जंगली जानवर किसान को आहत करता है तो उसको मुआवजा मिलता है। माननीय सभापति महोदय, फसल बर्बाद होने के बाद में, जंगली जानवर जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, अभयारण्य के पास में जिस प्रकार से किसानों को नुकसान होता जा रहा है, उसमें मुआवजा राशि दी जाये। इसके बारे में प्रोपर मोनिटरिंग होनी चाहिये ताकि किसान वहां पर अच्छी तरह से बस सके।

माननीय सभापति महोदय, पहली दफा माननीय भैरोंसिंह जी के समय से जो पैनोरमा का मामला चला, उसके पहले भी माननीय सुखाड़िया के टाइम में भी दो पैनोरमा बनाये गये थे। आज पहली दफा शासकों के बारे में और वह

(श्री रामनारायण मीना)

भी मीणा समाज के शासकों के बारे में पैनोरमा बनाने की श्री बूंदाजी मीणा, बूंदी की जो घोषणा की गयी, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और राजस्थान की जनता की ओर से और जाति विशेष की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि देश में जिस प्रकार जातिवाद हावी होता जा रहा है, यह हमारा दुर्भाग्य है कि देवी-देवताओं को जिस प्रकार से पार्टी विशेष अपने अधिकार में लेने की बात करती है और यही नहीं, गौमाता का नाम लेकर वोट लेने वाले लोग याद करें 1966-67 को, गाय का सींग पकड़कर जिस प्रकार से पोस्टरों में दिखाकर दिल्ली की पांचों सीटें एक पार्टी विशेष ले गयी, लेकिन आज ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 1966-67 में जिस तरह से 400 से ज्यादा...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज बैठिये। आप प्लीज बैठिये। (व्यवधान) don't disturb him. माननीय सदस्य, बैठिये आप। No, You are not allowed.

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): गाय के हत्यारों को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में किसने शामिल कर रखा है? इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ऐसे प्रधान मंत्री के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये देश की जनता के द्वारा। एक नहीं हैं, चार हैं। गौमांस के हत्यारे मंत्रिमण्डल...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गौमाता की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बार-बार मत खड़े होइये। Please don't disturb hon. Member. माननीय सदस्य को डिस्टर्ब नहीं करें। जब आप बोलते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता आपको। (व्यवधान) You are not allowed.

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि आप गाय का नाम लेते हो और गौ के हत्यारों को मंत्रिमण्डल में शामिल करते हो। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, यहां तक कि नन्दीशाला भी राजस्थान के बजट में डाली गयी है।

माननीय सभापति महोदय, समय पर गौशालाओं को किस प्रकार से अनुदान मिले, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा हो, उनकी संरक्षा हो। यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य, आप

(श्री रामनारायण मीना)

जानते हो, आपने तो देखा है विकास को जो गति दी गयी है, अभी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं, मैं सूची बताने में टाइम नहीं लूंगा, लेकिन पहला मौका है जब चंबल में चार पुलियाएं स्वीकृत हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान के इतिहास का पहला मौका है। झरेल की पुलिया, गोठडा की पुलिया, मंडावरा की पुलिया और कालीसिंध में भी पुलिया का कल-परसों तक हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार को, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मेरे अकेले के क्षेत्र में चार-चार पुलिया बन रही हैं। क्यों कर रहे हैं, कहां से पैसा आयेगा? जब पैसा खर्च होगा तो अड़ोस-पड़ोस से भी इकट्ठा किया जायेगा, बैंक से भी लिया जायेगा, कर्ज भी लिया जायेगा, शर्मनाक बात नहीं है। शर्मनाक बात तो यह है कि भ्रष्टाचार जिस कदर बढ़ रहा है, आज जिस तरह से पूंजीवाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस को बेचा जा रहा है और देश को कमजोर किया जा रहा है। केवल पाकिस्तान का नाम लेकर राज करना बहुत आसान है, लेकिन मैं डाक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो राज्य सभा के मैम्बर हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने यह पूछा था, माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्रीजी से कि चीन की सीमा पर लगती हुई 10 टेकड़ी पर चीन ने 15 किलोमीटर आकर कब्जा किया या नहीं किया? इसलिये मैं रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य से अर्ज करना चाहूंगा कि आपका ज्ञान ज्यादा हो सकता है, देशभक्ति ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रेक्टिकली स्वार्थवश होकर कभी राज नहीं करना चाहिये और जातिवाद के आधार पर नहीं करना चाहिये और धर्म की उन्मादता के आधार पर नहीं करना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा था। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम कोट किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। प्लीज, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य के मामले में जिस प्रकार से CHC खोली गयी, सब कुछ खोला गया। आप करप्शन की बात करते हो, मैं नहीं कहना चाहता। पहली दफा भारत सरकार के अधीन करप्शन नहीं था। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में

(श्री रामनारायण मीना)

कोरोना के समय में करप्शन हुआ और आज तक उसकी जांच नहीं हुई। करप्शन, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं रामगंज मण्डी से आने वाले सदस्य से, कि आप भ्रष्टाचार की जननी...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप इधर देखिये, उधर नहीं। प्लीज इधर देखें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): यह बीच में न बोलें।

श्री सभापति: आप मुझे ही सम्बोधित करें। आप आसन को ही सम्बोधित करिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश चल रहा है, उसके उलट राजस्थान में आपको ध्यान है, माननीय सभापति महोदय, आप तो बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं। पहले ड्रिंकिंग वाटर के नाम पर मात्र 10 प्रतिशत देती थी और हम पेयजल योजना बनाकर इर्रिगेशन की योजना को भी लागू करते थे। आज यह दुर्भाग्य है ERCP जैसा प्रोजेक्ट, जो राजस्थान के 13 जिलों की जनता की प्यास बुझायेगा, उस प्रोजेक्ट को किसी न किसी बहाने, उनको शर्म आनी चाहिये नेताओं को, जो दौसा में कह रहे थे। वह जो दौसा में कह रहे थे कि हम 13 जिलों को पीने का पानी देंगे। शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की असत्य बात करके, राजनीतिक बात करके, देश की जनता को और विशेषत: राजस्थान की जनता को भ्रमित कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा संघीय ढांचा है। आज राजस्थान को पूरा सहयोग नहीं करना, यह क्या संघीय ढांचा है? आज मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं? यह संघीय ढांचा है? आपकी पार्टी के साथ आप क्या कर रहे हो?

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब शुरू की थी, मैं भी उस समय पार्लियामेंट में था। स्टेट्स से एड जीरो परसेंट ली गयी थी, आज आप 40:60 की बात कर रहे हो। स्टेट को कमजोर कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इन सारी बातों के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की कोई काट नहीं है। हिन्दुस्तान के किसी भी स्टेट में यह चीज नहीं है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज और मेरे क्षेत्र में ट्रोमा सेंटर।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन एक बात अर्ज करूंगा, आपके

(श्री रामनारायण मीना)

माध्यम से सरकार को एक सिफारिश पहुंचाना चाहता हूं कि हम सब लोग दलित का, वंचित का, आदिवासी का नाम लेते हैं, उसकी दुहाई देते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देखिये, दलित वर्ग के लोग प्रमोशन में कमजोर कर दिये गये हैं। उनका कोटा फिक्स कर दिया गया है। गरीब आदमी को आप ऊपर उठाओगे तो कोटा कहां से आयेगा। जो कर्मचारी प्रमोशन के हकदार हैं, उनको इसलिए रोका जाता है कि आपकी जाति की शिड्यूल्ड कास्ट के कोटे में पहले से आलरेडी सीटें भरी हुई हैं। मैं गर्ग साहब से कहना चाहूंगा कि इस चीज को आप उठाइये। हम कांग्रेस वालों का फर्ज बनता है कि हम भी आपका साथ दें। सदन में प्रस्ताव लाइये।

आज आप इतना कर रहे हैं, देश को इस जातिवाद से किसने एकजुट रखा? आदरणीय बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया। आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हो और उनसे घृणा करते हो। यदि आपमें हिम्मत है तो इस राजस्थान विधान सभा में प्रस्ताव लायें और प्रधान मंत्री जी को कहें कि नये संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रखा जाये और मेरी पार्टी पूरा सहयोग करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं पार्टी का लीडर नहीं हूं, एक ऐसा पाइंट है जो देश को एकजुट कर सकता है। एक ऐसा आधार है।

श्री सभापति: कृपया 2 मिनट में समाप्त करें। दो मिनट ओनली, प्लीज।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): जी, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मेरा जहां तक ख्याल है मैंने तो शुरुआत ही की है।

श्री सभापति: समय की पाबंदी है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 5 मिनट तो हमारे साथी ले गये।

श्री सभापति: समय की पाबंदी है। 15 मिनट का है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, जो भी है। मैं कुछ बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है। हालांकि थोड़ा-थोड़ा भ्रष्टाचार हमारे यहां भी है। स्वायत्त शासन विभाग में

(श्री रामनारायण मीना)

करप्ट आदमियों को महत्व दिया गया है और मैंने मंत्री जी से भी कहा है। मैं मुख्य सचेतक जी से अर्ज करूंगा कि ऐसे मामलों को थोड़ा देखें ताकि भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका नहीं मिले।

आज भारतीय जनता पार्टी ने बूंदी कालेज की भूमि, वहां के विधायक बैठे हैं, एक किलोमीटर की परिधि में किसी भी पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन को नहीं जानी चाहिए, बूंदी में लगवा भूमि भारतीय जनता पार्टी ने ली है। यह अपनी पावर का मिसयूज है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी भूमि को वापस लिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ में राजस्थान के सांसदों से अर्ज करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि वह राजस्थान का पक्ष रखें। राजस्थान का नमक खाया है तो उसका चुकारा करें, राजस्थान के हित में काम करें।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): यह जिस भूमि की बात कर रहे हैं उसमें 01 करोड़ रुपये देकर के रजिस्ट्री करायी है।

श्री सभापति: कन्क्लूड करिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): नकद पैसे देकर के 01 करोड़ रुपये में उसकी रजिस्ट्री हुई है। पैसा दिया है सरकार को।

श्री सभापति: बोल देना आप।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मुझे पता है, डोगरा साहब।

श्री सभापति: आप प्लीज, इधर ही देखें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं डोगरा साहब को याद दिलाता हूं कि राजनीति के गरूर में, सत्ता में मदहोश मत होइये।

श्री सभापति: आप कन्क्लूड करिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): कालेज की जमीन वापस कालेज को दी जाये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री संजय शर्मा)

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 10 फरवरी को इस पवित्र सदन में बजट प्रस्तुत किया गया था। बजट प्रस्तुत करने से पहले सम्पूर्ण राजस्थान में बड़े-बड़े होर्डिंग माननीय मुख्य मंत्री जी की मुस्कुराते हुए फोटो के लगाये गये थे। इन होर्डिंग में बचत, राहत और बढ़त, तीन शब्द का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। जहां तक मुझे जानकारी है 10 फरवरी को पूरे राजस्थान में लगभग 14 हजार एलईडी भी लगायी गयी थीं और प्रयास यह किया गया था कि राजस्थान का एक-एक जन अपने मुख्य मंत्री को बजट प्रस्तुत करते हुए देखे। जो स्लोगन दिया है बचत राहत और बढ़त, उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी राजस्थान की जनता को क्या सौगात देंगे, उसको सीधा लाइव प्रसारण के माध्यम से देखें।

सभापति महोदय, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब यह प्रसारण शुरू हुआ तो एलईडी के ऊपर यूट्यूब के ऊपर राजस्थान की जनता ही नहीं, अपितु देश की जनता ने माननीय मुख्य मंत्री जी को 2022 से लेकर 2023 तक का जो बजट था उसको पढ़ते हुए देखा। राजस्थान की जनता को ना उस बजट में बचत दिखी, ना राहत दिखी, ना बढ़त दिखी। दिखे तो केवल असहाय मुख्य मंत्री दिखे। मानवीय भूल के कारण शर्मिंदा होते हुए माननीय मुख्य मंत्री दिखे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पवित्र सदन में अपनी उस मानवीय भूल के कारण माफी भी मांगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस मानवीय भूल को करने वाले मानव को भी सामने लायें। उस मानवीय भूल करने वाले मानव को भी प्रताड़ित करने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी करें। अधिकारी चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, इस दंडनीय अपराध के लिए, यह मुख्य मंत्री जी ने जो माफी मांगी है, शर्मसार हुआ है पूरा राजस्थान, उसके लिए उस अधिकारी को दंड मिलना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि अलवर नगर परिषद् को नगर निगम बनाने के लिए काफी लंबे समय से मांग चल रही थी। नगर परिषद् द्वारा 2 बार प्रस्ताव भी भिजवाये गये थे। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से नगर परिषद् अलवर को नगर निगम बनाने का जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय के अंतर्मन से बहुत-बहुत आभार

(श्री संजय शर्मा)

व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग भी करता हूं कि नगर विकास न्यास, अलवर को अलवर विकास प्राधिकरण के रूप में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 में 22 जुलाई को अनुदान मांग संख्या 16- पुलिस में मैंने अलवर में वैशाली नगर में थाना खोलने की मांग की थी। 2020-21 के बजट में भी मैंने इस मांग को पुन: दोहराया था। 2021-22 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने पत्र लिखकर आग्रह किया था। देर आये दुरुस्त आये, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को कि इस बजट में आपने अलवर शहर के वैशाली नगर में थाना खोलने की घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि अखैपुरा चौकी जो अलवर शहर में स्थित है, उसको थाने के रूप में क्रमोन्नत करने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी करें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेयजल की व्यवस्था को सुधारने के लिए इस बजट में चंबल-अलवर-भरतपुर पेयजल परियोजना अलवर, भरतपुर के लिए 5,776 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की गयी है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019-20 में इसी पवित्र सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा चंबल-अलवर पेयजल परियोजना से अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर जिले के 14 कस्बों एवं 3072 गांवों में चंबल नदी से 4,718 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति की परियोजना की घोषणा की गयी थी। इसके साथ-साथ 2021-22 में ईसरदा बांध परियोजना के तहत अलवर शहर सहित 14 विधान सभाओं में पेयजल व्यवस्था लागू करने की बात कही गयी थी।

सभापति महोदय, पूर्व में घोषित परियोजनाओं पर एक इंच काम विभाग द्वारा नहीं किया गया है। ये परियोजनाएं जनता का ध्यान रखते हुए कब

(समय: 14:00 बजे)

शुरू होंगी, कब अलवर शहर की जनता और अन्य शहरों के विधान सभा क्षेत्रों के लोगों को पानी मिलेगा, इसकी कोई संभावना मुझे नहीं लगती है।

(श्री संजय शर्मा)

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि आपने 2021-22 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों की अनुशंसा पर 10 ट्यूबवैल और 40 हैंडपम्प की घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 20 ट्यूबवैल की घोषणा अपनी रिप्लाई में निश्चित रूप से करके हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनको सौगात देने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं चिकित्सा क्षेत्र की बात करूं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जनता क्लीनिक की घोषणा की गई थी। यह घोषणा 2019-20 में की गई थी। आज अलवर शहर की जनता उस जनता क्लीनिक को गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में ढूंढ रही है, जनता क्लीनिक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 2021-22 के बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा सीएचसी को मानक सीएचसी बनाने की घोषणा की गई थी लेकिन, माननीय सभापति महोदय, घोषणा तो कर दी, मेरे से बजट भी मांग लिया, लेकिन एक साल बाद उस घोषणा को कैंसिल करने का काम चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया। माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर में शिशु वार्ड के रूप में हमारे अस्पताल के अंदर एक ऐसी जगह चल रही है, जहां हम पूरे नोर्म्स को पूरा कर रहे हैं, केवल उसको शिशु चिकित्सालय का दर्जा देने की मांग है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आग्रह किया था कि शिशु चिकित्सालय खोलकर अलवर शहर की जनता को सौगात दें।

माननीय सभापति महोदय, यदि पेयजल की बात करूं तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि अलवर के नजदीक सिलीसेढ़ बांध जो अलवर शहर की लाइफलाइन बन सकता है, उसका प्रस्ताव 37 करोड़ रुपये का जलदाय विभाग के द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है। यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी अपनी सहमति और 37 करोड़ रुपये का बजट सिलीसेढ़ बांध से अलवर शहर को पानी सप्लाई के लिए आबंटित कर देंगे तो निश्चित रूप से अलवर शहर में पेयजल की समस्या से बहुत बड़ी निजात हम लोगों को मिल सकती है।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में अलवर के अलग-अलग क्षेत्रों में रीको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों को खोलने की घोषणा की

(श्री संजय शर्मा)

है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि उद्योग खुलने चाहिए, उद्योग के माध्यम से विकास होता है लेकिन जिस किसी गरीब की जमीन उद्योग के नाम पर ली जाती है उस गरीब किसान के बेटे को रोजगार की चिंता भी माननीय मुख्य मंत्रीजी करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि सम्पूर्ण राजस्थान में हरियाणा की तर्ज पर 75 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगार युवकों को उस उद्योग में रोजगार देंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या से हम बहुत हद तक लड़ भी सकेंगे और बेरोजगारों को रोजगार भी दे सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2019-20 में विकास पथ की घोषणा की थी। मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक ही विकास पथ बना है। साथ ही साथ आपने इस बजट में 10 करोड़ रुपये नोन-पेचेबल और मिसिंग सड़कों की घोषणा की है। 35 किलोमीटर की नगर परिषद् के माध्यम से सड़क की घोषणा की है, उसमें आपसे आग्रह करूंगा कि 10 करोड़ रुपये की सड़कों का जो प्रपोजल है, पूर्व की भांति माननीय विधायकों की अनुशंसा पर करें तो ये अधिकारी जो दादागीरी उस वक्त करते हैं, उस दादागीरी से हमको भी निजात मिलेगी और आम जनता को भी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, 2022-23 में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा स्मार्ट सिटी की योजना अलवर शहर के लिए घोषित की गई थी, लेकिन उस घोषणा पर एक भी काम विभाग द्वारा नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा अलवर शहर में पार्किंग की व्यवस्था को देखते हुए कम्पनी बाग़ में 40 करोड़ रुपये से पार्किंग बनाने की घोषणा की थी लेकिन उस पर भी एक इंच भी काम नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 में गुरुनानक देवजी की 550वीं जयंती पर अलवर शहर सहित हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा व बूंदी में गुरुनानक जयंती पार्क की घोषणा की गई थी।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए बड़ा दुख है, मैंने प्रश्न लगाया था, उस प्रश्न के जवाब में विभाग ने यह कहा कि हमने गुरुनानक जयंती पार्क का निर्माण कर दिया है, लेकिन उस

(श्री संजय शर्मा)

स्थान पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, बिलकुल दुर्दशा है और राज्य सरकार के अधिकारी सरकार को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सभापति: थैंक यू। खिलाड़ी लाल जी बैरवा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 2021-22 में रूपवास आरओबी से हनुमान सर्किल तक नाला निर्माण कार्य करवाने का इन्हीं अधिकारियों द्वारा कहलवाया गया था, लेकिन मेरे प्रश्न के जवाब में यू डी एच विभाग ने यह बताया है कि यह नाला फिजिबल नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब आप माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा घोषणा करा रहे हैं तो पहले इसके बारे में जानकारी कर लें कि यह फिजिबल है या नहीं है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं, आग्रह करता हूं कि अलवर शहर की पानी की समस्या के समाधान के लिए सिलीसेढ़ से पानी लाकर 37 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

सूचना

मारवाड़ जंक्शन में श्री श्रवण सिंह की गुमशुदगी

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक लड़का पांच दिन से लापता है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में वहां लोग एकत्रित हुए हैं। श्रवण सिंह नाम का लड़का लापता है।

श्री सभापति: संज्ञान में आ गया है, प्लीज।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2023-24 पर चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

माननीय सभापति महोदय, बजट में सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने सबका ध्यान रखा है। वाद-विवाद एक अलग चीज है लेकिन देखा जाए तो हर चीज में, चाहे आप रसद विभाग को देखें, आगामी वित्त वर्ष में करीब एक करोड़ एनएफएसए परिवारों को नि:शुल्क राशन के साथ-साथ प्रति माह एक-एक किलो दाल, चीनी, नमक व एक लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराने का जो सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उज्ज्वला योजना है वो बिलकुल भी सिलेंडर घरों में रखाव में आ गये थे। आज उस सिलेंडर की कीमत हजार रुपये से ऊपर हो गई तो पांच सौ रुपये का जो सिलेंडर एलपीजी गैस का उज्ज्वला योजना में देने की घोषणा की है वो एक सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अगर विद्युत की बात की जाए तो 100 यूनिट बिजली तक के उपयोग को नि:शुल्क किया जा रहा है, यह आम आदमी के लिए बड़ा फायदेमंद है। इसमें साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में गोलारी में 33 केवी जीएसएस की सख्त आवश्यकता है। यह डांग क्षेत्र में आता है और मदनपुर वहां से लगा हुआ है जिसमें 3 फेज का कनेक्शन आज तक भी उपलब्ध नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम लीलोटी भी डांग क्षेत्र में है, वहां 33 केवी जीएसएस की व्यवस्था हो जाती है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे डांग क्षेत्र में बिजली का काफी फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जब से बसेड़ी का नया क्षेत्र बना है, उसके जितने भी कार्यालय हैं, दूसरे विधान सभा क्षेत्र में है। मैं जेवीवीएनएल का एक्स ईएन कार्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोलने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, युवा विकास और खेल मामलों की अगर बात की जाए तो 200 करोड़ रुपये दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण व रोजगारोन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने, 100 करोड़ रुपये समग्र व्यक्ति विकास एवं 200 करोड रुपये शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं सम्बन्धित संसाधनों हेतु, इस प्रकार से 500 करोड़ रुपये की जो घोषणा की है, यह बड़ा सराहनीय कदम है। सावित्री बाई फुले वाचनालय, लाइब्रेरी की हर ब्लाक में व्यवस्था की है, इससे बहुत बड़ा फायदा हम सबको मिलेगा।

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में ग्राम पंचायत कोटरा में एक खेल स्टेडियम हेतु हमने जमीन अलाट करवाई थी। उस पर हमने 50-60 लाख रुपये की बाउण्ड्री वाल कर दी है, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण अगर 2 करोड़ रुपये हमको मिल जाता है तो हमारा यह खेल मैदान तैयार हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने राजीव गांधी एविएशन विश्वविद्यालय स्थापित करने का साहसिक कदम उठाया है और अमेठी, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जयपुर में खोला जाना है। इस विश्वविद्यालय के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे डांग क्षेत्र में बहुत जमीनों की उपलब्धता है। इसको जिला धौलपुर में खोला जाए तो हम सबको बहुत फायदा मिलेगा। सरकार को भी बहुत आसानी होगी क्योंकि वहां जमीन की कीमतें बहुत कम हैं इसका फायदा सरकार को कम पैसे देने से होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा काफी हुई है लेकिन मेरे क्षेत्र के बसेड़ी और सरमथुरा ब्लाक में अभी तक कन्या महाविद्यालय नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पिछड़ा क्षेत्र है। इसमें अगर ये व्यवस्थाएं होती हैं तो निश्चित रूप से बच्चियों के लिए हमें बहुत फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उपखण्ड बसेड़ी में आईटीआई खोलने की अगर व्यवस्था हो जाए तो काफी कुछ फायदा मिलेगा। जिस तरह से देवनारायण स्कूटी योजना में 20 हजार से 30 हजार स्कूटी कर दी है, लेकिन इसमें जो विशेष योग्यजन हैं वो हमारे पास आते रहते हैं और ऐसी स्थिति है कि अगर इन लोगों के लिए भी 500 स्कूटी पूरे राजस्थान में कर दी जाएं तो मैं सोचता हूं कि ये जो विशेष योग्यजन हैं उनको इसका काफी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ, सरकार को दुआएं भी मिलेंगी।

सभापति महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो एक-एक कला, वाणिज्य, विज्ञान और कृषि का किया है, यह नाकाफी है, इसे कम से कम चार-चार किया जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे यहां भी आपने महाविद्यालय खोला है, उसमें कृषि का सब्जेक्ट नहीं होने से हमारा क्षेत्र पिछड़ रहा है और बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाये।

विद्यालयों में आधारभूत संरचना के लिए, जो जर्जर भवन हैं, इसकी

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें एमएलए लैड का पैसा नहीं लगता है तो ऐसे में जो पैसा दिया है 200 करोड़ रुपया, यह बहुत कम है, अगर इसे 400 करोड़ रुपया कर दिया जाये तो जितने भी स्कूल्स हैं, सबकी अच्छे से मरम्मत हो जायेगी और इसका सबको फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, जहां तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात है, यह आम आदमी के लिए, गरीब के लिए एक हथियार है। जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, उन्हें 25 लाख रुपये तक का इलाज मिला है। यह बहुत ही अच्छी चीज है। साथ-साथ, जो दुर्घटना बीमा योजना है, इसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। हम जब क्षेत्र में लोगों के पास जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक राजनेता यहां आया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ फल मिलेगा। इस योजना से हमें भी एक मजबूती मिली है। हम जब भी जाकर बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये 10 लाख रुपये आपको मिल सकते हैं, यह तरीका है, तो ऐसे में उनके परिवारों को काफी सम्बल मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। साथ-साथ मेरी भारली ग्राम पंचायत और बिलोनी में भी पीएचसी खोलने की मैं मांग करता हूं। अगर ये दोनों पीएचसी खुल जाती हैं तो मेरे क्षेत्र को चिकित्सा के क्षेत्र में काफी फायदा मिलेगा।

महोदय, सार्वजनिक निर्माण की अगर बात करें तो 10 करोड़ की लागत की आपने हमें सड़कें दी हैं, यह बहुत कम हैं। केवल 5-7 पंचायतों में ही रहकर ये 10 करोड़ रुपये खतम हो जाएंगे। आज चुनाव का टाइम है। कोरोना की वजह से सड़कों का काम बहुत पीछे रहा। पैसा नहीं मिला। एमएलए लैड में जो पैसा था, वह हमें चिकित्सा में देना पड़ गया। मैं ही नहीं, शायद सभी लोग चाहते होंगे कि इसे अगर 20 करोड़ रुपये कर दिया जाये तो जर्जर सड़कों का मैंटेनेंस हो सकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो-तीन चीजें बहुत खतरनाक हैं। हमारे यहां एक नदी जाती है। उसमें हर बरसात के टाइम में या तो ट्रैक्टर, ट्रोली, आदमी या पशु, कोई न कोई दुर्घटना होती है। भाहड़ी से बसेड़ी मार्ग पर भूतेश्वर का मन्दिर है। यह पार्वती नदी पर पुल चाहता है। बसेड़ी पुराना थाना है। उससे बालसर की ओर जाते हैं, वहां भी एक ओवरब्रिज की आवश्यकता है। चकियापुरा गांव के पास पार्वती नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता है। ममोधन से नोनेरा की ओर पार्वती नदी पर पुल निर्माण की भी मैं मांग करता हूं।

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

महोदय, मैं अभी चकियापुरा में बरसात के टाइम की स्थिति देखने गया था। वहां दो दयनीय मौतें हो गयीं। हम जब गये तो लोगों ने स्थिति बतायी। ऐसे में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा आवागमन खतम हो जाता है। ये जो पुल हैं, इन पर निश्चित रूप से विचार करें।

सभापति महोदय, मदनपुर में ईको टूरिज्म को बढ़ाने के हिसाब से मुझे दो करोड़ रुपये की लव-कुश वाटिका दी है। मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं। साथ-साथ एक बात और कहता हूं, रणथम्भौर से बाघों का करौली, सरमथुरा आदि वन्य क्षेत्र में विचरण होने लग गया है। आज स्थिति यह है कि मेरे सरमथुरा क्षेत्र में ही कम से कम पांच टाइगर देखे जा सकते हैं। सरकार की योजना के तहत पूरा सर्वे हो चुका है, सब बात हो चुकी है।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): महोदय, आपके टोकने के बाद थोड़ा गड़बड़ हो गया। अभी तो मैं लाइन पर आया था। सरमथुरा को टाइगर रिजर्व घोषित करें। इससे निश्चित रूप से बाघों को संरक्षित करने के साथ-साथ फायदा मिलेगा। एक क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय खोलने की भी मैं मांग करता हूं।

सर, आप मुझे थोड़ा-सा और टाइम देते तो अच्छा रहता।

श्री सभापति: टाइम निर्धारित है। आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): मैं इसे शोर्ट करता हूं। कानून-व्यवस्था पर जरूर बात करूंगा। कानून-व्यवस्था में मुझे भी सरकार ने आयोग का चेयरमैन बनाया है। मैं 32 जिलों में करीब दो बार घूम चुका हूं। वहां सब जगह बात करने के साथ-साथ और वर्किंग के साथ यह तय हुआ है कि कानून-व्यवस्था में जो सज़ा का प्रतिशत है, वह मात्र 5-7 परसेंट है। नतीजा यह निकलता है कि जो जुर्म करने वाला होता है, वह जुर्म के साथ-साथ चलते हुए फ्री हो जाता है। सज़ा एक ऐसा यंत्र है अगर उसका प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की जाये और वहीं पर जब हमारा एट्रॉसिटी एक्ट होता है तो आईओ को यह जो एफआर लगाने की आदत पड़ी हुई है, इसे मजबूती से ट्रीट किया जाये तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सज़ा प्रतिशत से कानून-व्यवस्था और मजबूत होगी।

महोदय, मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, आंगई में पुलिस चौकी खोली, उसके लिए धन्यवाद। मेरे यहां दो सीमाएं पड़ती हैं। एक तो सरमथुरा, करौली, दूसरी बयाना, बसेड़ी में। दोनों सीमाओं पर हम पुलिस चौकी की मांग करते हैं। महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट के ऊपर अपनी बात रखने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह सरकार का अन्तिम बजट है। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी का भी यह अन्तिम बजट है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को इस तरह का बजट पेश करने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ स्लोगन, सन्देश देने का काम, उन गरीब लोगों के साथ मजाक उड़ाने का काम, सिर्फ हमदर्दी दिखाने का काम सरकार के इन बजटों में देखने को मिलता है।

2019 में कहा कि मेरी सरकार सामाजिक समरसता, कमजोर वर्ग का कल्याण, सुशासन, शान्ति और अहिंसा के पथ पर चलने का काम करेगी। 2020 में कहा, हर आंख का आंसू पोंछ सकूं, यह मेरी मन:स्थिति है। 2021 में कहा, जन कल्याण ही प्रतिबद्धता और जन कल्याण ही प्राथमिकता। 2022 में कहा, आम आदमी के सपनों को साकार करने वाली, सतत विकास की ओर आगे बढ़ने वाली, सभी वर्गों का कल्याण चाहने वाली मेरी सरकार।

सभापति महोदय, वास्तविकता देखें। मैं सिर्फ आलोचना इस आधार पर नहीं कर रहा कि मैं वैचारिक रूप से आपका विरोधी हूं। मैं आलोचना तर्कों के आधार पर कर रहा हूं। आप घोषणाएं कितनी करते हैं और धरातल पर कितनी पहुंचती हैं। 2019 में आपने कहा कि हम गोशालाओं के लिए 145 परसेंट बजट की बढ़ोतरी करेंगे और गोशालाओं को 9 महीनों का अनुदान देंगे। इस बजट में कहा कि हम 12 महीनों का अनुदान गोशालाओं को देंगे। सभापति महोदय, आप ईमानदारी से बता दें, क्या पिछले चार साल से गोशालाओं को 9 महीनों का अनुदान दिया जा रहा है? 6 महीने का भी अनुदान नहीं मिल रहा है। यह सरकार की वास्तविकता है।

फिर बजट की घोषणा में यह कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी सरकार बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस हो चुकी है, बिजली हमारे पास बहुत ज्यादा है। यदि आपके पास बिजली ज्यादा है, पैदावार ज्यादा है, उत्पादन अधिक हो रहा है तो फिर बिजली की कटौती किस आधार पर हो रही है? आज भी सूर्यास्त के बाद बिजली नहीं है। गांवों में तो बिजली कटौती है ही, शहरों में भी सुबह साढ़े 6 बजे से बिजली कटौती शुरू हो जाती है।

आपने कहा था, मेरी सरकार किसानों की हमदर्द है। किसानों को रात में पानी पिलाने में तकलीफ होती है, हम दिन के दो फीडर देने का काम करेंगे। सभापति महोदय, आज भी राजस्थान के किसान रात में बिजली का उपयोग कर रहे हैं, दिन में उन्हें कोई बिजली नहीं दी जाती। इन्होंने इस बात

(श्री रामलाल शर्मा)

के लिए भी अपने बजट में कहा था, इमरजेंसी रेस्पोन्स सपोर्ट सिस्टम लागू करेंगे, जिसमें 112 नम्बर डायल करते ही अल्पावधि में पुलिस की मोबाइल टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सम्बन्धित अस्पताल में पहुंचायेगी। सभापति महोदय, मेरे कहने से आप एक बार टैस्ट तो कर लें, क्या 112 नम्बर डायल करने से कोई एम्बुलेंस आती है? बजट में आपने घोषणा की थी।

बजट में आपने कहा था, राजस्व न्यायालयों में साढ़े 3 लाख मुदकमे पैंडिंग हैं। इनका निस्तारण करने के लिए हम एक ऐसी कमेटी गठित करेंगे, जो अपनी सिफारिशों के आधार पर कानून बनाकर इनमें संशोधन करने का काम करेगी।

सभापति महोदय, मैं आंकड़ों के साथ और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राजस्थान के राजस्व मामलों के निस्तारण करने वाले अधिकारी, चाहे वे किसी भी स्तर के हों, 20 परसेंट ईमानदार हो सकते हैं, 80 परसेंट फैसले कैसे होते हैं, यह आपको भी पता है और मुझे भी पता है। क्यों नहीं राजस्थान की सरकार इन राजस्व प्रकरणों के निस्तारण करने वाले अधिकारियों के फैसलों की समीक्षा करने के लिए एक विजिलेंस टीम गठित करती? इनके फैसलों की जांच कौन कर रहा है? क्या पैसे, प्रलोभन के आधार पर न्यायालयों में फैसले होंगे?

सभापति महोदय, मैं यह प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं। अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मैंने कहा, मेरे यहां सामोद में मंदिर की बेशकीमती जमीन, सार्वजनिक प्याऊ की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम किया। यहां बैठने वाले अधिकारियों ने शायद लिखा होगा। जांच कलेक्टर के पास गई, कलेक्टर ने नीचे एसडीएम से जांच मंगायी पर वास्तविकता क्या है? सभापति महोदय, एडीएम ने पत्रावली रिमांड की, तहसीलदार को कहा कि इसका अवलोकन करें, साक्ष्यों को एग्जामिन करायें और फिर उसका निस्तारण करें। यह एडीएम का निर्णय है। उस पत्रावली के रिमांड के आधार पर सम्भागीय आयुक्त ने निर्देश दे दिये कि अमुक व्यक्ति के नाम सात दिन में नामान्तरण तस्दीक करके अवगत करायें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सम्भागीय आयुक्त के उस आदेश के आधार पर बिना किसी जांच किये, बिना तथ्यों का अवलोकन किये हुए सरकारी जमीन का नामान्तरण व्यक्ति विशेष के नाम खोलकर जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया जा रहा है। सभापति महोदय, यह वास्तविकता है। मैं एक परसेंट भी असत्य वाचन नहीं कर रहा पर सरकार की वास्तविकता यह है।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, दैनिक भास्कर चिल्ला-चिल्ला कर थक गया कि राजस्थान सरकार की आंख खुले और इसके लिए बार-बार लेख लिखता रहा कि राजस्थान के अन्दर आज भी मासूम बच्चों की तस्करी होती है। यह राजस्थान सरकार के ऊपर कलंक है, परन्तु एक कदम भी उठाने का सरकार ने काम नहीं किया। राजस्थान में मासूम बच्चों की तस्करी होती है इसको रोकने का कोई तो उपाय करे, पर एक कदम चलने का काम भी आपने नहीं किया।

सभापति महोदय, बात इतनी ही नहीं है, अगर हम पक्ष-विपक्ष के आधार पर बात करेंगे तो कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। आज इस राजस्थान में दूध का उत्पादन कितना हो रहा है और कंजम्प्शन कितना है? आज 15 तारीख की शादियां बहुत हैं और कल 14 तारीख की रात को किसी दूध की सप्लाई करने वाले व्यक्ति को कहो कि मुझे 5 क्विंटल दूध सुबह चाहिए तो वह यही कहता है कि कहां भेजना है। सभापति महोदय, यह दूध आ कहां से रहा है जब पशुओं का उत्पादन इतना नहीं है? तो फिर मिलावट के दूध के ऊपर हम अथोरिटी बनाएंगे, हम भर्ती करेंगे, हम अंकुश लगाएंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, पर राजस्थान की सरकार ने कितने लोगों को सज़ा देने का काम किया? आज भी राजस्थान के अन्दर बार-बार मुख्य मंत्री कहते हैं कि शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चलेगा पर कितने लोगों को सज़ा दे दी? कितने लोगों को फांसी के ऊपर लटकाने का काम किया? कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया? जो आपने सैम्पल उठाये उनमें कितने सैम्पलों के आधार पर आपने मुकदमे दर्ज करने और चालान पेश करने का काम किया? सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि एक साधारण व्यक्ति दूसरे के थप्पड़ मारता है तो 323, 341 में चालान होता है पर ये अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को मार रहे हैं, जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो इन लोगों को रोकने का काम कौन करेगा? पर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। फूड डिपार्टमेंट कहता है कि मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट कार्यवाही करेगा, मेडिकल एण्ड हैल्थ कहता है कि फूड डिपार्टमेंट कार्यवाही करेगा पर सभापति महोदय, इस क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। राजस्थान पत्रिका, गुलाब कोठारी जी की कलम लिखते-लिखते आंटण पड़ गया, गुलाब कोठारी का बोलते-बोलते गला थक गया कि हर व्यक्ति को हवा, पानी, रोशनी का अधिकार है पर बेशकीमती जमीनों को डकारने के अलावा जेडीए ने कुछ भी

(श्री रामलाल शर्मा)

नहीं किया। बेशकीमती सारी जमीनें जो जेडीए की पैरीफेरी में थीं, ग्राम पंचायतों की सारी जमीन जेडीए के पास है और आज ग्राम पंचायतें जमीन के लिए तरस रही हैं। आपने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत कर दिया पर कहां खुलेगा आंगनबाड़ी केन्द्र? आपने पीएचसी स्वीकृत कर दी पर कहां खुलेगी पीएचसी? आपने 33 केवी का जीएसएस खोल दिया पर कहां लगेगा 33 केवी का जीएसएस? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी जहां जेडीए की पैरीफेरी के अन्दर जमीन नहीं है और उस जमीन को बेचकर करोड़ों रुपये डकारने का काम जेडीए कर रहा है। क्यों नहीं आम आदमी की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए उन ग्राम पंचायतों को वह जमीन वापस लौटाने का काम करें या उन जमीनों को रिजर्व करें कि आने वाले समय में आबादी का विस्तार करने के लिए या आबादी विस्तार के आधार पर फैसेलिटी के लिए जमीन छोड़ने के लिए हम काम करेंगे। आज इन ग्राम पंचायतों में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे और उन ग्राम पंचायतों के विकास की ओर ध्यान दे।

सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन और करना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान का अन्दर सरकारी तंत्र इतना मजबूत नहीं है जिसके आधार पर आपातकालीन सेवाओं की मदद ली जा सके। कोविड के दौरान कहां थी सुविधा सरकारी हास्पिटलों के अन्दर? आपकी पीएचसी ने एक भी कोविड के मरीज का इलाज किया हो तो बताओ, आपकी सीएचसी ने एक भी कोविड के मरीज का इलाज किया हो तो बताओ। आपकी पीएचसी, सीएचसी और यहां तक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के अन्दर भी अगर आक्सीजन प्लांट लगे हुए हों तो आप बताओ, आक्सीजन की सप्लाई आपकी हुई हो तो बताओ। इलाज प्राइवेट हास्पिटल ने किया है। सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि प्राइवेट हास्पिटल्स की नाजायज मांगों को मानने का आप काम करो, लेकिन कम से कम उनके साथ में बैठकर जो जायज चीज है, जो जनता के हित की चीज है, सरकार की मन्शा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए है, जनता को सुविधाएं पहुंचाने के लिए है तो आप उनके साथ बैठकर इस गतिरोध को दूर करने का काम करें। चार दिन से चिरंजीवी योजना के अन्दर भी गरीब व्यक्ति का इलाज नहीं हो रहा है, इसलिए कृपा करके सरकार इस ओर भी कदम बढ़ाने का काम करे।

सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बजट में विद्या सम्बल योजना की घोषणा की थी। इस विद्या सम्बल योजना में कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार देने का काम किया? एक भी व्यक्ति को

(श्री रामलाल शर्मा)

विद्या सम्बल योजना में अगर रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया हो तो आप बता दें। सरकार कहती है कि हमने 2019 के अन्दर भर्ती की। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की आपने भर्ती की और कहा कि विभागों में इतने पद रिक्त हैं जिनको भरने का काम हम करेंगे। फोरेस्ट में भरेंगे, पुलिस में भरेंगे, मेडिकल के क्षेत्र में भरेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में भरेंगे पर आज भी 2019 की वे भर्तियां लम्बित हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। कोविड के अन्दर जिस तरीके से सीएचए ने अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किया वे 28 हजार सीएचए आज भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए टंकी पर चढ़े हुए हैं। वे सरकार से बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिये पर उसमें भी एक कदम चलने का काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय, सरकार ने कहा था कि हम संविदाकर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे। कितने संविदाकर्मियों को आपने नियमित कर दिया? आपने अभी इस बजट में घोषणा की है कि हम उनको सेवा का पूरा लाभ देने का काम करेंगे पर चार साल काम करने के बाद एक साल का लाभ देने की आप बात कर रहे हो। सभापति महोदय, जिस उम्र के अन्दर वे नौकरी लगे थे तब उनकी शादी नहीं हुई थी पर आज शादी होने के उपरांत उनके बच्चे शादी के लायक हो गये इसलिए अब तो कम से कम उनको नियमित करने का काम करो। ज्यादा सर्विस उनकी बची नहीं, दस-पन्द्रह साल की सर्विस बची है तो कृपा करके संविदाकर्मियों के ऊपर भी आप संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इनकी समस्या का भी समाधान करें।

सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर आपने पिछले बजट के अन्दर घोषणा की थी कि हम थानों के अन्दर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करेंगे, हम पुलिस थानों के अन्दर स्वागत कक्ष बनाने का काम करेंगे। सरकार बता दे कि उसने अपने कोटे से कितने पैसा देने का काम किया? या तो विधायक कोष से पैसा दिया या सांसद कोष से पैसा दिया या फिर किसी एसएचओ ने सीएसआर से अपनी लाइजनिंग से पैसा मंगाया। आज भी राजस्थान के अन्दर जितने भी स्वागत कक्ष बने हैं उनमें सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हुआ। इसलिए अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो कृपा करके घोषणा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, इस बजट में घोषणा की गई कि तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी को टैबलेट देने

(श्री रामलाल शर्मा)

का काम करेंगे, तो फिर आपने बीडीओ को क्या टाला? विकास अधिकारी ने आपका क्या बिगाड़ा? जब आप सबको क्रम से दे रहे हैं और वे भी सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम करते हैं तो मैं चाहूंगा कि बीडीओ की इस तरह से उपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और इस विषय में भी सरकार ध्यान दे।

सभापति महोदय, राजस्थान में हो क्या रहा है? मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि राजस्थान में परिवहन विभाग द्वारा किस तरीके से सरकार के विधायकों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सूची के आधार पर ट्रकों को पास किया जा रहा है। इनके विधायक और इनके कार्यकर्ता डीटीओ, आरटीओ को सूची देते हैं कि यह सूची है, इन ट्रकों को कोई रोकने का काम नहीं करेगा। आज भी नागौर, झुन्झुनूं, सीकर के अन्दर एक लम्बी श्रृंखला बनी हुई है और जो सूची इनके नेताओं द्वारा दी जाती है उन ट्रकों को कोई नहीं रोकता। सभापति महोदय, यह राजस्थान के कोष का सीधा-सीधा नुकसान है और मैं चाहूंगा कि इस तरह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार इनके ऊपर अंकुश लगाने का काम करे।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर आज भी पशुपालन के आधार पर लोग अपनी आजीविका चलाने का काम करते हैं। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भी यह बात कही थी और गंगानगर से आने वाले माननीय विधायक भी बैठे हुए हैं और ये मेरी बात से सहमत भी होंगे कि राजस्थान के चारे के ऊपर ही पशुपालक निर्भर नहीं है और पंजाब से जब तक चारा राजस्थान में नहीं आता तब तक पशुपालक अपनी आजीविका को नहीं चला सकते। इस चारे के मामले में भी जितनी अनियमितताएं हो रही हैं उन पर सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए ताकि उनके ऊपर भी अंकुश लग सके।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, एक अन्तिम निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिनका जिक्र भी मैं आपके सामने करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर जयपुर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 1984 में अवाप्त की हुई जमीन आज भी पैंडिंग पड़ी हुई है। किसानों के साथ विवाद है तो टेबल पर उनको बिठाइये और 15 परसेंट मुआवजा देना है, 25 परसेंट मुआवजा देना है वह सरकार जो भी तय करे, लेकिन कम से कम हाउसिंग बोर्ड की वह योजना धरातल पर आये ताकि आम आदमी को राहत मिल सके।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर एक अरबन पी.एच.सी. स्वीकृत हुई थी पर आज 5 साल बीत जाने के बाद भी वह अरबन पी.एच.सी. धरातल पर नहीं आयी है। सभापति महोदय, इसी तरीके से आज भी राजस्थान के अन्दर पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्य बार-बार अपनी मांग उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अन्दर उनको मानदेय दिया जाता है। मैं चाहता हूं राजस्थान के अन्दर भी पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद् के सदस्यों के लिए मानदेय की घोषणा करें और कम से कम उनको राहत पहुंचाने का काम करें।

श्री सभापति: थैंक यू। माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मेरा अन्तिम निवेदन इतना ही है कि आंगनबाड़ी के 5 हजार से 20 हजार कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लगातार हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके ऊपर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करें।

सभापति महोदय, मेरा एक अन्तिम निवेदन जरूर है, वैसे तो बहुत सी घोषणाएं अधूरी हैं। इनके मंत्री महोदय बड़बोले जरूर हैं।

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हैं, अब खाद्य मंत्री हैं। किसनारामजी, एक मिनट। राशन डीलरों की मांगों को लेकर उनके धरने पर गये और कहा कि मैं आपकी वाजिब मांगों को विधान सभा के बजट के अन्दर पारित कराने का काम करूंगा। मंत्री धरने पर चले जाएं फिर भी राशन डीलरों की मांग पूरी नहीं करें तो मुझे लगता है कि आमजन भी विश्वास खो चुका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राशन डीलरों की जायज मांगों को पूरा करने का काम करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने 10 तारीख को शानदार बजट पेश किया है। यह लगातार पांचवां बजट, सभी बजट एक के बाद एक बहुत ही जनकल्याणकारी बजट साबित हुए। प्रदेश की जनता को मालूम है कि जुमलों के साथ दूसरी बार देश में सरकार बनी। जिस सरकार ने बड़े-बड़े वादे किये, बेरोजगारी मिटाने

(श्री किसनाराम विश्नोई)

का वादा, महंगाई कम करने का वादा, वे उसमें खरे उतर नहीं पाये। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने कोरोना होने के बावजूद भी एक के बाद एक शानदार बजट, तीसरा बजट, चौथा बजट और पांचवां बजट पेश किया है। जिस ढंग से कुशल वित्तीय प्रबन्धन के साथ प्रदेश की जनता को राहत दी है, प्रदेश में बसने वाले गरीबों को राहत दी है, जो 10 तारीख को बजट आया है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट की चाहे रेल हो, बस हो, थड़ियां हों, गांव, ढाणी की चौपाल हो, सब जगह इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है, क्योंकि पिछले बजट की 80-85 प्रतिशत घोषणाएं कियान्विति हुई हैं। सभी जगह बजट धरातल पर आया है, जगह-जगह विकास के काम चल रहे हैं। सबको मालूम है, हमारे विपक्ष के साथियों के क्षेत्र में काम हो रहे हैं।

पूरे देश के अन्दर कमर तोड़ महंगाई, जब ये लोग सत्ता में आये थे तब 57 रुपये प्रति लीटर डीजल था, आज 93 रुपये है। महंगाई को कंट्रोल करने का जो काम किया है वह राजस्थान की सरकार ने किया है। चाहे एक करोड़ लोगों को नि:शुल्क राशन देने की बात हो और उसके साथ ही इस बजट में फूड पैकेट देने की बात कही है। गरीब आदमी को महंगाई की मार से बचाने के लिए काम किया है।

इन लोगों ने मनरेगा में कटौती करने की बात कही। हर साल कटौती की जा रही है। एक कानूनी योजना मनमोहन सिंह जी देश में लाये थे गरीबों को रोजगार देने के लिए, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, इससे इनकी बड़ी भारी दुश्मनी हो चुकी है। उस योजना में ये लोग हर साल कटौती कर रहे हैं। इस बार भी इन्होंने 30 परसेंट कटौती की है। मुख्य मंत्री जी ने 24 दिन और बढ़ाये हैं। शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू की है।

इसके साथ-साथ मुख्य मंत्री जी ने 500 रुपये में गैस सिलेण्डर देने की घोषणा की है, जिससे हर गरीब परिवार को, हर मध्यम परिवार को राहत मिलेगी। डीजल पर वैट कम करने की बात की है। युवाओं को छूट दी है। युवाओं को पहले भत्ता दिया जा रहा था, अब कोचिंग के लिए नि:शुल्क यात्रा की छूट दी गई है।

इसके साथ ही साथ किसान जो बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे, किसानों ने चार महीने आंदोलन किया, उसके बावजूद भी उनको निराश होकर दिल्ली से वापस लौटना पड़ा, सैकड़ों किसान मारे गये। किसानों की सुनी नहीं

(श्री किसनाराम विश्नोई)

गई। अशोक गहलोतजी ने बिजली की दो हजार यूनिट माफ करके किसानों को ऐतिहासिक राहत दी है। इससे 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूं, एक खेतिहर परिवार से आता हूं। इस राहत को कोई नहीं समझ सकता है, इस राहत को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जहां इतना बिल आ रहा है। आज हमारे मारवाड़ क्षेत्र में पानी गहरा है और पूर्वी राजस्थान में तो यह समझ लें कि पूरा का पूरा ही बिल माफ है, क्योंकि पानी ऊंचा है। इसलिए किसानों को यह राहत दी गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

पिछला दूसरा बजट, तीसरा बजट, चौथा बजट जमीन पर उतरा है। जिसका परिणाम यह हुआ कि हम एक को छोड़कर सभी उप-चुनाव जीते हैं। हम उप-चुनाव इसीलिए जीते हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किये हैं। यह उसका प्रतिफल है। जिस तरह से मुख्य मंत्री जी ने कहा, यह बजट 2028 का बजट है। 2023 का बजट तो है ही, 2028 का बजट भी है। इस बजट के हिसाब से सामने वाले साथी 2023 में और कम होने जा रहे हैं। इसलिए महंगाई की मार को कम करने के लिए ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

साथ ही साथ जो चिरंजीवी योजना है, माननीय सभापति महोदय, जिसके घर में बीमारी आती है, उसको मालूम पड़ता है कि यह क्या योजना है। आज 10 बजे मेरे पास भाजपा के एक कार्यकर्ता का फोन आया कि, साहब, मेरे घर में मरीज है और मैं तीन दिन से उसके पास बैठा हूं, पैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है और दनादन इलाज हो रहा है। मैं बड़ा हतप्रभ रह गया। इसका रिजल्ट, जिसके घर में बीमारी होती है उसको मालूम है चिरंजीवी योजना क्या है।

हमारे एसएमएस हास्पिटल में हरियाणा से लोग इलाज कराने आते हैं। हमारे जालौर, बाड़मेर में बोर्डर पर गुजरात से लोग इलाज कराने आते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित हो रही है। आम-जनता, आम अवाम इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस योजना के लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के पूरे 33 जिलों में मेडिकल कालेज खोलने की बात की। हमारे जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

आज युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बहुत चल पड़ी है, उसे रोकने के लिए मुख्य मंत्री जी ने जिला स्तर पर नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की बात की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

नि:शुल्क बिजली आम अवाम के लिए, आम उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के लिए, छात्राओं को रात में पढ़ाई करने पर अधिक बिजली खर्च होती है, उसको लेकर पिछले बजट में 50 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की और इस बजट में 100 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है। यह मान लें, ग्रामीण क्षेत्र के साधारण उपभोक्ता के लिए फ्री है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।

साथ ही साथ, मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार भी पूरे प्रदेश के अन्दर सड़कों का जाल बिछाया था, सभी जिलों मे स्टेट हाईवे दिये थे और पूरे प्रदेश में 257 राजस्व ग्राम में मुख्यमंत्री सड़क योजना की घोषण की थी। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस बार भी मुख्य मंत्री जी ने 10 तारीख को साढ़े तीन हजार से अधिक आबादी के राजस्व ग्राम और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मारवाड़ क्षेत्र में मरुस्थल क्षेत्र में 250 तक की आबादी को सड़क से जोड़ने की घोषणा की है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मारवाड़ में हम धरती धोरां री से आते हैं, छितराई ढाणियों का इलाका है, गांवों का सुदूर इलाका है, वहां भी लोगों को डामर की सड़क सुलभ होगी। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।

आम अवाम, मानव जीवन के इलाज के लिए चिरंजीवी योजना चल रही है। दूसरी लम्पी नामक महामारी आई। लोगों की दुधारू गायें अधिक संख्या में मारी गईं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए भी घोषणा की है कि जिस भी किसान की, जिस भी पशुपालक की दुधारू गाय मर गई, उसे 40 हजार रुपये दिये जायेंगे। उसके साथ ही साथ मुख्य मंत्री जी ने कामधेनु बीमा योजना भी शुरू की है, 40 हजार रुपये का बीमा करने की घोषणा की है। इसके लिए भी हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।

एक ऐतिहासिक घोषणा सामाजिक सुरक्षा की है। पशुपालक के लिए, किसान के लिए सामाजिक सुरक्षा में 500 रुपये से 1000 रुपये पेंशन बढ़ाई है। मनरेगा में रोजगार देने की बात की है।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, ओपीएस की बात हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की बात हो। आठ हजार आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की बात हो। साथ ही साथ, गरीब के बच्चे का अंग्रेजी पढ़ने का सपना होता है, वह सपना पूरा करने के लिए भी मुख्य मंत्री जी लगातार घोषणा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मारवाड़, जोधपुर जिले से आता हूं। हमारा जो फलौदी कस्बा है, उसको भी जिला बनाने की लम्बे समय से मांग की जा रही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र लोहावट, जो पहले फलौदी के साथ हुआ करता था। अब अलग विधान सभा क्षेत्र है। पहले लोहावट विधान सभा क्षेत्र के किसी भी जन प्रतिनिधि ने उसको जिला बनाने के लिए आज तक सहमति नहीं दी। हमने इस बार मुख्य मंत्री जी से लिखकर भी दिया है कि फलौदी को जिला बनाया जाये। आज फलौदी क्षेत्र सोलर के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर है, सोलर हब बना हुआ है। आज नमक क्षेत्र में हर जीभ के स्वाद पर फलौदी का नमक है इसलिए फलौदी को जिला बनाना भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही जरूरी है और इसी के साथ-साथ मैं मेरे क्षेत्र के विकास कार्य जो बहुत सारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किये और साथ ही साथ कई कामों की सूची आपकी आज्ञा से टेबल करता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में आप पूरा कर दीजिये। In one minute only. Please.

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): इसके साथ-साथ एक आखिरी मांग मैं करूंगा, माननीय सभापति जी। चूंकि एक पंचायत समिति के मैम्बर से विधायक बनकर इस हाउस में आने का मेरे को जनता ने, मेरी पार्टी ने मौका दिया है इसलिये चूंकि मैं पंचायत समिति सदस्य से विधायक बना हूं तो मैं जिला परिषद् के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्यों की भी पैरवी कर रहा हूं। उनको मासिक मानदेय दिया जाये और बैठक भत्ता दिया जाये। उनका भी मान-सम्मान बढ़े क्योंकि वो सीधा जनता से चुन कर आते हैं।

सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के लोक कल्याणकारी कार्यों की जो योजना है, विकास के कार्यों की जो सूची है आपकी आज्ञा से मैं टेबल कर रहा हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सम्माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बजट की इस सरकार के द्वारा मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की उसके लिए मैं तो आपसे यह कहता हूं कि राजस्थान पेपर लीक के लिए तो बदनाम था ही अब बजट भी लीक हो गया। मुख्य मंत्री जी को सात मिनट तक पता ही नहीं चला कौन-सा बजट वो बोल रहे हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आप ही के सरकार के विधायकों के लिए बोलता हूं कि हाई कोर्ट में कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार के मात्र 6 विधायकों ने अपनी इच्छा से इस्तीफे दिये हैं, यानी बाकी 85 विधायक भय, भूख और भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। इन विधायकों ने बजट की पवित्रता और जनता के हित को खतरे में डाल दिया है। अब बजट पारित भी हो जायेगा तो जनता को हमेशा यह शंका बनी रहेगी कि उनके विधायकों ने पैसे, प्रलोभन से या किस कारण से इस बजट को पारित करवाया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये बजट पर भाषण हो रहा है?

श्री सभापति: बजट पर ही बोलिये आप।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं वो ही बोल रहा हूं। इनके पीड़ा क्यों हो रही है? आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये। बैठिये। मैं बोल रहा हूं आप बैठिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): ये कौन होते हैं मेरे बीच में बोलने वाले?

श्री सभापति: बैठिये। आप बैठो तो सही।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बोलिये न। किस बारे में भाषण हो रहा है? ...(व्यवधान)...

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): आप जवाब दे देना, जब आपका नम्बर आये तब बोल देना। आप बोल रहे थे तब हमने कुछ बोला क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनिये आप। बजट भाषण 10 फरवरी, 2023 पर वाद-विवाद चल रहा है, kindly keep adherence to the subject which is for your consideration; which is for discussion today. Thank you!

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, सत्ता पक्ष को दु:ख हो रहा है मगर इस बजट में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक भी अब पल्ला झाड़ने में उतर गये हैं। अभी हमारे बलजीत सिंह जी यादव साहब ने इनकी सारी पोल खोली है, वो नहीं सुना। सारे विधायक इनके 6 महीने के विकास के लिए उनके समर्थन में हैं। आज सभापति महोदय, अगर गुप्त मतदान करवा दें तो ये सरकार आज गिर जाये क्योंकि निर्दलीय +++ सब दुःखी हैं।

श्री सभापति: आप बजट पर आइये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं आगे नहीं बोलूंगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार यह कहती है कि हम युवाओं का ध्यान रखेंगे। युवाओं का क्या ध्यान रखेंगे? इनके ही विधायक पूर्व उप मुख्य मंत्री +++ सचिन जी पायलट को उन्होंने उप मुख्य मंत्री से तो हटाया, अध्यक्ष से भी हटा दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो दिया उस पर वाद-विवाद चल रहा है। आप अपने पक्ष में अपनी तरफ से जो कुछ कहना चाहते हैं, kindly come to the point. नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, अब इनको इतना बुरा लग रहा है। मैं मैन पाइंट पर आ जाता हूं। सभापति महोदय, इनको तकलीफ हो रही है। (व्यवधान) इनका चार साल का काला चिट्ठा मैं खोल कर बताता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, सचिन पायलट सदन के माननीय सदस्य हैं उनको +++ कैसे कहा? आप एक्सपंज करिये इसको। +++ कैसे कहा उनको? सदन के माननीय सदस्य को +++ कैसे कहा? सवाल यह है।

श्री सभापति: डिलीट कर दीजिये। आप बोलिये। प्लीज।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनिये प्लीज। माननीय सदस्य, आपका समय दस मिनट का निर्धारित था।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): इन्होंने मेरा समय खराब किया है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: सुनिये आप। 2.41 बजे आपने बोलना शुरू किया, 2 बज कर 45 मिनट और 48 सैकंड हो गयी है, आपका 2.51 बजे भाषण समाप्त हो जायेगा। कृपया बोलिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र ट्राइबल एरिया है। टोटल ही जनजाति एरिया में ट्राइबल बसता है, उसके अन्दर स्कूलों की बात करूंगा। पोपल्टी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अन्दर 350 बालक हैं और केवल 5 कमरे हैं। 4 साल के अन्दर एक कमरे की भी व्यवस्था नहीं करवायी।

सभापति महोदय, बछार ग्राम पंचायत के अन्दर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। आठ कमरे हैं, जिनमें 5 कमरे जर्जर हैं और उसमें 600 बालकों की वहां पर एडमिशन की संख्या है। सभापति महोदय, दार पंचायत के अन्दर उच्च माध्यमिक विद्यालय, दार 9 कमरे हैं, 7 कमरे जर्जर हैं। हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक जी ने भी बहुत कुछ लिखकर दिया मगर एक भी कमरा उनको ठीक करके नहीं दिया।

सभापति महोदय, देवाली ग्राम पंचायत में 12वीं तक स्कूल हैं और चार कमरे हैं। अब मैं आपको क्या कहूं? बड़ी ऊंदरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 769 बच्चे हैं जिनमें 398 बालिका हैं, 367 बालक हैं और केवल 4 बालक अन्य हैं। ट्राइबल एरिया के अन्दर यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है और वर्षो से इनको वोट दिया है। चणमोरा ग्राम पंचायत में देवीमाता प्राथमिक विद्यालय है, दो कमरे हैं और उनमें पांचवीं तक स्कूल चल रही है। एक भी कमरा सही नहीं है, वह भी जर्जर है।

सभापति महोदय, चांसदा मानपुरा स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, चार कमरे हैं और वहां पर और जमीन भी नहीं है। एक कमरा भी बनाये तो कहां बनाये। छोटी ऊंदरी के अन्दर प्राथमिक विद्यालय का जो घूगली घाटी के अन्दर 300 बालक हैं और तीन कमरे हैं और वो भी जर्जर हैं।

सभापति महोदय, बड़ी पंचायत में हमारे 184 बालक दो कमरों में अध्ययन कर रहे हैं, एक भी अन्य दूसरा कमरा नहीं है। हमारी पंचायत के लोगबाग़ उनको कहां पढ़ायें, क्या करें? हमारे ट्राइबल के मंत्री भी आते हैं मगर वो भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत पोपल्टी के अन्दर राजस्व गांव आड़ के अन्दर दो स्कूलें चलती हैं और 6 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर आठवीं से आगे पढ़ने के लिए कहां जायें। वहां पर छठी के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते 6 किलोमीटर तक। बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं।

(श्री फूल सिंह मीणा)

छोटे बच्चे हैं, 6 किलोमीटर जाकर कैसे वो पढ़ाई करेंगे और उसकी दूरी अलसीगढ़, कालीवास और पोपल्टी बराबर है। इस स्कूल के अन्दर वास्तव में 23 बालकों ने पांचवीं पास की और बीस बालकों ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि इतनी दूरी मेन्टेन हो नहीं रही है।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायत पोपल्टी के अन्दर जो वास्तव में यह हमारी पढ़ाई प्रभावित है इसके लिए हमारी स्कूल को क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, चांसदा पीएचसी है उसके अन्दर जो वास्तव में पहले पीपीपी मोड पर दे रखी थी और उसका समय 2022 में खतम हो गया मगर अभी भी वह कब्जा कर रखा था। गांववासियों ने ताला लगाया और सरकार से कलेक्टर साहब के पास में धरना देकर बोला और उन्होंने अब जनता के हवाले किया। सभापति महोदय, यही नहीं यह सरकार क्या करना चाहती है, मुझे पता नहीं है।

श्री सभापति: प्लीज, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, अतिवृष्टि में हमारी रोडें टूट गईं थीं, उनका भी अभी तक कोई धणी धोरी नहीं है। अभी तक एक रोड और पुलिया ठीक नहीं हुई है। सभापति महोदय, ओलावृष्टि की भी अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है।

सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में नेटवर्क की बड़ी भारी समस्या है। ट्राइबल एरिये में राशन की भी भारी दिक्कत है। हमारी धार, कुंडाल, सुरुपाल, झाबला, सरुर, चांसदा, झामरकोटड़ा, खजूरी, खरपीणा, पोपल्टी, अलसीगढ़, पाई, पीपलवास, चणगौरा, बछार पंचायतों में बिलकुल नेटवर्क नहीं है, राशन लेने में तीन-तीन दिन लग जाते हैं। सभापति महोदय, मैं मेरी विधान सभा नहीं पूरे संभाग की बात कर रहा हूं। टीएसपी क्षेत्र में 2020-21 गणित और विज्ञान विषय की डीपीसी पर स्टे ले लिया था। वह स्टे भी खुल गया था, लेकिन आज दिन तक न तो बच्चों की भर्ती हुई है और न उन्हें काउंसलिंग का मौका दिया है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आज हमारे ट्राइबल के बालक-बालिकाएं वहां पढ़ने से वंचित हैं। जब गणित और विज्ञान के अध्यापक ही नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे, कैसे उनको अध्ययन करवायेंगे?

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ। थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि हमारे ट्राइबल का ध्यान रखते हुए हमारे स्कूलों को तो कम से कम सही करवा दें और अध्यापक दे दें। धन्यवाद।

श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत आभार, आपने मुझे बजट 2023-24 के उपलक्ष्य में बोलने का मौका दिया। मेरे हाथ में बजट की कापी है। यह 170 पेज का बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 10 फरवरी को पेश किया। इसको बहुत गहनता से पढ़ा जाये तो राजस्थान के दूर-दराज ढाणी में बैठे व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, इस तरीके से इस बजट को पेश किया गया, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं।

मैं एक दिन जन सुनवाई में बैठी थी, वहां विधान सभा क्षेत्र से काफी लोग भी बैठे थे। एक पीड़ित व्यक्ति मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में आकर कहता है कि सादुलपुर से चलकर बीकानेर जब इलाज के लिए जाता हूं तो ट्रेन का किराया जरूर देना पड़ता है, पर बीकानेर में जाकर इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के माध्यम से फ्री हो जाता है। जब पेशेंट के साथ 2-3 फैमिली मैम्बर जाते थे, वहां खाने-पीने का भी खर्चा होता था, उसके लिए भी एक बहुत रोचक बात उस व्यक्ति द्वारा कही गई कि अस्पताल में इलाज कराने जाता हूं और प्रति व्यक्ति 8 रुपये में इंदिरा रसोई में खाना खाता हूं, तो पांच व्यक्ति भी हैं तो 40 रुपये में हम पांच व्यक्ति भर पेट खाना खा लेते हैं। इन दो चीजों को जोड़ कर मैं देखती हूं तो एक गांव से, ढाणी से मजदूर व्यक्ति जब चलकर जाता है तो वह सोचता था किराया कहां से लाऊंगा, मरीज को दिखाऊंगा तो दवाई के पैसे कहां से लाऊंगा। यह सारी चीजें जो समाहित की हैं और जो लाभ दिया है और उसमें भी 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा और दुर्घटना बीमा 5 लाख से 10 लाख करने की घोषणा की। मैं इसके पक्ष में अपना समर्थन देती हूं और मुझे खुशी है प्रदेशवासी इसके बारे में चर्चा भी करने लगे हैं कि बहुत शानदार बजट आया है।

इसी उपलक्ष्य में मैं एक और बात आपसे कहना चाहती हूं। मैं राजस्थान के उस जिले से आती हूं और मेरी कांस्टीट्यूएंसी हरियाणा बोर्डर पर है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मुझ से एक बार चर्चा की कि, कृष्णा, आपके विधान सभा क्षेत्र में इस योजना का लाभ कैसे लिया जा रहा है क्योंकि

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

बहुत सालों से लोगों की आदत हिसार जाने की थी। जब भी कोई विपदा आती है तो कोई भी पेशेंट या उसका परिवार नजदीकी जगह ढूंढता है। सभापति महोदय, आधे व्यक्ति इसका लाभ उठा पा रहे थे, आधे नहीं उठा पा रहे थे। मैंने जब इस बारे में जिक्र किया तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि, यहां से चूरू कितनी दूर पड़ता है या सरदारशहर कितनी दूर पड़ता है? दूरी को देखते हुए उन्होंने इस समस्या को समझा और हमारी सीएचसी को उप जिला अस्पताल करने की घोषणा की है, मैं इसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

साथ ही महंगाई की वजह से गृहिणियों का जो बजट गड़बड़ा गया था, बड़ी मुश्किलें थीं, मैं यहां सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि 2013-14 में स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर घूमा करती थीं, अब वह भूल गई हैं। मैं माननीय सदन से कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आगामी वर्ष से 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। मेरे को लगता है कि स्मृति ईरानी जी के भी यहां से भरकर चला जाये तो उन्हें याद आ जायेगा कि वह जो महंगाई पर बात करती थीं, आजकल भूल कैसे गईं।

साथ ही फिर वही बात कहना चाहूंगी, मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा बोर्डर पर होने के नाते बिजली की भी काफी समस्या हमें थी। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 100 यूनिट बिजली ग्राहक को फ्री करने की बात कही है और 2000 यूनिट बिजली कृषि के लिए फ्री करने की बात कही है। मुझे लगता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों को या घरेलू ग्राहकों को शायद बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समस्या का निस्तारण करते हुए उन्होंने सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में 220 केवी के ग्रिड सब स्टेशन की घोषणा की है। सभापति महोदय, आपको ध्यान है कि आपके मंड्रेला से हमें बिजली आपूर्ति होती थी, इससे आप भी अच्छी तरह से अवगत हैं। इतनी बड़ी सौगात देने के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं।

अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, छोटे-छोटे गांवों से निकलकर कोई भी स्टूडेंट बड़े शहर में जाता था कि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और विशेष तौर से वाचनालय के लिए मैं यह बात कहना चाहती हूं। ब्लाक स्तर पर 'सावित्री बाई फुले वाचनालय' खोलने की जो बात कही गई है। एक उच्चतम स्तर का वाचनालय अगर ब्लाक स्तर पर हमारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है तो उन्हें अपने घर को छोड़कर दूर-दराज नहीं जाना होगा।

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

साथ ही खेलों की बात की जाये, चूंकि यह युवाओं को प्रेरित बजट रहा। मैं बड़ी खुशी से बताना चाहूंगी कि आउट आफ टर्न पालिसी, हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो और खिलाड़ी को कब इंजरी आ जाये और उसका खेल कब रुक जाये, उसे कुछ नहीं पता होता है। लेकिन आउट आफ टर्न पालिसी ऐसी पालिसी है जिसने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखा और इसमें 229 खिलाड़ियों को हम अभी तक नियुक्ति दे चुके हैं। बजट में इसमें और अच्छी बात माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई कि भविष्य में जितने भी पदक विजेता खिलाड़ी होंगे उनकी भर्ती हम स्पोर्ट्स विभाग में करेंगे। एक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी अगर स्पोर्ट से जुड़ेगा तो भविष्य में हमें कोचेज की कमी नहीं रहेगी। साथ ही विभाग में 100 कोचों की भर्ती के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है ताकि उच्चतम स्तर की ट्रेनिंग हम हमारे खिलाड़ियों को दे सकें।

साथ ही, राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक और आने वाले वर्ष में हम शहरी ओलम्पिक भी कराने जा रहे हैं। जब हमारे राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक हुए तो हर वर्ग ने इसकी सराहना की थी। हर वर्ग इससे जुड़ा था और राजस्थान में एक उत्सव का माहौल था। उसी से प्रेरित होकर और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हमारे राजस्थान में पार्टिसिपेट करें, 150 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय सदन की तरफ से, सभी सदस्यों की तरफ से ज्यादा स्टेडियम की मांग आती है। 'मेजर ध्यानचंद योजना' के अंतर्गत मैचिंग ग्रांट 25 लाख थी, जिसको बढ़ाकर एक करोड़ किया गया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूं। इससे हम उत्तम कोटि के स्टेडियम तैयार कर पायेंगे, इसके लिए भी बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय, इसी बीच मैं यह कहना चाहती हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की काफी समस्या है और विशेष तौर से सिद्धमुख क्षेत्र में। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी सिद्धमुख तहसील में ग्राउंड वाटर भी नहीं है और हमारे सप्लाई वाटर भी नहीं है, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

(समय: 15.00 बजे)

सिद्धमुख कैनाल के ऊपर भी मैं जरूर बोलना चाहूंगी। सिद्धमुख माइनर जो कि

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

सिद्धमुख तहसील के अन्दर आती है, लम्बे समय से किसानों के लिए बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। सिद्धमुख कैनाल का इनोग्रेशन किया गया था तो मुख्य धारा में सिद्धमुख तहसील को रखा गया था और आज तक उसे सिंचाई से नहीं जोड़ा गया है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि उसके ऊपर भी 100 करोड़ का बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय दें और साथ में ही इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का ए.ईएन. आफिस वहां खोलें, जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र से चूरू की दूरी लगभग 65 किलोमीटर की है और हमारे पास पीजी कालेज नहीं है, हमारे विधान सभा क्षेत्र में आज चार-चार डिग्री कालेज हैं, इसलिए पीजी कालेज के लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें, प्लीज।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): सर, बिलकुल दो मिनट में कर दूंगी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कृषि के लिए इतना बड़ा प्रावधान रखा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कड़वे जल के कारण हम खेती नहीं कर पा रहे थे। किसानों ने झींगा मछली फार्म का एक और व्यवसाय शुरू किया है। मुझे खुशी है कि हमारे चूरू क्षेत्र के अन्दर जो पानी है, विशेष तौर पर सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में है, वहां की जमीन का पानी झींगा मछली फार्म के लिए बहुत उत्तम है और वहां से बहुत अच्छी खेती झींगा मछली फार्म से की जा रही है। किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वह बिजली की है। मैं मांग रखती हूं कि बिजली की व्यवस्था भी उसी के हिसाब से की जानी है क्योंकि ये फार्मिंग किसान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब रिप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे।

चांदगोठी में मैं सीएचसी की मांग करती हूं। बेवड़, नेसल बड़े गांव हैं और काफी दूरी के कारण इनकी लम्बे समय से पीएचसी की मांग रही है, मैं इनके लिए भी जरूर मांग करना चाहूंगी। साथ ही, सिद्धमुख-राजगढ़-भादरा की जो सड़क है, उसके लिए भी मैं अवगत कराना चाहूंगी कि बहुत ही क्षतिग्रस्त सड़क है और उम्मीद करती हूं कि हमें वह रिप्लाई में जरूर मिले। आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। पिछली 10 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान सरकार का पांचवां और आखिरी बजट पेश किया है। बजट पेश करने के 10-15 दिन पहले से चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाये। मुख्य मंत्री जी की बड़ी फोटो के साथ राजस्थान बजट 2023, बचत, राहत और बढ़त। लोगों को भी लगा कि इसमें इतना प्रचार-प्रसार हो रहा है तो काफी रियायत भी मिलेगी। किसानों ने सोचा कि उनका ऋण भी माफ हो जायेगा। आखिरी बजट है। लोगों ने कहा कि डीजल-पेट्रोल पर वैट भी कम हो जायेगा। उसमें आपने 11 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर एलईडी लगायी। शहरों में, नगरपालिकाओं में, नगर निगम में, बाजारों में, स्कूलों में करीब 16 हजार एलईडी लगाकर आपने इसका लाइव टेलीकास्ट कराया। जब बजट 11 बजे शुरू हुआ तो 7 मिनट तक तो माननीय मुख्य मंत्री जी पुराना बजट ही पढ़ते रहे और उधर बैठे हुए मेरे साथी उनके समर्थन में तालियां बजाते रहे, टेबलें बजाते रहे। वह तो दीर्घा में बैठे हुए अधिकारियों ने टोका तब जाकर बजट रुका, नहीं तो पिछले साल का पूरा बजट ही पढ़ जाते। राजस्थान में ऐसी शर्मसार स्थिति हुई कि आज तक कभी नहीं हुई। बाद में मुख्य मंत्री जी को सदन से माफी मांगकर अगला बजट पढ़ना पड़ा। अगला बजट 3 घंटे 16 मिनट पढ़ा। गांव में जो लोग सुनने गये थे, वे काफी आशा और उम्मीदें लेकर गये थे, लेकिन 3 घंटे 16 मिनट के बजट के बाद सब सरकार को कोसते हुए उठे। न तो डीजल-पेट्रोल पर वैट कम हुआ और न ही किसानों के कर्ज माफ हुए और न ही उनके माफिक कोई काम हुआ। सबने यही कहा कि अब चुनाव में आयेंगे तब निपटेंगे।

पूरे बजट को मैंने भी दो-तीन बार पढ़ा है। इस पूरे बजट में जो घोषणाएं की हैं, उनका पैसा कहां से आयेगा, इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। आज यह स्थिति है कि 5 लाख 89 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जा राजस्थान सरकार पर हो चुका है। 32 हजार करोड़ से ज्यादा का सालाना ब्याज भुगतना पड़ रहा है। 32 हजार करोड़ से ज्यादा ब्याज में ही चले जाएंगे तो जनता का क्या भला होगा?

चार साल में आपने जो घोषणाएं की हैं, उसके लिए लिखा कि हमने 85 परसेंट पूरी कर दीं। मेरे पास चारों बजट हैं। 2019-20 में पेज नम्बर 9 पर पैरा संख्या 31-प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला स्थापित की जायेगी। मेरे यहां पर पांच पंचायत समितियां हैं, एक में भी नहीं बनी। पेज नम्बर 10 में पैरा संख्या 39-सरकार आने वाले पांच वर्षों में समस्त ग्राम पंचायतों को एक-एक नया विकास पथ उपलब्ध करायेगी। एक भी नहीं बना। पैरा नम्बर 47 में प्रदेश में अन्य जिलों में चरणबद्ध रूप से 220 केवी के 3 और 132

(श्री अशोक डोगरा)

केवी के 13 ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण कराया जायेगा, हमारे जिले में एक भी नहीं हुआ। पैरा संख्या 95 में आपने लिखा- राज्य में मोहल्ला/गली में जनता क्लिनिक खोले जायेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नहीं खुला। पैरा संख्या 106 में आपने लिखा कि प्रदेश के नगरपालिका, नगर परिषद् मुख्यालयों को छोड़कर सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनाये जायेंगे, एक भी नहीं बना। आपने पैरा नम्बर 158 पर लिखा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक स्वागत कक्ष बनाया जायेगा। वह विधायक कोष से बना, सरकार ने तो एक रुपया भी नहीं दिया। पैरा संख्या 182 में आपने लिखा कि राज्यभर के पत्रकारों, साहित्यकारों एवं लेखकों को स्थानीय निकायों के माध्यम से रिहायशी कालोनी में भूखण्ड आबंटित किया जायेगा। आज सारे पत्रकार गाली दे रहे हैं, किसी को एक भूखण्ड नहीं मिला।

उसके अगले साल 2020-21 में आ जायें। आपने पैरा संख्या 13 में लिखा कि मिलावट की जांच हेतु प्रत्येक जिले में एक लैब, मेरे जिले में तो कोई लैब नहीं खुली। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र, मेरे यहां पर एक भी नहीं खुला। पैरा संख्या 118 में लिखा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं चिह्नित शहरी क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी सिटी विकसित करेंगे, कुछ भी नहीं। पैरा संख्या 134 में लिखा कि प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क, कुछ भी नहीं हुआ। आपने पैरा संख्या 197 में लिखा, शहीद स्मारक, कुछ भी नहीं बना। पैरा संख्या 176 में लिखा गुरुनानक जयन्ती पार्क, कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है कि आपने पूरे चार साल तक असत्य का पुलिन्दा दिया और पांचवें साल में फिर इतना बड़ा पुलिन्दा लेकर आ गये। आपने किया तो कुछ भी नहीं।

आप चिरंजीवी योजना का इतना ढोल पीटते हो कि चिरंजीवी योजना। आज हालत यह है कि प्राइवेट हास्पिटलों में किसी भी तरह की डिलीवरी हो, चाहे नोर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, यह चिरंजीवी योजना में अलाउ नहीं है। महिलाओं को सरकारी हास्पिटल की भीड़ में धक्के खाने को मजबूर होना पड़ता है। हर महिला को 40-45 वर्ष की उम्र में बच्चेदानी या यूटरस निकलवाने की जरूरत पड़ती है, इसको आपने प्राइवेट हास्पिटलों में चिरंजीवी योजना में कवर नहीं किया। पाइल्स जैसा मामूली आपरेशन भी आपने चिरंजीवी योजना में प्राइवेट हास्पिटलों में कवर नहीं कर रखा है। सरकारी हास्पिटलों में चिरंजीवी योजना में दवाई लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी 30 परसेंट दवाइयां ही मिलती हैं, 70 परसेंट तो उनके पास होती नहीं हैं।

(श्री अशोक डोगरा)

आज भ्रष्टाचार और इल्लीगल माइनिंग। मेरा जो एरिया है वहां इल्लीगल माइनिंग इतनी हो रही है कि लोग कहते हैं कि आज तक रिकार्ड में नहीं देखा। सरेआम होती है। सांगोद से आने वाले माननीय विधायक रोज मुख्य मंत्री जी को और दिल्ली हाई कमान तक मंत्री जी के खिलाफ लिखते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। वे रोज प्रेस को जारी करते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री से लेकर ऊपर तक सबको पैसा पहुंचता है। सीएम साहब मास्टरों के कार्यक्रम में चले गये। उन्होंने पूछ लिया कि ट्रांसफर के लिए राजस्थान में पैसा तो नहीं देना पड़ता, तो सारे मास्टरों ने कहा कि हां, साहब, देना पड़ता है। उन्होंने फिर पूछा, क्या, तो कुर्सियों में खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर कहा कि हां, साहब, देना पड़ता है लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र पर आता हूं। मेरे यहां तालड़ा में बरूंदन पंचायत समिति में एक वार्ड बैरवा बस्ती है। दोनों के बीच में बड़ी नदी है। उसमें 32 से 35 फीट पानी रहता है, हम कई सालों से मांग कर हैं कि उस पर पुलिया बनायी जाये लेकिन उस पर कभी पुलिया नहीं बनी। हमने 50 लाख मेरे विधायक कोष से, 20-25 लाख प्रधान जी, 15-20 लाख रुपये पंचायत ने देकर और कुछ जिला परिषद् ने देकर कुल 01 करोड़ 26 लाख के लोहे के पुल के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ है। साल भर हो गया है, लेकिन जिला परिषद् का कोई 50 लाख से ऊपर का होता है तो जयपुर से परमिशन आती है, उसके नाम पर साल भर से 01 करोड़ 26 लाख रुपये रोक रखे हैं। वे गरीब बच्चे जो नाव में बैठकर उधर से आते हैं, नाव चलाने वाला भी कोई नहीं, वे खुद ही चलाकर आते हैं। कभी कोई घटना हो जायेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरा सरकार से यही कहना है कि जल्दी से जल्दी या तो उसके लिए एक बड़े पुल की घोषणा करें, या हमने जो 01 करोड़ 26 लाख रुपये दे रखे हैं, उसका लोहे का पुल बनवाने का कष्ट करें।

लालपुरा से बागदा तक एक पुल की अति-आवश्यकता है, यदि यह पुल बन जाता है तो केशोरायपाटन से किसान जो ट्रोलियों में माल लेकर बूंदी मंडी में आते हैं, उनको 25-30 किलोमीटर कम एरिया पड़ेगा। यह भी अति-आवश्यक है। एक करोल नदी पर हनुतिया से जैथल एक पुल है, यह रपट ही बना दिया जाए, यदि पुल बनाने में ज्यादा पैसा लगता हो तो रपट ही बन जाए तो बारिश के समय रुक जायेगी, बाकी चलता रहेगा। इससे भी बूंदी से कापरेन की दूरी 45 किलोमीटर कम हो जायेगी।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): साहब, बस एक-दो बातें हैं। एक मेरा गर्ल्स स्कूल जेल बिल्डिंग में चल रहा है। जेल बिल्डिंग पहले जब गिरने वाली थी तो बाहर नई बिल्डिंग बन गयी, उस पुरानी बिल्डिंग में गर्ल्स कालेज शिफ्ट कर दिया। अब वह ऐसी बुरी हालत में है, माहौल भी पढ़ाई का नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसके लिए पैसा देकर नई बिल्डिंग बनाई जाए।

मेरी कृषि उपज मंडी, चार-पांच साल पहले शहर से बाहर बड़ी मंडी बनी थी। वहां सीजन में दस किलोमीटर तक, दोनों तरफ पांच-पांच किलोमीटर तक ट्रोलियां लग जाती हैं, लेकिन अंधेरा रहता है, नानकपुरिया से लेकर मंडी तक रोड लाइट लगवायी जाए। दस हजार से ज्यादा ट्रोलियां उस मंडी में आ जाती हैं। बाहर ट्रैफिक जाम हो जाता है। निकास का एक अलग द्वार हर हालत में बनाया जाए। मंडी में दो नये प्लेटफार्म भी बनाये जाएं।

जल जीवन मिशन में जहां-जहां भी आपने पानी की लाइनें डालीं, उस सड़क को आपके अधिकारियों ने रिपेयर नहीं कराया। आज भी पूरे गांव में खड्ढ़े पड़े हुए हैं, जिससे लोग परेशान हैं।

मेरे गरड़दा पेयजल योजना, इसमें 118 गांव और 101 मर्जर हैं। 219 हेबिटेशन में पानी जाना था, 2018 में वसुन्धरा जी के राज में उस बजट में उन्होंने सेंक्शन किया था। पैसा भी दिया था। आज तालड़ा और बूंदी पंचायत समिति के 219 गांवों में पानी जाना था। आपकी सरकार ने रोक रखा है।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): साहब, दो मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त कर दीजिए आप। In only one minute. Please.

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): दस मिनट भी पूरे नहीं हुए। मेरा यह भी कहना था कि रामगढ़ विषधारी सेंक्चुअरी मेरे यहां है। 6 गांव विस्थापित हो रहे हैं। आप वहां 15 लाख रुपये प्रत्येक परिवार को दे रहे हैं, हमारा अनुरोध है कि 20 लाख दीजिए। आप 21 साल के बच्चे को एडल्ट मान रहे हैं, जबकि सरकार 18 साल पर वोट देने का अधिकार रखती है। 18 साल को उसमें शामिल किया जाए और उसी गांव में 700 बीघा चरागाह और सिवाय चक भूमि है, वहां उनको रहने के लिए, मकान के लिए जगह दी जाए।

(श्री अशोक डोगरा)

मेरे बूंदी में आज बाजार में पार्किंग की कोई जगह नहीं है। आजाद पार्क पड़ता है, वहां एक अंडरग्राउण्ड पार्किंग की व्यवस्था के लिए पैसा दिया जाए ताकि वहां पर यह भी हो जाए और यूआईटी भी खोलने की घोषणा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

सूचना

ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि मण्डल का राजस्थान विधान सभा पधारने पर स्वागत

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, दर्शक दीर्घा में, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक डेलिगेशन जो आज विधान सभा को विजिट कर रहा है, उनके लीडर बॉब ब्लेकमेन दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। पूरे सदन की तरफ से आपका स्वागत है।

श्री सभापति: Welcome to all. Thank you.

शोभारानी जी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, अभी जो बजट पेश किया गया है, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। इस बजट ने साबित कर दिया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी गरीबों के मसीहा हैं, क्योंकि इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान गरीबों का रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से 500 रुपये में सिलेण्डर देने की बात हो या 100 यूनिट मुफ्त में बिजली देने की बात हो, चाहे 8 रुपये में खाना खिलाने की बात हो, ...(व्यवधान) चाहे 25 लाख रुपये तक की चिरंजीवी योजना की बात हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सदस्या, 8 रुपये में ...(व्यवधान) अब हो गया।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बैठिए।

श्री सभापति: सुनिए आप सब।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): चाहे 30 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती की बात हो, इन सभी योजनाओं के लिए गरीब लोग दिल से माननीय मुख्य मंत्री जी को दुआ दे रहे हैं। (व्यवधान) मैंने अभी जन सुनवाई की।

श्री सभापति: सुनिए प्लीज।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): मैंने अभी जन सुनवाई की, जिसमें लोगों ने मुझे आकर बताया कि वाकई हमारे मुख्य मंत्री जी ने गरीब परिवारों की परवाह की है क्योंकि इन योजनाओं का सीधा असर गरीब लोगों की जिन्दगी पर होने वाला है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का इस बेहतरीन गरीब हितैषी बजट के लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): आप बीच-बीच में टोक रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया इनको डिस्टर्ब न करें। Please listen to her.

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): पूरे प्रदेश के साथ-साथ मेरी विधान सभा ...(व्यवधान) धौलपुर का भी ख्याल रखा गया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह तो ...(व्यवधान) डिस्टर्ब है। यह तो बजट पर ...(व्यवधान) बदलते हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): आप बीच में मत बोलिए। (व्यवधान) ये रुकने वाली नहीं हैं। डरने वाली भी नहीं हैं।

श्री सभापति: मंत्री महोदया, प्लीज। Please listen to her.

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): धौलपुर में कृषि विद्यालय, ... (व्यवधान) महाविद्यालय, क्राइम कंट्रोल के लिए अलग से एडिशनल एस.पी. कार्यालय। मालोनी खुर्द में नई पुलिस चौकी, धौलपुर से सरानीखेड़ा होते हुए महुआ खेड़ा तक सड़क। अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए छात्रावास, सावित्री बाई वाचनालय और युवाओं के लिए इंडोर स्टेडियम आदि महत्वपूर्ण विकास कार्यों को बजट में लेकर बहुत ही सराहनीय कार्य किये हैं। इसके लिए मेरी पूरी विधान सभा की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं।

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

अंत में माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं तीन मांगों का निवेदन करना चाहती हूं। नंबर एक, अभी हाल में महात्मा ज्योतिबा फुले विकास बोर्ड का गठन किया गया है, मैं चाहती हूं इसको जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए। इसके अंदर तीन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए। नंबर एक, इसमें आने वाली समाज की बच्चियों के लिए प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर नि:शुल्क छात्रावास की व्यवस्था की जाए। नंबर दो, इसमें आने वाले समाज के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए स्कालरशिप की व्यवस्था की जाए और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, इसमें आने वाले समाजों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, इसलिए इन युवाओं के लिए चार प्रतिशत सालाना इंट्रेस्ट पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे युवा अपना रोजगार शुरू कर सके।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से दूसरी मांग है कि पूर्वी राजस्थान में लोधा समाज बहुत अच्छी संख्या में रहता है और पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। इनके समाज के हजारों लोग कई बार मेरे पास आकर इस मांग को नोट करा गये हैं, इसलिए मेरी मांग है कि अन्य पिछड़े समाजों की तरह इनके लिए भी रानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे इस समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिले।

माननीय सभापति महोदय, तीसरी मांग है कि हमारी बच्चियों के लिए मेरी विधान सभा में रामसेवक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरानीखेड़ा को क्रमोन्नत करके बालिका महाविद्यालय किया जाए, जिससे हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां अच्छे से पढ़ सकें। यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। माननीय मुख्य मंत्री जी, इसके जो भामाशाह हैं, जिन्होंने इस विद्यालय को सरकार को दान किया हुआ है, वह महाविद्यालय के लिए और जमीन भी देने को तैयार हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विद्यालय को जल्दी से जल्दी क्रमोन्नत किया जाए। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय सभापति जी, आपने मेरे को 2023-24 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। करीब तीन घंटे का बजट भाषण जो मुख्य मंत्री जी ने दिया और झुनझुना पकड़ाया, मेरे को लगता है, वह बजेगा लेकिन धरातल पर नहीं आएगा। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर मुख्य मंत्री जी के कथन में यह सच्चाई है कि

(श्री सुभाष पूनिया)

कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा।

राजस्थान प्रदेश की जनता ने पिछले चार वर्षों में न कर्म में सच्चाई देखी, न संकट का हल, सिर्फ छलावा ही देखा। सरकार को बचाने के संकट से ही जूझती नजर आयी। आप कह रहे हैं आज नहीं तो कल होगा, लेकिन कल कब आयेगा? यह अभी तक पता नहीं। मैं कह रहा हूं-

'काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।

पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब।।

मैं सीधा-सा पेयजल के ऊपर आता हूं। बजट भाषण 2020-21, पैरा नंबर 107 के ऊपर कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना की घोषणा हुई थी और आज 2023-24 का बजट आ गया है और 24 मार्च, 2022 को राजस्थान प्रदेश के 8 जिलों में 4765.31 करोड़ रुपये की बजट में घोषणा की गयी थी। सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी को इसमें 1350 करोड़ रुपये का झुनझुना पकड़ाया था, वह आज तक कहीं धरातल पर नहीं है। पिछले बजट सत्र में मैंने जलदाय मंत्री जी से पूछा था और मैंने कहा था कि स्वीकृति हो गई तो टेंडर कब तक लग जाएंगे? उन्होंने ध्यानाकर्षण 131 में जवाब दिया था कि हम 31 मई तक टेंडर कर देंगे और अगला बजट फिर आ गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सूरजगढ़ विधान सभा क्या, ज़िले में भी कोई काम होता नजर आया।

आपने देखा होगा सड़कों के मामले में। अबकी बार बजट पेश हुआ, मैंने तो बहुत लम्बी-चौड़ी उम्मीद पाल रखी थी। मैंने ही क्या, पूरे राजस्थान ने ही। एक जगह नहीं पूरे प्रदेश में 16 हजार जगह एलईडी लगाकर, सरकार की जो फजीहत करवाई है, यह आज के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री जी खुद यह स्वीकार कर चुके हैं कि मानवीय भूल हुई है। अब यह भूल कहां हुई है? अगर आपने कुछ दिया भी होगा, तो यह बजट उसी दिन फिसड्डी साबित हो गया था। सड़कों में, 10 करोड़ रुपये एमएलए की अभिशंसा पर होने चाहिए, मैं चाहूंगा कि आप विधायकों की अभिशंसा से करें। अगर अधिकारी अपने हिसाब से करेंगे तो किसी के खेत तक, किसी को व्यक्तिगत लाभ देने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि इसमें जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

सभापति महोदय, जहां तक मैं नोन-पेचेबल सड़कों की बात करूं, सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विलेज रोड्स हैं वह 100 किलोमीटर की नोन-

(श्री सुभाष पूनिया)

पेचेबल रोड, जो दस साल से पहले बनी हुई है, वह सारी 100 किलोमीटर तक की क्षतिग्रस्त हैं, उनको अभी तक बजट में नहीं लिया गया है। पूरे ज़िले में, मैं समझता हूं राजस्थान में दी होगी, पूरे ज़िले में कहीं न कहीं सड़कें दी गईं, लेकिन मुझे एक किलोमीटर सड़क भी नहीं दी गई है। दो सड़कें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, पचेरी से बालोत, हरियाणा बोर्डर तक टच करती है, 15 किलोमीटर की सड़क बहुत जरूरी थी, मैं चाहूंगा इस सड़क को शामिल किया जाए। दूसरी सड़क, खांडवा-सातोर-नालोत, जो हरियाणा बोर्डर तक 14 किलोमीटर की सड़क है, वह भी अतिआवश्यक है। तीसरी सड़क है, पचेरी ढाला, देवलाबास और सातोर होकर, वह भी इसमें शामिल की जाए तो निश्चित रूप से सूरजगढ़ विधान सभा लाभान्वित होगी।

सभापति महोदय, कृषि विपणन बोर्ड, जो मार्केटिंग बोर्ड है, वह कुछ सड़कें बनाता था, कुछ सड़कों की रिपेयरिंग भी करता था। इस बार मुझे नहीं लगता, हमारे ज़िले में तो कहीं नहीं दी होगी, हो सकता है, सभापति जी, आपको कोई दी होगी तो। मेरे को तो आपने अछूत समझ रखा है। मेरे तो हो सकता है चार हजार वोट ही ज्यादा आए होंगे, लेकिन कुछ जनता तो आपकी भी है, उनका भी ख्याल रखें। मेरा आपसे यह आग्रह है।

आपने गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ दिया था। वह सभी जगह दे ही दिया पंचायतों में। यह आखिरी बजट है, मैं कहता हूं कि आपका भी आखिरी बजट है। बीस साल तक तो आप बजट पेश नहीं कर सकोगे। मैं चाहूंगा अब भी आपको सद्बुद्धि आए तो आप विकास पथ दें। आप अगर देंगे तो निश्चित रूप से गांवों का विकास होगा। नंदीशालाएं तो आपने खोल ही दी हैं न। शुरू का बजट पेश हुआ था तब नंदीशाला खोली, खूब वाहवाही लूटी, खूब तालियां बजवाईं, यह भी आपके सामने है।

ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के क्षेत्र में आपने कहा है कि हम किसानों को दिन में बिजली देंगे, वह भी आप आज तक पूरी नहीं कर पाये हैं। बूंद-बूंद सिंचाई कनेक्शन में आपने लोगों के पैसे जमा करवा लिए, आप आज तक कनेक्शन नहीं दे पाये हैं। नये जीएसएस नहीं बना पाये। कहीं घरेलू कनेक्शन दे रहे हैं तो वोल्टेज की प्रोब्लम हो रही है। पाले में किसान को नुकसान हुआ है, उसके लिए आप किसान का चार माह का बिल माफ करेंगे तो निश्चित रूप से किसान लाभान्वित होगा और आपकी जय-जयकार करेगा। अगर आपको जय-जयकार करवानी है तो, नहीं तो हालात वही होंगे, जिस दिन आपने बजट पढ़ा था, जनता तैयार बैठी है आपके लिए।

(श्री सुभाष पूनिया)

युवाओं के लिए आपने लम्बे-चौड़े वायदे किए थे कि हम बेरोज़गारों का कर्जा माफ करेंगे। किस तरह से पेपर लीक करके आपने उनको सड़कों पर छोड़ने का काम किया है। युवा आपके स्वागत के लिए तैयार बैठा है।

खेलों के लिए कहा कि हम खेलों का विकास करेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी खेल स्टेडियम नहीं बना है। जब घरडाना में, सीडीएस रावत के साथ कैजुअल्टी हुई थी, शहीद कुलदीप राव, उस समय यहां के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष व मंत्री जाकर आए थे, मुख्य मंत्री जी के सलाहकार जाकर आए थे कि हम यहां स्टेडियम बनाएंगे। आज तक वहां भी स्टेडियम नहीं बना है। बहुत शर्म की बात है।

चिकित्सा के क्षेत्र में, मेरा विधान सभा क्षेत्र ऐसा है जहां तीन सीएचसी हैं, वहां 30 बेड से ऊपर नहीं है तीनों ही सीएचसी में। एक-एक करोड़ रुपये आपने माडल सीएचसी के नाम पर विधायकों से ले लिए थे, उसके बावजूद भी जो मेडिकल उपकरण हमने दिये थे, डाक्टर्स के अभाव में, टैक्नीशियन के अभाव में वह बिलकुल बेकार पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। मैं यह आपसे आग्रह करना चाहूंगा। आरजीएचएस, सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट हास्पिटल के बिल हैं वह तो पेमेंट कर दिए लेकिन जिला उपभोक्ता भण्डारों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, वह भी शीघ्र करवाएं।

शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपने स्कूलों की खूब क्रमोन्नति की है। हायर एजुकेशन में भी कालेजेज बनाए, लेकिन कहीं भवन नहीं है। कहीं पर स्कूल के भवन बने हुए हैं वहां छतें टपक रही है। जर्जर स्थिति में भवन हैं, उनकी रिपेयरिंग की व्यवस्था करें, यह भी आग्रह हैं। स्कूल में विषय अध्यापक नहीं है। कालेजेज की हालत यह है कि हमने सूरजगढ़ में जमीन भी उपलब्ध करवा दी, उसके बावजूद भी वहां पीडब्ल्यूडी भवन नहीं बना रहा है, इसके लिए भी आपसे आग्रह है। वहां फर्नीचर, अन्य मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं वह पूरी करें। पदोन्नति व एरियर की समस्या भी है, उसको भी आप अतिशीघ्र पूरा करें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): नगरपालिका सूरजगढ़ की हालत खराब है। सीवरेज लाइन बननी चाहिए थी, वहां पर गंदा पानी भरता है, उसके निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सफाई की हालत देख ही रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी में तो एक-एक कर्मचारी के 15-15 बार ट्रांसफर हो रहे हैं। 10-15 दिन से ज्यादा कोई ई.ओ. नहीं रुकता है। आप किस तरह से विकास कराएंगे? जिस तरह का बजट पेश किया है, निश्चित रूप से आप एक फॉर्चूनर

(श्री सुभाष पूनिया)

में आएंगे, मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं। यह बजट असत्य का पुलिंदा है। मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2023-24 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया सुनें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2023-24 बजट पेश किया 270 पाइंट का। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, कृषि, युवा, महिला, सभी वर्गों के लिए इसमें लिखा है। सरकार ने अपना विजन दिया है, बजट दिया है कि इस साल में यह काम करेंगे। इस बजट को धरातल पर उतारने के लिए, किसी तरह का कोई ठोस रोडमैप या कोई विजन जो इसके पेरेलर काम करने वाली बात हो, वह नहीं कही गई है।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा की बात करूं। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें पिछले बजट में भी खोली गई थीं, अभी भी नई स्कूलें खोलने की बात कही गई है। जो स्कूल खोली गई है उसके अन्दर अभी हिन्दी माध्यम के अध्यापक ही पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के टीचर उसमें एवेलेबल नहीं हैं। इस बजट में ऐसा कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर कैसे, कब, कहां से आएंगे।

कालेज की बात करें तो कालेजों में भी वही स्थितियां हैं, स्टाफ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जो सीनियर सैकण्डरी की स्कूलें हैं उनमें सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं हैं, स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। जो स्कूल जर्जर स्थिति में हैं, उनकी मैंटीनेंस के लिए भी इस बजट के अन्दर कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है।

अभी शिक्षित बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी की जब बात करते हैं तो पिछले चार साल में सरकार ने जो परीक्षाएं आयोजित की हैं, उन परीक्षाओं में से 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। पिछली साल नकल को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए एक विधेयक लाया गया था लेकिन ऐसा लगता है कि विधेयक लाने के बाद भी उस विधेयक को इफेक्टिवली लागू नहीं किया गया, उस विधेयक को सही समय पर लागू नहीं किया गया, जिससे विधेयक लाने के बाद भी अभी सैकण्ड ग्रेड टीचर्स की जो भर्ती थी, उसमें वह पेपर लीक हुआ है।

(श्री पुखराज)

मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें पेपर लीक होने का अहम रोल है और बेरोजगारी कम करने के लिए इस बजट के अन्दर कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। हमने पिछले सत्र के अन्दर भी यह मांग की थी कि प्रदेश के अन्दर जितनी भी भर्तियां होती हैं उन भर्तियों के अन्दर प्रदेश के युवा बेरोजगारों को मौका मिलना चाहिए, इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए, इसके लिए कोई ठोस नियम बनना चाहिए लेकिन इस बजट के अन्दर वह चीज भी नहीं दिखी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह मांग करना चाहूंगा कि जो राजस्थान के बेरोजगार हैं, आगे जो भी भर्तियां हों, उन भर्तियों में राजस्थान के युवा बेरोजगारों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए।

बजट के अन्दर चिकित्सा के बारे में काफी बातें कही गयी हैं। चिकित्सा के अन्दर पिछले बजट के अन्दर भी निरोगी राजस्थान का संकल्प लिया गया था और अभी भी राइट टू हैल्थ का विधेयक सरकार लाने की तैयारी कर रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो सी.एच.सीज. हैं, पी.एच.सीज. हैं, उनके अन्दर कहीं पर डाक्टर्स नहीं हैं, कहीं पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है, कहीं पर विशेषज्ञ डाक्टर्स नहीं हैं और मेरे भोपालगढ़ के अन्दर पिछले बजट के अन्दर, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि सी.एच.सी. से उप जिला हास्पिटल करने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी वह सी.एच.सी. 30 बेड की चल रही है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह मांग करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ हास्पिटल के अन्दर उप जिला हास्पिटल के जो मापदंड है, उसके अनुसार सारी सुविधाएं दें। उस मापदंड के अनुसार उसमें डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ लगाया जाये।

साथ ही, जो सी.एच.सीज. हैं उनके अन्दर सोनोग्राफी की मशीनें हैं लेकिन उनको आपरेट करने वाले डाक्टर्स नहीं हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह मांग करना चाहूंगा कि जब हम राइट टू हैल्थ की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर सोनोग्राफी मशीनें हैं पर डाक्टर्स नहीं होंगे तो राइट टू हैल्थ जो विधेयक हम ला रहे हैं वह भी कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा।

(समय: 15.33 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह मांग करना चाहूंगा कि राइट टू हैल्थ जो विधेयक हम ला रहे

(श्री पुखराज)

हैं, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, इसको लागू करने के लिए हर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर, मुख्यालय पर पी.एच.सी. खोली जानी चाहिए।

ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अन्दर यह कहा कि जब सरकार बनी थी तब 6600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था लेकिन अभी हम 8600 मेगावाट का उत्पादन कर रहे हैं मतलब, दो हजार मेगावाट का उत्पादन बिजली के क्षेत्र में बढ़ना बताया गया है लेकिन धरातल पर गांवों के अन्दर न किसानों को ब्लाक सप्लाई से छह घंटे और सात घंटे बिजली मिल रही है और न ही गांवों के अन्दर सिंगल फेज सप्लाई जिनकी 18 और 24 घंटे देने की बात कही गयी थी, लेकिन वह भी पांच-छह घंटे ही सप्लाई मिल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर अभी बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं। जो बच्चे सीनियर सैकण्डरी में पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए सिंगल फेज सप्लाई को नियमित करवायें, उसको 24 घंटे सप्लाई दिलवाने के निर्देश प्रदान करायें। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा।

पिछले बजट के अन्दर बिजली के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि पिछले दस साल के कृषि कनेक्शन हम इन दो सालों के अन्दर दे देंगे लेकिन अभी तक 2015 तक के डिमांड नोटिस ही दिये गये हैं और न ही बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई नया सब-स्टेशन ही बनाया गया है।

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): न कोई नया सब-डिविजन ही बना है, न डिविजन बना है, न सर्किल बना है तो यह कैसे पोसिबल होगा? जो हम घोषणा कर रहे हैं उस घोषणा को धरातल पर लाने के लिए किसी तरह की ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पेयजल की बात करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ के अन्दर पेयजल की बहुत ही विकट समस्या है। जेजे.वाई. के जो ट्यूबवैल्स हैं वे बंद पड़े हुए हैं और जेजे.एम. की जो महत्वपूर्ण योजना है उसके टेंडर मेरी मंडोर पंचायत समिति के अन्दर हुए डेढ़ साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। बावड़ी पंचायत समिति की स्थिति उससे भी खराब है। बावड़ी पंचायत समिति के अन्दर अभी जे.जे.एम.

(श्री पुखराज)

के टेंडर भी नहीं हुए हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनके टेंडर जल्दी करें ताकि गांवों के अन्दर पेयजल की समस्या का निराकरण हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के 55 से 60 गांव हैं जो जोधपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर आते हैं लेकिन वहां पर समस्या यह है कि जब शहीद की बात आती है तो शहीद के सम्मान के लिए हम पैकेज की बात करते हैं, बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं, शहीद के नाम से स्कूल का नामकरण करते हैं लेकिन शहीद की मूर्ति लगाने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) से भूमि आबंटित नहीं की जा रही है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस क्षेत्र में जो शहीद हुए हैं, जिनकी मूर्तियां लगानी हैं, उनके लिए जमीन जोधपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) से तुरंत आबंटित करवाने की व्यवस्था करायें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए बजट के अन्दर एक बड़ी रोड दी गयी है 54 किलोमीटर की, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि मेरे आसोप ग्राम पंचायत जो भोपालगढ़ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अन्दर एक महाविद्यालय खोला जाये। सालवा कलां बड़ी ग्राम पंचायत है मंडोर की, उसकी पी.एच.सी. को क्रमोन्नत करके सी.एच.सी. बनायी जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): सी.एच.सी. बनाड़ जो तीन तरफ से उसके नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है उसके अन्दर ट्रोमा सेंटर खोला जाये। बुडकिया जो सब-सेंटर है, बड़ी ग्राम पंचायतें हैं- बुडकिया, साथीन, रूदिया, हीरादेसर, इन सब-सेंटर को पी.एच.सी. के अंदर क्रमोन्नत किया जाये।

साथ ही, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो काफी पुरानी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुवाणा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुड़ियों की बासनी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवनगर सांपला, इनको राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्दर क्रमोन्नत करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): गादेरी जो नई ग्राम पंचायत मुख्यालय है,

(श्री पुखराज)

उस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के आदेश करायें।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आज 2023-24 के बजट पर चर्चा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है, आय-व्यय के साथ बहुत गहरा संतुलन। छोटी-छोटी बातों को जिन्होंने, एक लाइन में प्राय: कहा जाता है, फिर विभाग उनका विवरण प्रस्तुत करते हैं, उनका बखान भी बजट में ही करके असत्य वाहवाही लूटने का प्रयास किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, अगर आप वास्तव में जनहित चाहते हैं तो मेरी मांग है कि पेट्रोल-डीजल पर राज्य स्तर के करों में कमी की घोषणा करें। आपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की बात दोहराई है। हम दोनों ही जोधपुर से आते हैं, जोधपुर की पहचान छीतर का पत्थर है। उसको मार्केटिंग में, सुन्दरता में उद्योग का दर्जा देने की मांग आप पहली बार मुख्य मंत्री बने तब से चल रही है। आपके तीसरी बार मुख्य मंत्री बनने तक भी यह अधूरी है। मेरी मांग है कि आप अपने जवाब में इसे सम्मिलित करें और उद्योग का दर्जा दें।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री ने हर विधान सभा क्षेत्र में विधान सभा सदस्य की अनुशंसा और 10 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों के निर्माण की बात कही है। परन्तु आप पता कर लीजिए, वहां विधायक की अनुशंसा नहीं चलती है, अधिकारियों की मनमर्जी चलती है। विधायक कहते हैं वह नहीं करते और अपनी मर्जी से करते हैं। मनमर्जी की सड़कों को जोड़कर राशि वसूल कर लेते हैं। सड़कें उतनी गुणवत्ता की भी नहीं बनती हैं। मेरी मांग है कि आप इसमें स्पष्ट प्रावधान करें कि यह सड़कें विधायक की अनुशंसा पर ही बनेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बिन्दु संख्या 46 पर खेल स्टेडियम विकास की घोषणा की है। मेरी मांग है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के कालीबेरी स्टेडियम के विकास एवं खेल परीक्षण, सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य की स्वीकृति आपके जवाब में सम्मिलित कराएं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बिन्दु संख्या 58 में

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

राजकीय चिकित्सालयों के क्रमोन्नत की घोषणा की है, परन्तु विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की अनदेखी की है। मेरी मांग है कि राजकीय चिकित्सालय चांदपोल को सेटेलाइट करें। वह मास्टर खेमराज कच्छावा के नाम से पहचानी जाती है। मास्टर खेमराज कच्छावा काठ का पक्का था, उसके नाम पर है। वहां कैसे-कैसे लोग रहते हैं, गरीब तबक़े के लोग रहते हैं, कई कालोनी ऐसी जगह हैं जहां भील बस्ती है, हरिजन बस्ती है, सारी बस्तियां वहां आई हुई हैं लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए सेटेलाइट स्तर का दर्जा दें। सेठ सूरजमल राजकीय चिकित्सालय, राजबाग को सामुदायिक केन्द्र स्तर पर क्रमोन्नत करने की घोषणा अपने जवाब में जरूर करें। राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मसूरिया में पंचकर्म केन्द्र आरम्भ करने की घोषणा भी अपने जवाब में सम्मिलित कराएं।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 102 में तालाबों के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य सम्मिलित किये हैं। मेरी मांग है कि आप उस सूची में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चतुरसागर तालाब का जीर्णोद्धार करें, सौन्दर्यीकरण कराएं। सूरसागर ऐसा क्षेत्र है, जो सूरसागर जाना जाता है, वहां तालाब है, उसका भी जीर्णोद्धार कराएं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिन्दु संख्या 128 में मंदिरों, स्मारकों का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन दृष्टि से विकास की घोषणा की है। जोधपुर में समस्त पुष्करणा समाज की कुलदेवी उष्ट्रवाहिनी के मंदिर का विकास जन सहयोग से करने का प्रयास चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी यह उष्ट्रादेवी वह है जो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी और महाराजा प्रताप सिंह जी के द्वारा बनाई हुई है। मूर्ति की स्थापना 400-500 साल पुरानी है। पुष्करणा समाज के गौरव के अनुकूल बने, इसलिए सरकारी सहायता अति आवश्यक है। अत: मेरी मांग है कि सम्पूर्ण विश्व में पुष्करणा ब्राहमण समाज की कुलदेवी का एक मात्र मंदिर उष्ट्रावाहिनी मंदिर पुष्करणा धाम है, जोधपुर के जीर्णोद्धार और पर्यटन की दृष्टि से आप विकास कार्य को अपने जवाब में सम्मिलित कराएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। मुख्य मंत्री जी ने कई ऐसी घोषणाएं की हैं स्कूलें खोली हैं, स्कूलें खोलना बुरी बात नहीं है। स्कूलें तो खोल दीं मगर मारवाड़ी में एक कहावत है, सेठ जी री बेटी पुटरी उन्हे मोने कई। अब आपने स्कूलें तो खोल दीं पर वहां पढ़े कौन? वहां कोई टाबर नहीं। टाबर है तो मास्टरनी नहीं। मास्टरनी है तो

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

मास्टर नहीं हैं। पढ़ें तो कहां पढ़ें, केवल चार कमरे हैं। मैं कई स्कूलों में खुद जाती हूं, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात करूं। मैं स्वयं जाकर देखती हूं। कई दानदाताओं को ले जाती हूं। मैंने जाकर देखा, वहां चार कमरे हैं, एक कमरा तो आंगनबाड़ी वालों ने ले लिया। अब तीन कमरे रहे और क्लास है 1 से 8 तक। अब तीन तो कमरे और चार मास्टरनी और एक हैडमास्टर। हैडमास्टर तो विराजते ही नहीं। तीन बार गई, तीन बार ही नहीं मिले। चार टीचर, एक टीचर नहीं, तीन ही थी। कक्षा 1 से 8 के अंदर, एक-एक कमरे के अंदर ऐसे लकड़ी लगा दी। टाट-पट्टी बिछाने का तो सवाल ही नहीं। ऐसे लगाकर, कि यह पहली है, यह दूसरी है, इस तरह से स्कूलों की हालत है। सबसे पहले मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप स्कूल खोलो, कोई भी सरकार हो, पर देखें तो सही कि जगह कहां है, टीचर कहां है, कौन पढ़ाएगा, यह आने वाले भविष्य के बच्चे हैं।

सभापति महोदय, मैंने चौथी क्लास के बच्चे को बुलाकर पूछा कि बेटा, राजस्थान का मुख्य मंत्री कौन है, तो उसने जवाब दिया कि मुझे तो पता नहीं है। कमाल है, अगर चौथी क्लास का बच्चा यह नहीं बता सके कि राजस्थान का मुख्य मंत्री कौन है, वह भी जोधपुर का। मुझे तो इतना घमण्ड रहता है कि मुख्य मंत्री हमारे जोधपुर का है। कांग्रेस का राज था तो कोई न कोई तो मुख्य मंत्री बनता ही, तो फिर हमारे जोधपुर का मुख्य मंत्री है, हमें इस बात का घमण्ड है। मैं और वह दोनों एक जगह से आते हैं, फिर भी जोधपुर का विकास नहीं हो, ब्याह में मां परोसने वाली फिर भी हम भूखे के भूखे, यह क्या बात हुई।

सभापति महोदय, मेरा आपसे यह कहना है, हास्पिटल हो, कुछ भी हो, मुख्य मंत्री जी ने जो-जो घोषणाएं की हैं ... (व्यवधान) मैंने कोई गलत थोड़े ही बोला है। मुख्य मंत्री जी जोधपुर की एक-एक गली, एक-एक मोहल्ला जानते हैं, वह हर जगह मरने-करने में जाते हैं, उनसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है, फिर भी जोधपुर में कोई काम अधूरा रह जाए, फिर तो हमारा दुर्भाग्य ही समझें।

हमारे मुख्य मंत्री हैं, जोधपुर के हैं। मैं आपको रोज ही बात कहती हूं। हमारे नेता कभी ऐसी सलाह भी नहीं देते हैं कि अच्छे काम को गलत बता दो। अगर वह अच्छा काम करते हैं तो हम तो उनकी तारीफ कर देंगे, उनको पुष्पहार पहना देंगे। कोई तकलीफ नहीं है। हमारे नेता गलत राय नहीं देते हैं।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, मैं रसोई करती हूं, खाना बनाती हूं, पानी के लिए मांग करती हूं। मैं इस हाउस में पहुंची हूं। मैं यह चाहती हूं कि जोधपुर की जनता प्यासी नहीं रहे मगर सरकार की घोषणा के बाद एक साल हो गया, ट्यूबवैल की घोषणा करने के बाद अभी तक भी नहीं लगे। मैं फोन करते-करते परेशान हो गयी, अधिकारी सुनते ही नहीं हैं। आपको मेरी बात को सीरियसली लेना चाहिए। मेरी बात को मजाक मत समझना। मुख्य मंत्रीजी नहीं चाहते हैं क्या कि जोधपुर में काम हों? लेकिन मानिटरिंग पूरी नहीं हो रही है। मारवाड़ी में एक कहावत है 'कागला माखन खावै' वह स्थिति हो रखी है। कागले माखन खाते हैं। क्या बात करते हो। कोई व्यवस्था नहीं है। मानिटरिंग नहीं हो रही है। कई घोषणाएं हैं, उनकी अगर मानिटरिंग हो तो आज जोधपुर चमक जाता। मैं तो जोधपुर की ही बात करूंगी। मुख्य मंत्रीजी जोधपुर के हैं। यहां पर काफी माननीय सदस्य बोले कि जोधपुर को यह दे दिया। जोधपुर को इन्होंने क्या दिया? जोधपुर ने तीन-तीन मुख्य मंत्री दिये हैं। जयनारायणजी व्यास, बरकतुल्ला खां और अशोकजी दिये। ये जोधपुर में जितना करें उतना ही कम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पानी के लिए कहना चाहूंगी। हर जगह कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है कि वहां पर पानी नहीं पहुंचे। हमारे वहां तीन विधान सभा क्षेत्र हैं। सरदारपुरा से तो खुद अशोकजी हैं। वह शहर है। दूसरा सूरसागर है, मैं 15 साल से सूरसागर का प्रतिनिधित्व करती हूं, कोई घर ऐसा नहीं है जो मेरे से छिपा हुआ है। मैं हर जगह जाती हूं, मिलती हूं। मेरे पास फैक्ट्रियां थोड़े ही हैं। मैं सबसे मिलती हूं।

मुख्य मंत्रीजी ने पहले एमएलए के लिए कहा था कि सड़कें बनेंगी। जहां पर पत्थर लगा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है कि मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा के अनुसार यह सड़क बन रही है। हम ऐसा भी नहीं करेंगे। हमारे यहां सारा सिस्टम है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता ऐसी राय नहीं देते। मुझे इस बात का भी घमण्ड है। अगर वह कहते हैं कि अच्छा काम है तो वह अच्छा है।

मैं मुख्य मंत्रीजी से यह चाहूंगी कि उष्ट्रवाहिनी देवी के लिए जो मैंने निवेदन किया है, उसके लिए घोषणा करें, वहां व्यवस्था करें। वहां पर इतने ट्यूरिस्ट आते हैं, पहले वहां दर्शन करते हैं, किले में बाद में जाते हैं। मूर्ति आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, ऐसी मूर्ति है।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

सूरसागर की माइनिंग को, खानों को उद्योग का दर्जा दिया जाये। यह मेरी मांग है। मैं एक और छोटी-सी बात कहकर बात खतम करती हूं। सूरसागर में केरूफाटा है, वहां पर वेटरिनरी का सेन्टर बना हुआ है। मैं आपको बताऊं कि वह इतना अच्छा बना हुआ है हमने सारा फण्ड देकर उसको बनाया। उद्घाटन राज्यपाल और मुख्य मंत्रीजी ने किया है लेकिन वह पत्थर अभी तक पड़ा है, लगाया नहीं है। खाली पड़ा है। यह तो बहुत छोटी-सी बात है। मानिटरिंग की मैंने आपको मिसाल दी है। यह मेरी आंखों देखी बात है। दो महीने पहले तो पड़ा था, उसके बाद लग गया हो तो मेरे को पता नहीं है। यह स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, हमने कहा था, यह बात सही है, मुख्य मंत्रीजी को कि आप कायलाना के अन्दर पुलिस चौकी खोल दो, कालीबेरी में पुलिस चौकी खोलो। इन्होंने खोल दी। कायलाना में मैंने जमीन दिलाकर वहां पुलिस चौकी बन गई। आज भी वहां पर स्थापित है। कालीबेरी के अन्दर जमीन तो नहीं दी लेकिन पटवार घर में पुलिस चौकी चल रही है। इसी तरीके से मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। अधिकारियों ने क्या किया? देवनगर थाना एक रूम में चलता है। पांच साल के अन्दर इनको जगह नहीं मिली। हम फिर-फिर कर परेशान हो गये। लोग एन्क्रोचमेंट करते हैं, सारे भाखर को खा गये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): भाखर के ऊपर क्या बनायेंगे। मैं मांग करती हूं कि भाखर के ऊपर पुष्प लगाओ, उसको सुन्दर बनाओ। वहां पर बाथरूम बन गया। कोई रोकने वाला अधिकारी नहीं है। ध्यान दिलाते हैं तो भी नहीं करते हैं। सारे भाखर को खा गये। वहां इतना एन्क्रोचमेंट हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। मैं आपको आंखों देखा हाल सुना रही हूं कि यह स्थिति है। मुख्य मंत्रीजी चाहते होंगे कि काम हों मगर अधिकारी लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। 10 तारीख को जो बजट पेश किया गया है, यह असत्य का पुलिन्दा है। मैं इसका विरोध करती हूं। आपने मेरे को समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुरमीत सिंह कुनर।

(समय: 16.00 बजे)

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): आदरणीय सभापतिजी, आपने बजट 2023-24 पर सदन में हो रही बहस पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने 2023-24 का बजट राजस्थान की विधान सभा में पेश किया। प्रस्तुत बजट में मुख्य मंत्रीजी ने स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, रसोई गैस, शिक्षा, यात्रा आदि में गरीब और आम जनता को राहत प्रदान करने की कोशिश की। गरीब और आम जनता को सबसे बड़ा घर चलाने का जो बोझ होता है, रसाई गैस का, बिजली बिल का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, यह सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उसको दूर करने के प्रयास माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किये, जो सराहनीय हैं।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना, जिसके लिए पहले कोई सोच नहीं सकता था कि 10 लाख तक बीमा कवर करेंगे, लेकिन इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक किया। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया।

माननीय सभापति महोदय, घरेलू बिजली के बिल, जो पहले प्रतिमाह 50 यूनिट गरीब आदमी को फ्री किया। गरीब हो, आम आदमी हो, उसको 50 से बढ़ाकर 100 यूनिट फ्री किया। ये सब स्वागत योग्य फैसले हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसान की बिजली 2 हजार यूनिट प्रति माह माफ करना, यह कोई छोटी बात नहीं। हजारों-लाखों किसान इससे लाभान्वित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, उज्ज्वला योजना, जो माननीय प्रधान मंत्रीजी ने शुरू की थी, किन्हीं कारणों से वह बंद हो गयी। लेकिन वे परिवार, जो गैस का चूल्हा जलाना सीख गये, लकड़ियां भूल गये, वे तंग हो गये थे, उनकी तकलीफ को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 500 का सिलेण्डर उन परिवारों को देने की घोषणा की है। ऐसे परिवार को जब दुबारा गैस मिलेगी, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के वे गुण गायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के लिए रोडवेज में 50 प्रतिशत किराये में छूट दी गयी है। लक्खी मेले में 100 प्रतिशत छूट दी गयी है।

मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा में बेरोजगारों के लिए जो बच्चे परीक्षा देने जाते थे, उनके परीक्षा शुल्क लगती थी, उसको बिलकुल माफ कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना बीमारी में जो बच्चे अनाथ हो गये थे, उनको नौकरी की व्यवस्था की है।

पुरानी पेंशन योजना में 100 प्रतिशत पेंशनधारियों को कवर किया

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

गया है। जब इस पेंशन की घोषणा हुई थी तो बड़े धूमधाम से कर्मचारियों ने प्रोग्राम किये और कहा कि हमारे तो बुढ़ापे में बेटा पैदा हो गया। इतनी खुशी मना रहे थे। पहले जो कर्मचारी इससे वंचित रह गये थे, वे भी सम्मिलित हो गये। यह भी खुशी की बात है।

प्रतिमाह नि:शुल्क अन्नपूर्णा खाद्य सामग्री के जो पैकेट शुरू किये जाने हैं, उससे भी गरीब आदमी को लाभ मिलेगा।

नवीन युवा नीति बनाने की घोषणा की गयी है। वह जल्दी ही बनकर तैयार हो जायेगी।

सरकारी विभागों में जो पद रिक्त होंगे, उनको प्राथमिकता से भरने का जो काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने हाथ में लिया है, वह भी पूरा होगा।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में वे गरीब बच्चे, जो पढ़ने में होशियार हैं, लेकिन उनको कोचिंग की जरूरत है आगे पढ़ाई के लिए, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी।

सभी ब्लाक मुख्यालयों पर सावित्री बाई फुले पुस्तकालय और वाचनालय खोले जायेंगे।

सरकारी विभागों की पदोन्नति में नये पदों का सृजन होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कोरोना के बाद जब लम्पी बीमारी आयी और गौमाता पर संकट आया, बहुत सारी गौमाता मर भी गयी थीं। इस सदन में उस समय चर्चा भी हुई थी। सभी चाहते थे कि गौपालकों को कोई मदद की जाये तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 40 हजार प्रति गाय अनुदान देने की जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है।

बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा पेंशन में वृद्धि की गयी। लम्बे समय से मांग चली आ रही थी कि पेंशन कम है और महंगाई ज्यादा हो गयी। महंगाई को देखते हुए पेंशन में वृद्धि करके मुख्य मंत्रीजी ने अच्छा काम किया है।

किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण वितरण करना, खेत में मकान बनाने पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी देना अच्छी बात है। सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर जोर दिया गया है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से नवीन राजकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की जो घोषणा की है, इससे हमारे बच्चों को बहुत लाभ

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

मिलेगा। 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 300 विद्यालयों में नवीन विषय विज्ञान संकाय खोलना, 01 हजार महात्मा गांधी विद्यालय खोलना और गंगानगर जिले में संस्कृत महाविद्यालय और वेद विद्यालय का खोलना एक बहुत बड़ी बात है। वर्षों से गंगानगर में ऐसा विद्यालय नहीं था, जो कि हमारी संस्कृति को वापस जिंदा करे। यह बहुत ही स्वागत योग्य बात है। स्कूलों में अध्ययनरत असहाय बच्चों को प्रतिदिन दूध, उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए देना, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विकास की नई ऊंचाइयों के उद्देश्य से कई घोषणाएं की हैं।

माननीय सभापति महोदय, हर विधान सभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपये की सड़कें, पेचेबल, नोन-पेचेबल, लिंक रोड है, उनको जोड़ने के लिए जो 10 करोड़ रुपये, 10 करोड़ पिछले बजट में दिये, 10 करोड़ अब दे दिये, तो मैं समझता हूं कि यह काफी बड़ी राशि है।

माननीय सभापति महोदय, शहरों के लिए नगरपालिकाओं को 30 किलोमीटर सड़क, आगे जैसे-जैसे बढ़ता गया, नगर परिषद्, नगर निगम में बड़ी सड़कें दी हैं। नगरपालिकाओं की सड़कें दी हैं, उसके लिए मैं छोटा-सा सुझाव देना चाहूंगा कि पिछले साल की जो घोषणाएं थीं, वे सड़कें अभी बन रही हैं, ऊपर से 20 किलोमीटर की स्वीकृति और आ गयी। इसमें कोई मापदण्ड रखा जाये सरकार की तरफ से, कि जो इस साल बनी हैं, अगले साल उन्हीं को न दिखाया जाये। उनको री-कारपेट करके पैसा नहीं उठाया जाये। कम से कम पांच साल तो वह सड़क चले। उन पैसों से कोई भी मंडी है, नगरपालिका है, उसकी पैरीफेरी में बनाने की इजाजत दे दें तो वहां की सड़कें और बन जायेंगी तो अच्छा काम हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, बजट ऐतिहासिक है, इसमें हर वर्ग को सहायता दी गयी है। जनता के प्रति वे संवेदनशील हैं, जवाबदेही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र करणपुर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत कुछ दिया है जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी छोटी-छोटी दो बातें हैं, वे रह गयी हैं, उनके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र 13 FF माणकसर ब्लाक करणपुर, जिला श्रीगंगानगर को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। यह बहुत बड़ा कस्बा है। पता नहीं ध्यान से निकल गया, वह रह गया।

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

मानीय सभापति महोदय, दूसरा है ज्ञान ज्योति महाविद्यालय का, वह मामला मेरे ख्याल में विचाराधीन है, सरकार कर रही है, वह भी हो जायेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक कस्बा मंडी है, 1942 की नगरपालिका है। वहां नगरपालिका भी है, मंडी समिति भी है, वहां पर सारे दफ्तर हैं, लेकिन वहां उप-तहसील का कार्यालय नहीं है। 20 किलोमीटर दूर किसी भी छोटे-से काम के लिए उनको करणपुर में जाना पड़ता है। उसके चारों तरफ एरिया रायसिंहनगर तहसील का आ जाता है। वहां उप तहसील नहीं बनी हुई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां उप तहसील का कार्यालय खोला जाये। वहां पर आबादी बहुत बढ़ चुकी है और मंडी के छोटेछोटे काम अटके पड़े रहते हैं। वहां से 20 किलोमीटर जाते हैं, आगे कोई अधिकारी मिलता है, कोई नहीं मिलता है और काम नहीं होते हैं। ये दो काम हैं, एक तो 13 FF में उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करना, दूसरा यह उप तहसील का काम। ये दोनों काम, यदि मुख्य मंत्रीजी की कृपा हो जाये तो बड़ी मेहरबानी होगी।

अंत में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धीरेधीरे सभी विभागों में नौकरियां कम होती जा रही हैं। संविदा पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। कहीं एन.जी.ओ. के मार्फत रखे जा रहे हैं। जो संविदा पर रखते हैं इनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। आये दिन सभी माननीय विधायकों के पास लोग ज्ञापन लेकर आते होंगे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाये, हमारा मानदेय बढ़ाया जाये, हमें पक्का किया जाये। पक्का करना, न करना सरकार के नोर्म्स में आता है कि नहीं आता, यह देखें। एक तो इनकी जान एन.जी.ओ. से छुड़वाओ। अगर सरकार उनको 10 हजार रुपया देती है तो एन.जी.ओ. उनको 6 हजार रुपया ही देता है, बीच में 4 हजार एन.जी.ओ. खा जाता है। वे गरीब बच्चे रोते रहते हैं। एन.जी.ओ. से उनकी जान छूट जाये और सरकार जो पैसा देना चाहे, वह व्यवस्था करके सीधा उनको मिले।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर और हनुमानगढ़ में नशामुक्ति केन्द्र खोलने का सरकार ने फैसला किया है। वह इसीलिये किया है कि वहां नशे की प्रवृत्ति ज्यादा है पंजाब के बाद, लेकिन जो नशामुक्ति केन्द्र खुले हैं, उनमें नशा नहीं छुड़ाया जाता। वे वहां पर तीन-चार महीने ही रखते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। 100 में से एक-दो आदमी छोड़ते हैं, चार छोड़ जाते होंगे, लेकिन नशे से मुक्ति पाने के लिए, हमारा बोर्डर एरिया है, पाकिस्तान के साथ

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

लगता है। आये दिन आप पढ़ते हो कि पाकिस्तान से ड्रोन आया और हेरोइन फेंक कर चला गया। सरकार को यह प्रयास करना पड़ेगा कि उस एरिये में अपनी इंटेलीजेंसी बढ़ाये। बोर्डर के थानों में स्टाफ बढ़ाये, ताकि उस पर निगाह रखी जा सके। बाहर से आने वाले तत्वों को रोका जा सके। स्टाफ होगा, इंटेलीजेंसी होगी तो कोई भी नशा बेचने वाला पकड़ा जा सकता है। पकड़े जाने के भय से यह नशा बंद होगा। कैम्प लगाकर बंद करते हुए तो हमें 25-30 साल हो गये देखते हुए, कोई बंद नहीं हुआ।

सभापति महोदय, यही मेरा सरकार से निवेदन था। इस बजट के समर्थन में आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: बिधुरी राजेन्द्र सिंह।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): सभापति महोदय, 2023-24 का बजट जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने पेश किया है, इसमें राजस्थान की तरक्की, राजस्थान की जनता का विकास, राजस्थान के सभी वर्गों का, दलित का, पिछड़ों का, अगड़ों का, छात्रों का, अल्पसंख्यकों का, एस सी, एस टी, बुजुर्गों, महिलाओं, नौजवानों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, संविदा कर्मी और पेंशनधारियों, खिलाड़ियों और दिव्यांगों सभी का ख्याल रखते हुए एक शानदार बजट पेश किया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा पेश 2023-24 बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और समर्थन करता हूं। हमारे सदन के नेता और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को हर महीने एक किलो दाल, चीनी, गेहूं, तेल और नमक का पैकेट फ्री देना, बीपीएल परिवारों को, उज्ज्वला योजना के परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर देना, 100 यूनिट की बजाय 300 यूनिट, 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को फ्री देना और 15 लाख परिवारों को 300 से 700 रुपये की छूट देना, ओल्ड पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों के लिए लागू करना, युवाओं के लिए 500 करोड़ का विकास कोष गठित करना, 1 लाख 42 हजार नौकरियां देना, 1 लाख 82 हजार नियुक्तियां प्रक्रियाधीन करना, आनलाइन एग्जाम के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च करना, जॉब ओरियंटेड के लिए मेगा फेयर लगाना जिससे हमारे राजस्थान के नौजवानों को नौकरियां मिल सकें। उन फेयर में जाकर के सलेक्शन हो सके।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

प्रोफेशनल और कंपीटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए 30 हजार स्टूडेंट्स का सलेक्शन करना, हर जिले में 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद होस्टल बनाना, युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 लाख तक की छूट देना, प्रदेश में युवाओं को उद्योग लगाने के लिए स्टार्ट अप एवं उद्योग के लिए 200 करोड़ का आरसीवीआई के तहत उपलब्ध कराना। मैचिंग शेयर की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 01 करोड़ देना। राजस्थान के नौजवानों के लिए जो कोई कुछ भी करना चाहता है, उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी वर्गों को जोड़कर, छात्रों को, किसानों को, 2 हजार तक यूनिट किसानों को फ्री देना, किसानों के बिजली के बिल माफ करना, किसानों के कर्जे माफ करना, किसान कल्याण कोष को 5 हजार करोड़ से 7 हजार करोड़ करना, ऐसा बजट न भूत में किसी ने दिया है, न तो भविष्य में कोई देगा।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो पिछले 4 बजट पेश किये हैं, उन सब बजटों को हमने क्रियान्वित किया है। जो हमने घोषणाएं की हैं उनको हमने बजट से पहले सबको पूरा कर दिया है। इस बजट की घोषणाओं के लिए अभी से काम चालू कर दिया है। सभी बजट की घोषणाओं का काम समय से पहले पूरा कर देंगे।

सभापति महोदय, इस बजट में विकलांग, दिव्यांग, बुढ़ापा पेंशन, डायवर्सी महिलाओं के लिए 750 रुपये से बढ़ाकर 01 हजार रुपये तक कर दी है। उन्होंने राजस्थान का गार्जियन होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते हर वर्ग का ख्याल रखा है। एससी, एसटी के लिए 500 करोड़ से बढ़ाकर 01 हजार करोड़ रुपये कर दिये। एम बी सी, ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस, माइनोरिटी विकास कोष की राशि 200 करोड़ कर दी।

सफाई कर्मचारी जिनकी कोई सुध नहीं लेता, महर्षि वाल्मीकि कोष को 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया। 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी, जिससे जो शहर की समस्या बहुत समय से अटकी पड़ी थी, उनको दूर किया जा सके।

हर सम्भाग में महिलाओं के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए जिलों में 50 कमरों के और सम्भाग पर 100 कमरे के होस्टल बनेंगे। बसों में किराये पर 50 परसेंट की छूट कर दी। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को 18 साल का होने के बाद सरकारी नौकरियां मिलेंगी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए एलएलए, सीएसआर फंड में 25 लाख की राशि बढ़ाकर 01 करोड़ कर दी।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

ट्यूरिज्म के लिए हमने 01 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये कर दिये, जिससे कि राजस्थान का ट्यूरिज्म बढ़े, ट्यूरिज्म का विकास हो और राजस्थान के नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया हो सकें।

पशुओं में गौ हमारी माता है। लम्पी में जब हमारी गायें मर जाती हैं या सड़क पर गाय का एक्सीडेंट हो जाता है तो माता कहने वाले भी माता को अर्थी पर कंधा नहीं देते हैं लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने गौ माता का सम्मान करते हुए लम्पी में गायों की मृत्यु पर हर पशु पालक को 40 हजार रुपये की सहायता दी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की गौ माता के प्रति प्यार और हिन्दुस्तान की जननी गाय माता को प्यार के प्रति उनका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, सड़क के विकास के लिए 53 हजार किलोमीटर राजस्थान में ग्रामीण, शहरी, राष्ट्रीय एवं राजमार्ग की सड़कें बनेंगी। इस पर 24 हजार करोड़ रुपये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने खर्च किये हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक पक्ष बजट के खिलाफ बोलता है। एक उसका विरोध करता है तो एक समर्थन करता है।

हम सब हिन्दुस्तानी हैं। हम सब भारतीय हैं। हम भारत के लोग हैं। हजारों वर्ष पहले, 536 ईसा पूर्व भारत पर फारस के राजा दारा-फर्स्ट ने आक्रमण किया था। वह सिंध तक बढ़ पाये थे। हिन्दुस्तान की जनता ने मुकाबला किया तो दारा-फर्स्ट को वापस जाना पड़ा।

उसके बाद भारत पर सिकन्दर का आक्रमण हुआ। एकजुट हिन्दुस्तान लड़ा। कुछ हमारे अंदर जयचन्द भी थे। कुछ आम्भी जैसे नरेश भी थे। लेकिन पोरस जैसे महान सम्राट ने उसका मुकाबला किया। पंजाब में झेलम एक छोटा राज्य था। खोखरों से युद्ध करते हुए जब सिकन्दर झेलम तक बढ़ा तो बूढ़े पोरस ने उसका मुकाबला किया। हार हुई, लेकिन भारत के महान सम्राट पोरस ने एक सम्मानित जिंदगी जीते हुए सिकन्दर से कहा कि राजा का एक सम्मान होता है, उसी तरीके से मेरे साथ बिहेव किया जाये। सिकन्दर को इतनी क्षति पहुंचायी कि सिकन्दर सिंध के रास्ते होते हुए बेबीलोन चला गया, जहां उनका स्वर्गवास हो गया।

हिन्दुस्तान कभी कमजोर नहीं रहा। विदेशी आक्रमणकारियों में यूनानियों के बाद भारत पर शकों के आक्रमण हुए। यूचिज के कुषाणों के

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

आक्रमण हुए। हूणों के आक्रमण हुए। पार्थियन के आक्रमण हुए। मंगोलों के आक्रमण हुए। तुर्कों के आक्रमण हुए। भारत ने हमेशा उनका मुकाबला किया। पूरा भारत टुकड़ों में लड़ा, लेकिन हमने हरेक का मुकाबला किया।

जो विदेशी जातियां शक और सीथियन, हूण आदि, जो हिन्दुस्तान पर आक्रमणकारी ट्राइब्स थीं, वे भारत माता की गोद में आकर भारतीय लोगों में शामिल हो गयीं। भारत माता का इतना प्यार मिलता है कि जो भी विदेशी आक्रमणकारी आया, वह यहां पर रहकर भारत की संस्कृति में ही घुल मिल गया। उसने हर विदेशी का मुकाबला किया।

हिन्दुस्तान में अगर हम आज आपस में बंटते रहेंगे, कोई हिन्दू रहेगा, कोई मुसलमान रहेगा, कोई सिख रहेगा तो हमारा देश कमजोर होगा। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी, हमने तुर्कों से लड़ाई लड़ी, एक हजार साल के संघर्ष के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। 1857 में मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की क्रांति और मेरठ की बिठूनी हुई, गदर हुआ। बहादुर शाह जफर, एक मुसलमान राजा के नेतृत्व में एक मशाल हम सब हिन्दुओं ने, वल्लभगढ़ के जाटों ने, दादरी के गुर्जरों ने और भिवाड़ी और रेवाड़ी के अहीरों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। (व्यवधान) कुछ ज्ञान सीख लो भाइयों। कुछ सोच लो भारत कैसा बनाना है। (व्यवधान) आएंगे, सरदार पटेल पर भी आएंगे। (व्यवधान) बैठ जाओ, भाई साहब, कुछ ज्ञान ले लो। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, भारत बना, हमने लड़ाई लड़ी। शक भी हिन्दू बन गये। मेरा गौत्र हूण है, हम भी हिन्दू बन गये। सब शामिल हो गये। मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि हिन्दूमुसलमान मत करो। हम सब पहले क्या थे, रियासतों, सब समझ लो, किताबें पढ़ लो। आगे 1857 की क्रांति में हार गये, सबने मिलकर, देशी रिसायतों ने, झांसी की रानी, तात्यां टोपे, राव नाहर सिंह, उमराव सिंह भाटी, राव तुलाराम हो, सबके, दिल्ली के इर्द-गिर्द बूढ़े बहादुर शाह जफर को देश का राजा बना दिया। मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली-शाहजहांपुर के आसपास थी। हम लड़ाई हार गये। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के बाद देश आजाद हुआ। चन्द्रशेखर आजाद, ऊधम सिंह, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, लाला लाजपतराय, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाखां, सब हिन्दुस्तानियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराबा,

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

खुदीराम बोस ने हिन्दुस्तान को आजाद कराया। आईएनए बनाई गई, गांधीजी ने जन आंदोलन किए, भगत सिंह ने जैसे शहीद होने के लिए अपनी जान पर खेलकर, ऊधम सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, अपनी जान की कुर्बानी देकर, 1947 में 15 अगस्त को हिन्दुस्तान को आजाद कराया। अंग्रेजों ने हमें टूटा भारत दिया। भारत के दो टुकड़े कर दिये, 14 अगस्त को पाकिस्तान जैसा एक नया देश बना दिया। देश की जनता की अदला-बदली हुई, राज तो बदले लेकिन जनता भी बदली। हिन्दू उधर से इधर माइग्रेट हुए और मुसलमान धर्म के नाम पर दो देश बन गये, लेकिन भारत का नेतृत्व इतना मजबूत था कि 3 करोड़ की आबादी को नेहरूजी और सरदार पटेल के नेतृत्व में उनको सही जगह पर बसाया गया और सरदार पटेल ने 600 से ज्यादा रियासतों को इकट्ठा करके अखंड भारत दिया। वे भी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, क्या हो रहा है यह? (व्यवधान) इंटरवीन न करें बीच में। इनका अपना समय है। आपने तो बोल दिया है।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, यह जो देश दिया है, वह सरदार पटेल ने दिया है। यह मुल्क जो दिया है, हिन्दुस्तान जो दिया है, भारत जो दिया है, ये सरदार पटेल की देन है। सरदार पटेल की वजह से, पंडित जवाहर लाल नेहरू की वजह से इस देश की तरक्की हुई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप तो यह बता दो कि यह बजट किसकी देन है? (व्यवधान)

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): एक मिनट। राठौड़ साहब, आप बैठिए। सरदार पटेल कांग्रेस के गृह मंत्री थे, नेहरूजी के नेतृत्व में देश का एकीकरण किया। प्रिवीपर्स बंद किया। राजाओं को जोड़कर भारत को बनाया। (व्यवधान)

श्री सभापति: पहली बार बोल रहे हैं, बोलने दो। पहली बार बोल रहे हैं।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा हिन्दुस्तान दिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। बंटवारा जो किया अंग्रेजों ने किया और हिन्दुस्तान के जो राजनीतिक लोग थे, जो आज आप लोग आपस में कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हो, हिन्दुस्तान की आन अगर पानीपत की लड़ाई में अगर मराठों की गद्दारी नहीं होती, मराठों की फौज के बारे में हिन्दू-मुसलमान करते हो, मराठी तोपखाने का सेनापति, इब्राहिम गार्दी था।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

महाराणा प्रताप की फौज का सेनापति कौन था, हकीम खां सूरी, एक मुसलमान था। अकबर की फौज का सेनापति एक हिन्दू था। अगर इतिहास में पीछे जाओगे तो देश के टुकड़े कर लोगे। इतिहास को बनाओ। सरदार पटेल ने इतिहास बनाया है। वो कांग्रेस के गृह मंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के निर्माता हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी का जो एकीकरण किया, उससे भी बड़ा काम सरदार पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर को हिन्दुस्तान में कबायली फौज के साथ में कंगन में मुस्लिम गुर्जरों की फौज बनाकर पाकिस्तान के कबाइलियों को खदेड़ा। लिखा हुआ है, पढ़ो, आईने-कश्मीर के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम हैदराबाद को भारत में शामिल कराया, जूनागढ़ को भारत में शामिल कराया। सारी देशी रियासतों को जोड़कर एक हिन्दुस्तान बनाया, वह भी एक किसान का बेटा था। आज भारत की आजादी को 75 साल से ऊपर हो गये, हमारे शहीदों ने, हमारे उन क्रांतिकारी नेताओं ने हमें एक सुन्दर हिन्दुस्तान दिया है, उसको हिन्दू-मुसलमान में नहीं बांटें। उसको हम सिख, ईसाई में नहीं बांटें। हम सब हिन्दुस्तानी हैं, कांग्रेस और बीजेपी में मत बांटों। 1947 से पहले, 1980 से पहले बीजेपी नहीं थी। सदियों का हिन्दुस्तान है, हमें आगे भी चलना है। हमें आगे तक हिन्दुस्तान को कायम रखना है, हमारे मतभेद हो सकते हैं। हमारे आपस में मनभेद नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग भी अपनी बात कह रहे हैं और आप भी अपनी बात कह रहे हैं। यदि केवल बजट पर ही बात करेंगे तो आप सबका विलोपित करना पड़ेगा। (व्यवधान) फिर तो एकाध लोग हैं जिन्होंने बजट पर अपनी बात कही है। (व्यवधान) प्लीज।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट दिया है, हम पक्ष-विपक्ष को उसकी तारीफ करनी चाहिए। (व्यवधान) बैठ जाइए आप। आपको कोई नॉलेज नहीं है।

आप अटल बिहारी वाजपेयीजी का 1977 का भाषण पढ़ो। आप गये हो कभी अफगानिस्तान? विदेश मंत्री थे, क्या कहा था उन्होंने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में? कनिष्क होटल के अंदर ठहरे थे। गये हो आप कभी अफगानिस्तान? गये हो?

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): जाएंगे भी नहीं। आप जाओ।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): जाना। (व्यवधान) जाना। छोड़िए, आपके मोदी भी जाकर आये हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे, छोड़िए। बातें मत कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, क्या बोला अटल बिहारी वाजपेयीजी ने? मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, सुनिए तो सही, आप उस पार्टी के मेम्बर हो। उन्होंने कहा था कि कनिष्क होटल? कनिष्क तो भारत का राजा था। अटलजी ने वहां पर स्पीच दी थी कि कनिष्क तो हमारा पुरखा था। अटलजी की स्पीच निकालकर पढ़िए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीजी महान नेता थे। कनिष्क अफगानिस्तान का भी पुरखा था। कनिष्क की राजधानी मथुरा और पुरुषपुर-पेशावर, पाकिस्तान में भी है। कनिष्क की तारीफ की कि हमारे पुरखे एक थे। धर्म बदल गया तो क्या हुआ, पूर्वज तो हमारे एक थे। उनका भाषण सुनो। (व्यवधान) हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। आपने क्या किया? पाकिस्तान से मार खाई? (व्यवधान) सुनिए तो सही। 1971 की लड़ाई में (व्यवधान) एक मिनट बैठिए नेताजी। माननीय सभापति महोदय, इनको बैठाइए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, वे कांग्रेस की प्रधान मंत्री 'दुर्गा' थी। अटलजी ने 'दुर्गा' बोला, 'दुर्गा'। हमने बांग्लादेश जैसा नया देश बनाया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आप समय तय कर दें कि विधान सभा में यदि कोई काम नहीं हो तो बिधुरीजी का भाषण होगा। आप समय तय कर दें। आज तो बजट पर बहस करा दो। (व्यवधान)

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, हमने बांग्लादेश जैसा देश बनाया, हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। जनरल अरोड़ा ने जनरल नियाजी को पाकिस्तान की एक लाख फौज के साथ पकड़ा। (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो आप? आपको नॉलेज नहीं है। एक लाख की फौज को पकड़ा था। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संजयजी, आप अपने स्थान पर जाइए। (व्यवधान)

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): हमने भुट्टो को बुलाया शिमला समझौते करने के लिए और आपने मुशर्रफ को यहां बुलाया। करगिल कराया, शहीदों को कुर्बानी देनी पड़ी अपनी जानों की। आपके परिवार में कोई फौज में नहीं होगा। आपको सैनिकों की क्या चिंता, जो इधर बैठे हैं, किसान का एक बेटा खेती में काम करता है और दूसरा देश पर जान देता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: टाइम दिया है, पार्टी ने टाइम दिया है, मैं क्या करूंगा? (व्यवधान)

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, वे होली-दीपावली नहीं मनाते और देश की रक्षा करते हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, आज तो कमाल कर दिया।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): आप बार-बार हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई करते रहोगे, देश को बांटते रहोगे, देश को तोड़ते रहोगे, आप अपने नेताओं की बात को याद रखो, जिन्होंने देश को बांटा है। इंदिरा गांधीजी ने सिक्किम को 22वां राज्य बनाया। (व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ सीख लो, जानकारी नहीं है तो इतिहास की बात बता रहे हैं, कुछ सीख लो।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): सिक्किम को 22वां राज्य बनाया।

चीन सिक्किम को भारत से छीनना चाहता था। इन्दिरा गांधी जैसी नेता ने सिक्किम को 22वां राज्य बनाया है। उस वक्त हिन्दुस्तान में 21 राज्य होते थे।

जब भारत में गेहूं पैदा नहीं होता था, पंजाब और हरियाणा में रेगिस्तान के टिब्बे होते थे, इन्दिरा गांधी ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आयीं। आज जो इतना अनाज हम हिन्दुस्तान में पैदा करते हैं, वह इन्दिरा गांधी की देन है। डीआरडीओ की स्थापना नेहरू जी ने की। जेएनयू की स्थापना नेहरू जी ने की। पोखरण का बम विस्फोट इन्दिरा गांधी ने किया और अमरीका के सेवंथ फ्लीट को वापस इन्दिरा गांधी ने भेजा। इन्दिरा गांधी जैसी नेता अमरीका जैसे देश से नहीं डरी। (व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें। समय की सीमा है।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): सभापति महोदय, ये तो बोलते रहते हैं। हमने बोकारो जैसे स्टील प्लांट खोले, जहां चालीस हजार लोग नौकरी करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। (व्यवधान)

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): आपके पास कोई जवाब नहीं। विकास की कोई परिकल्पना नहीं। आपका काम सिर्फ विरोध करना, देश को बांटना, देश को तोड़ना और भाई को भाई से लड़ाना है। (व्यवधान) सभापति महोदय, आप इन्हें याद दिलाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): त्राहिमाम, त्राहिमाम। सभापति महोदय, त्राहिमाम। (व्यवधान)

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): सभापति महोदय, आज राहुल गांधी जी ने एक सन्देश दिया है, हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नफरत छोड़ो, भारत को जोड़ो। (व्यवधान) भारत को जोड़कर रखें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। समय की सीमा है। विराजिये।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): सभापति महोदय, मैं यह बात कह रहा हूं कि हम सब अपने देश की तरक्की करें। हम आपस में बीजेपी-कांग्रेस नहीं करें। देश को नहीं बांटें। 135 करोड़ हिन्दुस्तानी एक हैं। इस लोकतंत्र की परिकल्पना क्या है? आज चाय बेचने वाला भी, दूध बेचने वाला भी, सब्जी बेचने वाला भी, किसान का बेटा भी इस लोकतंत्र की वजह से प्रधान मंत्री बन सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी संविधान सभा, जो संविधान की ताकत है, हमारा लोकतंत्र है, आज गरीब का बच्चा भी मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री बन सकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज। प्लीज सहयोग करें।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): हमारे नरेन्द्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चौधरी चरण सिंह जी, कोई भी किसान का बेटा प्रधान मंत्री बन सकता है। यह एक लोकतंत्र की गरिमा है।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): सभापति जी, एक मिनट। (व्यवधान) राठौड़ साहब, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा जनता के वोट से पैदा होता है। लोकतंत्र की ताकत है यह। पहले राज तलवार की ताकत पर छीन लिए जाते थे, लेकिन आज राज परिवर्तन वोट की ताकत पर होता है और वोट की ताकत पर ही राजा बनता है।

श्री सभापति: प्लीज विराजिये।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता का ख्याल रखा। (व्यवधान) मैं अपने भाइयों के लिए एक शेर सुनाता हूं।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सर, एक ही मिनट। ये पहली बार बोल रहे हैं।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): पहली बार बोल रहा हूं, भाई साहब।

श्री सभापति: पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन समय की सीमा है। ऐसे नहीं। महेन्द्र जी, ऐसे नहीं। समय की सीमा है।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): (व्यवधान) एक मिनट सुन तो लें। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। सुन लें।

उनकी तुरबत पर नहीं है एक भी दीया,
जिनके खूं से जलते थे चिराग-ए-वतन।
जगमगा रहे हैं मकबरे उनके,
बेचा करते थे जो शहीदों के कफन।।

जो शहीदों के कफन बेचते थे वे राज में हैं, मजे ले रहे हैं। शहीदों के परिवार भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, सरदार पटेल, चन्द्रशेखर आजाद। आप उस पार्टी के लोग हैं, स्टेट के मुख्य मंत्री ने चन्द्रशेखर आजाद जैसे क्रान्तिकारी को आतंकवादी बोला था, सत्ता की साझेदारी की थी यूपी के अन्दर।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आप हम से कहते हैं, "अंकित नहीं होगा", वैसे ही अभी कह दें, "अंकित नहीं होगा।"

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं होगा अब।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): 000

श्री सभापति: उप-सचेतक महोदय, प्लीज। अब अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, प्लीज विराजिये।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): 000

(माननीय सदस्य श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह के सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कृपया विराजिये, बिधुरी साहब। यह उचित नहीं है। तुष्टीकरण की साम्प्रदायिक आग में पूरे राजस्थान को आपने फेंका है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। आप भी विराजिये। आप सब लोगों के आग्रह पर मैं एक दिन इन्हें अलग से खड़ा कर दूंगा, ताकि आप लोगों के ज्ञान में भी वृद्धि हो जाये। श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आय-व्ययक पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, कितने समय तक मुझे बोलना है, जिससे उससे पूर्व ही मैं बैठ जाऊं, कृपया आप बता दें। माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण पर आपने मुझे बहस का अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, 10 फरवरी, 2023 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्य का पांचवां बजट सदन में प्रस्तुत किया। सरकार व जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण और मुख्य मंत्री जी की बजट से अनभिज्ञता के चलते वह दिन राजस्थान की विधान सभा का काला अध्याय बन गया। आजादी के बाद देश के किसी राज्य में ऐसी भीषण लापरवाही नहीं हुई होगी कि बजट जो कि एक गोपनीय दस्तावेज होता है, उसमें पिछला बजट पढ़कर सुनाया गया हो। मुख्य मंत्री जी द्वारा जो पुराने बजट का वाचन किया गया, सम्पूर्ण देश में हास-परिहास के रूप में इस बजट भाषण को देखा जा रहा है। इस घटना से हमारी, आप लोगों की और पूरे राजस्थानवासियों की किरकिरी पूरे देशभर में हो रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शान्ति रखें। आपस में वार्ता नहीं। वक्ता को अपनी बात कहने दें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): बजट तो वैसा ही है, जैसा हमारी पूर्व की कल्पना थी। बुद्धिजीवी वर्ग, राजनैतिक वर्ग, सबको अनुमान था कि यह बजट चुनावी बजट होगा और एक तरीके से पूर्णत: ऐसी घोषणाओं का बजट होगा, जिसमें असत्य के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बजट जो पढ़ा गया, उसकी आज गलियों में, मोहल्लों में, पार्कों में, मन्दिर के चबूतरों पर, आफिस के गलियारों में, चहुंओर आम अवाम में इस बात की चर्चा है कि यह सम्पूर्ण राजस्थान में जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है, ऐसा असमंजस और ऐसा अविश्वसनीयता वाला यह बजट है। जनता जनार्दन पशोपेश में है कि

(श्री संदीप शर्मा)

कैसे आठ माह के अन्दर इतनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं, इतने बड़े-बड़े वादे माननीय मुख्य मंत्री जी पूरा कर पाएंगे। छह महीने में क्योंकि 45 दिन पूर्व तो आचार संहिता लग जाती है।

मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैंने 2028 का बजट पहले ही पढ़ दिया। यह भी सम्भव हो सकता है। किसी भी देश या राज्य का बजट वहां की सकल आय और उसके अनुपात में खर्चा हो, इस भाव से निर्धारित किया जाता है। ऋण कम से कम लिए जाएं, जिससे प्रदेशवासियों के ऊपर अनावश्यक बोझ न आये। ऐसा प्रयास बजट में किया जाता है और देश और प्रदेश का स्वर्णिम व सुदृढ़ भविष्य भी इस बजट के माध्यम से हम तय करते हैं।

उच्च कोटि के विचारवान जो राजनीतिक दल हैं, जिनके विचार हैं वे अपने बजट का निर्धारण इस प्रकार से करते हैं कि आने वाली पीढ़ी पर भी इस बजट का प्रभाव सार्थकता के साथ पड़े। ऐसा ही लोक कल्याणकारी बजट 01 फरवरी को केन्द्र सरकार की केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। सम्पूर्ण देशवासियों के सर्वांगीण उत्थान के साथ नव-भारत के निर्माण की परिकल्पना, वर्तमान की आर्थिक विषमताओं से देश को उबारते हुए आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सुनहरे और मजबूत राष्ट्र प्रदान करने का दृढ़ संकल्पित इरादों वाला बजट माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पूरे देश को समर्पित किया। वहीं दूसरी ओर जो राजस्थान का हमारा बजट रहा और इस बजट की जो घोषणाएं हुईं यदि यह बजट लागू होता है तो राजस्थान को 5 लाख 80 हजार करोड़ की देनदारियों, ऋण के नीचे आना पड़ेगा और एक व्यक्ति को, एक परिवार को लगभग 5 से 7 लाख रुपये का ऋण चुकाना पड़ेगा। यह जो आपका लोक-लुभावन, मनभावन बजट है, जिसके लिए आपने तालियां बजवायीं, वाहवाही करवायीं उससे आप प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और यह प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा दण्ड राजस्थान की इस विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा दिया गया है।

आपने कोई आय के साधन सृजित नहीं किये तथा आप सिर्फ लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स लगाकर इस ऋण को चुकाओगे। आपके पास आय के साधन नगण्य हैं, आपके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है तो किस तरीके से आप अपने इस बजट को पूरा करेंगे, इस बात को लेकर आज पूरे प्रदेशवासी पशोपेश में हैं तथा जगह-जगह इसकी चर्चा कर रहे हैं।

(श्री संदीप शर्मा)

चिरंजीवी योजना में जो आपने बजट घोषणा में इलाज की सीमा 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी। पहले 10 लाख रुपये थी तभी प्राइवेट चिकित्सक, प्राइवेट हास्पिटल गरीब का, पीड़ित का, रोगी का उपचार अपने चिकित्सालयों में नहीं करते थे और इस 25 लाख रुपये के बाद तो उस प्राइवेट चिकित्सालय में उस गरीब, पीड़ित, मरीज, बीमार आदमी को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। आपके मेडिकल बिल का विरोध पूरे राजस्थान भर में चल रहा है क्योंकि आपने गलत नीतियों के हिसाब से मेडिकल बिल को बनाया है।

आपके पुराने बजट की आधी से ज्यादा घोषणाएं अभी तक भी आप पूरी नहीं कर पाये हैं। आप सिर्फ जनता को गुमराह कर सकते हैं जैसे 2018 में चुनावी वायदों के समय आपने किया, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। अब राजस्थान की जनता गुमराह होने वाली नहीं है।

कोटा शहर की तो आपके पिछले बजट की घोषणाएं भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। 10 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा में आपने पीडब्ल्यूडी को आदेश दिये थे, परन्तु एक रुपये का काम हुआ हो तो, सभापति महोदय, आप आकर देख लेना। उस 10 करोड़ रुपये में से एक पैसे का काम कोटा के किसी विधान सभा क्षेत्र में नहीं हुआ। कोटा में मिनी सचिवालय को लेकर आपने सदन में आश्वस्त किया था, पर बजट में वह कहीं दिखायी नहीं दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया। आपके द्वारा गत वर्ष कोटा में केडीए बनाने की घोषणा की गयी थी। कोटा में यह स्थिति है कि कोटा डवलपमेंट अथोरिटी के नाम पर यूआईटी 1300 करोड़ रुपये का बजट खर्च कर रही है जो कि जोधपुर और अजमेर के बजट से कई गुना अधिक है। आज स्वायत्त शासन मंत्री जी खुद कोटा से आते हैं तो निश्चित रूप से इसमें उनको संज्ञान लेना चाहिए। कोटा के तीनों डैम, गांधीसागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा-बैराज डैम को बने हुए वर्षों हो गये, जिनकी मियाद पूरी हो गई और इंजीनियरों ने नोटिस दे दिये कि इनकी दीवारों में दरार आ गई है और बरसात में जब ये लबालब भरे रहते हैं तो कभी भी ये टूट जाएंगे पर उस पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहां पर तो 5 हजार करोड़ रुपये से रिवर फ्रंट बन रहा है जिसमें हजारों-करोड़ रुपया बर्बाद किया जा रहा है।

कोटा शहर में 150 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशलिटी विंग चार वर्षों से तैयार खड़ी है, पर उसमें आप सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं लगा पा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, वहां पर यह स्थिति है कि वहां पर सुपर स्पेशलिस्ट

(श्री संदीप शर्मा)

डाक्टर नहीं लगाये जाने के कारण वह सुपर स्पेशलिटी पूरी तरह से चलती नहीं है। वहां पर संसाधन नहीं दे पाये हैं। कैथ लैब को वहां दस साल हो गये हैं, इसलिए उस कैथ लैब को रिन्यू करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से पिछली गवर्नमेंट में हमने मेडिकल कालेज में 29 करोड़ से द्वितीय तल बना दिया था, पर वहां चिकित्सक नहीं है, स्टाफ नहीं है, बेड नहीं है और लोग-बाग़ गैलरियों में अपना इलाज करा रहे हैं। आप अबकी बार पधारेंगे तो मैं लेकर चलूंगा।

श्री सभापति: इसको टेबल कर दें आप।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जो मैं बात बता रहा हूं वह एकदम सत्य बात बता रहा हूं। चम्बल किनारे स्थित कोटा शहर में आप शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। 40-40 साल से पाइप लाइनें टूटी पड़ी हैं और 40 साल से पाइप लाइनें बिछी नहीं हैं। कम से कम 40 से 50 प्रतिशत शुद्ध पेयजल का पानी व्यर्थ बह जाता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हां, दो मिनट में बोल लूं।

जो दो लाख बच्चे पूरे देश से कोटा शहर में पढ़ने आते हैं वे आपके राजस्थान की क्या छवि लेकर जाते हैं। जितना पैसा आपने कोटा के सौंदर्यीकरण में खर्च किया, उसके थोड़े से अंश में भगवान मथुराधीश जी, जो वल्लभ सम्प्रदाय की प्रथम पीठ है, उनका जीर्णोद्धार हो जाता तो निश्चित रूप से कोटा धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित हो जाता।

माननीय सभापति महोदय, कोटा एयरपोर्ट की बात करूं तो कोटा एयरपोर्ट में केन्द्र सरकार द्वारा सारी फार्मेलिटीज पूरी कर ली गयी हैं। आपने जो भूमि दी वह वन विभाग में दे दी। हमारे लोक सभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने वन विभाग से निकालकर उसको फ्री किया।

श्री सभापति: श्री राकेश पारीक।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): एक सैकण्ड में, साहब।

अब जो राज्य सरकार को पैसा देना है, वह पैसा दे दे जिससे कोटा में एयरपोर्ट प्रारम्भ हो जाए। वैसे आपने 8 मिनट भी नहीं बोलने दिया तो मेरे से तो आपकी बहुत नाराजगी है साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। आप पर खूब आशीर्वाद है, आप तो आराम से रहें। पारीक साहब, एक मिनट विराजें आप।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय सात बजे तक बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया गया।

श्री राकेश पारीक।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट पर बहस हो रही है और उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने गांव, गरीब और तमाम उन सब लोगों को इस बजट में सहायता दी है, जिनकी नजर थी कि केन्द्र सरकार का बजट पेश हो रहा है और उसके ठीक दस दिन बाद राजस्थान सरकार का बजट पेश होगा, उसमें क्या हमें सहायता मिलेगी, क्या हमारे लिए फायदा होगा। बहुत अच्छे-अच्छे बोलते हैं, बड़े-बड़े विद्वान हैं, वे तो चले गये। वे बड़े-बड़े विद्वान हैं। उस गैस की टंकी का क्या उपयोग हो रहा था? अभी कुनर साहब बता रहे थे कि गरीब आदमी की भी आदत बिगड़ गई कि वह गैस के चूल्हे के अलावा रोटी नहीं बना पा रहा था, पर वह वापस लकड़ी काटकर किसी ढंग से वे लोग काम कर रहे थे। वे सब लोग राजस्थान की कांग्रेस सरकार को दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यह जो मोदी जी का उलटा पड़ा हुआ गैस का चूल्हा था और जो टंकी थी, उसको उलटा रखकर उस पर मटकी रखकर पानी पी रहे थे। हम धन्यवाद करेंगे आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय का कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा तो आदमी वापस हिम्मत कर सकता है। आज महिलाएं बस में बैठकर जाती हैं। अभी ये बोल रहे थे कि रेवड़ी है, रेवड़ी नहीं है, उसका बस में आधा किराया लग रहा है। वे दुआएं देंगी। दिलावरजी की बीवी तो बस में बैठती नहीं हैं और बैठती होंगी तो एमएलए के

(श्री राकेश पारीक)

कूपन से बैठती होंगी। गांव की गरीब औरत, मां, बहन दुआ देंगी कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हमारे लिए सोचा है।

चिरंजीवी योजना, आज इस योजना के माध्यम से पूरे देश में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बड़ाई हो रही है। बेनीवालजी, गरीब आदमी इलाज करवाने जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? उन्होंने आज 25 लाख रुपये तक के इलाज का प्रावधान किया है। इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यह गांव और गरीब के लिए किया है।

नरेगा जैसी स्कीम शहरों में चालू की है। आज शहर में और गांवों में भी नरेगा की स्कीम को बहुत तेजी से, पहले बीजेपी का राज था, आप लोग ही होंगे। आप पहले एमएलए नहीं थे, गोपालजी, सुनें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं करें। आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): सन् 2018 के बाद नरेगा तेजी से चली और गांव और गरीब आदमी को जिस ढंग से जीने का हक मिला है, सौ, सवा सौ दिन नरेगा में काट रहे हैं। नरेगा से कोरोना जैसी महामारी में लोगों ने पेट भरा है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, योजनाएं कितनी बतायें। सरकार ने हमें इतनी योजनाएं पांचवें बजट तक दी हैं। आज किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है।

जहां तक चार बजट पूरे हुए हैं। उन बजटों से सरकार ने ऐसे विकास के काम किये जो आज तक उन इलाकों में नहीं हुए। कालेज खोले, स्कूल खोले, रोड बनाई, पेयजल के लिए जल जीवन मिशन में पैसा भी दिया। मैं इन तमाम कामों के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में पांच महत्वपूर्ण काम मेरे इलाके में हुए हैं। बिजयनगर में उप जिला चिकित्सालय खोला गया, रामगढ़ में पुलिस चौकी बनाई, सरकार ने मेरे इलाके में दो रोड कादोलाई से देवलिया कलां और एक भिनाय से बिजयनगर दी है। सरकार ने मेरे भिनाय के अन्दर एक न्यायालय खोला। इन तमाम चीजों के लिए मैं राजस्थान सरकार और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा।

मैं मेरे इलाके की कुछ मांगें हैं, लिखकर लाया हूं। मेरी इच्छा है कि मेरे यहां बांदनवाड़ा में एक कन्या महाविद्यालय खोला जाए। सरकार ने हमारे

(श्री राकेश पारीक)

बच्चों के लिए तो दो महाविद्यालय भिनाय और बिजयनगर में खोले थे, लेकिन इलाके की मांग है कि हमारे बांदनवाड़ा में एक कन्या महाविद्यालय खोला जाए। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इसी बजट में बांदनवाड़ा में कन्या महाविद्यालय खोला जाए।

मेरे इलाके में रोड्स दी हैं, लेकिन मसूदा से बागसूरी, देवलिया से बिजयनगर, गणा से जबरकिया और कादोलाई से जैतपुरा की रोड भी इस बजट में देने के लिए मैं आपके मार्फत मांग करूंगा। हमारे यहां पर इन रोड्स का भी विस्तार किया जाए।

मेरी मसूदा तहसील के अन्दर दो उप तहसीलों का निर्माण किया जाए। मैंने सी.एम. साहब को ज्ञापन भी दिया है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि मसूदा में दो उप तहसीलें खोली जाएं।

स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि मेरा बड़ा पहाड़ी इलाका है, वीरों की धरती है, अब तक मेरे इलाके से देश की आजादी में 23 शहीद हो चुके, मेरा मगरा भी है, पहाड़ी इलाका भी है, मैदानी इलाका भी है, मेरी सात पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए। तीन उप केन्द्रों को पीएचसी बनाया जाए। मेरे यहां भिनाय बहुत बड़ी जगह है, पंचायत समिति हैडक्वार्टर है। मेरी आपसे मांग है कि भिनाय के अन्दर सीएचसी में 20 बेड और बढ़ाये जाएं। अभी 30 बेड्स हैं, उनको 50 किया जाए। भिनाय और बिजयनगर में 132 केवी जीएसएस खोला जाए। 10 प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। 10 उच्च प्राथमिक शाला से उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया जाए। नई 8 प्राथमिक शालाएं खोली जाएं। पंचायत समिति, भिनाय बहुत पुरानी पंचायत है, उसका भवन बहुत पुराना है, वह जर्जर हो गया है, सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि उस भवन का नव निर्माण कराया जाए।

हमारे यहां पर जालिया सैकण्ड में संस्कृत महाविद्यालय है। मैं आपसे मांग करूंगा कि वह संस्कृत महाविद्यालय बिना किसी अनुदान के प्राइवेट की तरह गांव वाले चलाते हैं, उसको रिटायर्ड शिक्षक चलाते हैं। उस महाविद्यालय को सरकारी दर्जा दिया जाए, जिससे हमारे लोग संस्कृत को ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकें।

मेरे इलाके में कानिया गांव है, वहां विधायक और सांसद तो अजमेर के लगते हैं, पर वह भीलवाड़ा जिले में है। आदरणीय जोशी जी, हमारे जो

(श्री राकेश पारीक)

अध्यक्षजी हैं, उन्होंने चम्बल का पानी पिलाया, लेकिन कानिया में बीसलपुर का पानी पूरा नहीं जा पाता है, उसको भी चम्बल योजना से जोड़ा जाए। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, कानिया का जो उप केन्द्र है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए।

जल जीवन मिशन की जो योजना है। मेरे आधे इलाके में कार्य चालू हो गया है, घर-घर नल लग गये हैं, वहां सैकंड फेज बाकी है, उसको भी तुरन्त मंजूरी दी जाए जिससे सैकंड फेज का काम हो और गांव के लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। ये तमाम मेरी और मेरे इलाके के लोगों की मांग है।

अभी जैसा राजनैतिक वातावरण है, जैसी बातें हैं, देश की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद थोड़ा गम्भीर होना चाहिए। एक बहुत बड़ा नागरिक देश की बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठने वाला नेता।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): वह बहुत बड़ा नेता आकर ऐसी बात करे, यह राजनीति में शोभा नहीं देता है। अगर 20-30 सैकण्ड में अगर कुछ पढ़ लिया, अभी मैं भी पढ़ रहा हूं, भाई इंसान ही तो हैं, मशीन तो हैं नहीं कि जो उसमें डालेंगे वही निकलेगा। गलती हो जाती है और उस गलती के लिए आप देश के प्रधान मंत्री होकर, आप दो न 13 जिलों में वह योजना, पूरी जनता मांग रही है, जनता हाहाकार मचा रही है पानी-पानी, अगर करना है तो काम करो, काम करना नहीं है, सिर्फ जात-पात, धर्म की बात करनी है। जब सीधे आराम से वोट हिन्दू, मुसलमान से ही मिल जाएं तो काम करने की जरूरत कहां है।

सभापति महोदय, मेरा एक आग्रह है विपक्ष के साथियों से कि ऐसी भाषा बोलें। जहां तक वोट का सवाल है, आक्रोश यात्राएं निकलीं, मैने कहा मेरे इलाके में कि, भाई, किस बात का आक्रोश, हमने कालेज खोल दिया, हमने रोड बना दी। तुम्हारी सेवा कर दी, उसका आक्रोश है क्या? लोग नहीं आये, इलाके में टोटा पड़ गया। इसलिए आक्रोश और इन सब बातों को तो भूलो और दो, चार, छह महीने बचे हैं, सेवा करो जिससे आप लोगों को लाभ मिले। सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, राम राम सा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। श्री जब्बर सिंह जी सांखला।

(समय: 17:00 बजे)

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2023-24 पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, इस बजट में जो कहा गया है, जो भी घोषणाएं आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने की हैं मैं उन किसी भी घोषणा की निन्दा नहीं करूंगा क्योंकि घोषणा उन्होंने की है और पूर्ति भी उन्हीं को करनी है। राजस्थान की जनता सब देख रही है। राजस्थान की जनता को सब पता है ये घोषणाएं असत्य हैं या सत्य हैं, जो भी है यह सारा फैसला आठ महीने बाद राजस्थान की जनता करने वाली है क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने अभी कहा है, तीन दिन से इस बजट पर चर्चा चल रही है, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है 'भूतो न भविष्यति' मैं भी उस बात का समर्थन करता हूं। इस तरह का बजट न तो कभी किसी ने पेश किया है, न कभी कोई पेश कर सकता है क्योंकि इसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी को पूर्ति करनी है। यह बजट आचार संहिता से पहले अगर धरातल पर उतरता है तो सबसे पहले ताली पीटने वाला एक सदस्य मैं होऊंगा, माननीय सभापति महोदय, अगर ये उतार देते हैं धरातल पर तो।

इस बजट में कहा गया है पिछले चार साल में जितनी भी घोषणाएं हुई उनमें से हम लोगों ने 80 से 85 प्रतिशत घोषणाएं पूरी कर दीं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि चार बजट की किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं। यह जो बात कही गयी है यह बिलकुल उलटी बात है क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो अब तक बीस प्रतिशत भी पूरी नहीं हुई हैं और इस बजट में कहा गया है कि 80 से 85 प्रतिशत हम लोगों ने पूरी कर दी हैं। पिछली घोषणाओं में आपने पंचायत हैडक्वार्टर पर स्टेडियम की घोषणा की थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी स्टेडियम किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं बना है। आपने उसमें घोषणा की थी प्रत्येक पंचायत में नन्दी शाला खोलने की, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नन्दी शाला नहीं खुली है।

माननीय सभापति महोदय, आपने घोषणा की थी उस समय प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाने की। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक विकास पथ बना है केवल हुरड़ा में, इसके अलावा एक भी नहीं बना है। रामगढ़ भीण्डर सड़क की घोषणा आपने बजट में दो बार कर दी है। पिछले चार बजटों में आपने दो बार घोषणा कर दी है लेकिन वह आज भी अधूरी है। आपने इस बजट में कहा है कि हम यह बजट युवाओं को समर्पित करते हैं। युवाओं को

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है। भर्ती एक भी नहीं निकाली गयी है और सीएचए जिनको हमने कोविड सहायक का नाम दिया था उस समय, राजस्थान के सारे नेता, इस सरकार में बैठे हुए सारे जन प्रतिनिधि कोविड के समय में घरों में सोये हुए थे और कोविड सहायक जो अपनी जान को हथेली में रख करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके पूरे राजस्थान में लोगों की सेवायें कर रहे थे, वो 27-28 हजार कोविड सहायक आज घर पर बैठे हुए हैं और खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि लम्पी में जो गोवंश की मृत्यु हुई है हम उसमें 40 हजार रुपये प्रत्येक गोवंश के देंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि आपने न तो इसकी कोई गाइडलाइन बनायी है। आप इसका रिकार्ड कहां से लेकर आयेंगे? ये केवल एक जुमला है और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आपके अधिकारी कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यह आप भी जानते हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं राजस्थान के लोग जिनके गोवंश मरे हैं वो इस बजट के बाद दर-दर भटकते फिरेंगे और आपके अधिकारी और आपके जितने भी कर्मचारी हैं सब विभाग वाले, वो इनको आंकड़ों के जाल में फंसा देंगे और इनसे रिकार्ड मांगेंगे, तो किसी के पास रिकार्ड नहीं है। इस घोषणा को भी मैं थोथी मानता हूं।

सभापति महोदय, आपने राजकीय महाविद्यालयों की घोषणा की। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अंटाली में महाविद्यालय दिया, मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं लेकिन इसके साथ ही मेरे बदनोर उपखण्ड क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, वहां 17 ग्राम पंचायतें पहाड़ों पर बसी हुई हैं, उपखण्ड क्षेत्र होते हुए वहां महाविद्यालय नहीं है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी भी यहां विराजे हैं। आप भी मेरी पैरवी करेंगे क्योंकि आप भी मेरे क्षेत्र से ही आते हैं, आप मंत्री हैं। मैं तो आपको राजस्थान के सैकंड नम्बर के मुख्य मंत्री जी के रूप में देखता हूं। आप मेरी पैरवी करेंगे। मेरे बदनोर में महाविद्यालय और गुलाबपुरा में बॉय्ज कालेज की आप घोषणा करायें रिप्लाई में। यह मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, आपने अस्पतालों में नि:शुल्क जांच का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। मेरा आपसे निवेदन है धरातल पर पता कीजिये। अस्पतालों में जो आपने घोषणा की है जांच का दायरा बढ़ाने की, आपने मशीनरी लगा दी, आपने सब कुछ कर दिया लेकिन स्टाफ नहीं है। बदनोर मेरा इतना बड़ा कस्बा

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

है, उपखण्ड क्षेत्र है लेकिन एक डाक्टर वहां है। सीएचसी है, बहुत बड़ी सीएचसी है, सभापति महोदय, वहां केवल एक डाक्टर के भरोसे वह सीएचसी चल रही है। आसीन्द में 13 डाक्टर्स की पोस्टें खाली हैं आज की तारीख में। पूरा स्टाफ नहीं है, डाक्टर नहीं है। जांच करने वाले कोई नहीं है। आप यह जांच का दायरा बढ़ा करके क्या कर लेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, आपने पैरा नं. 58 में लिखा, 'माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार मुझे अवगत कराया। इनकी मांगों को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। मैंने कंवलियास में सी एच सी की मांग की थी। मैं चार साल से मांग करता आ रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, गुलाबपुरा से लेकर के भीलवाड़ा साठ किलोमीटर का एरिया पड़ता है, बीच में एक भी सीएचसी नहीं है और कंवलियास मेरे बहुत बड़ा कस्बा है। कंवलियास में सीएचसी, ब्राह्मणों की सरेरी में सीएचसी की मैं पिछले चार साल से मांग करता आ रहा हूं, मेरी आज तक नहीं सुनी है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जब आप रिप्लाई दें तो कंवलियास में सीएचसी, ब्राह्मणों की सरेरी में सीएचसी और बरसनी मेरी एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है वहां 21 मजरे ढाणियां लगती हैं, उसमें पीएचसी की घोषणा करें। एक बाशी ग्राम पंचायत है जो अरावली की पहाड़ियों पर बसी हुई ग्राम पंचायत है और वहां 40 गांव हैं उस पहाड़ के ऊपर, रतनपुरा अलग ग्राम पंचायत है और बाशी अलग ग्राम पंचायत है, दोनों पंचायतों के 40 गांव वहां ऊपर बसे हुए हैं। वहां एक पीएचसी की मांग मैं चार साल से करता आ रहा हूं। मेरा निवेदन है बरसनी में, बाशी में और कटार में तीनों जगह पीएचसी की घोषणा करें। मरेवड़ा आपलियास इन दोनों जगह मैंने चार साल से मांग की है, वहां सब सेन्टर खोलने की घोषणा करें।

सभापति महोदय, आपने पैरा 85 में ही कोविड में अनाथ हुए बच्चों को नौकरी देने का एक झुनझुना लोगों को दिखाया है। मैं इसको झुनझुना मानता हूं। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि कोविड में जो बच्चे अनाथ हुए उनकी आपने गाइडलाइन तय नहीं की। आपने केवल घोषणा कर दी कि अब कोविड के समय में बीमारी से अनाथ हुए बच्चों को हम नौकरी देंगे। अब किसी के घर में चार बहन-भाई हैं, वो अनाथ हो गये तो आप किन-किन को नौकरी देंगे? गांवों में जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, आपने यह तय नहीं किया कि जो अनपढ़ बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी गाइड

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

लाइन क्या होगी, यह आपने तय नहीं किया। मैं बता रहा हूं, मेरा निवेदन है, आप बोल रहे हैं लेकिन आपके अधिकारी लोग धरातल पर काम नहीं करते, मेरा निवेदन है आप पता कर लेना, वो इनको उलझायेंगे आंकड़ों में। आंकड़ों के जाल में उलझा कर रख देंगे। वह पहले ही अनाथ हैं और उनकी भावनाओं से खेला जायेगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय, चूंकि आपने एक लाख रुपये की घोषणा की थी, कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी विधवाओं को एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। मेरे वहां ब्राहमणों की सरेरी में एक केस आज भी पेंडिंग है, वह महिला दर-दर भटक रही है। कोई सुनने वाला नहीं है उसकी जबकि उनकी मृत्यु हास्पिटल में हुई है, भीलवाड़ा के एमजी हास्पिटल में लेकिन आज तक उसको पैसा नहीं मिला है।

सभापति महोदय, पैरा 87 में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही तो मैंने चार साल में...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): बोड़ता निम्बाहेड़ा में सिरेमिक जोन की मैं मांग करता आया हूं, आपने उसको नहीं लिया।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा आपने पैरा 93 में सड़कों का कार्य दिया है मेरे यहां आसीन्द से दौलतगढ़ 9 किलोमीटर तथा आसीन्द से रायला सड़क, इसके अलावा 65 सड़कें और भी हैं जो मैंने दे रखी हैं, उनकी आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई है। आसीन्द से दौलतगढ़ रामगढ़ भीण्डर का ही एक टुकड़ा है स्टेट हाई-वे का, वह इसी बजट में जब सीएम साहब रिप्लाई दें तो इसकी आप घोषणा करायें।

साथ ही, मेरा निवेदन दूसरा यह रहेगा, आदरणीय सभापति महोदय, जेजेएम योजना में पांच प्रतिशत तथा दस प्रतिशत जो जन सहभागिता में लिया जाता है वह आपने राज्य सरकार से देने की घोषणा की है, तो जिन लोगों ने पैसा जमा करा दिया, मेरा हुरड़ा क्षेत्र ऐसा है, सभापति महोदय, जहां चम्बल का पानी आज तक नहीं आया है, लोगों ने पैसा जमा करा दिया। उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने आज तक पानी नहीं पीया? मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्य मंत्री जी से उनका पैसा भी वापस दिलाया जाये क्योंकि उन्होंने आज तक पानी देखा ही नहीं है। जब योजना में पैसा ही सरकार को देना है तो जिन लोगों ने पानी नहीं पीया है उनका पैसा वापस दिलाया जाये।

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

सभापति महोदय, साथ ही, आपने पैरा 126 में प्रदेश में पैनोरमा निर्माण तथा महत्वपूर्ण स्मारकों, मन्दिरों के जीर्णोद्धार की बात कही है। मैंने चार साल में कितनी ही बार आपको अवगत कराया अन्तरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज मन्दिर तथा गोठा दड़ावर देव नारायण मन्दिर के लिए लेकिन आपने इसको नहीं लिया। सिर्फ एक मालासेरी देव नारायण की जन्म स्थली का नाम आया है, उसमें भी स्पष्ट नहीं किया। आपने उसमें लिख दिया कि विकास कार्य करायेंगे। मेरा निवेदन है कि पर्यटन की दृष्टि से देखते हुए सवाई भोज मन्दिर, गोठा दड़ावर देव नारायण मन्दिर, मालासेरी देव नारायण मन्दिर, वैंकाराणी माताजी मन्दिर, ताम्बेश्वर की बावड़ी, बदनोर महल, बेराठ माता मन्दिर तथा बैकुण्ठी धाम बरनागर इन सभी के सौन्दर्यीकरण तथा विकास के लिए आप फंड की घोषणा करें अपने रिप्लाई में।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): आदरणीय सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरा आपसे निवेदन रहेगा बाउंड्री विहीन स्कूलों में नवीन भवन, गुलाबपुरा में कालेज, बदनोर में महाविद्यालय, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करें। आसीन्द, बदनोर, गुलाबपुरा में स्टेडियम बनवाएं, कउलियास व ब्राह्मणों की खेडी पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करें। बारसी, बरसनी, कटार को पीएचसी में क्रमोन्नत करें। आपलियास व मरेवडा में सब-सेंटर खोला जाये। बोड़ता-निम्बाहेडा में सिरेमिक जोन की घोषणा करें।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरी 65 सड़कों की लिस्ट है, मैं अभी टेबल कर दूंगा। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जब वह रिप्लाई दें, उसमें मेरे आसीन्द गुढ़ा विधान सभा क्षेत्र की जितनी भी अधूरी घोषणाएं रह गई हैं और मैं पिछले चार साल से कहता आ रहा हूं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपका आखिरी बजट है, इसमें जाते-जाते आप मेरे आसीन्द गुढ़ा के लोगों का भी भला करके जायेंगे तो लोग आपको दुआएं देंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द। वंदे मातरम्।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद अर्पित करती हूं कि उन्होंने

(श्रीमती रमीला खड़िया)

राजस्थान के किसान, सरकारी कर्मचारी, मजदूर एवं 36 कौमों को ध्यान में रखते हुए यह ऐतिहासिक बजट पेश किया, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब को मैं धन्यवाद अर्पित करती हूं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चिरंजीवी योजना में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किये, इसके लिए मैं मेरी जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किया, इससे राजस्थान की आम जनता को बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बोर्ड, निगम आदि में पुरानी पेंशन लागू करके एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। यह एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। इससे राजस्थान के गरीब लोगों के परिवार में खुशी छा गई।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में बिजली पर विशेष ध्यान दिया है। इससे गरीब एवं किसान वर्ग को बहुत फायदा हुआ है। मेरा विधान सभा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र में है, इस बजट में जनजाति बहुल क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। बजट में रोडवेज में महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट देकर महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। पहले 1100 रुपये में गैस सिलेंडर आता था, आज 500 रुपये घरेलू सिलेंडर के किये गये। इससे महिलाओं में खुशी की लहर छा गई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये, इससे भी हमारे क्षेत्र को बहुत फायदा मिलेगा। मैं कहना चाहती हूं कि यह ऐतिहासिक घोषणाएं रही हैं। इसमें हमारी माता-बहनों एवं सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करती हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र के युवाओं की खेल की भावना को देखते हुए कुशलगढ़ में खेल स्टेडियम दिया। भीलकुआं सज्जनगढ़ में ट्रोमा सेंटर और जिलाखुटा में पीएचसी, छोटीसरवा में पुलिस चौकी, 50 करोड़ का एनीकट, सज्जनगढ़ में उप तहसील डूंगरा में और पाटन में सोकी, यह सब मुझे इस बजट में मिला है।

सभापति महोदय, अभी मैं सभी माननीय सदस्यों की बातों को सुन रही थी, यह कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी की पूर्व की घोषणाओं के काम

(श्रीमती रमीला खड़िया)

आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इस सदन में मैं कहना चाहती हूं कि जब से मैं जीत कर आई हूं, तब से जो कुछ कुशलगढ़ को मिला है, धरातल पर वे काम चालू हैं, प्रगति पर हैं। हमें बड़े-बड़े पुल मिले हैं, सड़कें मिली हैं। हमारे मंत्री जी यहां नहीं हैं, शिक्षा में दो कालेज भी मुझे मिली। छोटीसरवा में पी एच सी, सी एच सी मिली। डूंगरा और कुशलगढ़ में सी एच सी का बजट हमको मिला है। इस तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो भी काम मिले हैं, वे काम धरातल पर प्रगति पर हैं और मार्च में मैं कुछ कामों का हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे मंत्री जी के माध्यम से उद्घाटन कराऊंगी। सब कह रहे हैं कि आज तक ऐसा बजट नहीं दिया, ऐसा बजट हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी साहब ने दिया है।

मैं हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब से कुछ मांग करना चाहती हूं कि मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में छोटीसरवा में गानवन की 7 किलोमीटर की सड़क, राठरोलिया डूंगरीपाड़ा की 5 किलोमीटर की सड़क, माताजी मंदिर वाली सड़क, कासला वाली सड़क, यह ज्यादा बड़ी सड़कें नहीं हैं। इन 8-10 सड़कों की मैं मांग करती हूं। हमारे घाटा क्षेत्र में तालाब की भी मैं मांग करती हूं। बड़ीसरवा में 33 केवी सब स्टेशन की मांग करती हूं।

हमारे घाटा क्षेत्र में 21 पंचायतें पड़ती हैं और इन 21 पंचायतों में लाइट नहीं आती है। यहां हमारे प्रभारी मंत्री जी नहीं हैं, इनको भी मैं दे चुकी हूं और बजट में शामिल करने के लिए भी मैंने दिया है, 33 केवी का सब-स्टेशन बजट में मुझे दें। इसी तरह से सज्जनगढ़ में 133 केवी का मैंने पहले भी दे रखा है। कसारवाड़ी में सीएचसी का भी बजट दें और बड़ीसरवा का बजट नहीं आया है, उसका भी बजट मुझे दें। इस मांग के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

घाटा क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है, इस समस्या को देखते हुए हमारे खेड़ाधरती को हाई कैनाल देने की घोषणा करें। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि हमारे घाटा क्षेत्र में 21 पंचायतें हैं, वहां उप तहसील की मैं मांग करती हूं। कुशलगढ़ की जनता को आपने बहुत कुछ दिया है। मैं मांग करती हूं कि कुशलगढ़ में छोटीसरवा में उप तहसील दी जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2023-24 की बजट चर्चा में आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया,

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 फरवरी को 15वीं विधान सभा में पांचवां बजट पेश किया। पिछले चार बजटों का हश्र देखकर एक शेर याद आता है:-

तेरी मजबूरियां दुरुस्त होंगी मगर,
तूने वादा किया था, या तो कर,
पुराने वादे भूलते चलो, नये वादे करते चलो।

ऐसा इस बजट में हुआ है। यह खेल अब जनता समझ चुकी है। मैं अधिक विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन गरीबी हटाओ से लेकर 10 दिन में कर्ज माफी तक के नारे व वादे थोथे और असत्य साबित हुए हैं। प्रदेश की जनता 2018 में लुभावनी घोषणाओं के झांसे में आ गयी और आप सरकार में आ गये। ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता की मन:स्थिति पर एक शेर याद आता है:-

आदतन तुमने कर लिए वादे, आदतन हमने एतबार कर लिया।

कभी सौ दिन में महंगाई कम करने के नाम पर तो कभी दस दिन की कर्ज माफी के नाम पर भोले-भाले मतदाता को आप लोगों के द्वारा छला गया। जनता अब आपकी असलियत जान चुकी है। जो पार्टी केन्द्र सहित देश के कई प्रदेशों में राज करती थी, आज इनके कारनामों से यह कुछ ही प्रदेशों में सिमट चुकी है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में विकास की कुछ प्राथमिकताओं की ओर दिलाना चाहता हूं। माण्डलगढ़ एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है। यहां पर प्राचीन किला स्थित है। इस ऐतिहासिक किले में महाराणा सांगा का समाधि स्थल बना हुआ है। यहां पर प्राचीन महल, ऐतिहासिक सागर सागरी, चारभुजा नाथ का मन्दिर, बिजासन माता का मन्दिर, जैन मन्दिर, मदीना-मस्जिद आदि विश्वविख्यात दर्शनीय स्थल हैं। इस किले की तलहटी में जालेसर सरोवर विद्यमान है। मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे माण्डलगढ़ के लिए आप इस बजट में पर्यटन की दृष्टि से घोषणा करें, जिससे यहां पर पर्यटन का बहुत ही बढ़िया विस्तार होगा और इससे आम जन को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। यहां से सात किलोमीटर पहाड़ों के बीच महाराणा साहब ने गोवटा डैम बनाया था, उसके पास माता जी का मन्दिर स्थित है, उसकी नहरें पुराने टाइम की निकली हुई हैं, जीर्ण-शीर्ण हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

हूं कि इस बजट में जब रिप्लाई दें तो इस बांध की, नहरों की और गोवटा में बाण माता जी के मन्दिर में जो लाखों आदमी आते हैं, उनके लिए नया मन्दिर बनाने की घोषणा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैंडस्टोन के प्रचुर मात्रा में भंडार है। यह सैंडस्टोन पूरे विश्व में निर्यात होता है परन्तु सरकार की उदासीनता के कारण खनन नीति समान नहीं है। जोधपुर और मेरे बिजौलिया क्षेत्र में यह सैंडस्टोन समान है परन्तु इस सरकार की नीति ऐसी है कि जोधपुर से जो सैंडस्टोन का पत्थर निकलता है, उसकी लीज, रायल्टी और रेट कम है और बिजौलिया क्षेत्र की रेट बहुत ज्यादा है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो रेट का फर्क है। जोधपुर में बहुत कम है और बिजौलिया में बहुत ज्यादा है इसको समान किया जाये। आपकी आबंटन नीति में भी भेदभाव है। मेरे क्षेत्र में खनिज नीति में राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म सिंचित दर्ज है। यह दर्ज ही है, लेकिन मौके पर देखें तो यह जंगल टाइप की है। वहां पर कोई खेती नहीं होती है, उसमें आबंटन नहीं हो सकता है। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप जब 16 फरवरी को जवाब दें तो मेरी इस मांग की घोषणा करें, जिससे खनिज नीति चेंज हो, जिससे मेरे यहां आम आदमी व किसान आदमी को ज्यादा से ज्यादा इस सैंडस्टोन का लाभ मिल सके।

मेरे यहां बिजौलिया शहर और बीगोद बहुत बड़ा कस्बा है। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि ये नगरपालिका बनाने के सभी मानदंड पूरे करते हैं, इनको नगरपालिका बनाने की घोषणा करें तो वहां का विकास बहुत अच्छा होगा। बिजौलिया एक बहुत बड़ा कस्बा है, जहां पर एक बाईपास है। बाईपास थोड़ा संकरा है और रोड टूटी हुई है। जब बजट में रिप्लाई दें तो उस रोड को बनाने की घोषणा करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि आपने पहले बजट में जो घोषणा की है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरी करें।

मेरे यहां पर बिजौलिया एक खनन क्षेत्र है और वहां से नेशनल हाईवे निकला हुआ है, वह भीलवाड़ा जिले से सौ किलोमीटर दूर है, जिला अस्पताल से सौ किलोमीटर दूर है। मैं मांग करता हूं, पहले के बजट में यहां के लिए ट्रोमा सेंटर की घोषणा की थी, परन्तु अब तक नहीं बना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि जिला अस्पताल की घोषणा करें, जिसमें 100 बेड और सभी सुविधाएं वहां पर रहें क्योंकि सौ किलोमीटर दूर होने से वहां पर कोई बीमार होता है तो यहां पर आने में बहुत देर लग जाती है और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालाखेड़ा में कृषि संकाय खोलने की मांग करता हूं। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़, तहसील कोटड़ी में आर्ट संकाय खोलने की मांग करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंगोली श्याम के लिए पैनोरमा के लिए मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सिंगोली श्याम का मन्दिर देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आता है, मन्दिर बहुत पुराना हो चुका है। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि देवस्थान विभाग के द्वारा उस मन्दिर का जीर्णोद्धार करायें और वहां पर स्टाफ की सैलरी और भगवान के भोग लगाने का पैसा भी पूरा नहीं है। वहां पर जो भी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कराने का आदेश आप फरमायें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक त्रिवेणी संगम है, जहां पर साक्षात् तीन नदियों का संगम होता है। वह हमारे क्षेत्र का हरिद्वार है। संगम पर ऐतिहासिक मेला भी लगता है और मैं मांग करता हूं कि उसको हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाये तो वह पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छा होगा और हमारे पूरे क्षेत्र की जनता उसको गंगा मानती है। इससे उसका बहुत अच्छा विकास होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने की मैं मांग करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो महाविद्यालय हैं। शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय है, उसमें 1300 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, परन्तु दुर्भाग्य है कि उसमें 25 पद स्वीकृत हैं, उन 25 पदों में से केवल 4 प्रोफेसर हैं। 1382 बच्चों पर 4 प्रोफेसर हैं। यह सोचने की बात है। बिजौलिया में भी महाविद्यालय है, वहां पर भी प्रोफेसर पूरे नहीं हैं। मैं मांग करता हूं कि वहां पर जल्दी से जल्दी पूरा स्टाफ लगाने की घोषणा करें।

मेरे क्षेत्र में कृषि की दृष्टि से संतरा, अनार, अमरूद और पपीता की बम्पर पैदावार होती है तथा मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पोली हाउस है। मैं मांग करता हूं कि हमारे यहां पर कालेज में इस शिक्षा के लिए कृषि संकाय खोलने की घोषणा करें, जिससे मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आम आदमी को लाभ मिलेगा।

मैं माण्डलगढ़ में एडीजे कोर्ट खोलने की मांग करता हूं तथा माण्डलगढ़ में परिवहन कार्यालय भी खोलने की मांग करता हूं। बिजली विभाग का एक्स.ईएन. कार्यालय खोलने की मैं मांग करता हूं। माण्डलगढ़ शहर, मेरा पुराना शहर है, वहां पर बहुत गन्दगी रहती है। मैं वहां पर शहर के अन्दर

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

सीवरेज की मांग करता हूं। पूरे क्षेत्र का गंदा पानी वहां के इस जलेश्वर तालाब में जाता है और गर्मी के दिनों में बहुत बदबू मारता है। वहां पर रहने वाले बहुत तकलीफ में रहते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): दो मिनट में। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मांग करता हूं कि इसी बजट में हमारे वहां पर सीवरेज की घोषणा करें।

मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि मेरे यहां पर 5 किलोमीटर में दो टोल हैं। मेरा माण्डलगढ़ कस्बा है, उसके पहले दो टोल आते हैं। जहाजपुर से माण्डलगढ़ जो बसें चलती थीं, भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ जो प्राइवेट बसें चलती थीं, वे सब बन्द हो गयीं, क्योंकि पांच किलोमीटर दो टोल लगते हैं तो पूरा यात्री किराया ही उसमें देना पड़ता है। पांच किलोमीटर में में दो टोल हैं, इसलिए एक को तो बन्द कराया जाये। इससे आम जनता को वहां पर सुविधा मिलेगी।

मैं रोडवेज के लिए मांग करता हूं। हमारे यहां रोडवेज चलती थी, परन्तु कोरोना काल में बंद हो गयी। कोरोना काल के बाद अब तक वापस चालू नहीं हुई। इससे आम जनता को भारी समस्या होती है और वहां पर ग्रामीण जनता को बहुत परेशानी होती है। मैं मांग करता हूं कि जो रोडवेज बंद हो गयी हैं इसके लिए सर्वे कराकर जहां पर भी रोडवेज की डिमांड है, वहां पूरी करायी जाये।

मैं आपको मेरे यहां पर अस्पतालों की दुर्दशा की बात बताना चाहता हूं। मेरे माण्डलगढ़ में हास्पिटल है परन्तु डाक्टर नहीं है। डाक्टर नहीं होने से हर आम आदमी को 60 किलोमीटर भीलवाड़ा जाना पड़ता है। एक तरफ तो आप चिरंजीवी में घोषणा करते हैं और मेजें थपथपाते हैं परन्तु, हकीकत में मेरे क्षेत्र में देखा जाये तो वहां पर कोई भी आदमी इलाज कराने के लिए जाता है तो डाक्टर नहीं है। अगर कोई डाक्टर है, यदि वह जांचें लिखता है तो जांच करने वाला नहीं है। वहां एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है। कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं मांग करता हूं कि तुरन्त से तुरन्त डाक्टर लगाया जाये। वहां पर जो टेक्निशियन हैं, उनको लगाया जाए। मेरे बीगोद कस्बा है। मुख्य मंत्री जी अभी खेल हुआ तब पधारे थे। वहां पर घोषणा की थी। वहां पर माडल सीएचसी की घोषणा आपने पहले बजट में की थी, परंतु अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। मैं मांग करता हूं कि मेरे बीगोद में सी एच सी का तुरंत काम करवाया जाए। पूरे क्षेत्र में जो भी मेरी मांग है, उसको पूरा किया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिन्द। जय भारत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद, सभापति महोदय, बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। जो अभी बजट आया, उस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा चौरासी विधान सभा क्षेत्र के लिए, जैसे कि हमने मांग रखी थी कृषि मंडी की, कृषि मंडी खोली, उसके लिए धन्यवाद। साथ ही जनजाति आवासीय विद्यालय खोला, ए ईएन आफिस, चीकली खोला और खेल स्टेडियम जो खोला, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, 2022-23 के बजट में जो कडाणा बैकवाटर है, उस बैकवाटर से गेजीकांटा तक पेयजल परियोजना स्वीकृत की गयी थी। बजट घोषणा में इसको किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से और हमारे पी एच ई डी मंत्री इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, इस वजह से आज तक उसका टेंडर नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से हमारे पी एच ई डी मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जल्दी से टेंडर प्रक्रिया करवाकर इस कार्य को शुरू करवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट आया है, विशेषकर बेरोजगारों की बातों को लेकर आया, युवाओं को लेकर आया। पिछले आठ-दस सालों से हमारे राजस्थान का युवा परेशान हो रहा है। विभिन्न भर्तियां जो पहले हो चुकी हैं, पेंडिंग हैं, इनकी जो वेटिंग लिस्ट हैं, उनको लेकर परेशान हो रहा है। नर्सिंग भर्ती 2013, जो पिछली कांग्रेस की सरकार में हुई थी, उस समय से कुछ पद रिक्त हैं। लोग लम्बे समय से मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने कमेटी गठित की, लेकिन आज तक इसका निर्णय नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस साल के अंदर नर्सिंग भर्ती, 2013 की जो लड़के मांग कर रहे हैं, उसको पूरा किया जाए। साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 2016 जो बीजेपी के शासनकाल में हुई। हमारे अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो पद स्वीकृत थे, इन पदों में से 500 पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। पता नहीं इन पदों का क्या हुआ? मैं चाहूंगा जो रिक्त पद हैं, उन पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक पात्रता, राज्य के सदन को बार-बार अवगत कराना पड़ता है। कई बार मंत्रियों को, सरकार को अवगत कराना पड़ता है कि राजस्थान में एक यूनिट बनी हुई है शिड्यूल्ड एरिये

(श्री राजकुमार रोत)

की। अनुसूचित क्षेत्र के लिए कई योजनाएं अलग होती हैं, कई प्रावधान भी अलग होते हैं। रिजर्वेशन पालिसी भी अलग है। अभी राजस्थान में एक पात्रता घोषित की गयी तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी 40 परसेंट ही रखा गया है। समान रखने की वजह से अनुसूचित क्षेत्र की दो भर्तियों पर भयंकर प्रभाव हुआ है। जैसे कि कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती पात्रता, 888 पद स्वीकृत थे और मात्र 196 पद भरे गये, मतलब 600 पद आज भी रिक्त हैं। पीटीआई भर्ती में 647 पद थे और इसमें से 175 पद भरे गये हैं। ये 40 परसेंट की बाध्यता होने के कारण कुल जो ये 1535 पद थे, इनमें से 1164 पद आज भी रिक्त हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि रिप्लाई में अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो पात्रता 40 परसेंट की गयी है, उसको कम करके जो सारे रिक्त पद हैं, उनको भरा जावे।

माननीय सभापति महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी के तहत जो लड़के लगे थे, हमने कई बार मांग उठाई और राज्य सरकार ने उसको माना और सीएम साहब ने इसको स्वीकार किया, प्लेसमेंट एजेंसी के तहत जो शोषण हो रहा था, उसको बंद करने के लिए सरकारी नीति और सरकार की एक पालिसी लाए। इसमें ये किया गया है कि 2021 से पहले जो लगे हुए थे, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि ये सरकार 2019 में बनी, 2021 के बाद कई लोग प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे हैं, आज दिनांक तक जो लोग प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं उन सभी को इस पालिसी में रखा जाए। पहले सीएचओ को लेकर, कोविड में इन लोगों ने काफी मेहनत की, सीएचओ और सीएचए, दोनों ने, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना गया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट के रिप्लाई में इनकी मांगों को पूरा किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा को लेकर काफी कुछ हुआ है। इस सरकार में कई स्कूल क्रमोन्नत हुईं कई स्कूल नई भी खोली गयीं, लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर और विशेषकर हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात करें तो जो भौतिक सुविधाएं हैं, खेल मैदान चाहिए, भवन चाहिए, चारदीवारी चाहिए, शौचालय चाहिए, लेकिन आज भी हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर 70 परसेंट ऐसे विद्यालय हैं, जो इन भौतिक सुविधाओं से अभावग्रस्त हैं। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस पर विशेष ध्यान दे।

माननीय सभापति महोदय, कुपोषण को लेकर अभी दूध की बात हुई कि हम स्कूलों के अंदर दूध देंगे। अच्छी बात है, लेकिन इससे शिक्षण व्यवस्था पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं

(श्री राजकुमार रोत)

चाहूंगा, पहले भी ये चीज बता चुके हैं कि एक व्यक्ति पोषाहार पर लगा रहता है, एक कर्मचारी सूचना पर लगा रहता है और अब दूध पर फिर एक कर्मचारी व्यस्त होगा। गवर्नमेंट व्यवस्था करे कि पोषाहार के लिए, दूध के लिए, डाक के लिए एक अलग से ही पोस्ट क्रिएट करें। वह कर्मचारी उसी में ही लगा रहे ताकि बाकी जो शिक्षण व्यवस्था है, उस पर प्रभाव नहीं पड़े। अभी कुक-एंड-हैल्पर, हम लोग बात करते हैं श्रम विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप हमने राशि तय की हुई है कि राज्य का जो श्रमिक है, उसको इतना पैसा मिलना चाहिए, न्यूनतम 300 रुपये के आसपास, लेकिन कुक-एंड-हैल्पर जो हमारे विद्यालय के अंदर लगे हुए हैं, हम उनको 700-800 रुपये दे रहे हैं। महिलाएं 700-800 रुपये में अपने घर का गुजारा कैसे करेंगी? रिप्लाई में उनकी आमदनी बढ़ाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, पांचवीं अनुसूची क्षेत्र जो हमारा है, उसको लेकर अभी बजट का प्रावधान हुआ। हम जब विधायक बने तब से हमने डिमांड की थी कि ट्राइबल क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र पैटर्न की जगह राजस्थान पैटर्न लागू किया जाए। राज्य सरकार ने पिछले बजट में अलग से एस सी/एस टी बिल लाने की बात की और अलग से राजस्थान पैटर्न लागू किया। इसके तहत 500-500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। उस बजट को इस बार 1000 करोड़ रुपये किया। यह स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पिछला जो बजट था 500-500 करोड़ रुपया, हमारी जानकारी में नहीं है कि वह बजट आज तक कहां यूज हुआ? किसकी अनुशंसा पर यूज होगा, किस क्षेत्र में होगा? हमारा सुझाव है कि ये जो ट्राइबल के लिए बजट है, एस सी/एस टी के लिए जो बजट है, उसको विशेष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर यूज किया जाए ताकि एस सी/एस टी के लोगों को आगे आने में, मुख्य धारा में आने में मदद मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में भर्तियों को लेकर काफी भ्रमजाल फैला हुआ है। कहीं न कहीं युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ अन्याय होता है। 2013 की अधिसूचना के आधार पर और संशोधित अधिसूचना 2016 के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है। मैंने कई बार लिखा है कि ये 2013 और 2016 की जो अधिसूचना है, आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए एक काला कानून है। इस पर सरकार गम्भीर हो। एक भी भर्ती व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाई है। इसमें आरक्षण की जो पालिसी है, उसको व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं किया गया

(श्री राजकुमार रोत)

है। उस क्षेत्र का गरीब आदिवासी भी चाहता है कि मैं आर ए एस अधिकारी बनूं, मैं आई ए एस बनूं। आर ए एस अधिकारी तक की जो आरक्षण व्यवस्था पालिसी, स्टेट लेवल पर 12 परसेंट मिलता है और इस बार 2013 की अधिसूचना के आधार पर उन्होंने शिड्यूल्ड एरिये के लिए अधीनस्थ सेवा की अलग से पालिसी लागू की। जो उस इलाके का ट्राइबल है, उसको जो सामान्य सीट है, उस पर रोका गया और स्टेट लेवल पर जो 12 परसेंट मिल रहा है, इस 12 परसेंट में भी शिड्यूल्ड एरिये के आदिवासी को नहीं लिया गया पिछली तीन भर्तियों में। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। यह सरासर उस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में पेसा एक्ट, पेसा एक्ट को लेकर आदिवासी बहुल क्षेत्र में यह लगता है कि हमारे हित में कुछ न कुछ अच्छा होगा। वन अधिकार अधिनियम, एक टास्क फोर्स गठित की कि जो फोरेस्ट में रहने वाला ट्राइबल है, उसको वन पट्टा दिया जाएगा। पिछले तीन साल से मैं चिल्ला रहा हूं और हमारे अन्य साथी चिल्ला रहे हैं और बजट में भी इसका प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन नीचे वाले अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो फोरेस्ट के अंदर ट्राइबल बैठा हुआ है, उसको पट्टा नहीं दिया जा रहा है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): ग्राम पंचायत से फाइल तहसील में जाती है। तहसील से पंचायत समिति में, एसडीएम कार्यालय में और वहां से उसको वापस ग्राम पंचायत में लौटा दिया जा रहा है। इसका कोई भी निश्चित समय नहीं है कि उसको आवेदन करने के कितने समय बाद पट्टा दिया जाएगा। चार-चार साल हो गये हैं, वह पट्टे आज भी पेंडिंग हैं।

माननीय सभापति महोदय, एस सी/एस टी कोर्स जो आया, हमने पिछली बार जन-सहभागिता में अनुशंसा की थी, आज सालभर होने आ गया, लेकिन इस अनुशंसा का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला।

राजस्थान के बजट पर चर्चा हो रही थी। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ये केन्द्र के बजट पर चले गये। मैंने कल देखा कि केन्द्र के बजट में ऐसा क्या हुआ है? यहां राज्य के बजट की तारीफ नहीं करते हुए केन्द्र के बजट की तारीफ की जा रही थी। देखिये, यह लोकतांत्रिक देश है। उस बजट के अन्दर डिबेट और हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी द्वारा जो कहा गया, उसे

(श्री राजकुमार रोत)

देखने से यह लगा कि यह लोकतंत्र के साथ हत्या है। उन्होंने शब्द कहा कि- 'एक अकेला सब पर भारी' यह लोकतंत्र नहीं तानाशाही आई है इनके अन्दर। तानाशाही भावना आयी है। यह पूरे देश की जो जनता है उस जनता के साथ अन्याय है। एक उनके साथ छल-कपट, शुरुआत में यह कहा कि मैं सेवक बनकर काम करूंगा लेकिन बनने के बाद, बहुमत में आने के बाद एक तानाशाही जो रवैया आया है, इस देश की जनता ने यह देखा है और आने वाले समय में यह अहसास करायेगी कि यह तानाशाही नहीं, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है।

माननीय सभापति महोदय, उस बजट में डिजिटल इंडिया, क्या स्थिति है हमारे देश की? हमारे देश के अन्दर आज भी 70 प्रतिशत के आस-पास गरीब लोग हैं और हम कह रहे हैं डिजिटल इंडिया। हमने फोन दे दिया लेकिन उस गरीब को इसका महीने का जो रिचार्ज करना पड़ रहा है, उस रिचार्ज का पैसा नहीं है और हम डिजिटल इंडिया की यह थपथपा रहे हैं। किस बात का डिजिटल इंडिया? हालत खराब है। देश के अन्दर एक सर्वे आया है अभी यूनाइटेड नेशंस डवलपमेंट प्रोग्राम, 2020 का कि देश के अन्दर 22 करोड़ आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे है और देश के अन्दर एक सर्वे आया एनुअल सर्वे, देश के अन्दर 70 प्रतिशत लोगों के पास परमानेंट रोजगार नहीं है। हमारा देश गर्त में जा रहा है और हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, यह अर्थव्यवस्था, देश का प्रत्येक आदमी अगर आपकी जेब में कुछ है और मजबूत है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है लेकिन आज क्या हो रहा है? देश के अन्दर एक से दो प्रतिशत लोगों के पास देश की 70 प्रतिशत सम्पत्तियां हैं और यह पिछले दस सालों के अन्दर हुआ है। देश की 70 प्रतिशत आबादी बिलकुल गरीब है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री समाराम गरासिया।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, हमको जो समय मिला है, उस समय के अनुरूप हमें बोलने का अवसर प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे सदन के माननीय सदस्य असम के राज्यपाल चुने गये हैं, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन इसमें एक यह देखा कि 13 जो राज्यपाल नियुक्त किये गये हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): इनके अन्दर एक ऐसे जज जिन्होंने ऐसे जो फैसले दिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): जो कहीं न कहीं देश के अहित में थे। माननीय सभापति महोदय, हमें जो समय दिया गया है, हमारा समय सात मिनट ही हुआ है। आप समय पर ध्यान दें।

श्री सभापति: समय आपका दस मिनट था, वह दस मिनट आपका पूरा हो गया।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, हमको जो समय दिया है, उस समय में बोलने का अवसर प्रदान करें।

श्री सभापति: बाकी माननीय सदस्यों को भी समय देना पड़ेगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): एक जो जज, उस जज ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, एक मिनट में आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): उस जज ने एक तो राम मंदिर बनाने का फैसला दिया, नोटबंदी करने का फैसला दिया और उसको इनाम के रूप में यह दिया गया। यह कहीं न कहीं इस देश के लोकतंत्र को खतरा है।

माननीय सभापति महोदय, अभी सी.एम. साहब ने धार्मिक स्थलों पर 30 से 50 प्रतिशत की छूट की है। पहले जो 30 प्रतिशत था, उसको 50 प्रतिशत किया लेकिन हमारा बेणेश्वर मेला हुआ, उस मेले के अन्दर डूंगरपुर जिले और बांसवाड़ा के जो आर.टी.ओ. अधिकारी थे, उस मेले के अन्दर जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशान किया।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर सरकार पालिसी सही कर रही है लेकिन नीचे वाले अधिकारी इस सरकार को खतम करने का काम कर रहे हैं और जब तक यह सरकार नीचे वाले अधिकारियों को नहीं परखेगी तो यह सरकार रोड पर आ जायेगी, यह सच है। सरकार की योजना सही है लेकिन नीचे वाले अधिकारी उसको खोखला बना रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी चिरंजीवी योजना की बात हो रही थी। पिछले बजट में हुआ चिरंजीवी, दुर्घटना बीमा योजना। डूंगरपुर जिले में मात्र एक व्यक्ति को अब तक लाभ मिला है और यह अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह चीज नहीं हो रही है।

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, बंद करिये अब आप। प्लीज, सहयोग करें। विराजिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मेरे विधान सभा की कुछ मांगें हैं, वे मैं रखूंगा। चिखली में मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय खोला जाये।

श्री सभापति: आपका समय निर्धारित है, समय पूरा हो गया। प्लीज, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस सरकार का पांचवां और आखिरी बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मुख्य मंत्री को जो बजट भाषण पढ़ने को कहा तब उन्होंने पिछला बजट पढ़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यह तो मारवाड़ी में कहते हैं कि शकुन नहीं हुआ, अपशकुन हुआ है। मतलब, अशुभ हुआ है। पूरा राजस्थान देख रहा है कि वास्तव में यह शकुन ही नहीं हुआ तो क्या यह बजट लागू हो पायेगा, धरातल पर उतरेगा? यह नहीं उतरेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछ रहा हूं कि आपने इन चार साल के अन्दर नवाचार क्या किया? पूर्व सरकार में जिस प्रकार भामाशाह योजना, तीस हजार से तीन लाख रुपये तक फ्री इलाज था, उसमें यह धरातल पर था। प्राइवेट हास्पिटल को था, आपने उसको बदलकर चिरंजीवी किया। कहां पर चिरंजीवी? दो-ढाई साल के बाद में यह लागू किया, आपको यह पता था कि अब सरकार के चुनाव नजदीक आयेंगे तब चालू करेंगे। ढाई साल तक लोगों को लूटा, उसके बाद में आपने चिरंजीवी योजना वह भी मतलब, आयुष्मान भारत की जो योजना थी, उसमें जो प्रधान मंत्री का था, उसमें भी यह चालू किया, वह चिरंजीवी और दस लाख की जगह आपने पच्चीस लाख किया पर अर्थव्यवस्था क्या है? राजस्थान को कहां पर ले जाओगे?

(श्री समाराम गरासिया)

आपने जिस प्रकार से अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, पहले वह हमारी सरकार ने लागू किया था। अन्नपूर्णा एक मां का, एक अन्न देवता का नाम आता है, उसको इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दिया और वह भी दो साल, ढाई साल के बाद में किया। इसको आपने कोरोना में चालू किया होता तो कम से कम लोग इधर-उधर जो भटकते थे, उनको यह फायदा मिलता।

मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व सरकार को जो 2003 से 2008 तक रही, अक्षय कलेवा योजना, पांच रुपये में भरपेट भोजन मिलता था, वह पहली सरकार जो है वह भारतीय जनता पार्टी की है, जिस समय पांच रुपये में भरपेट भोजन मिलता था। कम से कम यदि आपने नकल में भी अक्ल लगायी होती तो नवाचार होता।

गौरव पथ योजना, आपने कहा कि हम विकास पथ करेंगे। कौनसे विकास पथ दिये पूरे राजस्थान प्रदेश को? पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना, एक भी किसी को कनेक्शन दिया हो घर का, बता दीजिए। इससे गरीब के साथ अन्याय हुआ है, एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया।

जिस प्रकार से यह सुकन्या योजना, उसमें पचास हजार रुपये मिलते थे, शुभ-लक्ष्मी योजना में पढ़ने पर मिलते थे, वह सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूर्व सरकार को धन्यवाद देता हूं। आपके मंत्री लोग जवाब नहीं दे पाते, हमारा पूरा मंत्रिमण्डल एकता के साथ में, किसी प्रकार का कोई भी जवाब हो तो वह सम्पूर्ण दिया करते थे। आपका जिस प्रकार से मंत्रिमण्डल है, उनको खुद को भी अनुभव नहीं, कोई जानकारी नहीं और इस झगड़े के अन्दर आपने कोरोना महामारी गिना, वह गिना और होटलों में मजे किये वह तो गिनते नहीं हैं, लोग मर रहे थे।

जिस प्रकार से आपने घोषणाएं कीं, मैं घोषणा आपको गिनाता हूं कि जिस प्रकार आपने 2011 में लीलूली बड़ली शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की, वह अब जाकर परकोटा बन रहा है। वहां पर भी अगर जायें तो बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां पर पूरी मिट्टी लगा रहे हैं। वह परकोटा भ्रष्टाचार की खाई में जा रहा है।

पिंडवाड़ा के अन्दर कालेज, पूर्व सरकार ने स्वीकृति दी लेकिन बिल्डिंग अभी तक भी नहीं हुई है। पूर्व में मैंने विधान सभा में एक प्रश्न लगाया था। उसके छह करोड़ पास हो चुके हैं और जल्दी ही शुरू होगा। शुरू होने के बाद में बंद है, तो क्यों वह कालेज बंद है? अभी तक आपके पास में बजट नहीं है। जहां पर हमारा कालेज स्वीकृत था, जमीन थी, अब वह कालेज क्यों नहीं बन रहा है?

(श्री समाराम गरासिया)

हर पंचायत मुख्यालय पर आपने नन्दी गौशाला खोलने की घोषणा की, कहां है वह गौशाला? हर उपखण्ड पर स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी, अभी उसके कागज कहां हैं? आप खाली वाहवाही करने के लिए, आपके सभी सदस्य जो सरकार में बैठे हैं उनको सबको पीड़ा है, सब चिल्ला रहे हैं, सब प्रश्न लगा रहे हैं लेकिन आपका कुछ भी होने वाला नहीं है और अगर वे विपक्ष में बोलेंगे तो उनको पता है कि टिकट काट दिया जायेगा, लेकिन चिंता में डूबे हुए हैं और जब आपको मालूम पड़ेगा, चुनाव आयेगा तब आपको इसी तरफ आना है और 25, 30, 35 से अगर ज्यादा आये तो आप मेरे को बता देना।

जिस प्रकार से दो लाख रुपये की किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ? बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात की थी, कहां हुई भत्ते की बात? उलटा युवाओं के साथ में धोखा हुआ और 17-17 बार पेपर लीक हुए। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए और प्रदेश का युवा यह जानता है कि जिस प्रकार की यह जो सरकार है वह नाकाम है इस प्रदेश को चलाने में। ये तो आपस में कुर्सी बचाने में लगे हैं।

दस करोड़ की घोषणा तो आपने पहले की थी मिसिंग लिंक रोड की और मरम्मत की, तो कहां गयी वह रोड? अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है और अब दस करोड़ की घोषणा और की है। पता नहीं वह कब लागू होगी, यह समझ से बाहर है।

गौ-माता की चर्चा आपने की और गौ-माता को लेकर चर्चा तो खूब हुई लेकिन आप यह बताओ कि इलेक्ट्रोनिक कत्लखाने किस सरकार ने चालू किये थे? यह तो बता सकते हो न? इलेक्ट्रोनिक कत्लखाने शुरू किये आपकी सरकार ने। दिल्ली में गौ-हत्या के विरोध में साधुओं ने धरना दिया था तब साधुओं पर गोली चलाकर उनकी हत्या की, उसके ऊपर क्या हो सकता था? श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं।

ऐसे हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो आप कह रहे हो कि 'एक सब पर भारी' तो वे यह नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। पूरे देशवासी यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सब पर भारी हैं, वह जनता कह रही है, पूरे विश्व के लोग यह कह रहे हैं। आज देश और दुनिया में उनका एक यह नारा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ का वह जिस प्रकार का नारा है, वह नरेंद्र भाई मोदी हैं जिन्होंने देश और दुनिया में नाम कमाया है। आज विदेशों में

(श्री समाराम गरासिया)

जाते हैं तो उनके सामने सब नतमस्तक होते हैं। ऐसे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी हैं। नौ साल हो गये उनको। आपने क्या किया? गौ माता के नाम अब चर्चा करते हो, अब जय श्रीराम के नारे लगाते हो। अब नाक डूब रही है न, तब आपको सारी यादें आती हैं। सारे कारनामे आप जिस प्रकार से कर रहे हो, वह किसी से छिपे हुए नहीं हैं।

मैं बजरी के बारे में निवेदन करता हूं। हमारे बहुत ही विद्वान साथी शिवगंज सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य वह सलाहकार हैं। उन्होंने भी आपको कहा था। आपने बजरी पर 1600-1700 रुपये रायल्टी कर के जनता को लूटा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? रायल्टी के पैसे के बराबर तो बजरी के दो ट्रैक्टर गरीब के घर में जाते थे। प्रधानमंत्री आवास जब बनता है तब वह रोता है कि वास्तव में बजरी की रायल्टी ज्यादा है। वह कहां से बजरी लाये? तीन-तीन हजार रुपये लगते हैं उस ट्रैक्टर के। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी के सलाहकार टैण्डर के समय चिल्लाये होते तो फायदा होता। हमने उस समय खूब विरोध किया, धरने प्रदर्शन किये। प्रभारी मंत्री चौधरी साहब जब सिरोही में आये थे तब हमने इनको भी ज्ञापन दिया। उसके बाद अब उनको लगा है कि चुनाव सिर पर हैं, अगर मैं अब नहीं बोलूंगा तो यह मामला मेरे ऊपर पड़ेगा। उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए अब उठाया है। जनता समझ चुकी है। यह पढ़ा हुआ बजट केवल असत्य का पुलिन्दा है। मैं समझता हूं कि कुछ होने वाला नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग यह घमण्ड नहीं करें कि हम सब कुछ कर लेंगे।

आपने स्कूलों की हालत देखी होगी। स्कूलों के अन्दर कमरे नहीं हैं। रमसा का बजट कहां गया? एक भी पैसा स्कूलों में नहीं लग रहा है। हास्पिटल्स की आपने दशा देखी होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अस्पतालों में एक भी महिला विशेषज्ञ डाक्टर नहीं है। एक मामूली सी, सामान्य डिलीवरी के लिए 17-17 हजार रुपये लूटे जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): आज हास्पिटल्स के अन्दर कोई डाक्टर नहीं हैं। पी एच सी, सी एच सी कहीं खोली नहीं। किवरली काफी दूर पड़ता है, वहां पी एच सी के लिए जमीन अलाट है लेकिन वहां अभी पी एच सी खुली नहीं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से स्कूलों के

(श्री समाराम गरासिया)

अन्दर इंग्लिश मीडियम खोला, इंग्लिश मीडियम के अध्यापक कहां हैं? आपने जनता के साध धोखा किया है। स्कूल्स में अध्यापक नहीं हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि मैरिट से जो भी भर्ती हो तो जिले के हिसाब से की जाये। पूरा जिला खाली है क्योंकि समय पूरा होने पर कर्मचारी अपने स्थान पर चले जाते हैं। राजस्थान में नौकरियों के मामले में अगर कोई पिछड़ा जिला है तो वह सिरोही है। माननीय सभापति महोदय, आप सरकार को निर्देश दें कि मैरिट की लिस्ट जिलेवाइज बनायी जाये ताकि कोई भी व्यक्ति जिले से बाहर नहीं जाये और वह जिले में ही रहे। आपने मुझे बोलने का समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेरे क्षेत्र की जनता को और पूरे राजस्थान को जो दिया है वह आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रतापगढ़ पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही। वहां विकास नाम की कोई सुविधा नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चार साल के अल्प काल में सात कालेज, मेडिकल कालेज, वह भी राज्य मद से, तीन-तीन पंचायत समितियां, दो-दो तहसीलें, 70 पंचायतें, 70 पटवार मण्डल, पांच-पांच बांध और ऐसे कई सारे काम करके प्रतापगढ़ की जनता को यह अहसास करा दिया कि प्रतापगढ़ का विधायक रामलाल मीणा नहीं, प्रतापगढ़ का विधायक अशोक गहलोत है।

महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन पांच बजट के माध्यम से जो सुविधाएं दी हैं वह राजस्थान ही नहीं, देश के इतिहास में देखने को कहीं नहीं मिली हैं। सबसे पहले मेरे क्षेत्र की जनता की जो डिमांड्स हैं, वह प्रस्तुत कर देता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने चार साल के कार्यकाल में 16 जीएसएस खोले हैं लेकिन कुछ पंचायतें मेरी बाकी रह गयी हैं। वीरावली-मण्डावरा के बीच में, गंदेर में, गादोला में, बोरिये में, ग्यासपुर में, देवपुरा में नये जीएसएस की मांग करता हूं। आज पांच बांधों के काम तो अभी चल रहे हैं। प्रतापगढ़ जिला ऐसा जिला है जहां नलकूप और ट्यूबवैल के माध्यम से किसान खेती करते हैं, तो वहां बिलेसरी, बागलिया, माण्डवी, दूधियातलाब, मोवाखेड़ी, चौरायता बांध, मोड़ा दामनिया बांध, रामपुरिया

(श्री रामलाल मीणा)

के दातलाकुण्ड-पाटाखोरा बांध, हवनियां बांध ऐसे कई एनिकट हैं उनकी पूरक बजट में देने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि पानमोड़ी, खेरोट, बोरिये, पण्डावा, पाल पी एच सी खोलने की घोषणा हो। सुहागपुरा और चुपना में सी एच सी खोलने की मांग करता हूं। कई सड़कें मैंने मुख्य मंत्रीजी को दे रखी हैं, उनके लिए मैं आस लगाकर बैठा हूं।

मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र की पूरी दो पंचायतें और एक पंचायत जहां मेरी मैडम सरपंच है, तीनों पंचायतों में भौतिक सुविधाएं नहीं हैं। सड़क, बिजली और पानी की सुविधा नहीं है।

राइट टू फोरेस्ट एक्ट सोनिया गांधीजी, राहुल गांधीजी ने कानून बनाया था। तब मनमोहन सिंहजी प्रधान मंत्री थे। राइट टू फोरेस्ट के अन्दर चाहे वह वन विभाग हो या अभयारण्य में हो, जहां आदिवासी निवास करता है वहां आदिवासियों को रहने के लिए, खेती करने के लिए बिजली, पानी और सड़क के लिए वनाधिकार पट्टे दिए जाएं। सामुदायिक पट्टे दिये जाएं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आते ही वनाधिकार एक्ट के अन्दर पट्टे देने की घोषणा की और कानून को लागू भी किया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पांच साल के कार्यकाल में सिर्फ यह मानते हुए आदिवासियों को एक भी पट्टा नहीं दिया कि यह कांग्रेस की सरकार की स्कीम है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राहुल गांधीजी भारत जोड़ो यात्रा में आये थे, तब उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को पूरा हक मिलना चाहिए। वह चाहे सीता माता अभयारण्य के अन्दर हों या वन विभाग में हों। उनकी सभी सड़कें बननी चाहिए। उनकी बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं यहां मांग करता हूं कि पाल, माडियाकलां और देवपुरा पंचायत या अभयारण्य के अन्दर जो पंचायतें हैं वहां बिजली, पानी और सड़क के लिए वनाधिकार सामुदायिक पट्टे तुरन्त प्रभाव से दिये जाएं। उनकी स्पेशल व्यवस्था की जाए और जो वनाधिकार के पट्टे बाकी हैं, पांच साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने पट्टे खारिज करने का काम किया, उन सभी आदिवासियों को जो वहां खेती कर रहे हैं, उनको वनाधिकार के पट्टे देने की मैं मांग करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रतापगढ़ को जो दिया, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मरोड़े चल रहे हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई

(श्री रामलाल मीणा)

क्या कह रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने आदिवासियों का अपमान किया है, यह ठीक नहीं है। डाक्टर किरोड़ी लालजी मीणा ने नांगल प्यारीवास की हाई कोर्ट में माननीय प्रधान मंत्रीजी की सभा करने की बात की। पीले चावल उन्होंने बांटे लेकिन आपने आदिवासियों का अपमान किया। केवल सिर्फ प्रधान मंत्रीजी का एक ही कार्यक्रम हुआ। प्रधान मंत्रीजी ने ई आर सी पी की घोषणा भी नहीं की और चले गये।

दूसरे नेताओं को भी आपने मार्गदर्शक मण्डल में डालने की घोषणा की है। मैं गुलाबजी का शिष्य रहा हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके मन में यह धारणा है गुलाब चन्दजी कटारिया की वजह से पूरा संभाग डिस्टर्ब हो रहा है, उनको राज्यपाल बना दिया जाए। मैं आप सभी को कह रहा हूं कि परिणाम जब आयेगा तो सभी 28 सीटों पर पंजे ही पंजे निकलेंगे क्योंकि गुलाबजी अब वहां रहेंगे नहीं।

मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। नरेगा योजना का आपने क्या कर दिया। आपने नरेगा के बजट को 35 प्रतिशत काट कर सभी मजदूरों का गला घोंटने का काम किया है। नरेन्द्र मोदीजी जब प्रधान मंत्री बन थे तब आते ही कहा था कि नरेगा खड्डा खोदने की स्कीम है क्योंकि उनको पता था कि नरेगा योजना मनमोहन सिंहजी की सरकार में बनी है और कांग्रेस चाहती है कि आदिवासियों और गरीबों का भला कैसे हो और मजदूरों का भला कैसे हो, इसलिए उन्होंने नरेगा योजना को बन्द करने का काम किया है लेकिन राहुल गांधीजी, सोनिया गांधीजी और मनमोहन सिंहजी ने सोचा कि अगर राज परिवर्तन हो गया तो इन आदिवासियों और मजदूरों का क्या होगा, इसलिए नरेगा को एक्ट बनाकर गये थे। इस कारण से मोदीजी आठ साल निकल जाने के

(समय: 18:00 बजे)

बाद भी नरेगा को बन्द नहीं कर पाये। लेकिन धीरे-धीरे गत बजट में उन्होंने नरेगा के 15 प्रतिशत बजट को कम किया, इस बजट के अंदर भी उन्होंने 35 प्रतिशत नरेगा के बजट को कम किया है। यहां तक कि कई मेटों का पेमेंट साल भर से नहीं हो पा रहा है, सामग्री का पेमेंट नहीं आ रहा है, लेबर का पेमेंट नहीं आ रहा है और तो और, नरेगा योजना को तो बिलकुल पैरालाइज करने का काम आप लोगों ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब को, कि आपने 100 दिन के रोजगार के

(श्री रामलाल मीणा)

साथ-साथ नरेगा मजदूरों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का काम किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं पूरे गरीबों की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां तक नगरीय क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को, मजदूरों को भी 100 दिवस का रोजगार इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू करके देने का काम किया। मैं उन गरीब मजदूरों की तरफ से भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

आयुष्मान भारत की बात करते हैं, उसमें कितने लोग रजिस्टर्ड हैं? मात्र 45 प्रतिशत लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं, और कहते हैं योजना तो हमारी है। किस-किसको लाभ हुआ? किस मजदूर को फायदा हुआ? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब को आपने पूरे राजस्थान की जनता के हित और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 10 लाख तक का इलाज हर व्यक्ति का फ्री करने का काम आपने किया था गत बजट के अंदर और 5 लाख दुर्घटना बीमा योजना का काम आपने किया था। गरीब जब एक्सीडेंट होकर मर जाता है, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अनाथों का कोई भगवान है तो अशोक गहलोत है। उन्होंने अनाथ बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस बजट के अंदर दुर्घटना बीमा योजना के अंदर भी 5 लाख की जगह 10 लाख करके वह भगवान का दर्जा आपने हम सबको प्रमाणित करके बता दिया।

आयुष्मान भारत की बात करने वाले लोगों, 10 लाख की बजाय माननीय मुख्य मंत्रीजी को हमने कहा कि 10 लाख भी कम पड़ते हैं, बड़े-बड़े हास्पिटल्स का खर्चा हम वहन नहीं कर पाते हैं, तो चिरंजीवी योजना में 10 लाख को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। पूरे भारत ही नहीं, विश्व में ऐसी योजना नहीं होगी। आज हर व्यक्ति को इसका फायदा मिल रहा है। आपको भी RGHS के अंदर फायदा मिल रहा है। हर जगह हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो बात है राइट टू हैल्थ लाकर इसका कानून बनाया जायेगा।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): कानून बनने के बाद में भले ही कोई भी सरकार हो, इसका लाभ मिलता रहेगा। कल-परसों कह रहे थे कि फोर्च्यूनर के अंदर आयेंगे। आपने जन आक्रोश रैली निकाली थी। पूरे राजस्थान के अंदर

(श्री रामलाल मीणा)

आपकी जन आक्रोश रैली फैल हुई। दिल्ली में एक फरमान जारी हुआ था। नड्डा साहब ने कहा कि कोरोना आ गया है, रैली को बंद कर दिया जाये। साथियो, कोरोना नहीं आया बल्कि पब्लिक आनी बंद हो गयी। पब्लिक तो अशोक गहलोत जी की कायल हो चुकी है। राजस्थान के अंदर चौथी बार अशोक गहलोत मुख्य मंत्री बनेगा और आप वहीं पर बैठोगे, यह भी मैं आपके सामने कह रहा हूं साथियों।

आज बड़ी-बड़ी बातें तो आप कर लेते हो। जितने स्कूल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने क्रमोन्नत किये, उतने आज तक कहीं नहीं हुए। जितने उप स्वास्थ्य केन्द्र उन्होंने क्रमोन्नत किये, उप स्वास्थ्य केन्द्र को PHC, CHC में किया, उप चिकित्सालय बनाया, जिला चिकित्सालय बनाया। मेरे मेडिकल कालेज को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो साल पहले घोषित कर दिया था केन्द्र -राज्य बजट से, लेकिन केन्द्र सरकार के उदासीन रवैये के कारण केन्द्र सरकार का स्टेटमेंट आया कि प्रतापगढ़ तो आदिवासियों का जिला है, छोटा-सा जिला है, इसमें मेडिकल कालेज की आवश्यकता ही नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब को कि आपने दो साल का इंतजार करने के बाद में बार-बार केन्द्र सरकार से बात करने के बाद में, आपने राज्य मद से मेडिकल कालेज देकर प्रतापगढ़ की जनता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं जिंदगी भर तक आपके ऋण को नहीं चुका सकता।

साथियों, मुख्य मंत्रीजी ने काफी कुछ दिया है। आप जो भर्तियों की बात कर रहे हो, इन्होंने बहुत सारी भर्तियां निकाली हैं। आप पेपर लीक की बात कहते हो, पेपर लीक कहां-कहां नहीं हुए? आपने मध्य प्रदेश की सरकार के व्यापमं घोटाले को देखा है। व्यापमं घोटाले का मतलब क्या था? फार्म भरा रामलाल मीणा ने, परीक्षा दी गणेश घोघरा जी ने, नौकरी लगी गंगादेवी जी की और पेंशन हुई चौथे व्यक्ति की। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हो।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने युवाओं की बात को ध्यान में रखते हुए कड़े कानून भी बनाये और नकल कराने वाले गिरोह की बिल्डिंगें भी ध्वस्त करने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। यह आज तक किसी ने नहीं किया है।

आप योगीजी की बात करते हो, लेकिन राजस्थान की बात कीजिये। यहां से 25 सांसद जीतकर गये, आप ERCP की योजना को नहीं ला पाये,

(श्री रामलाल मीणा)

आप नरेगा के बजट को नहीं बढ़ा पाये, आप तीन जिलों को कालेज नहीं दिला पाये। मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि मेरी दो सड़कें बड़ी साकली से अमरगढ़ तक की और दूसरी सिद्धपुरा से खोरिया तक की सड़क राज्य और केन्द्र के बजट के अंदर थी, लेकिन केन्द्र के उदासीन रवैये के कारण दो साल से नहीं बन पायी। मैंने बराबर आंदोलन किये, तब जाकर वह सड़कें बनी हैं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): आज नरेगा योजना को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 220 करोड़ रुपये देकर प्रतापगढ़ और राजस्थान की जनता का भला किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): आप सबका ध्यान रख रहे हैं। हम आपका भी ध्यान रखना चाहते हैं। पांच साल तक पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य जो वक्ता के रूप में अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें। बोलने के बाद आप अंत में यह कहते हैं कि मुझे अपना बाकी भाषण टेबल करना है, आप अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें। जो बात आपके क्षेत्र की है, वह बात पहले आप रख दें, उसके बाद आपका जो भी समय बचे, उसमें अपनी बात कहें। मैं इसके आगे टेबल करने की अनुमति नहीं दूंगा। जब्बर सिंह जी सांखला और राजकुमार जी रोत ने जो टेबल किया है, उसकी मैं अनुमति देता हूं। आगे से मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें और पहले आप अपने क्षेत्र की बात कहें ताकि समय जाया नहीं हो।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): आप मुझे थोड़ा बोल लेने देते, आपने बोलने ही नहीं दिया। मैं भी टेबल कर दूं?

श्री सभापति: मैं रामलाल जी मीणा को भी अनुमति देता हूं, लेकिन इसके आगे मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें।

(माननीय सदस्य श्री राजकुमार रोत व श्री रामलाल मीणा के सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: आसन को आप इस तरह से मत कहिये। मैंने आपसे कह दिया कि सब अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें और प्राथमिकता के आधार पर अपनी बात रखें। मैं आगे से अनुमति नहीं दूंगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आप दस बजे तक चलाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या हो रहा है यह? आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। हर बात पर जरूरी है बीच में बैठे-बैठे बोलना। आप विराजिये। बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आप। श्री पब्बाराम जी विश्नोई।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की एक बहुत ज्वलन्त समस्या है। 1977 से लेकर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे फलौदी को जिला घोषित किया जाये। बालोतरा वाले तो नंगे पैर घूम रहे हैं। मैं समझता हूं हम लोग निराश नहीं हैं। चलो बजट में घोषणा न हुई हम मुख्य मंत्रीजी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब नहीं होगा तो अंत में करेंगे। हम निराशावादी नहीं है, आशावादी हैं। कहीं न कहीं मुख्य मंत्रीजी मदन प्रजापत जी को मोजड़ी पहनायेंगे या बूट पहनायेंगे या चप्पल पहनायेंगे, पर जरूर पहनायेंगे, यह मेरी अपेक्षा है। इसके साथ ही हमारे फलौदी को भी जिला घोषित करेंगे।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, घोषणाएं तो घोषणाएं हैं, ऐसी कि जैसे स्वर्ग को धरती पर लाकर रख देंगे। वित्तीय प्रबन्धन कहीं नहीं है। मात्र चार माह का समय आपके पास में है। अप्रैल से शुरू होकर मई-जून तक आते-आते आपके काम शुरू होते हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते। सितम्बर में आते-आते आपके आचार संहिता लग जायेगी। आप तीन-चार महीने में क्या कर पाओगे? यह आपका अंतिम बजट है। यह सब जानते हैं कि यह चुनावी बजट है। मैं यह निवेदन करता हूं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति बुजुर्ग होता है, तब वह कहता है कि गायों को चारा डालो, वह कहता है मुझे तीर्थ यात्रा करवा दो, थोड़ा-थोड़ा आटा डाल दो, चींटियों को थोड़ा चून डाल दो, ताकि थोड़ा धर्म-पुण्य हो जाये, क्योंकि उसको अगला स्थान दिख रहा है, उसको यहां धरा-धाम से जाना है। ऐसी ही स्थिति इस सरकार की है। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार जाते-जाते धर्म-पुण्य का काम कर रही है। अंत में जाते हुए ऐसा कुछ कर रही है, ऐसा लगता है।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही संवेदनशीलता का मुद्दा हमारे लिए है, विशेषकर विश्नोई समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। आप किसी की संवेदना के ऊपर चोट भी करेंगे और

(श्री पब्बाराम)

वोट लेने का भी प्रयास करोगे, यह दो बात नहीं चलती है। माननीय सभापति महोदय, विश्नोई समाज, जहां पर उनको नीले वस्त्र पहनना मना है, पिछली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी से हमने निवेदन किया, वासुदेव जी देवनानी हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस नीले रंग को बदला और दूसरा रंग किया। मैंने +++ से पहले कहा था कि इस रंग से एलर्जी है। आप कोई दूसरा रंग कर दीजिये, परंतु नीला रंग मत लाइये। प्लीज, आप इसको करिये। लेकिन +++ तो +++ हैं। उन्होंने +++ मार दिया और वापस नीला पहनने के लिए मजबूर कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री सभापति: +++ का नाम इसमें अंकित नहीं होगा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, वह बड़े विद्वान हैं, बात-बात पर श्लोक वह बोलते हैं। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, लेकिन यह श्लोक वह पता नहीं पढ़ नहीं पाये या जान-बूझकर उन्होंने आंख मींच ली। वह श्लोक है,

'यथा स्नानं दानं जपो होमः, स्वाध्याय पितृ तर्पणम्।

पंच यज्ञा वृथा तस्य नीली वस्त्रस्य धारणात्'।

आपके नीले वस्त्र धारण करने से यह 5 जो पुण्य हैं वह वृथा हो जाते हैं। सरस्वती के मंदिर में जाकर के हमें मजबूर किया जा रहा है। हमारे बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि वह नीले वस्त्र धारण करके वहां पर सरस्वती की आराधना करें। इससे बड़ी बुरी बात कोई हो नहीं सकती।

मैं निवेदन करता हूं कि अब भी समय है कि हमारी संवेदनाओं पर चोट न करें। इस रंग को वापस बदल दें। वह हमारे वाला रंग मत करो। सफेद कर दो, कुछ भी कर दो लेकिन इस नील वर्ण से छुटकारा दिलवा दो। यह हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है। हमारे संतों के साथ में खिलवाड़ है।

सभापति महोदय, बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं। हमने इतनी दसवीं से बारहवीं कर दीं। पूरे हिन्दुस्तान में कोई दसवीं का स्तर रहा ही नहीं। कोई दसवीं का स्तर है नहीं। नई शिक्षा नीति के तहत आठवीं से सीधा बारहवीं है। मजबूरन आपको करना था। केन्द्र का यह आदेश था। यह जो किया है, इसको छोड़ दो, बाकी क्या किया है, यह बता दो।

ग्रामीण विद्यालयों के लिए आप बड़ी बात करते हैं कि यह खोल दिये, वह खोल दिये। हमारे वहां से सारे शिक्षक उठाकर के एमएलएज के दबाव में

(श्री पब्बाराम)

शहरों के पास में भर दिये। एमएलए हमारे पास में रहने चाहिए। यह आपने कर दिया और हमारे स्कूलों को खाली कर दिया। आज फिफ्टी परसेंट खाली हैं।

जब मुख्य मंत्री जी बजट का वाचन करने के लिए खड़े हुए निश्चित रूप से हमारे जोधपुर के साथ में कोई षड़यंत्र हो रहा है। या तो राठौड़ साहब का आदमी कहीं वहां पर बैठा है, या आपके विरोधी गुट का कोई व्यक्ति वहां पर बैठा है। वह जान-बूझकर 2022-23 का बजट लाकर के रख दिया। कह रहे हैं कि एक ही पन्ना था। 8 मिनट में 2 पन्ने तो उन्होंने पढ़ लिए थे।

मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, उस अधिकारी को ढूंढ रहा हूं क्योंकि उन्होंने मेरे जोधपुर का अपमान किया है। हमारे मुख्य मंत्री का अपमान किया है। उस अधिकारी को ढूंढ रहा हूं। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं यह मानकर चलना। जो इस प्रकार का तिरस्कार आपने पूरे हिन्दुस्तान को बताया है। 17 हजार एलईडी लगी हुई थी, आप लोगों ने मुख्य मंत्री का तिरस्कार करवा दिया। 17 हजार एलईडी पर लोग डेढ़ घंटे तक यह तमाशा देखते रहे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली से भी टीमें बुलायी थीं कि हम लोग बहुत अच्छा बजट दे रहे हैं। इन अधिकारियों ने सारी किरकिरी करवाकर रखवा दी, उस अधिकारी को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। तालियां तो बजा दो। मैं आपके ही पक्ष में बोल रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, 1 लाख 83 हजार और भर्तियों की लाइन में हैं। 16 बार पेपर आउट हुआ है। यह 16 बार नहीं है, मैं दावे के साथ में कहता हूं कि पेपर आउट हुए बगैर कोई भी परीक्षा नहीं हुई। सिस्टम ही ऐसा बना दिया। यह उदयपुर वाले भी इनकी वजह से नहीं पकड़े गये हैं। उस बस के अंदर 2 लड़के पैसे नहीं दे पाये तो उनको नीचे उतार दिया, उन्होंने उदयपुर एस.पी. को शिकायत की, तब जाकर के पकड़े गये। आपने क्या किया? मैं आपको बता रहा हूं।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मैं 7 मिनट पर शुरू हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, 7 मिनट पर शुरू हुआ हूं। ऐसा मत करो।

श्री सभापति: 10 मिनट का समय है, 7 मिनट पर आप शुरू हुए थे।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 7 मिनट पर शुरू हुआ हूं।5 मिनट हुई है।

श्री सभापति: अब आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मेरे को पता है कि जब आलोचना करूंगा तो मेरा यही हाल होगा।

(श्री पब्बाराम)

स्कूल में रसोइया 5 हजार लेता है, पूरे दिन तो रसोई करता है। आपने 2021-22 और 2022-23 में 3400 अंग्रेजी विद्यालय खोलने की बात कही है, इनमें से 1625 खुल पाये हैं और 1775 नहीं खुले हैं। 01 हजार की और घोषणा कर दी है। आप क्या कर रहे हो? क्या मतलब है इन घोषणाओं का?

आप 200 रुपये ड्रेस के दे रहे हैं, वह उनके खाते में नहीं जा पा रहे हैं। पिछले 4 साल में लैपटाप नहीं मिले। हमारे अंतिम साल 2018 में 27,900 लैपटाप दिये गये थे। एक भी लैपटाप और टेबलेट नहीं दिया गया। यह आपकी योजनाओं की हालत है।

इसी प्रकार से बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार की भी घोषणा करनी थी। वह भी आनलाइन कर दिया। वह कब होगी? राज्य और जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर विद्यालयों को पुरस्कृत करना था, वह भी नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, नन्हे-मुन्नों को दूध पिलाने की बात कर रहे हैं। आपने हमारे दूध पिलाने को बंद किया। आपने सांप बनकर 3 साल तक उन नन्हे-मुन्नों का दूध पी लिया, तब जाकर के आप मोटे हुए हैं। ऐसे थोड़े ही हुए हैं। अब कह रहे हैं कि हम दूध पिलायेंगे। आप दूध नहीं पिला रहे हो। वह नन्हें बच्चे भगवान का रूप हैं, उनके साथ में आपने धोखा किया है।

माननीय सभापति महोदय, युवा आज भी आपके 3500 रुपये के लिए तरस रहा है। वह आपसे पूछ रहा है। इसी प्रकार बिजली की दरें बेतहाशा बढ़ीं। दीनदयाल ज्योति योजना के अंदर हमने 18 हजार गांवों को बिजली के कनेक्शन दिये।

श्री सभापति: विराजे, माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम (फलौदी): एक कनेक्शन उसके बाद में नहीं दिया।

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज विराजिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): सौभाग्य योजना में भी आपने उसका प्रचार-प्रसार नहीं किया।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार। प्लीज, प्लीज विराजिये। सहयोग करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: सहयोग करें, सहयोग करें। श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शानदार बजट पेश किया, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

इस बार उन्होंने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इसमें 3 चीजें हम देखें, एक विकास की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, दूसरी तरफ उन्होंने रोजगार की तरफ देखा है, तीसरा सामाजिक है कि आम व्यक्ति को इस बजट से कैसे लाभ मिले, उसका ध्यान रखा। जहां तक व्यक्ति का जीवन यापन है, जो एक गरीब मजदूर आदमी है, कैसे आज इस महंगाई के दौर में अपना जीवन यापन करता है, उस तरफ उन्होंने बहुत ध्यान दिया है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे बिजली की बात हो, इसमें जहां उन्होंने राहत दी है, 50 से 100 यूनिट फ्री की है। इसमें लगभग सभी लोगों के बिजली के बिल माफ हो गये हैं।

दूसरा, सबने जैसे कहा और चिरंजीवी योजना की प्रशंसा की। जब भी मेडिकल की जरूरत होती है तो वह अस्पताल में जाता है, वहां उसको चिकित्सा सुविधा फ्री दी जा रही है। उसका दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा, जब कोई अनहोनी हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई कारण से दुर्घटना हो तो उसको भी बढ़ाकर के 5 से 10 लाख रुपया देकर उसको एक सांत्वना देने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है।

पालनहार योजना, जब कोई अनाथ बच्चा जिसको पालने के लिए उसके दादा-दादी या कोई संरक्षक होता है, तो उनको बड़ी मुश्किल होती है, उसका दायरा बढ़ाते हुए 500 से 01 हजार और फिर 1500 रुपये किया है, ताकि जो उसका पालन कर रहा है दादा-दादी, बुजुर्ग लोग जो उसको देख रहे हैं, उनको उसे पालने में दिक्कत नहीं हो। इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने ख्याल रखा है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में रोजगार की जहां तक बात है, बहुत लंबे समय बाद देखने को मिला है कि 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की उन्होंने घोषणा की है। बहुत लंबे समय बाद में इस तरह की घोषणा हुई है। इस समुदाय की बहुत बड़ी यह मांग थी। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह जो भर्ती है, इसे आगामी वित्तीय वर्ष में 6 महीने से पहले-पहले कर दी जाये, ताकि जो वर्षों से हम लोगों से मांग कर रहे थे कि

(श्री मनोज कुमार)

आप विधान सभा में इस चीज को उठायें कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, इससे एक तो यह होगा कि उनको रोजगार मिलेगा और दूसरा, शहरों की सफाई व्यवस्था इससे बहुत सुधरेगी। इस तरह से इसके 2 फायदे मिलेंगे।

मुख्य मंत्रीजी ने विकास की जहां तक बात की है, पूरे राजस्थान को दिया है। अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो सुजानगढ़ शहर में इन्होंने ड्रेनेज की जो पिछली बार डीपीआर तैयार की थी, उस डीपीआर को स्वीकृत करते हुए 25 करोड़ रुपये की घोषणा की है। डीपीआर करीब 75 करोड़ रुपये की बनी है। मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इसी वित्तीय वर्ष में कम से कम इसको 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएं ताकि जल्दी से जल्दी योजना का काम शुरू हो, जल्दी से पूरा हो ताकि शहर के लोगों को फायदा मिले।

माननीय सभापति महोदय, बालाजी की नगरी सालासर धाम, जहां लाखों श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं, वहां उन्होंने 30 करोड़ रुपये सीवरेज के लिए स्वीकृत किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, बड़ी लम्बी मांग थी 33 केवी जीएसएस की, हमारी ढाणी स्वामियान और ढाणी कालेरान क्षेत्र के गांवों की, वहां उन्होंने 33 केवी जीएसएस स्वीकृत किया है। बहुत बड़े राजस्थानी कवि कन्हैया लाल सेठिया, धरती धोरां री, जिनकी कविता, जो आजादी की अलख जगाती थी और इस बजट में उनके नाम से साहित्य पुरस्कार की उन्होंने घोषणा की है। सुजानगढ़ जो उनकी जन्म स्थली है, वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा, मांग रखूंगा कि मेरे क्षेत्र की कुछ और मांगें हैं जिनको पूरी करने की कोशिश करें। मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है, सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग, उसको इस बजट में जब भी जिलों की घोषणा करें, उसको पूरा करें। बहुत लम्बे अरसे से वहां के लोग जब 1949 में पुनर्गठन हुआ राजस्थान प्रदेश का, उस समय सुजानगढ़ कभी जिला रहता था, उस जिले का अस्तित्व समाप्त हो गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप उसका गौरव लौटा दें। अभी पट्टों का अभियान चल रहा है, लोग पुराने पट्टे जमा करा रहे हैं। जब वे अपने पुराने कागज देखते हैं, तो देखते हैं कि सुजानगढ़ शहर, जिला सुजानगढ़, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे पुराने दस्तावेजों में जिला 'सुजानगढ़' लिखा हुआ है। आज सुजानगढ़ की जगह सिर्फ 'तहसील सुजानगढ़' और 'उप खण्ड सुजानगढ़' है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री मनोज कुमार)

निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने बजट के उत्तर में जब भी जिलों की घोषणा करें तो सुजानगढ़ शहर को जिले में जरूर घोषित करें। हमारे क्षेत्र की यह हमारी सबसे बड़ी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने युवाओं को समर्पित किया है। 500 करोड़ रुपये उन्होंने युवा कल्याण कोष के लिए उपलब्ध कराए हैं। युवाओं की बहुत-सी मांगें उन्होंने इस बजट में पूरी की हैं पर फिर भी युवाओं की जो सबसे बड़ी मांगें हैं, रोजगार, पढ़ाई, खेलकूद के लिए अच्छा वातावरण, उसकी तरफ काफी ध्यान दिया है। मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं तो खेल स्टेडियम युवाओं को चाहिए, उसकी कमी अखर रही है। कल जब इस बजट में अपना उत्तर दें तो खेल स्टेडियम की घोषणा कर दें तो वहां के हजारों खेल प्रेमी हैं, युवा हैं, जो स्टेडियम की मांग कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ी सौगात इस बजट में मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, युवाओं की बात करें तो आज का युवा कहीं भटक भी रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों ने चिंता भी व्यक्त की है। 17 तारीख को प्राइवेट बिल आ रहा है, उसमें भी उसका उल्लेख हुआ है कि जो युवा मादक पदार्थों की चंगुल में फंसता जा रहा है उस पर कैसे रोक लगाएं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप हिम्मत करके इस बार शराब बंदी राजस्थान में घोषित कर दें और तमाम तरह के जो मादक पदार्थ हैं उन सब पर रोक लगा दें, ताकि न उनका यहां उत्पादन हो, न बिक्री हो, न कोई सेवन कर सके। जो युवा पीढ़ी भटक रही है, जो इसके जाल में फंस रही है, उसको आने वाले समय में कम से कम जो नई पीढ़ी आ रही है वो इस चंगुल में न फंसे, इस मकड़जाल से बाहर निकले। मुझे पता है कि इससे राजस्व का नुकसान होगा पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई दूसरे तरीके से अपने आप हो जाएगी क्योंकि अगर लाखों जिन्दगियां इससे खराब हो रही हैं, जो लाखों लोग इसके चंगुल में फंस रहे हैं, रोजगार और व्यवसाय जिनका जो होना चाहिए वो चौपट हो रहा है, उनको जो काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, दूसरा सरकार जो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, उसमें भी बचत होगी और उसकी भरपाई हो जाएगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सुजानगढ़ का 150 बेड का जो अस्पताल है, उसको मैं जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की मांग रखता हूं कि इसको

(श्री मनोज कुमार)

150 से 300 बेड का कर दिया जाए। वर्तमान में यह भीड़-भाड़ के एरिये में, तंग जगह में, कम स्थान पर है, पार्किंग की सुविधा पर्याप्त नहीं है, ट्रैफिक की दिक्कत है। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इसे शहर से इसको बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधा अच्छे से उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, पी.एच.सी. और सी.एच.सी. माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले तीन साल में खूब दी है। अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो काफी लम्बे समय से कातर छोटी जो उप तहसील मुख्यालय है और सडू गांव है वहां पर लम्बे समय से सी.एच.सी. की मांग हो रही है। इन पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाए। जोगलसर, मळसीसर, लोढ़सर और चरला जैसे बड़े गांव हैं जहां लम्बे समय से पी.एच.सी. की मांग है, वहां के सब-सेंटरों को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत कर दिया जाए। बीदासर शहर काफी बड़ा शहर है, उप खण्ड मुख्यालय है, 50 हजार की आबादी का शहर है, सीवरेज स्वीकृत कर दी जाती है तो वहां की सुन्दरता बढ़ेगी, गंदे पानी की समस्या का समाधान होगा इसलिए मैं बीदासर के लिए सीवरेज योजना शुरू करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सुजानगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में बिजली विभाग के नये सब डिविजन की मांग करता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, बीदासर उप खंड मुख्यालय है। लगभग सभी उप खण्ड मुख्यालयों पर ब्लाक सीएमएचओ कार्यालय स्वीकृत हो चुके हैं पर बीदासर उप खण्ड मुख्यालय पर अभी भी ब्लाक सीएमएचओ कार्यालय नहीं है। वहां भी बजट में इसे स्वीकृत किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अगर देखें तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया है, मैं तो इनके पहले कार्यकाल को भी स्वर्णिम युग कहूंगा। इसका कारण यह है कि अगर पिछले कार्यकालों से और इस कार्यकाल से तुलना की जाए तो बहुत कुछ समझ में आता है कि क्यों माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, क्यों राजस्थान के इतिहास में सबसे स्वर्णिम कार्यकाल रहा। अगर पिछले पांच साल की इन चार साल से तुलना की जाए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। स्कूलों की बात की जाए तो जहां 5 सालों में नाममात्र के स्कूल खुले, नया प्राथमिक स्कूल एक भी नहीं खुला था, कालेज मात्र 81 खुले, इसके जवाब में 210 कालेज 4 साल

(श्री मनोज कुमार)

के कार्यकाल में खुल चुके हैं और इसके अलावा करीब 40 या 50 कालेज और नये इसी बजट में खोलने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

माननीय सभापति महोदय, 266 नए प्राथमिक विद्यालय इस बजट से पहले खुल चुके हैं और 100 और नये प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा इस बजट में हुई है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 2013 से 2018 के बीच में 01 भी नया विद्यालय राजस्थान में नहीं खोला गया है।

माननीय सभापति महोदय, क्रमोन्नति की बात करें तो करीब 02 हजार 500 स्कूल प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए हैं और वहीं पिछले 05 साल की बात करें तो मात्र 500 के करीब स्कूल क्रमोन्नत हुए इसलिए इनका यह कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल है।

श्री सभापति: श्री मंजीत धर्मपाल।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा की बात करें तो जहां पिछले 5 साल में मात्र 700 सब-सेंटर खोले गये और 700 सब-सेंटर क्रमोन्नत किये गये। इस कार्यकाल में एक हजार से भी ज्यादा सब-सेंटर खुले हैं, क्रमोन्नत हुए हैं। अगर हम इस तुलना को देखें तो समझ में आता है कि क्यों माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, एक शानदार बजट पेश किया और इस शानदार बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, चुनावी वर्ष के इस बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, पैरा नम्बर 7 के अंदर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपके सचेतक महोदय का निर्देश है कि आप 7 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट पर मैं आपको कह दूंगा, 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। (व्यवधान) आपके सचेतक महोदय का निर्देश है।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, पैरा नं. 7 में...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, दस मिनट तो मिलने ही चाहिए। आप दस मिनट सबको बुलवाएं। हम तो अभिभाषण पर भी नहीं बोल पाये। दो-दो, तीन-तीन मिनट ही मिले। अभी भी नहीं बोलेंगे तो क्या मतलब है?

श्री सभापति: आप श्री जोगेश्वर गर्ग जी से कहें। बताइये आप। फाइनल करें। सात मिनट या दस मिनट?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): सात मिनट।

श्री सभापति: आप सबने सुन लिया? सात मिनट में अपनी बात रखनी है।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, पैरा नं. 7 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी को देखते हुए इस बजट को युवाओं पर केन्द्रित किया है। एक युवा होने के नाते इस बजट पर सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, कलाम साहब के कोट के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं, "the ignited minds of the youth is the most powerful resource on the Earth." अर्थात् युवाओं का प्रज्ज्वलित मस्तिष्क धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है, पर सरकार इस कथन के अनुरूप काम करती नहीं दिखती है। इसका कारण यह है कि सरकारी नौकरियां जो निकलीं, उनके लगातार पेपर आउट होते चले गये। आज अपने प्रज्ज्वलित मस्तिष्क के साथ युवा उसे अन्य कई कामों में लगाने पर मजबूर हो रहा है।

पैरा नं. 12 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेगा जॉब फेयर की बात की। क्या सरकार ने पूर्व में लगाये गये जॉब फेयर्स पर कभी ध्यान दिया कि उनमें जो नौकरियां लोगों को मिलनी थीं, वे मिलीं या नहीं? जो कम्पनीज वहां पर आयीं, युवाओं को जो उन्होंने शोर्ट लिस्ट किया, वहां उन्हें नौकरियां दी गयीं या नहीं?

स्थानीय उद्योगों में युवाओं को राजस्थान का निवासी कहकर नौकरी नहीं दी जाती है। अत: आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि एक कानून लेकर आएं, जिस तरह से राजस्थान से लगते हुए राज्य हरियाणा और गुजरात में है कि स्थानीय युवाओं को इन उद्योगों में कम से कम 75 प्रतिशत आरक्षण जरूर मिले। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं, हम युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, किन्तु हम युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2019 से वर्ष दर वर्ष लगातार नये राजकीय महाविद्यालय, नये कृषि महाविद्यालय खोले, नयी आईटीआई खोलीं, नये कन्या महाविद्यालय खोले, नये विद्यालय खोले और बहुत सारे विद्यालयों को क्रमोन्नत भी किया, पर क्या सरकार ने धरातल पर इनका हाल जानने का काम किया? आज एक भी विद्यालय, महाविद्यालय ऐसा नहीं है, जिसमें सम्पूर्ण स्टाफ हो या जिसकी पूरी बिल्डिंग बनी हुई हो।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

मुण्डावर में 2018 में वसुन्धरा राजे की सरकार में मेरे पिताजी स्व. धर्मपाल चौधरी जी की मांग पर राजकीय महाविद्यालय मुण्डावर में खोला गया था। आज वहां पर सात पद स्वीकृत हैं, जिसमें से केवल चार पद भरे हुए हैं। साथ ही, राजकीय कृषि महाविद्यालय, जो पिछले वर्ष मुण्डावर में खोला गया था, आज एक प्राथमिक विद्यालय में चल रहा है। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो उसका भवन है और न ही यह पता है कि आने वाले समय में वह कब तक बनकर तैयार होगा। वहां पर बारह पद स्वीकृत हैं, जिसमें से मात्र एक पद भरा हुआ है। क्या इसी तरह से सरकार युवाओं को आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रही है? अगर ऐसा है तो सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। पूर्व में खोले गये कृषि महाविद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य सरकारी संस्थाओं में आधारभूत ढांचा तैयार हो। वहां सभी स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां दी जाएं। जब वे पूर्ण हो जाएं, उसके बाद नये विद्यालय और अन्य संस्थाएं खोलने का काम हो।

इसी क्रम में मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गिलोट गांव लगता है, वहां रीको का एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। आस-पास पंद्रह किलोमीटर दूर तक कोई महाविद्यालय भी नहीं है, जिससे बच्चों को काफी दूर तक जाना पड़ता है। साधन की कनेक्टिविटी न होने से बच्चियां परेशान रहती हैं। आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि यहां पर एक कन्या महाविद्यालय खोलने की सरकार घोषणा करे।

आदरणीय सभापति महोदय, जब चिकित्सा की बात आती है तो सरकार में काबिज लोग चिरंजीवी योजना की बात करते हैं। क्या इन्होंने कभी जाकर देखा कि गांव के गरीब व्यक्ति के साथ हास्पिटल में पहुंचने पर कैसा व्यवहार किया जाता है? आईपीडी में तो डाक्टर उसे देखने के लिए मना कर देता है, जब उसे पता चलता है कि इसका पैसा चिरंजीवी योजना के माध्यम से उठेगा। ओपीडी में उसे हलाल किया जाता है, उसे काटा जाता है। जहां पर दो रुपये का सामान लगना होता है, वहां दस रुपये वसूले जाते हैं। मुख्य मंत्री जी ने इस चिरंजीवी योजना में मिलने वाले लाभ को दस लाख से बढ़ाकर पच्चीस लाख किया। मेरा आग्रह है कि बेशक वह दस लाख ही हो, लेकिन इस योजना का क्रियान्वयन अच्छी तरह से होना चाहिए।

जब एक गरीब व्यक्ति अस्पताल में पहुंचता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार न करके वास्तव में जो लागत उसके इलाज की है, उतना ही पैसा उससे वसूला जाना चाहिए। वह जब दुबारा अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचता

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

है तो उसे पता चलता है कि पूर्व में जब वह इलाज कराके गया, उसी समय में जो उसका योजना का पैसा था, वह वसूल लिया गया। आगे आने वाले समय में उसे लाभ नहीं मिल पाता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सी.एच.सी., पी.एच.सी. और जितने सब हैल्थ सैंटर्स हैं, करीब-करीब सभी जगहों पर पद रिक्त हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, मेरे यहां पर जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाये जिससे गरीब, किसान और गांवों में रहने वाली राजस्थान प्रदेश की सबसे अधिक आबादी को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा, मुण्डावर सी.एच.सी. को जिला उप-अस्पताल घोषित किया जाये। साथ ही साथ, सोडावास और बासनी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाये। अलीपुर सांचोद के अन्दर, चूंकि इस गांव की दूरी मुण्डावर हैडक्वार्टर से काफी दूर है, तो वहां पर एक पी.एच.सी. की घोषणा की जाये।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर जिले में पांच-पांच महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों को शामिल किया है। अन्य सड़कें जो अति क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें भी शामिल किया है। इसी क्रम में अलवर जिले में करीब ढाई सौ करोड़ रुपये से पौने तीन सौ किलोमीटर सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में एक किलोमीटर तो दूर की बात, एक इंच, एक मिलीमीटर सड़क की भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में घोषणा नहीं की गयी।

आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, दिसम्बर, 2020 से लेकर दिसम्बर, 2021 तक नेशनल हाईवे आन्दोलन के कारण बन्द होने की वजह से उसके लगते हुए क्षेत्र के अन्दर, गांवों में सड़कें बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिन पर गाड़ी चलाना बहुत असुविधाजनक है। आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा, 200 फीट गिलोट चौक से हरियाणा बोर्डर तक, शाहजहांपुर तातिया सड़क से मानका रामसिंहपुरा होते हुए हरियाणा बोर्डर तक, एनएच 48 से गूगलकोटा होते हुए हरियाणा बोर्डर तक। एनएच 48 से मानका तक। ये चार सड़कें इतनी अधिक क्षतिग्रस्त हैं कि आने वाले समय में जब बारिश और अधिक हो जायेगी तो यहां पर पैदल निकलना भी दुर्लभ हो जायेगा। अत: आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, जब मुख्य मंत्री जी इस बजट का रिप्लाई करें तो इन सड़कों की जरूर घोषणा करें।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

सभापति महोदय, मुण्डावर हैडक्वार्टर से जयपुर और दिल्ली, दोनों ही राजधानियों की सीधी कनेक्टिविटी बस की नहीं है। अत: आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि दोनों ही राजधानियों को मुण्डावर से जोड़ा जाये और यहां पर आने-जाने के लिए साधन उपलब्ध कराये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, पैरा नं. 148 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में उप-तहसील, तहसील और नगरपालिकाओं की घोषणा की। इसी क्रम में आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में एक शाहजहांपुर कस्बा लगता है, वह एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है, उसकी आबादी करीब दस हजार से अधिक है, नगरपालिका के सारे मापदण्ड वह पूर्ण करता है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री जी बजट का रिप्लाई करें तो शाहजहांपुर को नगरपालिका बनाने की घोषणा करें।

श्री सभापति: श्री हाकम अली।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): साथ की साथ, आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा, ततारपुर, सोडावास और शाहजहांपुर को उप-तहसील का दर्जा दिया जाये, जिससे कि आमजन और किसान को वहां पर लाभ मिल सके। आपके माध्यम से जो मेरा बचा हुआ भाषण है, वह टेबल करना चाहूंगा।

श्री सभापति: अब मैं अनुमति नहीं देता।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सर, सात मिनट में तो कैसे बोलेंगे पूरा?

श्री सभापति: अनुमति नहीं दूंगा।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री द्वारा 10 फरवरी, 2023 को जो बजट पेश किया गया, उस पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने आप लोगों से पहले भी आग्रह किया था कि समय आपके सचेतक द्वारा सात मिनट निर्धारित किया गया है। अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित कर लें और प्राथमिकता वाली बात पहले रख दें ताकि बाद में आपको यह टेबल करने की जरूरत न पड़े। मैं मंजीत धर्मपाल जी को अनुमति देता हूं, लेकिन आगे अनुमति नहीं दूंगा।

(माननीय सदस्य श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी के सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें।)

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री ने गरीबों की पीड़ा को समझते हुए प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह निःशुल्क अन्नपूर्णा खाने के पैकेट दिये जाने की घोषणा की है। इससे इन परिवारों को इस महंगाई में अच्छी सहायता मिलेगी। सभापति महोदय, सामने बैठे मेरे प्रतिपक्ष के साथी बजट पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बजट को रेवड़ियां बांटना, खैरात बांटना एवं चुनावी बजट बता रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी पार्टी की केन्द्र में सरकार है। आपके माननीय प्रधान मंत्री जी ने उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन और एक सिलेंडर दिया था, वह सिलेंडर एक बार तो भर के दिया, पर उसके खाली होने के बाद सिलेंडर की रेट 1200 रुपये होने की वजह से गांव, ढाणी एवं शहर में रोजमर्रा की मजदूरी करने वाला उस सिलेंडर को भरा नहीं सका तो उस सिलेंडर को खाली करके अलग से कोने में रख दिया। उसकी पीड़ा को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस सिलेण्डर को 500 रुपये में देने की घोषणा की है। अब आप लोग अपने प्रधान मंत्री जी से कहिए कि ये 500 रुपये केन्द्र सरकार दे तो उन सभी परिवारों को नि:शुल्क सिलेण्डर मिलेगा। यह तो आप बोल नहीं सकते और यहां इस बजट को क्रिटिसाइज कर रहे हो।

सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में 50 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की थी, उसको डबल करते हुए 100 यूनिट बिजली फ्री की है। इससे बहुत सारे परिवारों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को अन्नदाता मानते हुए दो हजार यूनिट बिजली प्रतिमाह फ्री देने की घोषणा की है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

सभापति महोदय, युवाओं का भी ख्याल रखते हुए युवाओं के लिए अपने निवास स्थान से शिक्षण संस्था तक जाने के लिए 75 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री किया है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। युवाओं द्वारा भर्ती परीक्षा में फार्म एक बार भरने के बाद सभी परीक्षाओं को नि:शुल्क किया गया है। यह भी बहुत ही सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले थे। उनकी मांग को देखते हुए हर ब्लाक, गांव व शहर में हजार-हजार स्कूल खोलने की घोषणा की है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों का अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने का जो सपना था, वह साकार होता नजर आ रहा है।

(श्री हाकम अली खां)

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में हमारे मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में 10 लाख की घोषणा की थी, उसे बढ़ाकर 25 लाख और दुर्घटना बीमा में 05 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया है। यह देश में पहला प्रदेश है, जिसने ऐसी योजना लागू की है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर को नगरपालिका से नगर परिषद् बनाया गया। विद्युत विभाग का एक अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने समस्त ब्लाक स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सक लगाने की घोषणा की है। मैं सरकार और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि समस्त ब्लाकों में, जिस तरह होम्योपैथिक चिकित्सक लगाने की घोषणा की है, उसी तरह यूनानी चिकित्सक लगाने की भी घोषणा करें। हर ब्लाक स्तर पर एक यूनानी चिकित्सक लगाया जाए।

सरकार ने नर्सिंग आफिसर-2022 भर्ती की घोषणा की है। उसमें अनुभव के आधार पर बोनस अंक मिलेंगे, उन बोनस अंक में अनुभव की गणना 23 नवम्बर, 2022 तक रखी गई है। इस अनुभव गणना तिथि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2022 की जाए, जिससे लगभग 3200 बेरोजगार युवाओं को इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा।

सभापति महोदय, अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में रामगढ़ शहर है, जहां नगरपालिका, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, विद्युत विभाग के सहायक अभियन्ता का कार्यालय है और तकरीबन तीस से चालीस गांव उस रामगढ़ शहर के नीचे लगते हैं। वहां एक सी.एच.सी. है। सी.एच.सी. की ओपीडी लगभग 700 से 1000 है। इस ग्रामीण इलाके को ध्यान रखते हुए उस हास्पिटल को 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड का किया जाए ताकि रामगढ़ एवं ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

रामगढ़ शहर एक बहुत पुराना शहर है। इसके बाजार के अन्दर से एक सड़क जाती है, बिसाऊ, झुंझुनूं होते हुए दिल्ली जाने वाली सड़क है। इससे

(श्री हाकम अली खां)

आये दिन बाजार में ट्रैफिक जाम रहता है। अत: शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए रामगढ़ में एक बाईपास सड़क बनाई जाए।

फतेहपुर एवं आसपास के इलाकों में बहुत सारे पशुपालक निवास करते हैं। वहां एक बहुत बड़ा भेड़ प्रजनन फार्म भी है। अत उसको देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में एक पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाए ताकि पशुपालकों को लाभ मिल सके।

फतेहपुर शहर में प्रवेश करने वाली एक मैन सड़क है, जिस पर दो पुलिस थाने हैं, पुलिस उप-अधीक्षक कार्यालय है, सब-जेल है, पी.डब्ल्यू.डी. का कार्यालय है, पी.एच.ई.डी. का शहरी एवं ग्रामीण कार्यालय है, राजकीय बालिका महाविद्यालय है, स्काउट गाइड का कार्यालय है, विद्युत विभाग का शहरी एवं ग्रामीण कार्यालय है, उप जिला अस्पताल एवं ट्रोमा सेन्टर है, नगरपालिका कार्यालय है, पंचायत समिति कार्यालय है, उपखण्ड अधिकारी का निवास, तहसीलदार का निवास, सारे सरकारी कार्यालय उस रोड पर हैं, अधिकारियों के निवास उस रोड पर हैं। अत: मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि इस सड़क के सौंदर्यीकरण के लिए बजट की घोषणा की जाए।

नगरपालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया है तो नगर परिषद् का एक टाउन हाल भवन बनाने के लिए बजट की मांग करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत भिचरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए। ग्राम पंचायत नयाबास में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए। फतेहपुर के ट्रोमा सेन्टर में नियमानुसार ट्रोमा में जितने पद होते हैं, उतने पद सृजित किये जाएं।

हमारे मुख्य मंत्री जी के प्रवास के दौरान गायंडा में एक सी.एच.सी. की घोषणा की थी। वह सी.एच.सी. बन गई है, लेकिन उसके भवन का अभाव है इसलिए गायंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन एवं कायमसर, हरसावा, खोट्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का बजट दिया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक खुड़ी गांव है, उस गांव के लोगों की मांग है। उस गांव में ज्यादा पशुपालक हैं, किसान हैं। उनकी मांग है कि हमारे गांव में एक प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोला जाए। गांव वालों ने भूमि दान करके उस भूमि पर एक भवन बनाने की भी तैयारी कर रखी है। इसलिए मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग है कि गांव खुड़ी, ब्लाक फतेहपुर में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोला जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरी कुछ सड़कें हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की अहमद खां की दरगाह से बेसवा, कांगणसर, अलपसर होते हुए हिरणा, हटवास तक, एक बलौद बड़ी से ठेढ़ी तक, कायमसर से ताकलसर तक, नारसर से बीबीपुर तक, फतेहपुर से चुवास तक, फतेहपुर से मांडले तक, इन सड़कों की मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में रामगढ़ बहुत पुरानी तहसील है। उस तहसील में पद सृजित करें, क्योंकि जितने पद सृजित होने चाहिए उतने पद तहसील में सृजित नहीं हैं। मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट पर रिप्लाई दें तो इस तहसील की ये सारी घोषणाएं पूरी करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। आपको देखा, आपके वायदे देखे, ऊंची दीवार के लम्बे साएं। इसी लाइन को साकार करते हुए जब माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं कि मैं 156 सीटें लेकर आया था, वैसी ही सरकार रिपीट करूंगा। माननीय सभापति जी, सरकार रिपीट हो या नहीं हो, पर बजट जरूर रिपीट हो गया। हम देखते हैं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी फिर उस बात को घुमाते हैं, तो पोलिटिकल क्रेडिबिलिटी सभी पोलिटिशियंस की डाउन होती है। पूरे राजस्थान ने देखा कि मुख्य मंत्री जी ने बजट रिपीट किया और उस चीज के लिए वे कहते हैं कि गलती से पेज आया, तो राजस्थान की साढ़े सात करोड़ की जनता मुख्य मंत्री जी से यह पूछती है कि, मुख्य मंत्री जी, आप कहते हो, हर गलती सज़ा मांगती है, तो अब इस बात पर आप किसको सज़ा देंगे?

माननीय सभापति जी, इस देश का आम नागरिक होने के नाते मुझे गौरव की अनुभूति होती है। जब मोदीजी 2014 में प्रधान मंत्री बने तब भारत विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, पिछले 9 सालों में यह वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनोमी बना और आज पौने चार ट्रिलियन या लगभग साढ़े तीन और पौने चार ट्रिलियन डालर के बीच इंडियन इकोनोमी है। अगले 2027 तक हम लगभग 7 ट्रिलियन डालर इकोनोमी से जर्मनी को पास करके फोर्थ इकोनोमी बनेंगे और 2030 तक हम जापान को क्रोस करके 10 ट्रिलियन डालर इकोनोमी बनेंगे।

(श्री सुमित गोदारा)

गर्व होता है कि जब साढ़े तीन, पौने चार ट्रिलियन इकोनोमी में, देश के प्रधान मंत्री इतने शानदार मेगा हाईवे बना रहे हैं, इतनी शानदार रोड्स, इतने शानदार एयरपोर्ट्स का डवलपमेंट हो रहा है तो 10 ट्रिलियन डालर इकोनोमी में देश कहां पर जायेगा।

ये काम प्रधान मंत्री जी द्वारा हो रहे हैं। इसकी साक्षी हमारे लूणकरणसर क्षेत्र की जनता भी है। जो अमृतसर से जामनगर 1296 किलोमीटर 35 हजार करोड़ की लागत से, कभी सुनते थे कि विदेशों में सड़कें हवा में ऊपर चलती हैं, सड़क ऊपर चलती है, वहां न कोई आ सकता है, न कोई जा सकता है, वैसी सड़कें हमारे क्षेत्र में बनीं। यह विश्वास माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के शासन में आया।

जब देश याद करता है प्रोटेक्शनिस्ट इकोनोमी, जो कांग्रेस के द्वारा चलाई गई। जिसमें हमेशा उन्होंने यह प्रयास किया देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा आगे नहीं बढ़े, क्योंकि यह एक सत्य है कि जैसे-जैसे भारत आर्थिक समृद्ध हो रहा है, वैसे-वैसे भारत कांग्रेस मुक्त हो रहा है। यह एक हकीकत है कि जैसे-जैसे इंडियन इकोनोमी प्रोग्रेस कर रही है, कांग्रेस हाशिये पर जा रही है और क्यों नहीं जाए? जब मोदीजी नोटबंदी लेकर आये, इन्होंने विरोध किया। आज भी ये नोटबंदी के बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं।

माननीय सभापति जी, नोटबंदी से यह फायदा हुआ, रफीक भाई जी, आप तो व्यापारी हैं, पूरी दुनिया में घूमते हो, आप थोड़ा सुना करें। अब सुनें, उसका क्या फर्क रहा है। आप जैसे जो पढ़े-लिखे लिटरेट हैं, जो व्यापार करते हैं, उन लिटरेट पीपुल के लिए है जवाब कि 2021 का जो सर्वे आया वर्ल्ड का डिजिटल ट्रांजेक्शंस में दुनिया में नम्बर वन देश जिसमें सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए, 4800 करोड़ के साथ दुनिया में भारत नम्बर 01 देश था। दूसरे नम्बर पर चीन था 1600 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन के तहत और तीसरा जो आप बहुत यूरोप में घूमते हो व्यापार के तहत साढ़े छह करोड़ यू.के., यू.एस., फ्रांस, जर्मनी चारों-पांचों देशों का मिलायें तो साढ़े छह करोड़ हुआ था। गर्व करो अपने देश पर कि आम नागरिक, जो आपके तत्कालीन वित्त मंत्री थे, जब मोदी जी लोक सभा में बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि अब भारत में तो ठेले वाले हैं, वो क्या ये पेटीएम चलायेंगे। आज हर जगह पेटीएम मिलता है। मैं गांव जाता हूं लूणकरणसर में, वहां पेटीएम है।

(श्री सुमित गोदारा)

सभापति महोदय, यह बदलता भारत है जो मोदी जी ने बदला। यह क्रान्ति लाये डिजिटल ट्रांजेक्शन की यह प्रधान मंत्री मोदी जी लाये और वह आपसे सहन नहीं हो रही। वह सहन इसलिये नहीं हो रही है क्योंकि आपने सत्ता हमेशा नारों पर की। आपकी पार्टी पहले नारा देती थी 'गरीबी हटाओ, देश बचाओ'। तीस साल आपने यह नारा लगाया। फिर बाद में आप नारा लेकर आये 'कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ'। नारों वाली पार्टी है, विकास नहीं किया। विकास देश ने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जब आये तब से और आज नरेन्द्र मोदी जी के शासन में देश ने देखा कि विकास क्या हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं लूणकरणसर से आता हूं। पहली बार मुख्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां जीती। हमेशा वहां ज्यादातर कांग्रेस जीती और उसका असर यह है कि हमारे लूणकरणसर का ये पांच बजट हो गये, हम लूणकरणसर का नाम ही सुनने को तरस गये, पर नाम नहीं आया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस के साथियों और मुख्य मंत्री जी से कि प्रधान मंत्री जी का नारा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास' उनसे सीखिये कुछ। उन्होंने हर राज्य को दिया है। आप भी हर विधान सभा क्षेत्र में दीजिये। पर यह पता है वैसे देकर भी क्या दिया। बीकानेर से हमारे तीन मंत्री हैं, दो कैबिनेट मंत्री। हमारे दो कैबिनेट मंत्रियों की लड़ाई पूरे बीकानेर में चर्चा में रही। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी और गोविन्द राम जी मेघवाल लड़े किस बात के लिए। कैबिनेट मंत्री गोविन्द राम जी मेघवाल ने कहा कि मेरे खाजूवाला से जितने भी अध्यापक थे कल्ला जी बीकानेर ले गये। हम गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि शिक्षक नहीं हैं। यह तो कांग्रेस के कैबिनेट मंत्रियों के हाल हैं तो अपना क्या होगा। यह शिक्षा का हाल है और हकीकत है और आप सड़कों की बात करते हो...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): राजस्थान को अफसोस हुआ जब राजस्थान का मुख्य मंत्री खुद के गृह जिले जोधपुर में उद्घाटन करने दस किलोमीटर हेलीकोप्टर से गया। राजस्थान की जनता शर्मसार हुई कि ऐसा मुख्य मंत्री जो अपने खुद के गृह जिले में हेलीकोप्टर से उद्घाटन करने दस किलोमीटर जा रहा है तो क्या राजस्थान में सड़कों का निर्माण हुआ?

सभापति महोदय, गैस के सिलेण्डर की आपने बात रखी। मैं गांव में

(श्री सुमित गोदारा)

जाता हूं, आप भी जाते होंगे। ग्रामीणों से पूछता हूं कि कैसा लगता है, तो वो बोलते हैं कि, साहब, आजादी के बाद पहली बार किसी ने गरीबों को गैस के चूल्हे दिये। दस करोड़ गैस सिलेण्डर गांवों में आये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इंटरवीन मत करिये आप बीच में। प्लीज, बोलने दीजिये उनको।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): और मोदी जी ने ...(व्यवधान) और उसमें क्या फायदा, उसमें दस करोड़ गैस के चूल्हे आये उसमें फर्क क्या कि जैसे गरीब आदमी जो काम पर जाता है, मोदी जी के आने के बाद यह हुआ कि जो किसान दिहाड़ी पर जाता है हस्बेंड वाइफ दोनों, धणी-लुगाई जो कहते हैं अपनी देशी भाषा में सात बजे सुबह जाता है और एक बजे आता है, वहां आठ सौ-आठ सौ दिहाड़ी एक जने को मिल रही है, कुल सोलह सौ क्योंकि हमारे उधर सरसों के जो आपके शासन में साढ़े तीन हजार के भाव थे वह आज साढ़े छह-सात हजार के भाव हैं। नरमा के जो आपके शासन में चार से पांच हजार रुपये थे वह आज बीजेपी के शासन में नौ से दस हजार रुपये क्विंटल है। जो मूंगफली हमारे क्षेत्र में आपके शासन में चार-पांच हजार रुपये थी वह सात और आठ हजार रुपये क्विंटल बिक रही है। लेबर मिलती नहीं है, लेबर सात सौ-आठ सौ रुपये पांच घंटे के काम के लेते हैं। वो कहते हैं, साहब, सुबह उठते हैं पन्द्रह मिनट लगते हैं, गैस का चूल्हा है, रोटी बनाते हैं और दिन की दिहाड़ी 15-16 सौ रुपये लेकर आते हैं। यह मोदी जी का राज है कि अब हम पांच मिनट में गैस में रोटी बनाकर जाते हैं। आपके टाइम उसे लकड़ियां चुननी पड़ती थी जिसमें उसे कितना धूम्रपान और कितना ट्यूबरक्लोसिस और कितनी बीमारियां होती थीं। यह किसी ने ध्यान दिया तो यह नरेन्द्र मोदी जी ने दिया।

माननीय सभापति जी, पेज 24 पैरा 50 पर रेफरल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा के लिए बात रखी। लूणकरणसर में विधायक कोटे से हमने एम्बुलेंस दी है पर सी.एच.सी. में वहीं खड़ी है। वहां पर ये निर्देश दिये गये हैं कि बी.जे.पी. के विधायक हैं, मोदी जी का फोटो और बी.जे.पी. के विधायक का फोटो है इसलिये इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाये। पेज 73 पैरा 10 पर घोषणा की गई कि घूमचक्कर चौराहा डूंगरगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड बनाने की घोषणा की गयी और दूसरी तरफ माडल स्टेट और राजस्थान के...

श्री सभापति: विराजिये। श्री सुरेश टाक।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): बस आधा मिनट, साहब। दूसरी तरफ माडल स्टेट और राजस्थान...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज विराजिये। अंकित नहीं होगा। माननीय सचेतक महोदय, मैं आपके आने वाले वक्ता का समय काटूंगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बजट 2023-24 पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का मेरे हृदय की अनन्त गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने हर वर्ष उत्तरोत्तर हर बजट में जो प्रत्येक साल आपने दिया हर वर्ग का हितैषी बजट बनाते हुए दिया। हर वर्ग को आपने इसमें समावेशी जगह दी है और इस बार 2023-24 का बजट तो इतना शानदार और इतना जानदार और राजस्थान के विकास को ऊंचाइयों पर ले जाना वाला प्रस्तुत कर राजस्थान के आम जन का दिल जीत लिया।

सभापति महोदय, आपने इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए अहसास कराया कि उसके साथ राजस्थान की सरकार और राज्य का मुखिया खड़ा है। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने गरीब को, किसान को, मजदूर को, महिला को, युवा को, उद्यमी को, सभी को साथ रखते हुए नौकरीपेशा लोगों को सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। इस बजट की जितनी भी तारीफ मैं करूं उतनी कम है। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, 'पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से संवारा जाये।' कुछ इसी तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट को संवार कर राजस्थान के विकास की गति को बढ़ाने का एक सच्चा और सार्थक प्रयास

(श्री सुरेश टाक)

किया। यह साबित किया कि राजस्थान की सम्पूर्ण जनता उनका परिवार है और हर तरह से ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा धर्म भी है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। यह सदन है, यहां पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी बात कहते हैं। हम लोग इंडिपेन्डेंट जीत कर आये हैं, पर सरकार का साथ मिला। यही कारण है कि आज हमारे विधान सभा क्षेत्र में हमारा सम्मान है। हमारे को लोग विश्वास की नजर से देखते हैं। अगर मुख्य मंत्री जी का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद जो आज किशनगढ़ में विकास हुआ है, तीस सालों में इतना विकास आज तक नहीं हुआ। एकदम सच्ची बात है और मैं उस बात को रोज पढ़ता हूं। मैं सामने बैठा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से 'या तो इस सभा में प्रवेश नहीं किया जाये, अगर प्रवेश किया जाये तो यहां स्पष्ट और सच बोला जाये। अगर आप स्पष्ट और सच नहीं बोलते हैं तो पाप के भागीदार हैं।' और इस बात को मैं बोलूंगा और ठोक कर बोलूंगा क्योंकि मैंने तीस सालों में वह नहीं देखा जो मैं कह रहा हूं। मेरी जनता उस बात से उस विकास से महरूम रह जाती अगर मैं यहां नहीं होता।

सभापति महोदय, मैं इस बात को इसलिये कतई नहीं दोहरा रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ लेना है, लेकिन जो दिया मैं उसे कभी भूल नहीं सकता, जीवन भर नहीं भूल सकता और इतना दिया है कि तीस सालों में जो सड़कें मेरे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे चार-चार सौ करोड़ की सड़क, दो स्टेट हाईवे जो बन रहे हैं और पूरे होने को आये हैं। मैं कैसे भूल सकता हूं इन बातों को? कभी नहीं भूल सकता। यह ऐसे काम हैं जो जनता को जरूरत थी। ऐसे अनछुए काम जिनकी तरफ किसी ने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, उन कामों को माननीय मुख्य मंत्री जी को एक निवेदन पर उन्होंने मेरे हर काम को किया। मेरी जनता को उपकृत किया और मेरी जनता जहां उपकृत है मैं वहां जमीन पर लम्बा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जनता खुश होनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं इस बजट के साथ एक बात, ...(व्यवधान) बाद में बोल देना आप, जो बोलना है। मैं यह बात कहने में कतई हिचक नहीं रखता हूं, किसी भी तरह की हिचक मेरे मन में नहीं है। बहुत कुछ मिला है और इसी बजट में इतना मिला है कि मैं गिना भी नहीं सकता आपको। अभी जो दस तारीख को बजट आया था उसमें भी किशनगढ़ की जनता को इतना कुछ दिया है कि मैं आपको गिना भी नहीं सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि

(श्री सुरेश टाक)

मेरे जो छोटे-मोटे दो-चार काम रह गये हैं माननीय मुख्य मंत्री जी कल रिप्लाई करेंगे तब भी देंगे और जब लास्ट में पूरक बजट आयेगा तब भी देंगे।

सभापति महोदय, इस बजट में आम आदमी के साथ जुड़ाव है, उस पीड़ित, शोषित, गरीब और वंचित परिवार के साथ जुड़ाव दिखा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, मैं एक छोटी-सी बात का उदाहरण देकर मेरी बात को शुरू करूंगा। वह व्यक्ति जो वेण्डर है, जो ठेला चलाता है और बीमार हो जाता है, अगर वह बीमार हो गया तो वह सात दिन, दस दिन उसका ठेला बन्द रहेगा। वह अगर रोज कमा कर रोज अपने परिवार को पाल रहा है, जिस दिन वह बीमार हो गया तो उस दिन उसके परिवार की रोटी बन्द हो जायेगी। वह कहां से लायेगा? वह चिन्ता माननीय मुख्य मंत्री जी ने की। बहुत छोटी-सी बात है लेकिन गरीब के साथ खड़ा होना, यह सोच दिमाग में आना बहुत बड़ी बात है तो उस वेण्डर को अगर वह सात दिन तक अस्पताल में एडमिट है तो दो सौ रुपये पर डे सरकार उसकी मजदूरी देगी ताकि उसका परिवार भूखा नहीं सोये। उसकी चिन्ता सरकार कर रही है। यह एक छोटी-सी बात है लेकिन बहुत बड़ा काम है।

सभापति महोदय, आज चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में पचास प्रतिशत लोगों का जीवन बचेगा। इस योजना से जो लोग बीमारी में पैसे की वजह से जीवन खो देते थे वो अब जीवन को बचा लेंगे। सरकार के इस प्रयास से जो दस लाख से सीधा पच्चीस लाख पर चला गया। आजकल बीमारियों में इलाज बहुत महंगे हो गये हैं और इसलिये शायद माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह विचार किया कि दस लाख रुपये में किसी का जीवन शायद बच नहीं सकता है, बहुत बड़े-बड़े इलाज, बहुत बड़े-बड़े आपरेशंस होते हैं, तो दस लाख से पच्चीस लाख रुपये करना एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है और उस गरीब को यह हिम्मत देना कि तू चिन्ता मत कर, तुझे 25 लाख रुपये सरकार देगी,

(समय: 19.00 बजे)

तू इलाज करवा, तुझे कोई भी अस्पताल मना नहीं कर सकता। राइट टू हैल्थ बिल आ रहा है और वह इसीलिए आ रहा है कि कोई भी अस्पताल किसी भी गरीब का इलाज करने से मना नहीं करे।

इसी के साथ एन.एफ.एस.ए. से जुड़े हुए लोग, यह छोटे-छोटे काम हैं, बड़े काम तो बहुत सारे किये हैं, यह छोटे काम जो उस गरीब और पीड़ित के चेहरे पर मुस्कुराहट लायेंगे। सरकार एन.एफ.एस.ए. में गेहूं दे रही है। वह आटा

(श्री सुरेश टाक)

पिसा लेगा लेकिन दाल, तेल, नमक, चीनी कहां से लायेगा? यह एक ऐसा प्रयास सरकार ने बहुत बड़ी सोच के साथ किया है कि एक किलो दाल, एक किलो चीनी, नमक, तेल, मसाले, यह सब देकर उसको इस चिंता से भी मुक्त किया है कि अगर आज ही तेरे को गेहूं मिल रहा है तो तुझे दूसरा राशन लाने की आवश्यकता नहीं है, इसी गेहूं के साथ-साथ यह तुझे सरकार दे रही है। यह बहुत बड़ी बात है।

50 यूनिट बिजली के बाद 100 यूनिट फ्री करना, इससे कितने लोगों को फायदा मिलेगा, इस बात का हम अंदाज नहीं कर सकते। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि 50 यूनिट के बाद 100 यूनिट फ्री बिजली में हम सब उस दायरे में आते हैं, हम सबको फायदा मिलेगा। हर दिन मैसेज आता है कि आपकी 50 यूनिट पर इतना बिल कम हो गया। हमने यहां फ्लैट लिया, अभी तक एक बिल भी जमा नहीं कराया। सरकार की इस छूट से ही हमारा बिल जमा हो रहा है। हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी यहां बिल जमा कराने की। अब 100 यूनिट की छूट हो गई है तो उसके बाद कितने लोगों को फायदा होगा, कितने गरीब लोगों को फायदा होगा। (व्यवधान) आपको भी मिलेगा।

युवाओं के रोजगार की जहां तक बात है, सरकार ने 03 लाख 23 हजार भर्तियों की बात की है। 01 लाख 42 हजार नियुक्तियां हो चुकी हैं और 01 लाख 81 हजार प्रक्रियाधीन हैं। मैं यह गारंटी देता हूं यह 03 लाख 23 हजार की भर्तियां कम्प्लीट भी होंगी और उन युवाओं को रोजगार भी मिलेगा जो इंतजार कर रहे हैं।

इसी के साथ मैं उद्यमी हूं। सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ है तो वह यह हुआ है कि राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड जो 25 लाख रुपये था, आज कई कारपोरेट बिजनसमैन हैं, जिनके घर में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वह बच्चे अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो वह नौकरी करके वापस अपने घर आ रहे हैं क्योंकि उनको इंडस्ट्री लगानी है और वह इनोवेशन के साथ इंडस्ट्री लगा रहे हैं। अगर सरकार उस कैपिटल वेंचर फंड को 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपया कर रही है तो जो युवा उद्यमी बनना चाह रहा है, उसके लिए इससे बड़ी कोई सहायता हो नहीं सकती। सरकार की इससे बड़ी सोच हो नहीं सकती कि वह अपने यहां आकर अपने खुद का उद्योग स्थापित करेगा और उसको एक करोड़ का कैपिटल वेंचर सरकार की तरफ से मिलेगा।

मेरे किशनगढ़ में आईटीआई में माइनिंग का ट्रेड चालू करके मुख्य मंत्री

(श्री सुरेश टाक)

जी ने यह भी जता दिया है कि उनकी नजर हर जगह है। उनको पता है कि किशनगढ़ में किस सेक्टर का काम होता है। वह इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर माइनिंग है, वहां पर मार्बल और ग्रेनाइट की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। इस सेक्टर में आपने यह देकर मेरे वहां के लोगों को स्किल्ड करने का प्रयास किया है ताकि जो बेरोजगार घूम रहा है वह माइनिंग में स्किल होकर वहीं पर उसको नौकरी मिल जाये, उसको किशनगढ़ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलना, यह माइल स्टोन वर्क है। आज के बच्चों में इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई और अंग्रेजी स्कूल की इतनी डिमांड है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और 1000 स्कूल खोलना बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा में 1000 रुपये पेंशन करना। उस गरीब को भले ही 250 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन वह 250 रुपये उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। जब भी हम गांवों में जाते हैं कभी कोई बुजुर्ग महिला, कभी कोई दिव्यांग कहता है कि 750 में क्या होता है, 500 में क्या होता है? यह अपने आप मुख्य मंत्री जी ने सोचा और यह सौगात लोगों को दी है। यह सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा काम आपने किया है जिसमें 500 और 750 से बढ़ाकर 1000 रुपये आपने किया। स्ट्रीट वेंडर के लिए मैंने आपको पहले बोल दिया। बच्चों को प्रतिदिन दूध देना, यह भी एक बड़ा काम है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी बात कहूंगा। मैं बजट पर जितना बोलूं उतना कम है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): बिलकुल दो मिनट में। आपने अभी अरांई में रोडवेज का नया बस स्टैंड दिया। मेरी मांग पर अरांई में कृषि उपज मंडी दे दी। आपने अरांई में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय दे दिया। मेरे सुरसुरा में हमारे लोक देवता तेजाजी का पैनोरमा दे दिया। मेरे किशनगढ़ में रीको कार्यालय को इकाई कार्यालय घोषित कर दिया। वहां रीको कार्यालय का नया आफिस बन गया। जिले की पांच सड़कों में दो महत्वपूर्ण सड़कें थीं, हमारे रामदेवरा खुंडियास की 23 करोड़ की सड़क मिली है। 55 करोड़ की सड़क मैंने मांगी थी, वह मुझे मिली। गुन्दोलाव झील पर संत नागरीदास पैनोरमा बना हुआ है, 9 करोड़ से एक पुलिया बनेगी। उस पुलिया के बाद उस झील पर आप इधर से उधर जा सकते हैं, यह एक बहुत बड़ा काम मेरे वहां हुआ है।

(श्री सुरेश टाक)

मेरी विधान सभा में कोई भी काम जो मुझे अब तक मिला है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी विधान सभा के लोग इस बात को सुनेंगे। एक भी काम ऐसा नहीं है जो चालू नहीं हुआ है। जितनी घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री जी ने की हैं, वह सारे के सारे काम चालू हैं और यह काम भी अतिशीघ्र चालू हो जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, मेरे बोराडा एक बड़ा कस्बा है, जहां 20 से 30 हजार बच्चे आस-पास की पंचायतों में रहते हैं, वहां एक कालेज की आवश्यकता है, इसकी बहुत लंबे समय से डिमांड है। इस बार जब कल माननीय मुख्य मंत्री जी रिप्लाई करें तो बोराडा में एक कालेज दे दी जाये ताकि वहां छात्र-छात्राओं को पढ़ने का एक अच्छा अवसर मिले। हमारी बेटियां पढ़ नहीं सकती हैं, कालेज नहीं होने की वजह से उनके माता-पिता उनकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की बड़ी सोच है, बड़ा दिल है और बेटियों के लिए लगातार काम हो रहे हैं, तो मैं भी यह अपेक्षा करूंगा कि कल बजट में हमारे बोराडा में एक कालेज सेंक्शन हो जायेगा।

किशनगढ़ के शहरी क्षेत्र में इतना ट्रैफिक हो गया है, वहां तीन, साढ़े तीन लाख लोगों की जनसंख्या है, बहुत बड़ा शहर है। वहां एक ही सड़क है जिस पर पूरा आवागमन होता है, बार-बार ट्रैफिक जाम होता है। एक बाईपास लिंक रोड मैंने दिया है, महेश नगर से अंतरनाला सर्किल होते हुए आरके कम्युनिटी सेंटर, बहुत छोटासा रोड है, अगर यह रोड मिल जायेगा तो इस शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि यह भी मुझे मिलेगा।

श्री सभापति: श्री गुरदीप सिंह।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक एनआईए कोर्ट, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। मेरा शहर व्यावसायिक शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है। वहां चैक अनादरण के चार हजार मामले लंबित हैं। यह कोर्ट नहीं होने की वजह से मेरे व्यापारियों के अरबों रुपये फंसे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि कल के बजट में एनआईए कोर्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत वहां चैक अनादरण मामले की विशेष न्यायालय की स्वीकृति दी जाये ताकि मेरे व्यापारियों को परेशानी नहीं हो।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): बांदरसिंदरी हाई-वे पर बसा हुआ है, वहां एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए, सहयोग कीजिए, प्लीज।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सिर्फ एक सैकण्ड। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा और डबरेला में एक पी.एच.सी. की घोषणा करवा दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुरदीप सिंह।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, धन्यवाद 2023-24 के बजट पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया। टाइम कम है, जो मेरी मांग है मैं वही रखूंगा। मेरे मिडल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल कराने के लिए, मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं गांवों के नाम बोलूंगा। 1 डीएलपी बख्तावर सिंह वाली ढाणी ग्राम पंचायत नाथवाना। लम्बीढाब ग्राम पंचायत हरिसिंहवाला, ढोलनगर ग्राम पंचायत भाखरावाली, चक 12 एमजेडी, ग्राम पंचायत अमरापुराजालू, 8 पीटीपी ग्राम पंचायत इन्द्रगढ़, 12 केएसडी मलूमोड ग्राम पंचायत रासूवाला, ढाबा स्टेशन ग्राम पंचायत ढाबा, 2 एचआरपी ग्राम पंचायत हरिपुरा, 3 एमजेडी ग्राम पंचायत रतनपुरा, 5 केएचआर ग्राम पंचायत खाराखेडा, 2 एमजेडडब्ल्यू ग्राम पंचायत मिरजेवाली, कमरानी ग्राम पंचायत शेरेका, चक प्रताप नगर ग्राम पंचायत मोरजण्ड सिखान, 2 एसबीएम ग्राम पंचायत साबूआना।

कुछ मेरी सड़कों की मांग है, शाहपीनी से किशनपुरा तक, 19 एएमपी से सादुलशहर संगरिया मार्ग तक 18-20 एएमपी व 10 व 13 पीटीपी होते हुए गांव ढाबा से चक 4 बीजेपी होते हुए हरियाणा बोर्डर तक, ऐलनाबाद मुख्य सड़क से चक 3 टीएलडब्ल्यूबी 33 केवी जीएसएस तक, सादुलशहर संगरिया मार्ग से संगरिया हनुमानगढ़ रोड तक चक 5 एनटीडब्ल्यू, 3 एमजेडी 73 हैड होते हुए संगरिया हनुमानगढ़ रोड तक, 19 एएमपी से 14, 15 एमजेडी होते हुए चक 9 डीएलपी धोलीपाल सड़क तक। गांव दीनगढ से गांव ढाबा तक मिसिंग लिंक। संगरिया टिब्बी मार्ग से एसबीएन माइनर के किनारे होते हुए हरियाणा बोर्डर तक। मसींतावाली हैड से 6 आरडब्ल्यूबी (मोटेवाला चक) गांव संतपुरा से चक 5 केएसडी होते हुए ढोलनगर नुकेरा रोड तक। गांव हीरपुरा से गांव ढाबा तक। सुरेवाला नाईवाला रोड से चक 1 एसआरडब्ल्यू चरण सिंह की ढाणी तक। तंदूवाली नाईवाली रोड से गिलवाला कूलचन्द्र रोड तक। पन्नी वाला

(श्री गुरदीप सिंह)

शरेका तक। पीरकामडिया से सलेमगढ तक। टिब्बी संगरिया रोड से घग्घर नदी के किनारे होते हुए हनुमानगढ़ टिब्बी रोड तक। हनुमानगढ़ सुरेवाली रोड से दोलतपुरा तक। मेहर वाली से उब्बलीकलां तक। चाइयां सादुलशहर रोड से आईजीएनपी के आरडी 22 से मेहरवाली तक। थलडका हनुमानगढ़ रोड से भरानपुरा गांव से 13 आरडब्ल्यूडी बकेवाली जोडी तक। इंदग्रढ गांव से पंजाब बोर्डर तक। गुडीया से हरियाणा बोर्डर तक। टिब्बी से रताखेडा तक और फतेहपुर से कमरानी तक।

मेरी नगरपालिका संगरिया में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 37 हजार थी, अब वह बढ़कर 55 हजार हो चुकी है। वहां पर गन्दे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, उसके अन्दर मैं आपको सीवरेज लाइन डालने की मांग करता हूं। टिब्बी के क्षेत्र में गेहूं की बिजाई बहुत ज्यादा होती है। वहां पर आगजनी होती है, मैं बार-बार फायर ब्रिगेड की मांग करता रहा हूं। उसके लिए मुझे जवाब नहीं मिलता है। इसको सार-संभाल के लिए नगरपालिका को भी दे सकते हैं। टिब्बी नगरपालिका बन चुकी है। मैं मांग करता हूं कि यहां पर फायर ब्रिग्रेड दी जाये।

इस बजट में नगरपालिकाओं में 20 किलोमीटर सड़कों की घोषणा की है। मेरी टिब्बी नगरपालिका नयी बनी हुई है, वहां पर कम से कम 50 किलोमीटर रोड दी जाये ताकि पूरे कस्बे में नयी रोड बन सके।

मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरेवाला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरेवाला बनाने की मांग करता हूं। उप स्वास्थ्य केन्द्र शाहपीनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपीनी बनाने की मांग करता हूं। उप स्वास्थ्य केन्द्र पीरकामडिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की मांग करता हूं। उप स्वास्थ्य केन्द्र खाराखेड़ा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खाराखेड़ा तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र सालीवाला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालीवाला बनाने की मांग करता हूं। मेरे यहां तीन सीएच.सी. हैं, तीनों में डाक्टर बहुत कम हैं। मेरे यहां पर हास्पिटलों के नाम ही रैफर हास्पिटल रख रखा है। मैं जब से एमएलए बना हूं तब से मंत्री जी से डाक्टर के लिए कई बार मिला हूं। हमारे यहां डाक्टर नहीं हैं, मैं डाक्टर की मांग करता हूं कि हमारे यहां सीएच.सी. और पी.एच.सी. के अन्दर डाक्टरों के रिक्त पद भरे जायें।

मेरे यहां तहसील जमाबंदी के अन्दर अभी आनलाइन हुई है। उसके अन्दर जमीनों के जो साझे खाते थे, 2300 खाते अपवादित हो चुके हैं। उसके लिए भी

(श्री गुरदीप सिंह)

मंत्री जी ने वहां पर मीटिंग ली थी। उस समय भी कलेक्टर साहब के सामने बात हुई थी। जमीन के काश्तकार न तो जमीन बेच सकते हैं न उनका इन्द्राज होता है, न उनको बैंक का लोन मिलता है। इन 2300 खातों में हजारों किसान हैं इस कारण सॉफ्टवेयर सही करें, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। यही मेरी मांग थी। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2023-24 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने काफी शानदार और जानदार बजट पेश किया है। हमारे विपक्ष के साथियों को पच नहीं रहा है। धरातल पर वास्तविक काम हुआ है। पहले के बजट में जो-जो घोषणा सीएम साहब ने की है, भले कालेज की हो, भले पुलिया की हो, भले सड़क की हो, सबके शिलान्यास भी हो गये और किसी का उद्घाटन भी मैंने कर लिया है। इनको खाली यह लगता है कि धरातल पर कोई काम नहीं है। गरीबों के मसीहा, राजस्थान के गांधी और मैं समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में नम्बर वन मुख्य मंत्री ने ऐसा काम किया है। इनको खाली बातें ही करनी हैं धर्म के नाम पर, हिन्दू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, किन्तु विकास नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि धरातल पर काम नहीं हुआ है तो आपको बजट में वापस मांग भी नहीं करनी चाहिए। आप मांग क्यों कर रहे हैं, अगर आपके यहां धरातल पर काम ही नहीं हो रहा है तो। आप किस आधार पर मांग कर रहे हैं? आपको मांग करनी ही नहीं चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की आम जनता, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, आम जनता इस बजट से खुश है। आप कह रहे हैं कि यह अन्तिम बजट है। यह अन्तिम बजट नहीं है, आने वाले 2024 में बजट भी यहां पर कांग्रेस का मुख्य मंत्री पेश करेगा, यह मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइये। आप ऐसे क्यों करते हो? आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांग रखना चाहता हूं। बिलयारा नदी पर नीला पानी, मेला स्थल गांव

(श्री गणेश घोघरा)

हथोड़ में पुलिया निर्माण कराया जाये। यह हमारे आदिवासियों का शिवजी का मन्दिर है, वहां आने-जाने में तकलीफ होती है और स्कूल भी है। हजारों लोग यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। हमारी सामाजिक परम्परा और रीति-रिवाज के हिसाब से वहां पर दो-तीन दिन का मेला भरता है। वहां पर आने-जाने की काफी दिक्कत है। इस बिलयारा नदी पर मैं पुल की मांग करता हूं। एक दूसरा है, ददोरिया से खैरवाड़ा रोड पर ब्रिज व पुलिया निर्माण।

मैं कुछ सड़कों की मांग करता हूं। काकरी महूड़ी से बाबा रोहण होता हुआ मनजी/नानजी मनात के घर से श्मशान घाट तक डामर सड़क लाम्बा भाटड़ा। वाडीला वाली घाटी से बुसीदरी स्कूल वाया श्मशान घाट लाम्बाभाटड़ा तक डामर सड़क निर्माण। थाना मेवाना मैन रोड सुनिया घाटी से मोहनमरता के घर तक डामर सड़क। कालकी माता से उपलाफलां स्कूल होता हुआ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसियावाव तक डामर सड़क, अमूलवा फलां आंगनबाड़ी से जैलाणा सीमा तक डामर सड़क, काला खाइया से मउड़ीफलां तक डामर सड़क खजूरी।

मैं पी.एच.सी. और सी.एच.सी. की मांग करता हूं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गड़ामोरैया, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मजोला, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर मेवाड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गलन्दर, उप स्वास्थ्य केन्द्र बोलादरा-बटकाफलां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहल्ला घाटी, डूंगरपुर।

सभापति महोदय, हमारे वहां पर न तो सिंचाई के बड़े तालाब हैं, न कोई ऐसी सुविधा है। छोटे-छोटे तालाब हैं, उनके लिए मैं मांग करना चाहता हूं कि उनका सुदृढ़ीकरण कराया जाये। मजोला तालाब का सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य, सिसोद तालाब का सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं नहर का मरम्मत कार्य। ईसरवाल तालाब से कनबा माता जी तालाब तक नहर का निर्माण कार्य। खुमान सागर तालाब से गेब सागर तालाब तक लिंक नहर के निर्माण कार्य की मांग करता हूं।

सभापति महोदय जी, 2013 नर्सिंग भर्ती, जीएनएम, एएनएम में 11 हजार 233 सृजित पद हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों से उनको नियुक्ति दी जाये, यह भी मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीटीआई भर्ती परीक्षा में टीएसपी में 647 में से 112 योग्य बच्चे माने गये हैं। टीएसपी की 535 सीटें विभिन्न वर्गों में 35 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत की बाध्यता रखकर खाली रखी गयीं, यह बाध्यता हटायी जाये और युवाओं को रोजगार दें। उन पदों को भरा जायेगा तो युवाओं में खुशी की लहर दौड़ेगी।

(श्री गणेश घोघरा)

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र 75 परसेंट ट्राइबल बैल्ट है, वहां पर मैंने बसों के लिए पहले भी मांग की है। डूंगरपुर से थाना वाया माड़ा गामड़ी, जालुकुआं और गुजरात बोर्डर, विरपुर शरम तक एक बस चालू की जाये। यहां से बच्चे-बच्चियां स्कूल और कालेज में पढ़ने आते हैं, इसमें काफी दिक्कत होती है। वहां पर कभी-कभी घर जाने में दिक्कत आती है और रात भी हो जाती है। डूंगरपुर से रतनपुर तक बस चालू की जाये। डूंगरपुर से चुण्डावड़ा, मौदर, पालीछोड़ा होती हुई गुजरात सीमा तक सरकारी बस चालू करने की मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, हमारा डूंगरपुर एरिया पूरा टीएसपी एरिया है, मनरेगा से ही लोगों को रोजगार एवं काम मिलता है। इसके अलावा हमारे वहां पर कोई बड़े उद्योग-धन्धे नहीं हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने नरेगा में 125 दिन कर दिये। भले ही शहर में हो, ग्रामीण में हो, लेकिन मनरेगा में मेट, कारीगर और मैटेरियल का भुगतान नहीं हो पाया है। कहीं-कहीं पर नेटवर्क नहीं पकड़ता है। भले मोदर पंचायत में हो, पालीछोड़ा पंचायत में हो, वहां पर ऑनलाइन हाज़िरी नहीं हो पाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी ऑनलाइन हाजिरी हटाकर ऑफलाइन हाजिरी की कुछ व्यवस्था की जाये तो हमारे लोगों को रोजगार मिल सके और ये 125 दिन हो पायें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे टीएसपी एरिये में जो 125 दिन हैं, उनको 200 दिन किया जाये। मजदूरी को कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन किया जाये। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में गामड़ीअहाड़ा, रामसागड़ा में पंचायत समिति खोलने की मांग करता हूं और पालदेवल में भी पंचायत समिति खोलने की मांग करता हूं।

हमारे विपक्ष के जो साथी आये थे, हमारे युवाओं ने हमको चुनकर भेजा है, लेकिन वे बोल नहीं रहे हैं। हमारे टीएसपी से जो जनजाति के एमएलए आये हैं, वे रिमोट कंट्रोल से चलने वाले एमएलए हैं। उनको पता है कि हमारी टिकट कट जायेगी। हमारे वहां पर युवाओं की दो ही खास मांगे हैं। भले ही हमको एनिकट नहीं मिले, सड़क नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, लेकिन सरकारी नौकरियों में वहां पर जनसंख्या के आधार पर हमको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी भर्ती की जाए। यही हमारी मांग है। प्रशासनिक सेवा में आज तक हमको कोई आरक्षण नहीं मिला है। आज तक हमारे आरक्षण का फायदा दूसरों ने उठाया है। 12.5 प्रतिशत एस.टी. को आरक्षण मिलता है प्रशासनिक सेवा

(श्री गणेश घोघरा)
में, लेकिन हमारे टीएसपी में भील मीना रहते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, जो अशिक्षित हैं, उनके रीति-रिवाज अलग हैं। भौगोलिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। हमारे पास एक-एक बीघा, दो-दो बीघा जमीन है। इस पर भी हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। हमको 6 प्रतिशत आरक्षण, इस 12 प्रतिशत में से टीएसपी एरिये को अलग दिया जाए। यह हमारे टीएसपी युवाओं की मांग है। इस वजह से कई बार हमारे आंदोलन हुए हैं, कई बार हमने ज्ञापन दिये हैं। हमारी यह मांग पूरी नहीं हुई है। मैं लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री जी, सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि क्या आपत्ति है? उस 12 प्रतिशत में से आधा हमको, टीएसपी को दे दिया जाए। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। अगर हमारी यह मांग पूरी हो गयी तो हमारे टीएसपी के आदिवासियों का, भीलों का भला हो जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं। हमारे जो इधर विपक्ष के साथी बैठे हैं, ये मांग करने के लिए तैयार नहीं हैं। इनको पता है हमारी टिकट कट जाएगी। टिकट कट जाए लेकिन ये लिखा है कि सभा में आये हो तो सत्य बोलो। सत्य बोलना पड़ेगा।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट। जैसे इन्होंने बताया कि मुख्य मंत्री जी तो खाली झुनझुना दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार थी, एक नींव भी कहीं रखी हो तो बता दीजिए। मुख्य मंत्री जी ने कांग्रेस की सरकार थी तब हर पंचायत में राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन बनाया था। इनकी सरकार आयी तब खाली दस रुपये का कलर लाकर उसका नाम बदलने का काम किया है। ये विकास नहीं करते हैं। मोदी जी कह रहे थे कि 15 लाख खाते में आएंगे, कहां गये 15 लाख? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहां गये रोजगार? अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी कह रहे थे। कहां गये अच्छे दिन? आज जो 1100 में आपकी टंकिया मिल रही हैं, गरीबों के पास, वह टंकिया जहां बकरी बांधते हैं, गाय-भैंस बांधते हैं, वहां टंकिया पड़ी हुई हैं और वापस लोग चूल्हे पर रोटियां बना रहे हैं। ये मोदी जी के अच्छे दिन थे क्या? आज महंगाई बढ़ा दी, आज बेरोजगारी बढ़ा दी, और नरेगा खतम करने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चाहते हैं कि गरीबों को रोजगार नहीं मिले। ये इनकी सोच है।

आप विकास नहीं करना चाहते हैं। खाली गाय के नाम पर, गाय को क्या खिलाते हैं, ये भी पता नहीं होगा आपको। हम तो गाय पालते हैं, गाय

(श्री गणेश घोघरा)

का गोबर उठाते हैं, उसका दूध निकालते हैं। आप कहते हैं कि हम गो माता के पूजक हैं। गाय रखते नहीं हैं और फिर गाय की बात करते हैं। आप सिर्फ बातें करना जानते हैं, विकास करना नहीं जानते हैं आप। लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी, इतना काम किया है, जो मांगा वह दिया है। मेरी विधान सभा में मैं कहता हूं और मेरी विधान सभा के लोग भी सुन रहे होंगे आज तक इतना काम नहीं हुआ है जो इन दो साल में काम हुआ है।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। विराजिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): मैं पांच साल नहीं मानता हूं, दो साल तक तो कोरोना था। दो साल में खाली इतना विकास किया है।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे एक मिनट और बोलने का समय दीजिए।

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज, सहयोग कीजिए। आठ बजे तक का टाइम निर्धारित है, प्लीज।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था आज बहुत शादियां हैं। पूरा राजस्थान, बिजली मंत्री जी, इस वक्त आपने उपहार दे दिया, कटौती में है। मैं 5 मिनट के लिए बाहर गया, पूरे राजस्थान में विशेष तौर पर शेखावाटी में 6 बजे से लेकर ऐसी कटौती कर रखी है, ये उपहार आप दे रहे हैं। ये खा जाएगा आपको।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, बजट 2023-24 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बजट की बहस में बढ़-चढ़कर भाग लिया और बजट की सराहना करने का प्रयास किया।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप सनसनी फैला रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरी नजर में यह बजट नीतिगत बजट न होकर पूर्णतया राजनीति से प्रेरित बजट लग रहा है। मैं सीधे-सीधे, क्योंकि समय का अभाव है और आप मुझे पांच मिनट में ही टोक देंगे, यह मुझे पहले ही पता लग गया।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मैं सीधे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ बात रखना चाहूंगी और ये भी कहना चाहूंगी कि अगर पिछले बजट का इम्प्लीमेंट होता तो बहुत अच्छा होता क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं पिछले बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हुई। पूरे राजस्थान के अंदर हुई। अभी भी सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चिरंजीवी योजना में 10 से 25 लाख रुपये की जो सीमा बढ़ाई है, बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद देती हूं इस बात के लिए लेकिन मेरा यह निवेदन है, यह करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम इस बात को जानते हैं कि यदि हम मंदिर में भी जाते हैं, जिस मन से, जिस भाव से देवता के सामने खड़े होंगे, निश्चित तौर पर भगवान उसी मन से हमें आशीर्वाद देंगे। हम इस बात से अंदाज लगाएं कि अगर राजस्थान में चिरंजीवी योजना में 300 करोड़ रुपये का अगर पूरे प्रदेश का बजट बकाया हो तो निश्चित तौर पर अस्पताल में जब भी कोई भी पेशेंट जाएगा तो उसे एक बार जरूर धिक्कारा जाएगा। इस बात को लगातार देखने का मौका हमें मिल रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से सभी अस्पतालों का जो बजट है चिरंजीवी योजना का, उसे ट्रांसफर किया जाए, उसे उनको दिया जाए ताकि समय पर पेशेंट को उचित इलाज मिले।

साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो घोषणाएं की थीं, सीधे मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही बात रखना चाहती हूं, वह भी इसलिए रखना चाह रही हूं कि सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट के 31 नंबर पैरे में यह बात कही, नेल्सन मंडेला का जो उन्होंने कथन दोहराया 'कि शक्तिशाली हथियार हमारी शिक्षा है, अगर इसका इस्तेमाल हम अच्छे-से करेंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया बदल सकते हैं।' मेरा आपसे निवेदन है कि आपने पिछले बजट में जो घोषणाएं की थीं माडल स्कूल, उनमें भी कहीं न कहीं बिल्डिंग का अभाव हैं, टीचर्स का अभाव हैं। साथ ही साथ जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, उनमें यदि हम स्टाफ उचित मात्रा में लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा।

पिछली सरकार के समय प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर एक कालेज खोलने की घोषणा की थी। मुझे यह पता नहीं है कि मेरी विधान सभा जिसमें तीन उपखण्ड आते हैं और जो 150 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, आखिर में क्या कारण है कि पिछली सरकार के समय घोषणा हुई, जैसे ही सरकार बदली वह ठंडे बस्ते में चली गयी? अभी-भी मैं सुन रही हूं, मैं जिस जिले से आती

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हूं, बूंदी जिले में आप देखिए एक विधान सभा में 5-5 कालेज दे दिए मुख्य मंत्री महोदय ने। अभी मेरे से पूर्व सम्माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 7 कालेज मेरी विधान सभा में मिले हैं। आखिर में क्या कारण है, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, मेरी जनता के लिए मैं मांग करती हूं कि जब वह बजट पर जवाब दें तो मेरी इस घोषणा को पूरी करें कि मेरे तीनों ही उपखण्ड में एक कालेज, जो पिछली सरकार के समय घोषणा हुई थी, उसको खोलने का प्रयास करें।

साथ ही साथ लाखेरी में कालेज खोला जाए। इन्द्रगढ़ में एग्री कालेज खोला जाए, इसकी भी मैं मांग करती हूं। कापरेन में आईटीआई कालेज, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो भी वहां से एमएलए थे, सी.एल. प्रेमी जी, उन्होंने शिलान्यास भी कर दिया था। मुझे आज तक पता नहीं है कि सात साल, आठ साल में वह हमारा आईटीआई कालेज कहां संचालित हो रहा है? अभी तक उसका अता पता नहीं है। केशोरायपाटन में अगर गर्ल्स कालेज भी खोलेंगे तो निश्चित तौर पर वहां की बेटियों को बहुत बड़ा लाभ उससे मिलेगा। करवर में पोलिटेक्निक कालेज खोलने की मैं मांग करती हूं। करवर को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाए।

साथ ही साथ मैं यह भी मांग करना चाहूंगी कि पिछली बार अधिकारियों ने पूरी तैयारी की थी क्योंकि मेरे यहां पर 52-52 पंचायतें पड़ती हैं और 130 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है, पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर आने के लिए पंचायत के लोगों को, मेरा निवेदन है कि जब एसडीएम साहब ने जमीन देख ली, सब कुछ कर लिया तो आखिर में क्या कारण है कि नई पंचायत समिति मेरे यहां पर नहीं खुल पाई? इसकी भी मैं मांग करती हूं। सम्माननीय सीएम साहब जब भी जवाब दें तो मेरी इस बात को बड़े गौर से सुनकर वहां की जनता के लिए न्याय प्रदान करें और इसकी घोषणा करें।

साथ ही यह भी निवेदन करती हूं कि जो मिसिंग लिंक सड़कें मुझे गत वर्ष मिलीं और इस बार भी जो मिलीं, उनका तुरंत प्रभाव से काम पूर्ण किया जाए।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साथ ही साथ यह भी मैं मांग करना चाहूंगी कि सम्माननीय सीएम साहब ने पिछली बार बजट में घोषणा की थी चम्बल नदी पर चाणदा पर पुलिया की, क्योंकि नाव पलटने से

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कई डैथ्स वहां पर हो चुकी थीं, उसका भी तुरंत प्रभाव से काम शुरू किया जाए। अभी तक उसका काम शुरू नहीं हो पाया है। साथ ही साथ दो बजट हो चुके हैं, मेज नदी की पुलिया पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और लाखेरी के अंदर, वहां भी सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी, अभी तक पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कब तक उसका काम शुरू होगा? इसकी भी मैं मांग करती हूं। साथ ही अरनेटा में फ्लाईओवर की सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी, उसका भी काम तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, वक्ता डिस्टर्ब हो रही हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): केशोरायपाटन का जो फ्लाईओवर है, सात साल उसको होने जा रहे हैं और सात साल में भी जिस तरह से चींटी चलती है, उस चाल में उसका निर्माण हो रहा है। तुरंत प्रभाव से उसे भी पूर्ण किया जाए।

अधिकारियों ने नया एमडीआर रोड घोषित करने के लिए, जेथलवाला, अरनेटा टू जेथल से रायथल है, उसकी भी घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम वहां की जनता के लिए होगा।

अवैध खनन के लिए सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने खनन नीति बनाने की घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से इतना-सा निवेदन करना चाहती हूं कि इस बात को भी हमें दिखाना चाहिए कि जो ख़ानें 6-6, 8-8 साल पहले पूर्ण रूप से पूरी तरह से कट चुकी है, उसके बावजूद भी उन खानों के नाम से, खान मालिक करोड़ों में एक लेन वालों को दे रहे हैं, आस-पास के पूरे के पूरे गांव को खोदकर फेंक दिया, इस बात पर भी हमारे अधिकारी ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर वहां बहुत अच्छा काम होगा। अवैध खनन की वजह से लगातार लड़ाई-झगड़े, एक्सीडेंट हो रहे हैं। नये जीएसएस....

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैं तो मांग ही कर रही हूं।

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरी 14 पंचायतों का प्रस्ताव बनाकर पहले भी भेजा।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। विराजिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, जिन्होंने राजस्थान की जनता को 15वां बजट पेश किया, लगभग 170 पृष्ठ के इस बजट में पृष्ठ संख्या 3 है, विपक्ष में बैठे हुए लोगों को पीड़ा हो रही है, मुख्य मंत्री महोदय ने पृष्ठ संख्या 3 में 3 चीजें की हैं, वह इनको पच नहीं रही है।

माननीय सभापति महोदय, गरीब की झोंपड़ी होती है, वह 200 रुपये की मजदूरी करता है, सुबह से शाम बाहर रहता है, उसका बिल आता था, परिवार का जीविकोपार्जन करता था, उसके परिवार को शिक्षा दिलाता था, उसमें खर्च हो जाता था, उसके परिजनों से वह बिल जमा नहीं होता था। उसका कनेक्शन काट दिया जाता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वह अंधेरे में रहता था। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हम सबकी भावना को ध्यान में रखते हुए पिछले बजट में 50 यूनिट और इस बजट में 100 यूनिट बिजली फ्री करके उसको राहत देने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, विकलांग पेंशन थी, विधवा पेंशन थी, वृद्धावस्था पेंशन थी, 500 व 750 रुपये मिलते थे, उसको बढ़ाकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 1,000 किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस टाइम तक 384 रुपये का सिलेण्डर मिलता था, 68 रुपये में डीजल मिलता था, 72 रुपये में पेट्रोल मिलता था, 40 रुपये किलो में सरसों का तेल मिलता था, 55 रुपये किलों में दालें मिलती थीं। आज 2023 में पेट्रोल 108 रुपये लीटर, डीजल 95 रुपये लीटर, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर, गैस का सिलेण्डर 1100 रुपये, यह है आपका नारा। आपने 2014 में कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब तो 9 साल हो गये, आपको 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। आपने कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगुनी होगी। 2022 खतम हो चुका है, 2023 चल रहा है, किसान की आय कहां दुगुनी हुई?

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। यह कह रहे हैं कि चुनावी बजट है, यह क्रियान्वित नहीं होगा। यह चुनावी बजट है और क्रियान्वित नहीं होगा तो फिर आप में से कोई कालेज की मांग कर रहे हैं, कोई सड़कों की मांग कर रहे हैं, कोई सी एच सी की मांग कर रहे हैं, कोई पी एच सी की मांग कर रहे हैं। जब यह बजट पूरा नहीं होगा, इसके लिए व्यवस्था नहीं है तो मांग क्यों कर रहे हो? आपको मांग करने का अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत्तबहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बारां ज़िले में जो काम दिए गये हैं, वह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हम राजस्थान के उस ज़िले से आते हैं, जहां दो बार वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री रही हैं, उनका खुद का लोक सभा क्षेत्र रहा है, वह पांच बार सांसद रही हैं, उनका बेटा चार बार सांसद, इसके बाद भी बारां जिला विकास के लिए तरस रहा था। बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैंने निवेदन किया था कि बारां, हाड़ौती के किसानों का उत्थान करना है तो आपको परवन वृहद् सिंचाई परियोजना को स्वीकृत करना होगा। आपने उसमें 8 हजार करोड़ रुपये सैंक्शन किये, उसका काम चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि उस परवन वृहद् सिंचाई परियोजना की धीमी गति चल रही है, उसमें तीव्रता लाई जाए। हम सितम्बर, अक्टूबर में आचार संहिता के पहले उसका पानी छोड़ें और किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा किसानों को 2 हजार यूनिट प्रतिमाह छूट देने का काम किया गया है। आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यही निवेदन है, आपने 2 हजार यूनिट कहा है, इसमें लगभग 11 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मेरा राजस्थान के किसानों की तरफ से निवेदन है कि एग्रीकल्चर की थ्री फेज की बिजली किसानों के काम आती है, उसको 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, आपका जो मापदण्ड है, उसको एग्रीक्लचर के लिए फ्री करने की घोषणा करने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली साल 10 करोड़ रुपये दिए थे, उससे पहले 5 करोड़ रुपये दिए थे, इस बार 10 करोड़ रुपये का बजट, विकास कार्य के लिए हर विधान सभा क्षेत्र में देने की घोषणा की है। मेरा निवेदन है कि जो ग्रामीण इलाका होता है, किसी के 200 गांव होते हैं, किसी के 250 गांव होते हैं,

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

किसी के 300 गांव होते हैं, उसमें 10 करोड़ रुपये को डिवाइड करने में बहुत परेशानी आती है, इसलिए इसको बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां हैण्डपम्प हैं, वहां वॉटर लेवल बहुत डाउन हो चुका है, 350, 400, 500 फीट पर पानी निकलता है। आप हैण्डपम्प सैंक्शन करते हो वह सक्सेस नहीं होते, इसलिए हर विधान सभा क्षेत्र में, जहां पर डार्क जोन है, कम से कम 50 ट्यूबवैल की आप बजट में घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, स्कूल मिडल से हायर सैकण्डरी कर दिए, सेकण्डरी से हायर सैकण्डरी कर दिए लेकिन कालांश, कक्षा के रूम पर्याप्त नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि जीर्ण-शीर्ण कमरे हैं, उनका जीर्णोद्धार करवाया जाए। अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, बारां नगर परिषद् की हालत सही नहीं है, उसमें 11 गांवों को और मिलाया गया है, इसलिए वहां विकास की जो गति मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। मेरा निवेदन है कि 50 करोड़ आधारभूत ढांचा संरक्षण के लिए बारां नगर परिषद् को देने की घोषणा करें। बारां ज़िले में आस्था का केन्द्र डोल तालाब है, जिसमें आपने पिछली बार 25 करोड़ रुपये दिए थे, उसका काम चल रहा है, उसके सैकण्ड फेज के लिए मैं 50 करोड़ रुपये और घोषणा करने की मांग करता हूं। बारां नगर परिषद् की जनसंख्या लगभग 2 लाख के ऊपर है, इसलिए इसको नगर निगम बनाये जाने की मांग करता हूं। अटरू नगर पालिका को 'ए' श्रेणी की बनाये जाने की मांग करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में, क्योंकि एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करता है, बिजली का वोल्टेज किसानों को नहीं मिल पाता है। मेरे बारां-अटरू विधान सभा में कटावर, रीछंदा, माथना, खुरी, खरखड़ा रामलोथान में 33 केवी जीएसएस बनाए जाएं, साथ ही सहरोद में 132 केवी जीएसएस बनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बारां का डिपो मध्य प्रदेश, श्योपुर से शिवपुरी से, गुना से, झालावाड़ से जुड़ा हुआ है लेकिन वहां यात्रियों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस पर कम से कम 10 करोड़ रुपये उसके जीर्णोद्धार के लिए, यात्रियों को बैठने के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, छाया के लिए घोषित करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में शेरगढ़ वन्य जीव

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

पर्यावरण में आता है, इस नदी से उस पार जाने के लिए लोगों को 30 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आना पड़ता है। अगर नरसिंहपुरा से शेरगढ़ के बीच छोटी पुलिया बन जाएगी तो उन लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि 30 किलोमीटर का चक्कर काटकर आना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री गहलोत साहब को तीसरी बार मौका दिया। जो बजट पेश किया गया है, उस बजट को लेकर गांव की चौपाल की बात करो, गरीब की बात करो, किसान की बात करो, नौजवानों की बात करो, हर व्यक्ति इस बजट की प्रशंसा कर रहा है। आलोचना करने वाले लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।

केन्द्र का भी बजट पेश हुआ है। हम उन ज़िलों में से आते हैं जहां 13 जिले ई आर सी पी योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं। हमारे ज़िले में 600 किलोमीटर नदियां हैं। बरसात के समय बाढ़ आती है, गांव के गांव उजड़ जाते हैं, लेकिन जब किसान को एग्रीकल्चर के पानी की जरूरत पड़ती है तो एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। ई आर सी पी योजना के तहत, चाहे बारां ज़िले की परवन नदी हो, पार्वती नदी हो, कालीसिंध, अंडेरी, इस प्रकार की नदियां जिनको रोककर, उसका पानी रोका जाए तो 13 ज़िलों के लोगों की मांग है, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, खेती के पानी की समस्या हो या जीव-जन्तुओं के पीने के पानी समस्या हो, उन सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए मेरा प्रतिपक्ष के नेताओं से निवेदन है कि माननीय प्रधान मंत्री जी जिस प्रकार दौसा में आये, उन्होंने इस पर नहीं बोला, मेरा आप सबसे निवेदन है कि 13 जिलों के किसानों की, लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय को यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने राजस्थान की जनता को गणेश मानकर, यह बजट पेश किया, इसको क्रियान्वित करने में आपको गति देनी होगी।

मैं राजस्थान की जनता की तरफ से और मेरे बारां जिले की जनता की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो बजट पेश किया है, वह एक ऐतिहासिक बजट है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, तीन दिन से बराबर इस सदन में बजट की चर्चाएं चल रही हैं और पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। आज मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह पक्ष वाले बजट की तारीफ करते हैं और विपक्ष वाले बजट की आलोचना क्यों करते हैं, यह बात आपको समझनी होगी। क्योंकि इस बजट में जो आपने पक्ष वालों को दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री पब्बारामजी विश्नोई, सदन में ऐसे क्रॉस न करें। ध्यान रखें।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): केवल इस बजट में खोदा पहाड़ और निकली चुहिया हाथ लगी है क्योंकि मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती है और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता है, इसलिए महत्व सबको देना चाहिए।

मैं बराबर यह देख रहा हूं। आज मैं बात करता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र और जिले की तो 2021-22 में खानपुर और मनोहर थाना पेयजल परियोजना की घोषणा हुई थी, आज तक उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है।

आज मैं बात करता हूं कि झालावाड़ जिले में ट्रोमा सेंटर की घोषणा की, आज तक भी उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। मैं बात करता हूं ज्योतिबा फुले वाचनालय की, प्रत्येक जिले में यह खोले जायेंगे, तो वह आज तक भी वाचनालय मेरे जिले में नहीं खोला गया है। मैं गुलेंडी और कालिखा परियोजना की बात करता हूं तो वह भी आज तक उसकी भी पेयजल हेतु कोई क्रियान्विति नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करता हूं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन चार वर्षों में एक भी पी.एच.सी. को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। चाहे वह जावर हो, गेहूंखेड़ी हो या भालता हो या सरड़ा हो, एक भी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। सी.एच.सी. को उप जिला अस्पताल में घोषित नहीं किया गया है तो मैं मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं आपके माध्यम से, मैं मांग करता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि आप जावर, गेहूंखेड़ी, भालता और सरड़ा को पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करें और मनोहर थाना ब्लाक पर सी.एच.सी. को उप जिला अस्पताल में घोषित करें और वहां 30 ही बेड है उसको 50 बेड करने की घोषणा करें।

दूसरी बात, मैं यह मांग करता हूं कि जो हमारे फ्लड में पुलियाएं

(श्री गोविन्द प्रसाद)

क्षतिग्रस्त हुई हैं, पिछले दो वर्ष से लगातार बेमौसम बरसात और लगातार अतिवृष्टि से जो पुलिया क्षतिग्रस्त हुई हैं, वे बिलकुल भी आज तक नहीं बनी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंजीतजी।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): मैंने हमेशा यह मांग की है पिछले चार वर्षों में कि ब्रिज और पुलियाओं की घोषणा की जाये तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं मांग करता हूं कि देवरी जागीर से हरनावदा रोड के बीच नेवज नदी पर हाई लेवल ब्रिज की मांग की थी मैंने और मैंने केलखोयरा पुलिया की मांग की थी, गेहूंखेड़ी पुलिया की मांग की थी, एक भी पुलिया मुझे नहीं दी गयी है। सरड़ा से मानपुरा के बीच की पुलिया या गुराड़खेडा से भुलन खेड़ी के नेवज नदी पर पुलिया, यह एक भी उन्होंने मुझे पुलिया के सम्बन्ध में कुछ नहीं दिया है।

मैं यह मांग करता हूं कि आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया है। न तो यू.पी.एस. को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है और न इन्होंने पी.एस. को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया। चार वर्ष होने को जा रहे हैं, आज तक भी इन्होंने एक भी विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया है।

नई सड़कें, नई सड़कें तो आज तक भी मुझे एक भी नहीं दी हैं। पेच वर्क और दस करोड़ रुपये की सड़कें दी हैं, वे भी बिना विधायक की अनुशंसा से इन्होंने सड़कें बनाई हैं, तो अब मैं यह निवेदन करता हूं कि आने वाले बजट में, दस करोड़ रुपये के बजट में विधायक की स्वीकृति अनिवार्य की जाये।

दूसरी बात, जो हैण्डपम्प लगाये गये हैं वे भी पूर्ण रूप से नहीं लगाये हैं, उनको भी पूर्ण रूप से लगाया जाये। जो पहले चालीस हैण्डपम्प हमें दिये गये थे, वे भी आज तक नहीं दिये गये।

मिसिंग लिंक रोड के लिए मैं बीन्दा से उगेना, उगरपुरा से नयापुरा, टोड़री जगन्नाथ से एन.एच. 37 महाराजपुरा रोड तक, तलवाडिया से खेड़ला तक, मोग्याबेह से बासखेड़ा, जावर रोड के मोड से हरनावदा रोड तक, देवरी खुर्द से कोटड़ा, ताजपुरिया से किला अमरगढ़, लावासर से टाण्डी साहेनपुरा तक, इन नये मिसिंग लिंक की मांग करता हूं और नये रोड के लिए आमेटा से उदयपुर, मोतीपुरा, चित्तौड़ी, कासखेड़ली, सेमली नाबाद, भवानीपुरा, गोकुलपुरिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): कोड़ियापाटन, सेमली गोकुल, सागोनी, गुराड़खेड़ा, नीमखेड़ा, मालाटोटा, मानपुरा, कालापाटा, शिवपुरा, टोलखेड़ा रामपुरिया, बलवटपुरा, हमीरपुरा, धनवास, ये जो 73 गांव हैं मेरे यह सड़क के अभाव से नहीं जुड़ पाये हैं, तो मैं मुख्य मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि इन गांवों को सड़क से जोड़ा जाये ताकि मेरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहे।

दूसरी बात, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरे मनोहर थाना में एक महाविद्यालय है, वहां पर कन्या महाविद्यालय खोला जाये। जिस तरह से वसुन्धराजी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले थे, उसी तर्ज पर मैं मुख्य मंत्रीजी से पूरे सदन की ओर से यह मांग करता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कन्या सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले जाएं। मैं यह मांग करता हूं इस बात की कि आज के युग में इसकी आवश्यकता है। आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो और कन्याओं के लिए ही स्कूल नहीं है। जितने भी कन्याओं के स्कूल हैं उनको क्रमोन्नत किया जाए क्योंकि यह आवश्यकता है आज के युग की। मैं यह मांग करता हूं कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर कन्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं।

दूसरी बात, मैं आपसे यह भी मांग करता हूं कि मेरे प्राइमरी स्कूल जिनको उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना है, काजलिया, बिलोनिया, केंवचीखुर्द, बरड़ावदा, कटफली, पंचपीपली, बीनागंज रोड, कॉलोनी मनोहर थाना, नेशचारनान और बाड़िया गोरधनपुरा, ये पी.एस. हैं, इनको यू.पी.एस. में क्रमोन्नत किया जाये।

सिंचाई हेतु माइक्रो डैम बनाये जायें। मैं चार वर्षों से निरंतर मांग कर रहा हूं। बोरबन्द, खेरदन्ता, कोहड़ीझर, पीतापुरा, नानागरड़ा, आवलहैड़ा, बिसलायी, पछेटा, सेमलाबेह, टाण्डी, टोडरीमीरा, दांगीपुरा, खाताखेड़ी और लसुड़ियागेंद, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और पिछड़े क्षेत्र होने के नाते यहां पर लोग पलायन कर जाते हैं।

श्री सभापति: श्री रूपा राम मुरावतिया।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): अगर यह माइक्रो डैम बन जायेंगे तो पलायन रुक जायेगा क्योंकि सिंचाई और पेयजल हेतु इनको पानी उपलब्ध होगा।

श्री सभापति: श्री रूपा राम मुरावतिया।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): मैं यह निवेदन करता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि मेरी मांगों पर ध्यान दें और मेरे मनोहर थाना में सी.डी.पी.ओ. कार्यालय में एक भी सुपरवाइजर नहीं है और ब्यूरोक्रेसी के तो हाल बेहाल हैं।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): 000

श्री सभापति: विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है। आपके आगे आने वाले वक्ता का समय कम हो रहा है। विराजिये प्लीज। प्लीज, सहयोग करें।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): 000

श्री सभापति: सहयोग करें, आपके आगे आने वाले वक्ता का समय खराब हो रहा है। प्लीज।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट वर्ष 2023-24 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं या हम सदन में फिर से आयें या न आयें, आवाज हमारी यहां गूंजती रहेगी। लोग पूछें या न पूछें हमारी आत्मा हमें यह पूछती रहेगी। हमको जनता ने विकास और समस्या समाधान का सदन में आने का मौका दिया, अब हम खुद ही यह फैसला करें कि हमने विकास जनता का किया या हमारा विकास करके जनता को धोखा दिया? धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट पढ़ तो लूं।

श्री सभापति: धन्यवाद दे दिया, फिर काहे का?

श्री रूपा राम (मकराना): मैं टू द पाइंट बोलूंगा आज पहली बार ही तो। मैं पहली बार ही टू द पाइंट बोलूंगा, आप सुनो, साहब। महेन्द्रजी साहब, सुनो। चूंकि सात मिनट ही बोलना है, फिर कहा कि पांच मिनट ही बोलो, अब कह रहे हैं कि चार ही मिनट बोलो, तो बोलने में फायदा क्या है? ऐसे तो बाहर रोजाना ही बोलते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने जो बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना में एक भी विकास के कार्य की बजट में घोषणा नहीं की गयी है। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र के, मकराना की जनता के साथ घोर अन्याय है, धोखा है।

महोदय, संगमरमर नगरी मकराना से सरकार को हर साल करोड़ों रुपये का राजस्व होता है, जिसमें फिर भी मकराना को एक भी पैसा विकास का नहीं दिया, यह मेरे लिए और मेरी जनता के लिए दु:ख का विषय है।

(श्री रूपा राम)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से विधान सभा क्षेत्र मकराना की समस्या समाधान, विकास कार्यों की स्वीकृति के बाबत अनुरोध किया था, वह इस प्रकार है-

मकराना तहसील के नये भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में गच्छीपुरा उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने बाबत, गच्छीपुरा गौण मण्डी को कृषि उपज मण्डी समिति की स्वीकृति एवं भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति। ग्राम पंचायत रानीगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

ग्राम बेसरोली व ग्राम गेलासर में 132 केवी जीएसएस निर्माण के संबंध में। ग्राम बुड़सू में 3.15 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर की स्वीकृति के संबंध में।

ग्राम पंचायत जूसरी के धानक्या नाडा में ओवर हैड पानी की टंकी के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में।

नगरपालिका बोरावड़ से सबलपुर-मामडोली-बेसरोली-खुड़द माताजी गेहडा कलां गच्छीपुरा तक 30 किमी व 7 मीटर चौड़ी डामरीकरण सड़क निर्माण बाबत। शहीद हरिराम भाकर बाईपास से जूसरिया-बुड़सू-भरनाई-नान्दोली चांदावता-गेलासर तक 30 किमी व 7 मीटर चौड़ी डामरीकरण सड़क निर्माण बाबत।

मकराना में खोले गये महाविद्यालय के भवन निर्माण के बारे में।

ग्राम सबलपुर से नान्दोली मेड़तिया, धांदोली, ततारपुरा, कुचिपला, खेड़ीशिला और बाजोली तक 25 किमी 7 मीटर चौड़ी डामरीकरण सड़क निर्माण बाबत। आपके द्वारा बजट सत्र 2022-23 में घोषित कुचामन-डेगाना एमडीआर सड़क से कालवा बड़ा से डेगाना तक 30 किलोमीटर वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

अब मैं माननीय कृषि मंत्रीजी को यह निवेदन कर रहा हूं, विधान सभा क्षेत्र मकराना के राजकीय प्रथम श्रेणी चिकित्सालय भाकरों की ढाणी मकराना एवं पशु चिकित्सालय भींचावा के भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

राजकीय पशु चिकित्सालय बुड़सू को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने बाबत, जिसके लिए माननीय कृषि मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 25.01.2023 को माननीय मुख्य मंत्री जी को बजट में शामिल करवाने के लिए पत्र दे चुका हूं, शामिल करने के लिए निवेदन करता हूं।

(श्री रूपा राम)

माननीय सभापति महोदय, कृषि व पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार को विधान सभा क्षेत्र मकराना में निम्न स्थानों पर कृषि पर्यवेक्षक को पदस्थापित करने के साथ ही किसान सेवा केन्द्रों की स्वीकृति बाबत पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत ईटावा लाखा, भैयाकलां, भरनाई, कुकड़ोद, जूसरिया, देवरी, सफेड़बडी, धानणवां, रानीगांव, लोरोली, काशीनगर, मोड़ीचारणा, सबलपुर, मामडोली, निंबड़ी, खारड़िया, खेड़ीशीला, हु ड़िया और डोबड़ी कलां में किसान सेवा केन्द्र खोलने का आग्रह किया गया था, मैं अब भी कर रहा हूं।

मेरे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन विहीन पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण की स्वीकृति बाबत निम्न स्थानों के प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे, जो इस प्रकार से हैं- उप केन्द्र बरवाली, जूसरी, नान्दोली मेड़तिया, बाजोली, बिल्लू, कचोलिया और वीएच रामसिया, मिंडकिया। उपरोक्त संस्थाओं कि लिए भवन निर्माण के लिए पट्टा, भू-स्वामित्व दस्तावेज उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी के कार्यालय में सरकार के पक्ष में स्थानान्तरण कर दिया गया है। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण क्षेत्र में काफी गांव ऐसे हैं जहां पशु चिकित्सा के लिए कोई केन्द्र नहीं होने के कारण पशु पालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उप केन्द्र खोलने बाबत माननीय मंत्री महोदय को पत्र प्रेषित किया गया था जो इस प्रकार से है- ग्राम चांडी, जाखली, जूसरिया, धानणवां, देवरी और भरनाई।

माननीय सभापति महोदय, एक कागज और है। मुझे बैठा मत देना।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी द्वारा बजट घोषणा 2022-23 के बिंदु संख्या 28 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीधे ही उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक मेरे क्षेत्र की नव गठित ग्राम पंचायत लोरोली की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है, जिसकी मैं आपसे आशा रखता हूं कि उसकी घोषणा करें।

महोदय, मेरे क्षेत्र की उप तहसील गच्छीपुरा की श्रीमती पतासीदेवी अग्रवाल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण यहां अध्ययनरत बालिकाओं ने विद्यालय के दरवाजे पर धरना एवं प्रदर्शन करके शिक्षकों को वापस पदस्थापित करने के आग्रह पर मैं स्वयं शिक्षा मंत्री जी से मिलकर

(श्री रूपा राम)

शिक्षकों को वापस लगाने का निवेदन किया था, लेकिन आज तक यहां शिक्षकों को पदस्थापित नहीं किया गया हैं तथा रिक्त स्थान होने से बालक-बालिकाओं की पढाई बाधित हुई है। मैं चाहता हूं कि स्कूलों में अध्यापक लगाये जाएं। मैंने शिक्षा मंत्री जी को पत्र प्रेषित करके मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना के अनेक प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों और सभी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, उनके बारे में निवेदन किया है। उन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने बाबत आग्रह किया था।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैंने मेरे क्षेत्र के अनेक विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने के संबंध में भी माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र प्रेषित किया था। मैं निम्नलिखित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की प्रार्थना करता हूं- जाखली, मकराना, गच्छीपुरा, बेसरोली, जूसरी बाजोली, नान्दोली मेड़तिया, मनाना, रानीगांव, ईटावा लाखा में नये कृषि संकाय खोलने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पूर्व में ग्राम मनाना एवं बुड़सू में खेल काम्प्लेक्स खोलने की भी मांग की थी, मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर भी ध्यान देगी।

गच्छीपुरा में दूर-दूर के कई गांव हैं, उसमें मैं कालेज खोलने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने 94 गांवों के नाम लिए हैं।

श्री रूपा राम (मकराना): नहीं, 60-70 ही हैं।

श्री सभापति: जल्दी रखिये अपनी बात।

श्री रूपा राम (मकराना): मैं काम की बात कर रहा हूं। आपके डर से मैंने कविता तो बन्द ही कर दी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कई ग्राम ऐसे हैं जो अब तक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं से वंचित हैं। क्षेत्र में अनेक जगह पर उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं लेकिन आज तक भवन से विहीन हैं। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि उप स्वास्थ्य केन्द्र नावद, मामडोली, शिवनगर (बेसरोली), शिव मंदिर कुचामन रोड जूसरी, आदर्श नगर जूसरी भैयाकलां, अमरसर, विजयपुरा, कूकड़ोद, पुरोहितों की ढाणी जूसरिया, गिंगालिया, गुणावती एवं सिणियां में भवन निर्माण के लिए वित्तीय

(श्री रूपा राम)

स्वीकृति जारी की जाये जिससे यहां के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मरीजों को देखने के लिए एक स्थायी जगह मिल सके।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र के अनेक उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने की जरूरत है। मैं ग्राम ईटावा, लाखा, भरनाई, गिंगालिया, इन्दौखा, बाजोली, खारडिया, सबलपुर, देवरी, आसरवा, बरवाली, बरवाला एवं मिण्डकिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री रूपा राम (मकराना): मैं मेरे क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगांव, जाखली, मनाना, जूसरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गच्छीपुरा को 30 बेड से बढाकर 50 बेड में क्रमोन्नत करने की विशेष मांग करता हूं।

बस लास्ट 30 सैकण्ड मुझे और दे दिये जाएं।

श्री सभापति: जल्दी करो।

श्री रूपा राम (मकराना): गांवों में इस वक्त बिजली का संकट है, रबी की फसल तैयार हो रही है, आप कृपया बिजली दीजिये और जो इस बरसात खराबे से किसानों को नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दीजिये।

पेपर लीक में बच्चों के साथ में आपने जो भविष्य बर्बाद किया, उसके परिवार का, बच्चों का तो श्राप लगेगा और आप उस श्राप से चले जायेंगे। अब बैठ जाऊं, इससे ज्यादा क्या करूं?

श्री सभापति: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, मैं सीधे ही आपकी अनुमति से उद्योग मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र है, उसमें बेवंजा में जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां के किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी जो मांगें हैं...

श्री सभापति: आपके पास एक मिनट का समय है। आप टेबल करा दो।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): चाहे राजस्व से संबंधित हों, चाहे और भी कोई हों, तो उनको आप सुनें और उनकी मांग को सरकार पूरी करे। मैं आपकी अनुमति से इसको टेबल करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: हां, मैं अनुमति देता हूं।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में भी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार लोक-लुभावनी घोषणाएं की थीं, उनमें से कुछ भी धरातल पर नहीं उतर पायी हैं, बाकी का क्या होगा, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। मैं यह दो पंक्तियां आपके सामने कहना चाहूंगा:

हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे,

पर राजस्थान की जनता आपको ढूंढेगी, आप कहां पर होंगे?

इन बातों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो यह आदेश संयुक्त सचिव के माध्यम से जारी किया है पीसांगन उपखण्ड कार्यालय को स्थानांतरित करने का, मुख्य मंत्रीजी वैसे भी कार्यालयों की घोषणा कर रहे हैं, तो कम से कम मेरे यहां करें।

(माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप लाम्बा के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

श्री सभापति: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 16 फरवरी 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.59 बजे गुरुवार, दिनांक 16 फरवरी 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मेड़ता में उप स्वास्थ्य केन्द्र से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय

22. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में सभी 53 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चिकित्सा संस्थान स्वीकृत हैं। इनमें से 2 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 15 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 36 पर उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चिकित्सा संस्थान उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की घोषणा

31. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना से वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक जिला नागौर में कितनों को लाभान्वित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के आधार पर ही युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की घोषणा नहीं की गई वरन् मुख्यमंत्री लघु उदयोग प्रोत्साहन योजना की घोषणा वर्ष 2019 में की गई। इस योजनान्तर्गत 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 25 लाख रुपये से अधिक एवं 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 5 करोड़ रुपये से अधिक एवं 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। गत तीन वर्षों में नागौर में योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु स्वीकृत ऋण प्रकरण निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष	**लाभान्वित व्यक्ति**
2019-20	140
2020-21	296
2021-22	231

(2) योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 25 लाख रुपये की श्रेणी में 10,000 का लक्ष्य है तथा 25 लाख रुपये से 5 करोड़ की श्रेणी में 750 एवं 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ की श्रेणी में 30 का लक्ष्य वित्त विभाग से निर्धारित है।

वार्षिक वित्तीय भार के अनुरूप लक्ष्य निर्धारण किया जाता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में नवीन सीटी स्कैन मशीन की स्थापना

15. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार चित्तौड़गढ़ में संचालित श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में नवीन सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। डी.एम.एफ.टी. मद से चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में नवीन सीटी स्कैन मशीन क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में सप्लाई कर इन्सटाल कर दी जायेगी।

आहोर में नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना

16. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में विगत तीन वर्षों में कितने नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये व भवन निर्माण हेतु कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रसियावास खुर्द (पावटा), पलासिया (पावटा), सुमेरगढ़ खेड़ा (सिवणा), पाण्डगटा (ऊण) में मापदण्डों के अनुसार उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक खोले गये उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पीपलडा की ढाणी
2. कोराणा
3. रेवडाकलां

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र आहोर में विगत 3 वर्षों में निर्माण हेतु खर्च की गई राशि का बजट मदवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) ग्राम रसियावास खुर्द (पावटा), पलासिया (पावटा) पंचायत समिति आहोर एवं सुमेरपुर खेडा (सिवणा), पाण्डगटा (उण) पंचायत समिति जालोर जिला जालोर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में वर्तमान में कोई भी एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान स्वीकृत नहीं है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 03 की ग्रामीण जनसंख्या पर 01 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में गुणावगुण/वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र आहोर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रिक्त पद

17. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्थायी अभिहित अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कुल कितने पद स्वीकृत व कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्ष 2019 से 2022 तक खाद्य सामग्री के कुल कितने सैम्पल भरे गये व उनमें से कुल कितने सैम्पलों में मिलावट पाई गई? वर्षवार एवं जिलावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में विगत चार वर्षों में कुल कितने मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? जिलावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में स्थायी अभिहित अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है, परन्तु विभाग के आदेश क्रमांक 128 दिनांक 09.08.2019 द्वारा मुख्य

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ही जिले में अभिहित अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की हुई हैं। आदेश की प्रति परिशिष्टअ पर संलग्न हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कुल 298 पद स्वीकृत हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 9(1) के तहत राज्य में 18 जून, 2007 से कार्यरत 41 विभागीय कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की हुई हैं। आदेश की प्रति परिशिष्टब पर संलग्न है।

वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नियमित भर्ती होने तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 37 (2) के तहत इस वर्ष आदेश क्रमांक एफ.5(1)चिस्वा/ग्रुप-3/2022 जयपुर दिनांक 02.12.2022 से 31 विभागीय कर्मचारियों को निर्धारित प्रशिक्षण दिलाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक 5148 दिनांक 11.11.2022 से 38 विभागीय कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न हैं।

वर्तमान में 226 पद रिक्त चल रहे हैं।

(2) प्रदेश में वर्ष 2019 से 2022 तक खाद्य सामग्री के कुल 34,525 सैम्पल जांच हेतु लिए गये जिसमें से 9,165 सैम्पल मिलावटी (अमानक) पाये गये। वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में विगत 04 वर्षो में मिलावट के 7342 प्रकरण न्याय निर्णयन अधिकारी एवं 507 प्रकरण सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजसमन्द के बहु उद्देशीय पशु चिकित्सालय में रिक्त पद

18. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजसमन्द में संचालित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में किस-किस संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद पर कार्मिक कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त चिकित्सालय में कितने पशुओं का उपचार किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है व निर्माण की प्रगति क्या है? क्या आबंटित भूखण्ड को अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला राजसमंद का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय नाथद्वारा में स्वीकृत है, जिसमें विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों तथा उन पर कार्यरत कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) जिला राजसमंद के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में विगत 03 वर्षों में कुल 20,731 पशुओं का उपचार किया गया है।

(3) जिला राजसमंद के नाथद्वारा स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए जिला मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट से कुल 5.0 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं जिससे निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

जिला मुख्यालय राजसमंद पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए ग्राम धोईन्दा में 4.15 बीघा भूमि पूर्व में आबंटित की गई थी, जिस पर अतिक्रमण था।

दिनांक 20.01.2023 को जिला प्रशासन के सहयोग से इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ (थानागाजी) में सहायक अभियंता कार्यालय की स्थापना

19. **श्री कान्ति प्रसाद** (थानागाजी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के प्रतापगढ़ में सहायक अभियंता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में सम्मिलित 265 आबाद राजस्व ग्रामों

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के निम्न वर्णित सहायक अभियन्ताओं के अधीन है:-

(अ) सहायक अभियन्ता, उपखण्ड कार्यालय, थानागाजी के अधीन थानागाजी कस्बा एवं 127 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का कार्य 03 कनिष्ठ अभियन्ताओं क्रमशः अनुभाग थानागाजी-शहरी (थानागाजी कस्बा एवं 22 ग्राम), अनुभाग थानागाजी-ग्रामीण (41 ग्राम) एवं अनुभाग, प्रतापगढ़ (64 ग्राम) द्वारा किया जा रहा है।

(ब) सहायक अभियन्ता, उपखण्ड कार्यालय, राजगढ़ के अधीन 109 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का कार्य 02 कनिष्ठ अभियन्ताओं क्रमशः अनुभाग प्रथम, राजगढ़ (राजगढ़ कस्बा एवं 07 ग्राम) एवं अनुभाग द्वितीय, राजगढ़ (102 ग्राम) द्वारा किया जा रहा है।

(स) सहायक अभियन्ता, उपखण्ड कार्यालय, नारायणपुर के अधीन 58 ग्रामों में से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के 29 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का कार्य कनिष्ठ अभियन्ता, अनुभाग नारायणपुर द्वारा किया जा रहा है। उपखण्ड कार्यालय, नारायणपुर के अधीन शेष 29 ग्राम विधान सभा क्षेत्र बानसूर के हैं।

सहायक अभियन्ता, उपखण्ड कार्यालय, थानागाजी के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता अनुभाग प्रतापगढ़ द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र की तहसील थानागाजी (उप तहसील, प्रतापगढ़) के 64 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का कार्य वर्तमान में सुचारू रूप से किया जा रहा है। उक्तानुसार उपलब्ध कार्यभार एवं कार्यक्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय प्रतापगढ़ में सहायक अभियन्ता के नवीन कार्यालय का पृथक् से सृजन किया जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचाराधीन नहीं है।

कोटा व बूंदी में जल जीवन मिशन योजना की क्रियान्विति

20. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रगतिशील जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत शहरों व गांवों में स्थित पक्की सड़कों, गलियों को खोदकर नवीन पाइप लाइनें बिछाई जा रही हैं? यदि हां, तो जिला कोटा व बून्दी जिले में उक्त योजना अन्र्तगत खोदी गई सड़कों व गलियों को पुनः दुरुस्त करने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी व्यय की गई एवं कितनी राशि व्यय किया जाना शेष है तथा कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही लागू किया गया है तथा इसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत/प्रगतिरत वृहद् पेयजल परियोजनाओं तथा अन्य जल योजनाओं (वृहद् परियोजनाओं के अतिरिक्त) के अंतर्गत ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार सड़कें काटी जाकर नवीन पाइप लाइनें बिछाने एवं जोड़ने का कार्य किया गया/जा रहा है।

उक्त मिशन के अंतर्गत कोटा एवं बून्दी जिले में प्रगतिरत पेयजल परियोजनाओं एवं अन्य जल योजनाओं में पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने के कार्यों के अन्तर्गत सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु क्रमश: राशि रुपये 4,531.14 लाख एवं रुपये 6,230.02 लाख के स्वीकृत प्रावधान के विरुद्ध, रुपये 1,460.30 लाख एवं रुपये 2,726.33 लाख की राशि का व्यय माह दिसम्बर, 2022 तक किया गया है।

उक्त वर्णित जिलों में पूर्ण की गई/प्रगतिरत पेयजल परियोजनाओं एवं अन्य जल योजनाओं के अंतर्गत काटी गई सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत, व्यय की गई एवं शेष रही राशि तथा परियोजनाओं/अन्य जल योजनाओं की पूर्णता अवधि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सलूम्बर की ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना हेतु बजट आवंटन

21. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार जल जीवन मिशन योजना में पांच या दस प्रतिशत राशि जमा कर उपभोक्ताओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की ग्राम पंचायतों

(श्री अमृतलाल मीणा)

में उक्त योजनान्तर्गत नि:शुल्क पेयजल उपलब्ध कराने की क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त बजट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को घरेलू जल संबंध द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली अन्त:ग्राम पाइप लाइन जल आपूर्ति अवसंरचना की पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र तथा डीडीपी ब्लाक्स में 5 प्रतिशत) भाग ग्रामवासियों द्वारा वहन किया जाना उल्लेखित है।

उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों में ग्रामवार जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाकर समिति द्वारा राशि एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है।

(2) उक्त मिशन के तहत क्रियान्वित की गई/जा रही बहुग्राम जल योजनाओं एवं वृहद् पेयजल परियोजनाओं के अंतर्गत विलेज ट्रांसफर चैम्बर (वी.टी.सी.)/ग्राम की सीमा तक निर्मित आधारभूत संरचनाओं के कार्यों का संचालन एवं संधारण का कार्य राज्य सरकार द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष निर्धारित बजट प्रावधान के अनुसार किया जा रहा/जायेगा।

बहुग्राम जल योजनाओं एवं वृहद् पेयजल परियोजनाओं के तहत अन्त:ग्राम निर्मित संरचनाओं तथा एकल ग्राम जल योजनाओं के तहत निर्मित समस्त घटकों के रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम पंचायत की रहेगी।

सुमेरपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

22. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जेतपुरा से

(श्री जोराराम कुमावत)

किरवा के बीच ग्रेवल सड़क क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो उक्त सड़क कब तथा किस योजना में बनाई गई थी? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर तीन स्थानों पर बरसात के पानी निकासी हेतु पाइप कल्वर्ड बनाने थे किंतु नहीं बनाये गये? क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क पर उक्त तीन स्थानों पर पाइप कल्वर्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त ग्रेवल सड़क वर्ष 2008-09 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बनाई गई थी।

जी हां। उक्त कार्य महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक कार्ययोजना 2023-24 में सम्मिलित है एवं वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी नहीं। उक्त कार्य की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग पाली से चाही गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।

सूरजगढ़ के सार्वजनिक श्मशानों में विकास कार्य

23. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के कौन-कौनसे गांवों में सार्वजनिक श्मशान बने हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने श्मशानों पर चारदीवारी, टिन शैड व अन्य सामुदायिक सेवाएं पानी, बैठने का स्थान आदि उपलब्ध नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में कितने श्मशानों पर कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे विकास कार्य कराये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के गांवों में बने सार्वजनिक श्मशान स्थलों की सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के श्मशान स्थलों पर चारदीवारी, टिन शैड व अन्य सामुदायिक सेवाएं पानी, बैठने का स्थान आदि का विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(3) वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में श्मशान स्थलों पर किये गये विकास कार्यों एवं उन पर व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सिवाना में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

24. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जो भवन विहीन हैं? क्या सरकार उक्त भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग में केन्द्रांश के कारण नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने हेतु भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार के पत्र, दिनांक 28.07.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि आईसीडीएस सेवा विस्तार हेतु अभी नवीन केन्द्र स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

इसके उपरान्त भी स्थानीय प्रतिनिधियों/जन प्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति के बाबत महिला

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021, 27.08.2021 व 09.02.2022 को पत्र प्रेषित किये गये हैं। जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

(2) प्रतिउत्तर बिन्दु संख्या 1 में ही समाहित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अंतर्गत 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: सिवाना एवं सिणधरी संचालित है। जिनमें से परियोजना सिवाना में 42 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना सिणधरी में 44 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।

आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है। उक्त भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रेवदर में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

25. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के लगभग सभी आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन विहीन उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए पर्याप्त सुविधायुक्त भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रेवदर में बाल विकास परियोजना रेवदर एवं आबूरोड परियोजना का आंशिक क्षेत्र संचालित है। परियोजना रेवदर में 169 एवं परियोजना आबूरोड के 125 केन्द्रों सहित कुल 294 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिनमें से परियोजना रेवदर में 24 एवं परियोजना आबूरोड के 44 सहित कुल 68 आंगनबाड़ी केन्द्र ही किराये के भवनों में संचालित हैं।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित नोर्म्स के अनुसार करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर के विज्ञान नगर एवं जोन्सगंज स्थित रेलवे फाटकों पर आर.ओ.बी. का निर्माण

26. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जन घोषणा-पत्र में एक लाख से अधिक वाहन भार वाले रेलवे फाटकों पर आर.ओ.बी. बनाये जाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो घोषणानुसार विगत चार वर्षों में कितने रेलवे फाटकों पर आर.ओ.बी. निर्माण हेतु स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अजमेर दक्षिण में स्थित विज्ञान नगर एवं जोन्सगंज स्थित रेलवे फाटक एक लाख से अधिक भार वाले वाहनों की सूची में सम्मिलित है? यदि हां, तो उक्त रेलवे फाटकों पर आर.ओ.बी. निर्माण की स्वीकृतियां कब तक जारी कर दी जाएंगी? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त मापदण्ड अनुसार पिछले चार वर्षों में आर.ओ.बी. निर्माण हेतु जारी की गई स्वीकृतियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। अजमेर दक्षिण में स्थित विज्ञान नगर में रेलवे फाटक संख्या-3 पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्य हेतु जी.ए.डी. तैयार कर उत्तर पश्चिम रेलवे को अनुमोदन हेतु दिनांक 26.12.2022 को भिजवाई गई है।

जोन्सगंज में रेलवे फाटक संख्या-1 एवं 50 पर आर.ओ.बी. निर्माण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कार्य हेतु जी.ए.डी. तैयार कर उत्तर पश्चिम रेलवे को अनुमोदन हेतु दिनांक 23.12.2022 को भिजवाई गई है।

जी.ए.डी. अनुमोदन पश्चात् निर्माण कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

निर्माण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर सम्भाग में कारागार की क्षमता

27. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर सम्भाग में कितने कारागार हैं? उक्त कारागारों में कितने-कितने कैदियों को रखने की क्षमता है? उक्त कारागारों में नवम्बर-दिसम्बर, 2022 की समयावधि में कितने-कितने कैदी रखे गये? जिलेवार, कारागारवार व क्षमतावार कैदियों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सम्भाग की कारागारों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार क्षमता से अधिक कैदियों को अन्य जेलों में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर सम्भाग में महिला बंदी सुधारगृह सहित कुल 19 कारागृह हैं। कारागारवार क्षमता व निरुद्ध रहे बंदियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उदयपुर सम्भाग की कुछ कारागृहों में जनाधिक्य की समस्या है। इन कैदियों को यथासम्भव अन्य कारागृहों में जहां जनाधिक्य की स्थिति नहीं है, वहां समय-समय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

खींवसर में जल जीवन योजना के तहत असफल नलकूपों का पुनः प्रारम्भ

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर)

महोदय, उपर्युक्त विषय में सादर अनुरोध है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र छितरी हुई आबादी में बसा हुआ है और अधिकतर लोग ढाणियों में निवास करते हैं, जिनके लिए पेयजल व्यवस्था नलकूपों से होती है लेकिन भावण्डा खुड़खुड़ा कला, ताडावास, आकला, ताडो की ढाणियां, देउ, दांतिणा, बलाया, माणकपुर, पंचारो-बिछओं की ढाणियां, दघवाडी, रावो की ढाणी, शिवपुरा, माडपुरा, साटिका, गुलासर, जसनाथपुरा, नारवा कलां, नारवा खुर्द, पांचौड़ी, विश्नोईयो की ढाणी, भोजास, हनुमानसागर, सोवो की ढाणी पिपलिया, ताडावास, हरसोलाव, खटोडा, पाबूसर, रिया श्यामदास, भाटियो की ढाणी, भेड़, सिंधीपुरा, भोमासर, गुढा भगवानदास इत्यादि सहित अन्य गांवों में जेजेवाई असफल नलकूपों हेतु नागौर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अति. मुख्य अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र अजमेर को स्वीकृति हेतु फाइलें भेजी जा चुकी है। उक्त गांवों से सम्बन्धित फाइल उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है तो यह कहकर निरस्त कर देते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पानी पहुंचा दिया जायेगा, परन्तु जब तक जल जीवन मिशन के तहत कार्य होगा तब तक पेयजल व्यवस्था हेतु त्वरित बजट जारी करवाकर मेरे क्षेत्र में असफल नलकूपों को विभाग द्वारा चिन्हित करवाकर जल्द चालू करावें, ताकि आमजन को पेयजल में हो रही कठिनाई से राहत प्रदान हो सके।

अत: महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में विभाग द्वारा असफल नलकूपों को चिन्हित करवाएं एवं अतिरिक्त बजट जारी करवाने की कार्यवाही को अतिशीघ्र पूरा किया जाकर आमजन को राहत प्रदान करावें। सधन्यवाद।

जालौर में फसल बीमा कम्पनियों द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार फसली नुकसान के भुगतान का अभाव

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा

योजना के अंतर्गत जालौर जिले में फसलों का बीमा बजाज कंपनी दवारा किया जा रहा है। जब कभी भी किसी फसल में नुकसान होता है तो प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने का काम करते समय सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अथवा बीमा कंपनी के कार्मिकों दवारा जाने-अनजाने में ऐसी गलती कर दी जाती है अथवा कमी छोड़ दी जाती है जिसके कारण कृषक को मिलने वाला मुआवजा या तो शून्य हो जाता है अथवा बहुत कम हो जाता है।

ऐसा ही कुछ घटित हुआ रबी 2021 के दौरान जब मेरे विधान सभा क्षेत्र के तिलोडा, हरमू, सूराणा, देता, रोहिनवाडा, पोषाणा, ऊनडी, धनानी आदि गांवों के किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया।

ऐसा ही कुछ खरीफ 2022 के दौरान हुआ जब मूंग एवं ग्वार की फसल की क्रॉप कटिंग के दौरान संबंधित किसानों को सूचित नहीं किया गया एवं निर्धारित टेबल 2 का प्रयोग नहीं किया गया। उक्त प्रपत्र पर किसानों के हस्ताक्षर नहीं होना प्रमाणित करता है कि उक्त रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर ही तैयार की गई है। ऐसा मेरे क्षेत्र की ग्राम पंचायत आंवलोज के चारों गांवों के अलावा अन्य भी कई गांवों में होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

कृपया ऐसे सारे प्रकरणों की सक्षम अधिकारी से जांच करवाकर प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाना सुनिश्चित करावें।

बनास नदी पर निर्मित मातृकुण्डिया बांध के पानी की कृषि हेतु उपलब्धता

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)

महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि मैं निम्न बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा-

1. मातृकुण्डिया में बनास नदी पर 40-50 वर्षों पूर्व मेजा फीडर का बांध बनाया गया था।
2. उक्त बांध की भराव क्षमता 1800 एमसीएफटी थी लेकिन आज तक 1289 एमसीएफटी से अधिक नहीं भरा जा रहा है।
3. उक्त बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य भीलवाड़ा शहर की पेयजल समस्या का समाधान करना था। 55 किमी. लम्बाई की मेजा फीडर के माध्यम से मेजा बांध को भरा जाता है।
4. वर्तमान में भीलवाड़ शहर को चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। भीलवाड़ा शहर को मातृकुण्डिया बांध के पानी की आवश्यकता नहीं है।

अतः मातृकुण्डिया बांध के पानी का पुनः आरक्षण करके कपासन विधान सभा क्षेत्र में पेयजल कृषि के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

5. मातृकुण्डिया बांध से एक नहर और बनाकर किसानों को कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

6. उक्त बांध के 170 एमसीएफटी पानी का आरक्षण रेलमगरा व गंगापुर के लिए किया गया लेकिन अभी तक रेलमगरा व गंगापुर के शहरों को पानी ले जाने के लिए पाइप लाइन की व्यवस्था नहीं करने से पानी नहीं लिया जा रहा है। 170 एमसीएफटी पानी का आरक्षण निरस्त कराने की आवश्यकता है।

अतः निवेदन है कि मातृकुण्डिया बांध के पानी का पुन: आरक्षण करवाकर कपासन विधान सभा क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध कराने की कृपा करावें।

बयाना में उच्च क्षमता के जी.एस.एस. की स्थापना

श्री अमर सिंह (बयाना)

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना रूपवास की ओर आकर्षित करते हुए निवदेन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना रूपवास में किसानों को दिन-रात्रि के समय बिजली दी जा रही है। सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से भरतपुर जिले में किसानों को दिन के समय में कृषि आपूर्ति देना प्रस्तावित है। वर्तमान में बयाना रूदावल क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बयाना स्थित 132 केवी जीएसएस से की जा रही है। रूदावल क्षेत्र का विद्युत भार 60-70 मेगावाट है। बयाना रूपवास क्षेत्र में इसी वर्ष में 2000 से 2500 हजार कृषि कनेक्शन जारी किये जाने हैं, इस कारण विद्युत तंत्र पर भार बढ़ेगा। इसके अलावा रूदावल क्षेत्र में पत्थर व्यवसाय को देखते हुए बड़ी संख्या में विद्युत कनेक्शन होने की संभावना है। क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा जीएसएस की तकनीकी साध्यता मापदण्ड के अनुसार माना है और 220 केवी जीएसएस हेतु जमीन भी रूदावल क्षेत्र में उपयुक्त है और इसी के साथ ही ग्राम पंचायत कपूरा मलूका, थानाडांग, कोट (परूआ), पहाडपुर, मिलकपुर आदि ग्राम पंचायतों में 33 केवी जीएसएस खोले जायें।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इसी बजट सत्र में 220 केवी जीएसएस और 33 केवी जीएसएस खुलवाने की कृपा करें जिससे क्षेत्र की जनता को बार-बार फाल्ट एवं ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिल सके एवं किसानों को पूरी बिजली मिल सकें।

कृषि भूमि में रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़)

महोदय, प्रक्रिया एवं नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि वर्तमान में खेती में रासायनिक पद्धति के बढ़ते प्रचलन के कारण मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खोती जा रही है, इससे साल-दर-साल फसलों का उत्पादन तो कम हो ही रहा है, साथ ही इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जैविक कृषि के कारण हृदयघात, ब्लड प्रेशर एवं कैंसर जैसी घातक बीमारियां आम हो गई हैं, जो समाज के लिए आने वाले समय में एक विकराल समस्या बन रही है।

उल्लेखनीय है कि जैविक कृषि जहां की जा रही है उससे प्राप्त खाद्य अनाज, सब्जियों का स्वाद व सुपाच्यता, स्वरूप बहुत अच्छा है तथा उक्त कृषि से मिट्टी की सेहत और फसल का बेहतर उत्पादन भी होता है, जोकि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है, अगर राज्य सरकार जैविक कृषि को बढ़ावा देकर इस कृषि को करने के लिए अनुदान (सब्सिडी) भी प्रदान करेगी तो राज्य का किसान जैविक कृषि का प्रोत्साहन भी करेगा, जिससे भूमि की उर्वरता में सुधार होने के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने से मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होगा तथा हृदयघात, ब्लड प्रेशर एवं कैंसर जैसी घातक विकराल बीमारियां मानव के आस-पास भी नहीं मंडराएंगी। उत्तराखंड सरकार ने भी प्राकृतिक जैविक खेती के सभी पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड जैविक विकास बोर्ड का गठन किया हुआ है।

अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जैविक कृषि बोर्ड का गठन कर, जैविक कृषि हेतु अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करने की योजना बनाये, जिससे इस कृषि पद्धति को बढ़ावा मिले और मानव जाति को इन घातक बीमारियों से निजात भी मिले।

ओड व भाट जाति के आर्थिक व शैक्षणिक स्तर को प्रोत्साहन

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर)

महोदय, निवेदन है कि राजस्थान में ओड जाति लगभग 22 जिलों में निवास करती है। ओड जाति गरीब जन जाति है। इस जाति के लोग पत्थर

की खानों में, खेतों में भेड़ बकरियां चराने, तालाब, बांध, नहर, किलों के निर्माण में मजदूरी का कार्य आदि काल से करते आ रहे हैं। यह जाति आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजनैतिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति है। इस गरीब समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ओड विकास बोर्ड का गठन करावें जिससे इस पिछड़े समाज का शैक्षणिक आर्थिक स्तर ऊपर उठ सके व समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ सके।

पाली, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, नागोर, श्रीगंगानगर, जोधपुर जिलों में निवास करने वाले ओबीसी वर्ग के बंजारा व भाट जाति के लोग आदिकाल से अनाज, खाद्य सामग्री, युद्ध के समय आवश्यक सामग्री काबुल के म्यांमार तक बैलगाड़ियों से परिवहन का कार्य करते थे। वर्तमान में पशुपालन, खेती, मजदूरी का कार्य करते हैं। शैक्षणिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति है। वर्तमान में बंजारा जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, उप जाति भाट को शामिल नहीं किया गया है, जबकि बंजारा व भाट एक ही जाति है। जिस तरह राज्य सरकार ने गुर्जर, देवासी, गाडोलिया लोहार जातियों की उपजाति को भी अति पिछड़ा वर्ग में जोड़कर आरक्षण का लाभ दिया है, उसी तरह भाट जाति को भी अति पिछड़ा वर्ग में जोड़ने का श्रम करावें जिससे इस जाति वर्ग का भी शैक्षणिक व आर्थिक स्तर ऊपर उठ सके व समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ सके।

बाड़मेर जिला मुख्यालय में जीरा मण्डी की स्थापना

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर)

महोदय, मैं नियम 295 के तहत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जीरा मण्डी खोलने की घोषणा वर्ष 2013 को हुई थी, उसके बाद मण्डी में दुकानों की अलॉटमेंट की कार्यवाही हुए भी काफी समय हो चुका है लेकिन उक्त मण्डी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है।

महोदय, बाड़मेर जैसलमेर का किसान रबी की बुआई में जीरे की खेती बहुतायत मात्रा में करता है और बाड़मेर का जीरा गुजरात की मण्डियों में बिकता है। चूंकि गुजरात की मण्डियों की दूरी अधिक होने के कारण किसानों को परिवहन का खर्च अधिक उठाना पड़ता है, वहां पर कई दिनों तक इन्तजार के बाद जीरे की ब्रिकी होती है इसलिए बजट में बाड़मेर में सरकार ने जीरा मण्डी की घोषणा की थी।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जीरा मण्डी अतिशीघ्र शुरू कर किसानों को राहत प्रदान कराने का श्रम करावें। सधन्यवाद।

भोपालगढ़ में जल जीवन योजना अन्तर्गत बंद पड़े ट्यूबवैलों का पुनः प्रारम्भ

श्री पुखराज (भोपालगढ़)

महोदय, उपर्युक्त विषय में सादर अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पानी की भारी समस्या है। ग्राम पंचायतों में बहुत सारी ट्यूबवैल जो जेजेवाई में थी, वो अभी बन्द पड़ी हैं, उनकी जगह विभाग द्वारा नई ट्यूबवैल नहीं खुदवाई जा रही है। पीएचईडी के स्थानीय अधिकारी बताते हैं कि जेजेवाई के कार्य के लिए बजट का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। जेजेवाई के अन्दर बहुत सारी ग्राम पंचायतों के ट्यूबवैल जिसमें प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत लवेरा कलां में खदावों की ढाणी, मेलाणा में मेघवालों का मोहल्ला, सोयला में रेगर समाज मोहल्ला, चटालिया में नायक समाज मोहल्ला, पालडी राणावतों में मेघवालों की ढाणियां सहित ग्राम पंचायत गरासनी, असाण्डा, रूदीया, खारिया खंगार, बारनी कलां, लवारी, धौरू एव उस्तरा की ट्यूबवैलें वर्तमान में बन्द पड़ी हैं। जेजेएम स्कीम के तहत हर घर कनेक्शन करने की बात की गयी है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति भोपालगढ, पंचायत समिति पीपाड़, पंचायत समिति मण्डोर में इसके टेण्डर हुए लगभग डेढ़ साल हो गये हैं, उसके बावजूद कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं। पंचायत समिति बावड़ी में मेरी विधान सभा की ग्राम पंचायत बावड़ी, गांगाणी, कास्टी, लवेरा कला, पूनियो की बासनी, लवेरा खुर्द, खेड़ापा, मेलाणा, कजनाउ, सोयला, सुरपुरा कलां, सेवकी एवं बुचेटी के अभी तक टेण्डर तक नहीं हुए हैं। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति बावडी की ग्राम पंचायतों के टेण्डर करवाने व अन्य पंचायतों में कार्य की गति बढ़ाने व जेजेवाई की जो ट्यूबवैल बन्द पड़ी हैं, उनके स्थान पर नये ट्यूबवैल खुदवाकर भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था सुचारु करावें।

अतः महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में विभाग द्वारा असफल ट्यूबवैलों को चिन्हित करवाकर पुन:

खुदवाने एवं जेजेएम स्कीम के तहत टेण्डर करवाने की कार्यवाही को अतिशीघ्र पूरा किया जाकर आमजन को राहत प्रदान करावें। सधन्यवाद।

कोटा शहर के घड़ियाल वन क्षेत्र में निवासरत परिवारों को आवासीय पट्टे जारी नहीं करने से मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में कई वर्षों पुरानी बसी आवासीय कालोनियों एवं कच्ची बस्तियों में बड़ी संख्या में पक्के मकान बन चुके हैं, राज्य सरकार द्वारा बिजली पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 35-40 वर्षों से बसी घोड़ा बस्ती, दुर्गावरती बंगाली बस्ती, उडिया बस्ती, बंजारा बस्ती, गुर्जर बस्ती, झाडु बस्ती आदि बस्तियों में अभी तक सरकार ने पट्टे नहीं दिये हैं तथा केशवपुरा से. 4 में निगम व न्यास द्वारा सर्वे नहीं करने के कारण इन कालोनियों को भी पट्टे जारी नहीं हो पाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के शिवपुरा हनुमान बस्ती. किशोरपुरा आदि को घड़ियाल अभयारण्य या वन विभाग की सीमा में होने के कारण होने के साथ पट्टे जारी नहीं किये गये। सच्चाई यह है कि इन बस्तियों का कुछ भाग ही वन या घड़ियाल अभयारण्य की सीमा है, बाकी एक चला भाग अभयारण्य और वन सीमा में आता है।

वहीं दूसरी ओर वन भूमि पर बसी इन बस्तियों में जैसे अन्नतपुरा, बरडा बस्ती, केशर बस्ती. आवली रोझड़ी, नयागांव, भदाना, तालाब बस्ती, हरिजन बस्ती, जगपुरा में सूर्य नगर बस्ती, सकतपुरा क्षेत्र में करणी नगर बस्ती, सालकिया बस्ती, उम्मेदगंज तलाब की पाल में 2 लाख से अधिक लोग 35 वर्षों से भी अधिक समय से निवास कर रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बहुत ही दयनीय स्थिति में यहां के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। वन विभाग के अधिकारीयों की नजरों के सामने यह बस्तियां बसी हैं और अब वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी नाजायज वसूली के लिए मकानों को तोड़-फोड़कर लोगों को परेशान करते हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि घड़ियाल क्षेत्र में बसी पुरानी कालोनियों को पट्टे दिये जाएं और वन भूमि पर बसी कालोनियों का पुनर्वास हो या इन्हें आधारभूत भूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।

आमेर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री सतीश पूनियां (आमेर)

महोदय, विधान सभा क्षेत्र आमेर की अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें यथा मोडी से जालसू कचहरेवाला स्टैंड से जोशीवालों की ढाणी, डिसा से साहिबरामपुरा, देवगुढा (गौरव पथ) से जालसू दादर बावड़ी, प्रतापपुरा रीको सड़क से खपरिया मोड़-पंचायत भवन-डागरों की ढाणी से बहर की ढाणी होते हुए प्रतापपुरा (मुख्य ग्राम) तक एवं एनएच 8 से घटवाडा मुख्य आबादी की सड़क, छापराड़ी सड़क से बोल्या की ढाणी, रायथल से बासडीकलां की सड़क, प्रागपुरा सड़क नाथी की ढाणी से पोखरसा का बास तक, प्रागपुरा से कालाडेरा, अनोपपुरा से कुमावतों की ढाणी गुढासुर्जन सड़क, रायथल की आफरियों की ढाणी से राबडों की ढाणी होते हुए गुमानपुरा सीमा तक, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढासुर्जन से मोहनपुरा कालाडेरा सड़क, गुढासुर्जन भीलपुरा सड़क से सिरसली प्रागपुरा सड़क तक वाया राउप्रावि खेल मैदान, गुढासुर्जन की मिसिंग एवं नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण अभी तक नहीं करवाये जाने के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सड़क मार्गों पर गड्ढे होने के कारण सदैव वाहन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। बरसात के समय स्थिति और भी विकट हो जाती है।

उक्त सड़कों का जनहित में निर्माण/नवीनीकरण/पेचवर्क करवाया जाना नितांत आवश्यक है। अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

जायल में पत्थर खनन उद्योग पर अधिक रायल्टी वसूली

श्रीमती मंजु देवी (जायल)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश में जगह-जगह बहुत सारे खनिज का खनन किया जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में भी ग्राम बड़ी खाटू में चुनाई पत्थर, पट्टी, कातला का प्रचुर मात्रा में खनन किया जा रहा है। बड़ी खाटू में हो रहे खनन पत्थर पर वर्षों से रायल्टी वसूली जा रही है। स्थानीय जनता द्वारा बार-बार मांग की जा रही है कि उन्हें इस रायल्टी से मुक्त किया जाये। बड़ी खाटू में रहने वाले लोगों को भी मजबूरन जोधपुर से पट्टी आयात कर उपयोग में लेनी पड़ती है, कारण स्थानीय पट्टियों पर सरकार द्वारा ज्यादा रायल्टी वसूली जाती है।

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मकराना में स्थानीय लोगों के उपयोग में लिए जाने वाले पत्थर को रायल्टी फ्री कर रखा है तो बड़ी खाटू में भी स्थानीय लोग यानी ग्राम बड़ी खाटू के निवासियों को चुनवाई पत्थर व पट्टियों पर ली जाने वाली रायल्टी से मुक्त किया जावे, ताकि गरीब व मजदूर अपने आशियाने आसानी से बना सकें।

अजमेर शहर में सुचारु पेयजल आपूर्ति हेतु बीसलपुर तृतीय फेज के स्वीकृत कार्य का शीघ्र प्रारम्भ

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)

महोदय, बीते मानसून में भरपूर बारिश के चलते बीसलपुर बांध के लबालब भरने के बाद भी अजमेर को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। अजमेर शहर को वर्तमान में 110-135 एमएलडी पेयजल मिल रहा है जो अपर्याप्त है। सरकार द्वारा अजमेर को प्रारम्भ में 24 घण्टे में पेयजल आपूर्ति करने का वादा किया गया, उसके बाद 48 घण्टे में देने के स्वप्न दिखाये गये लेकिन दोनों ही बातें "मुंगेरी लाल के हसीन सपने" जैसी साबित हुईं। फिलहाल 60 से 72 घण्टे में भी पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर जनता में भयंकर आक्रोश है। पंचशील, वैशालीनगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, ज्ञानविहार, शांतिपुरा, आतेड, किशनगंज, यूआईटी कालोनी, कीर्ति नगर, राज कालोनी, स्वास्तिक नगर, लोहागल, माकड़वाली, हाथीखेडा, बोराज, कांजीपुरा, अजयसर, खरेखड़ी सहित सम्पूर्ण अजमेर क्षेत्र से प्रतिदिन पेयजल संबंधित शिकायतें आ रही हैं। इन कालोनियों में सर्दियों में भी पेयजल संकट है तो गर्मियों में क्या हालात होंगे, कल्पना की जा सकती है। कई कालोनियों में पाइप लाइनें लीकेज पड़ी हैं। विभागीय अधिकारियों को बराबर अवगत कराने के बाद भी चार-चार माह तक दुरुस्त नहीं हो पाती हैं।

बीसलपुर थर्ड फेज की अभी से व्यवस्था करें नहीं तो पेयजल को लेकर त्राहि-त्राहि होना तय है। गत सरकार में स्वीकृत बीसलपुर थर्ड फेज का कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए, साथ ही केन्द्र सरकार की अमृत योजना फेज द्वितीय के अजमेर शहर में 186 करोड़ के प्रस्तावित पेयजल कार्यों को केन्द्र सरकार से सकारात्मक समन्वय स्थापित कर जल्द धरातल पर लाने की आवश्यकता है, ताकि गर्मियों में लोगों को पेयजल समस्या से राहत मिल सके।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार "अजमेर शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारु करने एवं बीसलपुर तृतीय फेज का स्वीकृत कार्य तत्काल

प्रारम्भ करने" की दिशा में संबंधित विभाग को पाबंद करते हुए संबंधित आवश्यक कार्यवाही कराकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करावें।

सलूम्बर के राजस्व ग्राम डूंगावतफला के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपुर्ण अंकन का यथा स्थितिवार संशोधन

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, 1. तहसील सलूम्बर के राजस्व ग्राम डूंगावतफला जो कि पटवार मण्डल डाल गांव है, उक्त डूंगावतफला गांव जो कि मूल गांव डाल से बना है, जिसके बनने के बाद सन 2018 में सलूम्बर में उदयपुर-बांसवाड़ा नया बाईपास बनाया गया। उस बाईपास के दोनों ओर कई खातेदारों की भूमि राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में जितनी दर्ज थी उतनी भूमि का नक्शे में तरमीम नहीं किया गया, खातेदारों का जमाबन्दी में रकबे के मुकाबले नक्शे में रकबा कम अंकित किया गया तथा कई प्रभावशाली लोगों को जो कि सड़क के पास कभी भी उनकी भूमि नहीं थी, उन्हें भी कहीं अन्य जगह की अलोटशुदा भूमि को नक्शे में सड़क के पास बताया गया, जबकि उनको वहां कभी भी कोई जमीन आबंटित नहीं की गई थी।

2. यह कि नक्शे में जिस जगह नहर बता रखी है, उस जगह मौके पर नहर ही नहीं है तथा जिस जगह वास्तव में नहर है, उस जगह को नक्शे में नहर के रूप में अंकन नहीं किया गया है।

3. यह कि नई तरमीम में खातेशुदा जमीन के मुकाबले तरमीम मौके के अनुसार नहीं हुई है।

4. यह कि नक्शे की स्थिति मौके की स्थिति से काफी भिन्न है।

5. यह कि बिलानाम राजस्व भूमि में कड़े गरीब एवं असहाय काश्तकार जिनके पास धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली के नोटिस प्राप्त हुए, उन्हें मौके से राजस्व के संबंधित स्थानीय अधिकारियों ने उनके काबिज होने के तथ्य को नजर-अंदाज कर ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को नक्शे एवं जमाबन्दी में गलत तरीके से इन्द्राज कर दिया, जबकि ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति कभी भी उस भूमि पर गये नहीं एवं न ही उन्हें उक्त भूमि कभी आबंटित ही की गई है।

अतः निवेदन है कि डूंगावतफला राजस्व ग्राम के तरमीम नये सिरे से राजस्व रिकार्ड मे सैटलमेंट की पूर्व की स्थिति के अनुसार किये जाने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही किये जाने का आदेश फरमावे।

चौहटन में अनुसूचित जनजाति परिवारों को कृषि विद्युत कनेक्शनों में प्राथमिकता

श्री पदमाराम (चौहटन)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चौहटन सीमावर्ती क्षेत्र है। यहां पर रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग गरीब हैं व शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। जीवनयापन करने का मूल साधन कृषि है और शिक्षा का स्तर निम्न है। इन लोगों को विद्युत कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाये और शिक्षा को मूल धारा में लाने हेतु टाडा व माडा योजना के तहत नई योजना शुरू करनी चाहिये एवं जिस तरह आदिवासी क्षेत्र में नौकरी में अतिरिक्त प्रावधान है उसी प्रकार बाड़मेर जिले के अनुसूचित जनजाति लोगों को विद्युत कृषि कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन व शिक्षा की मूल धारा में जोड़ने हेतु नई योजना लाई जाये।

राजकीय सेवाओं में प्रदेश के मूल निवासियों को अधिकतम प्रतिनिधित्व

श्रीमती गंगा देवी (बगरू)

महोदय, राजस्थान हमारी जन्म भूमि है। हम राजस्थान के निवासी हैं तो पहला हक हमारा है। राजस्थान सरकार की सरकारी नौकरियों में 90% हमारे राज्य के छात्र और छात्राओं को नौकरी मिले। पहला हक राजस्थान के लड़का/लड़कियों का है। राजस्थान ही हमारी कर्म भूमि है।

मैं सदन के माध्यम से निवेदन करती हूं कि हमारे राजस्थान के लड़के/लड़कियों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन करें और संविदा पर भी राजस्थान के युवक/युवतियों का ही रिजर्वेशन होना चाहियें। राजस्थानवासियों को उसका हक मिले।

राजकीय सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करना

श्री हरीश चौधरी (बायतू)

महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के संबध में मैं ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं।

राज्य में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या लगभग 50 प्रतिशत से भी

ज्यादा है और राज्य सरकार की सेवाओं में ओबीसी वर्ग का आरक्षण केवल मात्र 21 प्रतिशत ही है। उसमें भी विभिन्न विसंगतियों के कारण यह प्रतिशत और कम हो जाता है।

उल्लेखनीय है कि मंडल कमीशन की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा 1992 में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जिसके अनुरूप राज्य में भी अन्य पिछडा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देना था परन्तु 1992 में इन्दिरा साहनी व अन्य बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के निर्णय में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक की बाध्यता रखी गई थी।

2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देते समय अधिकतम आरक्षण की बाध्यता समाप्त की गई, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा 07 नवम्बर, 2022 को वैध करार दिया गया। उक्त बाध्यता समाप्त होने के पश्चात् छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी जनसंख्या को आधार मानकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया गया है।

केन्द्रीय सेवाओं की तर्ज पर और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप राजस्थान में भी जनसंख्या के अनुपातानुसार ओबीसी वर्ग का आरक्षण सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थानों में 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाये ताकि इस वर्ग के साथ न्याय हो सके।

अतः मैं सरकार का ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत आकर्षित करना चाहता हूं।

परिशिष्ट-02

लिखित वक्तव्य

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद पर माननीय सदस्यगण के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं)

(1) रावतभाटा उप जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करना।

(2) रावतभाटा नगरपालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत करना आबादी 1 लाख।

(3) कुण्डाल ग्रामीण क्षेत्र रावतभाटा उपखण्ड में नहर Lift Irrigation Project की DPR बनवाकर, राणा प्रताप सागर का Back water से सभी ग्रामीण क्षेत्रों को नहर का पानी देना।

(4) बेगूं नगरपालिका को उच्च श्रेणी में क्रमोन्नत करना।

(5) बेगूं एवं रावतभाटा उपखण्ड पर नर्सिंग कालेज खोलना।

(6) बेगूं उपखण्ड में ब्राह्मणी नदी पर वामनहेड गांव पुल निर्माण करवाना।

(7) गगरांर पंचायत को नगरपालिका बनाना।

(8) साडास (गगरांर) को उप तहसील में क्रमोन्नत करना।

(9) गगरांर में राजकीय महाविद्यालय को PG में क्रमोन्नत करना।

(10) पारसोली उप खण्ड बेगूं के ग्रामीण क्षेत्र ITI स्थापित करना।

(11) नवीन पुलिस चौकी खोलना गोरला, मोती पुरा, राजगढ़।

(12) रावतभाटा में उप परिवहन कार्यालय को DTO में क्रमोन्नत करना।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी)

(1) चीखली में मुन्सिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जावे।

(2) CHC सीमलवाड़ा को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जावे।

(3) चौरासी विधान सभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोला जावे।

(4) सहायक अभियन्ता कार्यालय झोथरी में खोला जावे।

(5) सहायक अभियन्ता कार्यालय धुम्बौला को अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में क्रमोन्नत।

(6) राजकिय महाविद्यालय सीमलवाड़ा में अतिरिक्त कला संकाय खोला जावे।

(7) सहायक कृषि कार्यालय सीमलवाड़ा खोलना।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़)

(1) TSP क्षेत्र में पे स्केल 1 से 9 तक में सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग करता हूं।

(2) RAS & RJS में राजस्थान में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 12.5% में से 6% अलग से TSP के लिए रिजर्व हो ताकि वहां के युवाओं का RAS & RJS बनने का सपना साकार हो।

* 2013 GNM & ANM भर्ती जिसके पद भी सृजित हो रखे हैं, को पूरी किये जाने की मांग करता हूं।

* अरनोद उपखण्ड और दलोट तहसील को नगरपालिका बनाने की मांग करता हूं। सुहागपुरा और दलोट को उपखण्ड कार्यालय बनाने की मांग करता हूं।

* कम्प्यूटर अनुदेशक एवं शारीरिक शिक्षक भर्तियों में पात्रता में छूट देकर भर्ती में खाली रहे पदों को भरे जाने की मांग करता हूं।

* पानमोडी, बारावरदा को उपतहसील बनाने की मांग करता हूं।

* देवगढ़ राजा-महाराजाओं के काल में स्टेट था, को तहसील बनाये जाने की मांग करता हूं।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

आपने पैरा 93 में सड़कों का कार्य दिया। मेरे यहां आसीन्द से दौलतगढ़ 9 कि.मी. तथा आसीन्द से रायला सड़क तथा इसके अलावा 65 सड़कें जो या तो टूटी हुई हैं तथा कुछ जो आज भी कच्ची हैं। मैंने सब सड़कों की लिस्ट विभाग में दे रखी है, उनको आपने एक सड़क के अलावा कुछ नहीं दिया। मेरा निवेदन है आपने अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन कार्य की जो योजना है उसमें 1. आसीन्द से दोलतगढ़, विजयनगर चौराहा से आकडसादा, घाटी से आमेसर, सापोला से रामगढ़, गागेडा से तिलोली, संग्रामगढ़ से दांतडा, अटांली से भिमलत, ब्राम्हणों की सरेरी से केरिया, गांगलास से छोटी रूपाहेली, उदलपुरा से रायला, गांगलास चौराहा से रायला वाया खारडा, रूपाहेली से भोजरास बाईपास सड़क, खातीखेडा से आनन्दीपुरा, आगुचा से अमरतिया, परा से बाजुन्दा, परा से भैरूखेडा, मोहरा से जालरिया, नेगडिया से दौलतगढ़, जबरकिया से धोली, जोधडास से खारडा, डोटा से करियाला, आसीन्द से चैनपुरा वाया अरजुनपुरा, सबलसागर से गायत्रीनगर, नारायणपुरा से एनएच 158 लिंक सड़क, जालरा से धरडीया जोगीभाटा, कटार

से सिरोली घाटी, आसीन्द से दातड़ा बांध, उखंलीया से देवरीया, अमरतीया से बालापुरा। कोटड़ी से आगुचा तथा और भी कई सड़कें हैं जो टूटी या कच्ची हैं।

2. शाहजहांपुर दादिया सड़क से मानका रामसिंहपुरा होते हुए हरियाणा बोर्डर तक।

3. एनएच 48 से गुगलकोटा होते हुए हरियाणा बोर्डर तक।

4. एनएच 48 से सख्तपुरा बावद होते हुए मानका तक।

उक्त सड़कें वर्ष 2021 दिसम्बर से वर्ष 2022 दिसम्बर तक पूरे एक वर्ष तक एनएच 48 बंद होने की वजह से पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिन पर वाहन चलाना दूर पैदल चलना भी असंभव है क्योंकि इन सड़कों पर डामर तो बचा ही नहीं जिसकी वजह से धूल उड़ती है, जो लोगों को अस्थमा व अन्य बीमारियों से ग्रसित कर रही है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि इन सभी सड़कों का विशेष पैकेज के द्वारा पुनः निर्माण करवाया जाए क्योंकि यह सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण नॉन-पेचेबल में भी कवर नहीं होती हैं।

आपने पैरा 103 में गांवों में Shallow Sewer Treatment Plants व FSTP लगाने की घोषणा की है। इसी के तहत मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो मुख्य कस्बे शाहजहांपुर व नीमराना जो कि बड़े औद्योगिक क्षेत्र भी हैं और इन कस्बों में बाहरी लोगों की बहुत बड़ी आबादी रहती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोनो कस्बों शाहजहांपुर व नीमराना को इसमें शामिल किया जाए।

आपने अपने पहले बजट में चार हजार कुछ करोड़ की लागत से चंबल नदी व ईसरदा बांध से अलवर जिले के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की बात कही थी जिस पर आज तक एक रुपये का कार्य नहीं हुआ है। आपने एक बार फिर इस बजट में सतही स्रोत आधारित पेयजल परियोजना के तहत चंबल अलवर भरतपुर परियोजना अलवर भरतपुर के तहत 5,776 करोड़ की लागत से पीने के पानी के लिए अलवर जिले के लिए घोषणा की है। इस पर कहना चाहूंगा कि सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करे इनको धरातल पर लाने का काम भी करे जिससे आमजन गांव में रहने वाले किसान गरीब को राहत मिल सके।

आपने राज्यपाल अभिभाषण में और इस बजट में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रदेश के हालात हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। बिजली तो आती है नहीं, फिर पता नहीं हम ऊर्जा के

क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे हो गए? आपने पैरा 116 में इफेक्टिव बिजली प्रबंधन के लिए ट्रांसमिशन network energy accounting एंव demand side management के लिए विभिन्न श्रेणी के केवी सब स्टेशन, विद्युत सर्किल, विद्युत कार्यालय बनाने की बात कही है जिसके तहत आपने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इनके बनाने की घोषणा की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंडावर के चिरूनी में 132 केवी सब स्टेशन व बधिन में 33 केवी GSS बनाने की घोषणा की जाए जिससे ग्रामीणों को सुचारु रूप से बिजली मिल सके।

बड़ा क्षेत्र होने की वजह से और कनेक्शन अधिक होने की वजह से सहायक अभियंता विद्युत कार्यालयों पर काम का अधिक दबाव रहता है जिसकी वजह से आमजन किसान गांव का गरीब व्यक्ति परेशान रहता है, इसलिए आमजन को राहत पहुंचाने के लिए मुंडावर में स्थापित सहायक अभियंता विद्युत को अधिशाषी अभियंता विद्युत में क्रमोन्नत किया जाए। साथ ही ततारपुर में नवीन सहायक अभियंता विद्युत का कार्यालय खोलने की घोषणा करें।

आप कहते हैं कि शांति के बिना हमारे तमाम सपने मिटकर खाक हो जाते हैं और राजस्थान सदा से एक शांतिप्रिय प्रदेश रहा है पर प्रदेश के हालात आज इसके बिलकुल विपरीत हैं जो कि हम रोज सुबह अखबार व दिनभर elctronic मीडिया पर खबरों के माध्यम से पढ़ते व देखते हैं। अगर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंडावर में हाल ही में हुई घटनाओं की बात करूं तो उसमें मुख्य रूप से-

1. नीमराणा में आरपी सन्स ज्वैलर्स धर्मवीर सोनी के यहां पर चार-पांच बदमाशों ने देशी कट्टे के साथ लूट की।
2. बासनी गांव में वहां के एक व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर दिनदहाड़े कट्टे से फायर कर 20 लाख रुपये की फिरोती मांगी गई।
3. रामसिंहपुरा व मानका गांवों में हरियाणा के बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई।
4. नीमराणा में रात के समय कुछ दुकानों जिसमें मुख्य रूप से सुनार व महंगा सामान रखने वाले स्थानों पर ताले तोड़ कर उन दुकानों का सामान लूटा गया।

ये तो अभी कुछ दिनों में हुई घटनाएं हैं अगर मैं इस सरकार के कार्यकाल में हुई सभी घटनाओं का जिक्र करने लग गया तो मुझे बहुत लम्बा समय लगेगा, जो कि आपके द्वारा मुझे निश्चित रूप से नहीं दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की बात करूं तो उसके एक तरफ हरियाणा का बहुत लंबा हिस्सा लगता है जिसकी वजह से अपराधी अपराध करके दूसरे राज्य में आसानी से चला जाता है और हमारी पुलिस को उसे पकड़ना मुश्किल (कठिन) हो जाता है इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हरियाणा से लगते हुए बासनी, शीलगांव, रामसिंहपुरा, कांकर में पुलिस चौकियां खोली जाएं। साथ ही सोडावास व अजरका चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया जाए व मुण्डावर में उप अधीक्षक कार्यालय खोला जाए। साथ ही मुण्डावर के थानों में नफरी की भारी कमी है, जिसे भी सरकार पूर्ण करने का कार्य करे। साथ ही विधान सभा क्षेत्र के तीन बड़े कस्बे मुण्डावर, नीमराणा व शाहजहांपुर में यातायात पुलिस की व्यवस्था की जाये जिससे आने वाले समय में अपराधी अपराध करके भागने में सफल ना हो, अपराध पर अंकुश लग सके और आमजन को राहत मिल सके और वो शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके और जो बात आपने कही "शांति के बिना हमारे तमाम सपने मिट कर खाक हो जाते हैं" वो भी पूर्ण हो सकें।

आपने पैरा नं. 148 में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार की बात कही, जिसके तहत आपने प्रदेश में उप तहसील, तहसील, उपखण्ड, नगरपालिका खोलने व क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शाहजहांपुर कस्बा आता है जो कि एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है और एनएच 48 पर लगता है और आबादी के हिसाब से भी शाहजहांपुर कस्बा मुण्डावर विधान सभा के अंतर्गत आने वाले गांवों में सबसे अधिक बड़ा है। जिसकी वजह से शाहजहांपुर कस्बा नगरपालिका बनने के सभी मापदंड पूरा करता है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जब मुख्य मंत्री बजट पर अपना रिप्लाई दें तो शाहजहांपुर को नगरपालिका बनाने की घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर, भौगोलिक दृष्टि से अलवर जिले की सबसे बड़ी विधान में से एक है जिसमें 58 ग्राम पंचायतें व एक नगरपालिका (अब दो) आती हैं और कुल 54 पटवार मण्डल आते हैं। अतः लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए मेरे विधान सभा के शाहजहांपुर, ततारपुर व सोडावास को अपने बजट रिप्लाई में उप तहसील बनाने की घोषणा करें जिससे आमजन व किसान को राहत मिल सके और आमजन के कार्यों में तेजी आ सके।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान वीरों, शूरवीरों की धरा है, ये सदन में उपस्थित हर एक सदस्य जानता है। जिसमें विशेष तौर पर अलवर जिले का विशेष योगदान है। मैं मेरे विधान सभा मुण्डावर के गांव कुतीना के शहीद हजारी सिंह जिन्हें अपने शौर्य के लिए वीर चक्र भी दिया गया, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं वीरों का सम्मान करते हुए गिलोठ इण्डस्ट्री में स्थापित चौक को हजारी सिंह के नाम से किया जाये और साथ ही उनकी मूर्ति लगाई जाये, जिससे इन वीरों का सम्मान हो सके और साथ ही युवा पीढ़ी इनकी शौर्य की गाथा जान सके और अपने जीवन में बदलाव कर सके।

आपने पैरा 126 में नये पैनोरमा निर्माण की बात कही है। इसी क्रम में सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजपूत समाज की भावना को देखते हुए नीमराणा उपखण्ड पर पृथ्वीराज चौहान का निर्माण किया जाये।

आपने पैरा 162 पंचायती राज संस्थानों के अमूल्य योगदान को देखते हुए प्रमुख प्रधान व सरपंचों के मानदेय व भत्तों में 15 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। प्रमुख, प्रधान व सरपंचों के साथ-साथ पंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् सदस्यों की भी विकास की कड़ी में अहम भूमिका है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इनके लिए उचित अनुपात में मानदेय दिया जाए और साथ ही जिस तरह सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुखों को विकास के लिए पैसा मिलता है उसी तरह पंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद् सदस्यों को भी उचित अनुपात में अपने क्षेत्र में विकास के लिए बजट आबंटित किया जाए।

आपने पैरा 167 में किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली की बात करी है। आपने अपने पूर्व में दिये गये बजट में घोषणा की थी सभी किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी पर आज हालात इसके बिलकुल विपरीत हैं। किसान इस कड़ाके वाली ठण्ड के समय रात को अपने खेतों में पानी देने को मजबूर है। रात के समय बिजली आये वो भी किसान झेलने को तैयार है पर उसमें भी सरकार कटौती करके उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार अपनी घोषणाओं को पूरा करके किसान को राहत प्रदान करे।

साथ ही गांव में बसने वाला गरीब, किसान, ट्रांसफार्मर की कमी झेल रहा है जिसकी वजह से परीक्षाओं के इस समय में अपने बच्चों के भविष्य को

लेकर वह चिंतित है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि 72 घंटों में ट्रांसफार्मर उपलब्ध करायें, जिससे बच्चों की परीक्षा व किसानों की फसल खराब न हो तथा बच्चों व किसानों का भविष्य अंधकार में न जाये।

बजट 2023-24 के पैरा नं. 42 व 43 में आपने युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से कोच के 100 पद सृजित की जाने की घोषणा की है। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन हेतु 150 करोड खर्च होने की घोषणा की है जबकि मुख्य मंत्री जी द्वारा पूर्व में बजट 2011-12 के पैरा नं. 149 में राज्य खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 78 नये प्रशिक्षकों एवं सभी संभागीय मुख्यालयों पर खेल प्रबंधकों की नियुक्ति करने की घोषणा की गई थी जिसमें से कितने पदों पद खेल प्रशिक्षक व खेल प्रबंधकों की नियुक्ति की गई तथा इस बार के बजट भाषण में 100 पदों की घोषणा की गई, उसमें खेल प्रबंधकों के पदों की घोषणा नहीं की गई, इसमे आपकी खेलों के प्रति मंशा साफ जाहिर नहीं हो रही है।

मेरी जानकारी के अनुसार पूर्व में बजट घोषणा 2011-12 के अनुसार सभी संभाग मुख्यालय पर खेल प्रबन्धकों के 7 पदों में से 5 पदों को ही भरा गया जबकि 2 पद अभी भी रिक्त हैं। क्या इनको भी मुख्य मंत्री द्वारा पुरानी बजट घोषणा को वर्तमान में 100 कोचों के साथ ही भरे जाने की घोषणा करेंगे अथवा नहीं? स्पष्ट करें क्योंकि आप खेलों के प्रति अधिक रूझान रखते हैं। इसलिए अच्छा तो यह होता कि कम से कम 100 कोचों के साथ 10 पद खेल प्रबन्धकों के स्वीकृत करने चाहिये थे।

यही नहीं राजस्थान राज्य में आयोजित किये जाने वाले विभिन्न खेलों के आयोजन को सफल बनाने के साथ-साथ उसके प्रचार-प्रसार मार्केटिंग, रजिस्ट्रेशन इत्यादि के लिए राजस्थान क्रीड़ा परिषद् में स्पोर्ट्स मैनेजर की नियुक्ति की जावे जिससे राष्ट्रीय खिलाड़ी को जिसने बैचलर आफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट (BSM) की उपाधि प्राप्त की है, उसे स्पोर्ट्स मैनेजर के पद पर नियुक्ति का लाभ मिल सके।

अन्त में आपने जो पैरा नं. 5 में कहा है कि-

"हर संकट का हल होगा

आज नहीं तो कल होगा।"

बिलकुल सही कहा क्योंकि आने वाले कल हम आपके स्थान पर होंगे और हर समस्या का हल करेंगे।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के इस कार्यकाल के अंतिम बजट पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में जो सपने दिखाये हैं उन सपनों का साकार होना असंभव लगता है क्योंकि अब सरकार का समय भी कम बचा है। अक्टूबर में हमारे यहां चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी जबकि सरकारी कैलेण्डर में बजट का समापन 31 मार्च तक होता है। मुझे लगता है कि जितनी घोषणाएँ की हैं, राजस्थान में संसाधनों की भी कमी है जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं ये किसी भी सूरत में पूरी नहीं हो पायेंगी।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की सबसे प्रिय योजना चिरंजीवी योजना है। आप जहां भी जाते हैं चिरंजीवी योजना की बात जरूर करते हैं। इस योजना का भी धरातल पर बुरा हाल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मा. मुख्य मंत्रीजी ने इसका दायरा तो बढाया है सीधे 10 लाख से 25 लाख रुपये कर दिया है परन्तु जितने भी प्राइवेट हास्पिटल हैं वे आईपीडी में सर्जरी वाले केस तो देखते हैं लेकिन ओपीडी में न तो मरीजों को देखते हैं न ही भर्ती करते हैं। किसी भी मरीज को लगने वाले सामान की कीमत व क्वालिटी के बारे में नहीं बताते हैं। मरीज से 20 हजार के सामान के 01 लाख रुपये तक वसूल लेते हैं। किसी भी सामान की कीमत के बारे में मरीज को पूरी जानकारी देकर ही लगाने हेतु कहें। मरीज जब मर रहा होता है तो परिजनों की पहली प्राथमिकता उसकी जान बचाने की होती है। इसलिए क्वालिटी निर्धारित की जाये ताकि आम जनता, गरीब आदमी इसका फायदा ले सके।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में विकास के क्या हालात हैं? सारा का सारा विकास कितनी जल्दी धराशायी हो जाता है। सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं, पुलिया बनती है जल्दी ही टूट जाती हैं। मा. मुख्य मंत्री जी घोषणाएं तो अच्छी कर लेते हैं पर उन घोषणाओं का लाभ धरातल पर जनता को मिल रहा है अथवा नहीं, यह देखने की उन्हें फुर्सत ही नहीं है। मा. मुख्य मंत्री महोदय ने अन्नपूर्णा योजना की घोषणा की है कि जो परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं उन्हें आप दाल, तेल, शक्कर नमक एवं मसाले आदि दोगे। ये बहुत अच्छी बात है। माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने का पोर्टल विगत चार वर्षों से बन्द पड़ा है, उसे चालू करवाया जावे, जिससे पात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड जाये।

मा. सभापति महोदय, बजट भाषण में मा. मुख्य मंत्री जी ने जो रेवड़ियां बाटी हैं उनसे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। सरकार द्वारा राइट टू हैल्थ बिल लाया गया जो प्राइवेट हास्पिटलों के विरोध व दबाव में धरा का धरा रहा गया।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक आदर्श/मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की घोषणा की थी, उसका कोई अता-पता नहीं है। मौहल्ला क्लिनिक खोलने की घोषणा भी पूरे प्रदेश में 5-7 जगहों के अलावा कहीं नहीं खोले गये हैं। पूरे प्रदेश के माननीय यहां बैठे हैं, बता दें किस-किस के विधान सभा क्षेत्र में मौहल्ला क्लिनिक खोले गये हैं?

2018 में जन घोषणा पत्र में किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी का वादा कर किसानों से वोट लिए थे लेकिन 2.50 लाख से ज्यादा किसान आज भी कर्जमाफी का इंतजार कर रहे हैं। आपने 2009 के बजट में सभी किसानों को दिन में बिजली देने की घोषणा की थी, उसका क्या हश्र हुआ, आप भी जानते हैं। दिन में तो दूर किसानों को रात में 6-6 घंट के ब्लाक निर्धारित किये गये हैं, उसके अनुसार भी बिजली नहीं मिल रही है।

मा. सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट 2021 एवं 2022 में प्रत्येक विधान सभा में स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर क्रमश: 5 एवं 10 करोड़ रुपये की लागत से सड़क बनाने की घोषणा की थी, उसमें से अभी तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 2 सड़कों का निर्माण हुआ है। विभागीय अधिकारियों में मुख्य मंत्रीजी की घोषणा को पूर्ण कराने का भी उत्साह नहीं है। मा. मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में भी 10 करोड़ रुपये की लागत से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराने की घोषणा की है, तो अधिकारियों को निर्देशित करें कि शीघ्र पूर्व की घोषणा में स्वीकृत सड़कों का निर्माण मार्च से पूर्व किया जावे तथा आगामी बजट में घोषित सड़कों की निर्माण की अनुशंसा भी स्थानीय विधायक से शीघ्र प्राप्त कर स्वीकृत की जावे ताकि जल्दी निर्माण हो सके।

पेयजलः मा. सभापति महोदय, नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या को देखते हुए जन जीवन मिशन के अन्तर्गत नसीराबाद क्षेत्र हेतु मा. मुख्य मंत्री महोदय द्वारा गत बजट सत्र 2022-23 में बिन्दु संख्या 88 में 36 वृहद् पेयजल परियोजना के कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिनमें से एक नसीराबाद वृहद् पेयजल परियोजना जिला अजमेर राशि 163 करोड़ रुपये भी थी किन्तु एक वर्ष व्यतीत होने के उपरांत

भी उक्त योजना पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। यह घोषणा मात्र घोषणा बनकर रह गई है। इस योजना में विलम्ब होने से नसीराबाद शहर सहित आस-पास के गांवों को बीसलपुर योजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित था, किन्तु राज्य सरकार एवं विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते विगत एक वर्ष से यह योजना मात्र कागजी बनकर रह गई है। इस संबंध में विभाग में जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि जब तक अजमेर जिले को बीसलपुर बांध से मिलने वाले पानी की मात्रा में इजाफा नहीं होगा तब तक इस योजना पर कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

बीसलपुर से अजमेर को 5 टीएमसी पानी एवं जयपुर को 11.2 टीएमसी पानी आरक्षित किया गया है। वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नई परियोजनाएं आरम्भ होने से अतिरिक्त पानी की मांग की जा रही है। वैसे तो सही तो यह है कि अजमेर जिले के लिए बीसलपुर से 3.7 टीएमसी पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकता है। अजमेर जिले के लिए बीसलपुर बांध से अतिरिक्त पानी का कोटा बढ़ाया जाये। इससे जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनता को लाभ मिल सकेगा एवं नसीराबाद वृहद् पेयजल परियोजना जिला अजमेर राशि 163 करोड रुपये के कार्य को भी गति मिल सकेगी। नसीराबाद के पास नेशनल हाईवे स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय झडवासा को भी बीसलपुर योजना एवं जल जीवन मिशन योजना से जोड़ा जावे।

माननीय सभापति महोदय, मा. मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले बजट में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नंदी गौशालाएँ खोलने की घोषणा की थी। मेरे विधान समा क्षेत्र में अभी तक एक भी गौशाला नहीं खोली गई है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में मुख्य मंत्री महोदय ने महात्मा गांधी विकास पथ बनाने की घोषणा की थी। मेरे द्वारा विधायक निधि से 10-10 लाख रुपये सहयोग निधि प्रदान करने के बावजूद मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी विकास पथ का निर्माण नहीं हो सका है।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा भी छलावा साबित हुई है। मेरा मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि इस तरह की घोषणा नहीं करें और यदि करें तो उन्हें धरातल पर उतारने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की 24 घंटे सप्लाई की घोषणा भी थोथी साबित हुई है। गांवों में तो लोड सैटिंग के नाम पर रोजाना 2-2 घंटे दिन में कई बार बिजली सप्लाई बाधित कर दी जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मे तो वीसीआर भरने के लिए इंजीनियर सुबह ही पहुंच

जाते हैं। उन्हें मात्र वीसीआर ही भरनी है, बिजली सप्लाई व्यवस्था को सुधारना नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के नसीराबाद में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय जिला परिवहन कार्यालय खोला गया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने आते ही बन्द कर दिया। नसीराबाद क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगरी है। अतः बन्द किये डीटीओ कार्यालय को पुनः शुरू किया जावे।

माननीय सभापति महोदय, अंग्रेजी माध्यम स्कूल आपने खोल दी है पर उनमें अध्यापकों की नियुक्ति हिन्दी माध्यम के विद्यालयों से हटाकर अंग्रेजी माध्यम में लगा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बालिका स्कूलों की पुराने भवनों में ही संचालित किया जा रहा है जिससे हिन्दी माध्यम की बालिकाओं को इधर-उधर जाना पड़ रहा है। आपने मेरे निरंतर आग्रह करने पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के पीसांगन में राजकीय कालेज खोलने की बजट में घोषणा की है, उसके लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसका संचालन नवीन सत्र में प्रारम्भ किया जावे एवं भवन निर्माण के लिए बजट में प्रावधान करें एवं प्राध्यापकों एवं स्टाफ की व्यवस्था भी कराई जावे।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के रा.उ.प्रा.वि., शिवपुरा व मोडी, समरथपुरा आदि अनेक स्कूल हैं जिनमें 300-400 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन्हें 12वीं स्कूल में क्रमोन्नत किया जावे एवं स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जावे।

सभापति महोदय, पीसांगन से पुष्कर, मांगलियावास से पीसांगन, बुधवाडा से पिचौलिया, धोलादांता से भोमाजी का बाडिया आदि सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराया जावे। नसीराबाद के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सक व अन्य नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जावे। नेत्र चिकित्सा आपरेशन थियेटर को पुनः चालू किया जावे, जो इस सरकार के आने के बाद से बन्द है। नसीराबाद शहर हाईवे पर स्थित होने से अजमेर से पहले कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण नसीराबाद उप जिला चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर स्थापित किया जावे।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का पीसांगन कस्बा जो ग्राम पंचायत मुख्यालय होने के साथ-साथ उपखण्ड मुख्यालय है एवं तहसील कार्यालय भी है, अतः पीसांगन कस्बे की वर्तमान जनसंख्या भी नगरपालिका की अर्हताएं पूर्ण करती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पीसांगन को आप बजट रिप्लाई में नगरपालिका घोषित करने का कष्ट करें।

उद्योगों को बढ़ावा देने का जो राज्य सरकार बजट के माध्यम से नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की जो घोषणा इस बजट में और पिछले बजटों में हुई हैं परन्तु आज मैं उद्योग मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इन औद्योगिक क्षेत्रों की आपने घोषणा तो कर दी। जिन गांवों व ढाणियों की जमीन अवाप्त की जाती वहां के किसानों की दुर्दशा पर उद्योग विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं।

सभापति महोदय, बेवन्जा रीको जो नसीराबाद के निकट स्थित है, जिसमें 1st phase की अवाप्ति हो चुकी है। कुछ औद्योगिक इकाइयाँ यहां पर संचालित हो रही हैं। अब तो IInd phase की अवाप्ति कार्रवाई चल रही है।

कई दिनों से बेवन्जा, दिलवाड़ा व आसपास के किसानों की जिनकी जमीनें अवाप्ति की कार्रवाई चल रही है। सभी धरनों पर कई दिनों से हैं। अत: मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि रीको के अधिकारी किसानों की मांगों को पूरा करें एवं किसानों का धरना समाप्त करने की कारवाई करें।

बेवन्जा व आसपास के किसानों की हमारे से भी बात हुई। वे सभी उपखण्ड मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं। प्रशासन से बातचीत भी हुई। जिला कलेक्टर साहब से मोबाइल पर वार्ता भी हुई परन्तु उन्होंने यह मामला रीको का होने के कारण सीधे तौर पर ग्रामीणों की मांगों पर कार्रवाई करने में असमर्थता जताई। इसलिए माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि मामले की जल्द सुनवाई कर किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करें। उनके राजस्व, अवाप्ति से सम्बन्धित एवं रास्ते की समस्या का निस्तारण करें।